जापान में महिला पीएम

भारत के प्रति मित्रवत

दुनिया की सबसे एडवांस्ड इकॉनमी में से एक होने के बावजूद, जापान एक ट्रेडिशनल एशियाई समाज बना हुआ है जहां पुरुषों ने राज किया है और महिलाएं अक्सर पब्लिक लाइफ से दूर रही हैं। हालांकि, ताकाइची के देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ, देश एक नया रास्ता बनाने और कुछ बड़े कदम उठाने के लिए तैयार है जो बहुत समय से टल गए थे। जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर के तौर पर साने ताकाइची का चुनाव सिंबॉलिज्म और मतलब दोनों से भरा हुआ है।

जापान में सबसे ऊंचे पद पर ताकाइची का आना वाकई भारत के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि वह चीन के प्रति सख्त मानी जाती हैं और उन्होंने पहले भी भारत समेत दूसरे एशियाई देशों से दोस्ती करने की इच्छा दिखाई है ताकि अपने देश का स्ट्रेटेजिक रुख मजबूत किया जा सके और इस इलाके में गुंडों का सामना किया जा सके।

भारत के लिए, उनकी नियुक्ति पार्टनरशिप में एक नया चैप्टर खोलती है क्योंकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इंडो-पैसिफिक स्टेबिलिटी पहले से ही ऐसे फैक्टर हैं जो दोनों देशों को जोड़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बधाई मैसेज ने जापान के साथ स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप को मजबूत करने के उनके कमिटमेंट को फिर से कन्फर्म किया, जिसे दोनों देशों ने पिछले एक दशक में ध्यान से बढ़ाया है। इस वीकेंड अरएअठ और ईस्ट एशिया समिट के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों की होने वाली मीटिंग, दोनों देशों के बीच बातचीत के अगले फेज के लिए माहौल बनाएगी और सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक रेज़िलिएंस में सहयोग को अगले लेवल पर ले जाएगी।

शिंजो आबे के शागिर्द ताकाइची को भारत-जापान दोस्ती की विरासत मिली है, जिसे आबे ने बहुत ध्यान से संभाला था। आबे के ह्लफ्री और ओपन इंडो-पैसिफिकह्व के विजन को नई दिल्ली में पहचान मिली, जिसने क्वाड अलायंस की रूपरेखा को आकार दिया, जो अब रीजनल स्ट्रैटेजी की नींव का काम करता है।

ताकाइची से उम्मीद है कि वे आबे के इंडो-पैसिफिक फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाएंगे, शायद क्वाड में ज्यादा प्रोएक्टिव भूमिका निभाएंगे और एशिया में एक स्थिर और ज़िम्मेदार ताकत के तौर पर जापान की भूमिका को मजबूत करेंगे। भारत के लिए, यह एक मौका और ज़िम्मेदारी दोनों है। दोनों देश पहले ही पारंपरिक इकोनॉमिक रिश्तों से आगे बढ़कर स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आ चुके हैं, अगस्त में साइन किए गए इकोनॉमिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट से लेकर जरूरी मिनरल्स, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में जॉइंट वेंचर तक। मोमेंटम साफ है। फिर भी, ताकाइची की लीडरशिप में, पार्टनरशिप और भी ज्यादा प्रोएक्टिव हो सकती है। हालांकि, आगे का रास्ता बिना सावधानी के नहीं है। इमिग्रेशन और सोशल कंजर्वेटिज्म पर ताकाइची का हार्डलाइन रुख लोगों से लोगों के बीच होने वाली पहल पर दबाव डाल सकता है, जैसे कि हाल ही में साइन किया गया इंडिया-जापान ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज प्लान, जिसमें दोनों देशों के बीच पाँच लाख स्किल्ड वर्कर्स के आने-जाने का प्लान था।

देश में, रूलिंग कोएलिशन से मॉडरेट कोमेइतो पार्टी के बाहर निकलने से जापान की फॉरेन पॉलिसी की पहल पर और असर पड़ सकता है। फिर भी, जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यूटी और बदलाव के संगम पर खड़ी हैं। उनकी लीडरशिप पर करीब से नजर रखी जाएगी कि वह असरदार डिप्लोमेसी को इनक्लूसिविटी और इनोवेशन के साथ कैसे बैलेंस करती हैं।

वाद से अलग होने की न्यायिक प्रवृत्ति

सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लगभग 16 जजों ने उत्तराखंड कैडर के आईएफएस ऑफिसर, संजीव चतुर्वेदी के केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। श्री चतुर्वेदी को एम्स, हरियाणा और उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गवर्नेंस में गड़बड़ी और अधिकार के गलत इस्तेमाल और कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए जाना जाता है।

वी के बहुगुणा
लेखक, भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के पूर्व डीजी हैं।

भारतीय न्याय व्यवस्था में एक बहुत कम होने वाले मामले में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लगभग 16 जजों ने उत्तराखंड कैडर के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, श्री संजीव चतुर्वेदी के केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। श्री चतुर्वेदी को एम्स, हरियाणा और उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गवर्नेंस में गड़बड़ी और अधिकार के गलत इस्तेमाल और कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए जाना जाता है, जहां उन्होंने काम किया था।

सर्विस मामलों, सेंट्रल डेप्युटेशन, अप्रेजल रिपोर्ट और कैट मेंबर्स के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स पर उनकी कानूनी लड़ाइयों ने बिना कोई कारण बताए केस वापस लेने का यह सिलसिला शुरू कर दिया, जब तक कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने (उत्तराखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आलोक वर्मा के कंटेम्प्ट पिटीशन से पीछे हटने के बाद, जो 16वीं बार हुआ) रजिस्ट्री को उनके हेड वाली बेंच के सामने केस रखने का निर्देश देकर स्थिति को संभाला।

खुद को अलग करने का यह सिलसिला न केवल पहले कभी नहीं हुआ बल्कि हैरान करने वाला भी है और सिविल सर्वेंट्स और मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। पहले भी, कई जजों ने ऐसे केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है, जिनमें वे पहले वकील रह चुके हैं या जिनका केस से किसी भी तरह का कोई लिंक था।

कॉमन सेंस कहता है कि इस मुद्दे पर पब्लिक इंटरेस्ट में बहस होनी चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में लोगों या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हाथों होने वाली मनमानी के खिलाफ न्याय पाने के लिए ज्यूडिशियरी आखिरी सहारा है। पिछले कुछ दशकों से, इंडियन ज्यूडिशियरी ने काफी मजबूत इच्छाशक्ति और हिम्मत के साथ, पटरी से उतरे एग्जीक्यूटिव कामों को ठीक करने के लिए ज्यूडिशियल दखल के जरिए एक्टिव कदम उठाए हैं। इस ऑफिसर के मामले में, जजों के खुद को अलग करने के लिए कोई भेदभाव का कारण नहीं दिखता, क्योंकि ज्यादातर मामले सर्विस मैटर और हैरेसमेंट से जुड़े हैं।

इंडियन ज्यूडिशियरी के लिए यह एक अजीब स्थिति है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट को बहस करनी चाहिए और तय करना चाहिए कि किन हालात में कोई जज खुद को अलग कर सकता है; नहीं तो, यह नेचुरल जस्टिस देने की अपनी ज़िम्मेदारी को छोड़ने जैसा होगा। फिर भी, संविधान आर्टिकल 14 (बराबरी का अधिकार) और आर्टिकल 16 (जीवन और निजी आजादी का अधिकार) में दिए गए नैचुरल जस्टिस को पक्का करने के लिए केस से अलग होने को सपोर्ट करता है, सिर्फ.तभी जब किसी खास जज की सुनवाई आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन करती हो, ताकि नीमो जूडेक्स इन कॉसा सुआ (कोई भी अपने मामले में खुद जज नहीं होना चाहिए) के सिद्धांत के तहत फेयर ट्रायल पक्का हो सके। केस से अलग होने से असल या साफ भेदभाव, जिसमें पर्सनल, पैसे से जुड़े या प्रोफेशनल झगड़े शामिल हैं, को रोका जा सकता है।

इसलिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत ठाकुर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1987) जैसे अहम फैसलों में कहा कि केस से अलग होने से ज्यूडिशियरी में लोगों का भरोसा बना रहता है। इसके अलावा, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (2021) में साफ किया गया कि अगर भेदभाव की सही आशंका हो तो जजों को केस से अलग होना चाहिए, लेकिन आजादी से समझौता करने से बचने के लिए उन्हें डिटेल में कारण बताए बिना ऐसा करने का फैसला करने का अधिकार उनके पास होता है।

कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 (सेक्शन 479) के तहत, अगर पक्षपात का आरोप लगता है, तो पार्टियां केस ट्रांसफर करने की मांग कर सकती हैं, लेकिन जज खुद ही केस से अलग होने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। कैट जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, 1985 के तहत आते हैं, ऐसे ही नियम लागू होते हैं, जिसमें सदस्य सर्विस नियमों के तहत केस से अलग होते हैं।

इस केस ने लीगल सिस्टम के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है, अगर इसे सरकारी अधिकारियों के खिलाफ केस पर आसानी से फैसला करने से बचने के लिए या जब भी कोई जज किसी केस की सुनवाई के बोझ से बचने का फैसला करता है, तो एक मिसाल के तौर पर मान लिया जाए। चतुर्वेदी के केस में ज्यादातर मामलों में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन गोगोई (2013) और यूयू ललित (2016), या कैट के सदस्य जैसे हरविंदर उपल और बी. आनंद (2025) शामिल हैं, कोई कारण नहीं बताते हैं, जिससे बाहरी दबाव या विरोधियों द्वारा फोरम शॉपिंग की अटकलें तेज हो जाती हैं।

यह पैटर्न मनकलाल बनाम डॉ. प्रेम चंद (1957) की भावना के खिलाफ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भेदभाव की संभावना भी कार्रवाई को खराब कर सकती है। मिस्टर चतुर्वेदी जैसे पक्के इरादे वाले फाइटर के लिए, जो एक व्हिसलब्लोअर की तरह काम करते हैं और व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014 के तहत सुरक्षित हैं, ऐसे रिक्यूसल आर्टिकल 32 के संवैधानिक उपायों के अधिकार को खत्म करते हैं, जो शायद जल्दी न्याय से इनकार करने जैसा है। कानूनी तौर पर, जबकि व्यक्तिगत रिक्यूसल अजेय हैं, उनका कुल असर सिस्टमिक भेदभाव के लिए जांच को बुलावा दे सकता है, जिससे शायद निकट भविष्य में न्यायिक जवाबदेही पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू हो जाए।

मिस्टर संजीव चतुर्वेदी का मामला यह भी दिखाता है कि कैसे सिस्टम ने एक बार राष्ट्रपति के दखल से उनकी मदद की और उसी समय, ब्यूरोक्रेसी ने कुशासन और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने के लिए उन्हें दबाने की कोशिश की। ऐसे कई मामले हैं जहां सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के एडमिनिस्ट्रेटिव सदस्य सरकार के एक्सटेंशन विंग के रूप में काम करते हैं और नेचुरल जस्टिस इसका शिकार बन जाता है। कई सेक्रेटरी न्याय को रोकने के लिए सदस्यों से संपर्क करके एक अलग तरह की ह्लफोरम शॉपिंगह्व करते हैं। बिल्लियों को भी बड़े सुधारों की जरूरत है। सुधार की जरूरत है, और उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी बेंच के सामने केस रखने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी करके ट्रेंड सेट किया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए बड़े सुधारों की जरूरत है। इसके लिए, हायर ज्यूडिशियरी अकाउंटेबिलिटी पर जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी (2018) की सिफारिश के अनुसार, रिक्यूजल के लिए बिना किसी भेदभाव वाले कारणों को लिस्ट करने के लिए ज्यूडिशियल कोड में बदलाव करना जरूरी है।

रिक्यूज करने वाले जज को एक स्पीकिंग ऑर्डर देना चाहिए जिसमें बताया जाए कि वह रिक्यूज क्यों कर रहा है और किस तरह से केस की सुनवाई से नेचुरल जस्टिस पटरी से उतर सकता है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 275वीं रिपोर्ट (2018) में, पैटर्न को ट्रैक करने और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए डिजिटाइज्ड रिक्यूजल लॉग का आग्रह किया था।

सिविल सोसाइटी को, अपनी ओर से, सुप्रीम कोर्ट के सामने पीआईएल के जरिए इसे आगे बढ़ाना चाहिए, जिसमें रिक्यूजल की लिमिट और फालतू विड्रॉल के लिए पेनल्टी पर गाइडलाइन मांगी जानी चाहिए। बार एसोसिएशन भेदभाव की सोच पर एथिक्स ट्रेनिंग की वकालत कर सकते हैं।

भारतीय न्यायपालिका ने बार-बार खुद को सुधारने का रास्ता चुना है, और भारत के मौजूदा चीफ जस्टिस, जस्टिस गवई ने 2020 में अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट पर सुनवाई करते हुए कहा था कि ट्रांसपेरेंसी डेमोक्रेसी को मजबूत करती है। उम्मीद करते हैं कि न्यायिक खुद को सुधारना जल्द ही होगा।

सड़क सुरक्षा की नवीन कल्पना

आंकड़ों से पता चलता है कि सड़क हादसों में होने वाली लगभग आधी मौतें टू-व्हीलर चलाने वालों की होती हैं। 2024 में, सड़क हादसों में मरने वाले 1.80 लाख लोगों में से 45 प्रतिशत से ज्यादा टू-व्हीलर चलाने वाले थे।

स्वप्ना मजूमदार
लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं।

जब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अनुसार, 2025 के पहले छह महीनों में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसों में लगभग 27,000 लोगों की मौत हुई। सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें टू-व्हीलर चलाने वालों की होती हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि सड़क हादसों में होने वाली लगभग आधी मौतें टू-व्हीलर चलाने वालों की होती हैं। 2024 में, सड़क हादसों में मरने वाले 1.80 लाख लोगों में से 45 प्रतिशत से ज्यादा टू-व्हीलर चलाने वाले थे। पुलिस के डेटा से पता चलता है कि सड़क हादसों का असर किसी और के मुकाबले जवान लड़कों पर ज्यादा पड़ता है। आईआईटी दिल्ली के ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर (ट्रिप) की 2024 की रोड सेफ्टी स्टडी में पाया गया कि आज एक जवान लड़के के सड़क दुर्घटना में मरने की संभावना, बच्चे को जन्म देते समय मरने वाली जवान लड़की के मुकाबले तीन गुना ज्यादा है। यह 1990 के दशक से उलट है, जब सड़क टक्कर में बच्चे को जन्म देते समय मरने वाली जवान लड़की के मुकाबले दोगुने से ज्यादा मौत होती थी। इसके अलावा, डेटा फॉर इंडिया के एक एनालिसिस के मुताबिक, 15-29 साल के नौजवानों में सड़क हादसों में दिल की बीमारी से होने वाली मौतों से दोगुनी से भी ज्यादा मौतें होती हैं, और कैंसर से होने वाली मौतों से छह गुना ज्यादा मौतें होती हैं। ये चिंताजनक आंकड़े सड़क सुरक्षा की अहमियत को दिखाते हैं। ट्रिप रिपोर्ट कहती है कि देश भर में खासकर मोटरसाइकिल चलाने वालों को बहुत ज्यादा खतरा है।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर स्टार्ट-अप अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव के सीईओ और को-फाउंडर नारायण सुब्रमण्यम जानते हैं कि वह खुशकिस्मत हैं कि कुछ साल पहले जब वह अपनी मोटरसाइकिल चला रहे थे और सामने वाली कार बिना किसी वॉर्निंग के अचानक रुक गई, तो सड़क पर होने वाली मौतों के आंकड़ों में उनका नाम नहीं जुड़ा। टक्कर से बचने के लिए जब सुब्रमण्यम ने ब्रेक लगाए तो उनकी मोटरसाइकिल लड़खड़ा गई। खुशकिस्मती से, वह समय पर रुक गए और न सिर्फ कार से टकराने से बच गए, बल्कि मोटरसाइकिल से बिजी सड़क पर गिरने और कुचल जाने से भी बच गए। इस बाल-बाल बचने से सुब्रमण्यम, जो ट्रेनिंग से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, को एक कभी न भूलने वाला सबक मिला, कि राइडर की सुरक्षा सबसे जरूरी है। यह डरावना अनुभव अल्ट्रावॉयलेट के सभी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए नए सेफ्टी उपाय डिजाइन करने के पीछे भी वजह बना। जहां कई बड़ी, जानी-मानी टू-व्हीलर कंपनियां सेफ्टी पर फोकस कर रही हैं, वहीं कुछ ने सेफ्टी टेक्नोलॉजी रिसर्च में सालों लगाने या अपनी गाड़ियों की पूरी रेंज में मजबूत सेफ्टी फीचर्स देकर लागत कम करने का सब्र दिखाया है। लेकिन सुब्रमण्यम ने अपना सबक अच्छी तरह सीख लिया था। सुब्रमण्यम और उनके को-फाउंडर पार्टनर, वश के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, नीरज राजमोहन कहते हैं कि इसका मतलब अल्ट्रावॉयलेट की समय इन्वेस्ट करने की इच्छा (यहां तक कि एक प्रोडक्ट के लिए छह साल तक) और सबसे जरूरी बात, डिजाइन के लिए सेफ्टी से समझौता करने की अनिच्छा थी। यही वजह है कि इसने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को डुअल एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम पक्का किए बिना लॉन्च करने से मना कर दिया, भले ही इसके लिए इसे शामिल होने में कितना भी समय क्यों न लगे। इसकी लगन तब रंग लाई जब यह नई स्टार्ट-अप टू-व्हीलर इंडस्ट्री में ऐसा करने वाली पहली कंपनी बन गई।

हालांकि, यूवी ने अपनी सेफ्टी यात्रा यहीं खत्म नहीं की। पिछले महीने, यह दुनिया की पहली कंपनी बन गई जिसने राइडर की सेफ्टी को और बेहतर बनाने के लिए एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कर-के मोटरसाइकिल में रडार टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की। अब, मोटरसाइकिल चलाने वाले देश के अस्त-व्यस्त ट्रैफिक, अलग-अलग मौसम और शहरी और ग्रामीण इलाकों में बदलती और अनप्रेडिक्टेबल सड़क की हालत में एकदम सही तरीके से चल सकते हैं। क्योंकि रडार टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करती है, इसलिए यह तेज बारिश, घने कोहरे और अंधेरे जैसी खराब और खतरनाक कंडीशन में भी बेहतर विज़िबिलिटी देती है। एडवांस्ड राइडर असिस्टेंस सिस्टम के आने से, रडार टेक्नोलॉजी न सिर्फ पेरिफेरल विजन देती है जो आमतौर पर राइडर के हेलमेट से ब्लॉक हो जाती है, बल्कि कई सौ मीटर दूर तक की चीजों या दूसरी गाड़ियों का भी पता लगा सकती है। इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ब्लाइंड स्पॉट, लेन बदलना, गलत साइड से ओवरटेक करना और तेज रफ़्तार गाड़ियों से पीछे से टक्कर लगने से जुड़े रिस्क झ्र जो सड़क हादसों और मौतों के चार बड़े कारण हैं, काफी कम हो गए हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक, भारत को सड़क हादसों की वजह से अपनी सालाना जीडीपी का 3.14 परसेंट का नुकसान होता है।

आईआरएफ इंडियन चैप्टर के फाउंडर प्रेसिडेंट के के कपिला के अनुसार, 2030 तक सड़क पर होने वाली मौतों और चोटों को 50 परसेंट तक कम करने के लिए ब्रासीलिया डिक्लेरेशन (2015) पर साइन करने वाली सरकार ने इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के साथ मिलकर एक रोड सेफ्टी प्लान बनाया है। इसका मकसद न सिर्फ सड़कों की इंजीनियरिंग, बल्कि गाड़ियों की इंजीनियरिंग और दूसरी चीजों को भी बेहतर बनाना है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए अल्ट्रावॉयलेट के रडार टेक्नोलॉजी के नए इंजीनियरिंग इस्तेमाल ने दिखाया है कि यह रोड सेफ्टी के लिए एक गेम चेंजर है।

आप की बात

छठ पूजा यूनेस्को की सूची में शामिल हो

लोक आस्था का महापर्व छठ अपनी आस्था के लिए प्रसिद्ध है जो हमें एकता, प्रेम एवं भाईचारा का संदेश देती है जिसमें समाज का संस्कार समाहित है जो भेदभाव जाति पाति एवं धर्म से ऊपर उठकर समाज की छवि को नई रूप से स्थापित करती है जो आज के समाज के लिए बहुत जरूरी है यह एक स्वच्छ पूजा व्यवस्था है जिसमें सभी चीज श्रद्धालु के शक्ति और भक्ति पर निर्भर हैं इसमें कहीं मंदिर, ब्राह्मण की जरूरत नहीं पड़ती है यह मुख्य रूप से सूर्य देव तक के प्रति समर्पित है जिसको शाम एवं सुबह में गंगा में खड़े होकर अर्घ दिया जाता है लोगों की भीड़ उमरती है सभी की आस्था में एक ही चीज देखा जाता है की एकता का बल हैं इस महापर्व को यूनेस्को में शामिल होना जरूरी है यूनेस्को वह संस्था है जिसमें संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है जो संस्कृति,विज्ञान,ज्ञान एवं ऐतिहासिक परंपरा के गुणकता पूर्ण विविधता का संरक्षण करती है हाल में ही इसकी चर्चा जोरों पर थी कि यूनेस्को में छठ पूजा को शामिल किया जाएगा ऐसा देखा जाता है कि यह चुनावी मोहरा बनकर रह जाता है और नेताओं का चुनावी प्रोपेगेंडा फिर चुनाव खत्म हो जाता है और यह यूनेस्को की सूची से बाहर रह जाता हैं इस बार छठ पूजा को यूनेस्को में शामिल करने की सरकार को पहल करनी चाहिए।

– **तारामुनि देवी**, लालगंज, वैशाली

पुनर्विचार करे व्हाट्सऐप

आज व्हाट्सएप हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुका है। बातचीत, कामकाज और रिश्ते सब इसी ऐप पर टिके हैं। लेकिन इसकी कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स जैसे लास्ट सीन, रीड रिसीट और डिलीट फॉर एवरीवन अब सुविधा से ज्यादा भ्रम और अविश्वास का कारण बन गई हैं। कुछ लोग लास्ट सीन छिपा कर रखते हैं, ताकि किसी को पता ना चले कि वे कब ऑनलाइन थे। डिलीट फॉर एवरीवन का दुरुपयोग कर लोग गलत या अपमानजनक संदेश भेजकर तुरंत मिटा देते हैं। नतीजा, सामने वाले के पास न कोई सबूत बचता है, न कुछ जवाब देने का अधिकार। इससे मन में कई सवाल उठने लगते हैं कि उक्त व्यक्ति ने क्या भेजा होगा? इस फीचर ने दो लोगों के बीच संवाद की पारदर्शिता को खत्म कर दिया है। व्हाट्सएप एक निजी मंच है, लेकिन यह समाज का हिस्सा भी है। लेकिन जब इसके फीचर लोगों की मानसिक शांति और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने लगे तो कंपनी को सोचना चाहिए। प्राइवेसी का मतलब यह नहीं कि इंसान दूसरों के प्रति गैर-जिम्मेदार हो जाए। ऐसे फीचर जो संवाद में भ्रम और अविश्वास पैदा करे उन्हें हटाना या सीमित करना जरूरी है। लास्ट सीन जैसी जानकारी सबके लिए दिखनी चाहिए, यह चैटिंग में पारदर्शिता लायेगी। डिलीट फॉर एवरीवन जैसी सुविधा भी केवल तकनीकी गलती (जैसे गलत फाइल भेजना) तक सीमित होनी चाहिए, न कि हर मैसेज पर।

– **संदीप कुमार**, मधुपुर, झारखंड

भाई दूज में संस्कार का प्रेम

हमारे समाज में दीपावली के /दूसरे तीसरे दिन भैया दूज पर्व मनाया जाता है जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है यह भाई बहन के प्रेम और दीघार्यु की की आस्था से जुड़ा हुआ है इसका संबंध यमराज और उसकी बहन यमुना जी की कथा से जुड़ा हुआ है जिसमें यमुना जी ने अपने भाई यमराज की रक्षा के लिए भगवान से अमर होने का वचन मांगी थी तब से यह त्योहार हमारे समाज में मनाया जाता है आज भी समझ में महिलाएं एवं कन्या अपने भाई की रक्षा के लिए यह पर्व बड़े उत्साह से मनाती है आज भी देखा जाता है की बहन पर यदि कोई संकट आता है तो सबसे पहले उसका भाई उसे संकट में साथ देने के लिए आता है जिससे यह त्यौहार आज भी समाज के संस्कार में समाया हुआ है अपने भाई को तिलक लगाती है, उसके स्वस्थ एवं दीघार्यु की कामना करती है भगवान से मान्यता मांगती है कि मेरा भाई कुशल एवं मंगलमय रहे इस संस्कार में भाई-बहन के प्रेम की कथा समाज को प्रेरणा देती है कि परिवार में समर्पण एवं प्यार से एक संतुलित परिवार एवं समृद्धि के लिए सभी रिश्ते में प्यार का संबंध का गठजोड़ होना चाहिए आज के कुछ बिगड़ते रिश्ते एवं मनमुटाव पर प्रहार करती है एवं सभी को एक सिरों में पिरोने की सलाह पेश करती है जो समाज में नैतिकता के साथ अपने संबंध को बरकरार रखकर संयुक्त परिवार का निर्माण कर खुशी से जीवन जीने में सहयोग करें।

– **मीना देवी, उर्मिला देवी,** बसंतपुर, दिघवारा (सारण)

आतिशबाजी एक कुरीति

सनातन संस्कृति और हिंदुस्तान धर्म ने सदैव कुरीतियो का त्याग करने में कोई संकोच नहीं किया है इसलिए बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियो का त्याग कर विधवा विवाह जैसी नवीन लोकहित कारी परंपरा को सहर्ष अपनाया है। इसी प्रकार कुछ प्रतिशत ही सही मृत्युभोज जैसी प्रथाए भी कम हुई है। आज पर्यावरण के दृष्टिगत आतिशबाजी भी ऐसी ही परंपरा या कुरीति है जिसका त्याग किया जाना चाहिए। यह विचार आवश्यक है कि आतिशबाजी से मनोरंजन के अलावा क्या हांसिल होता है। यह पर्यावरण पैसा और प्राणी तीनो का ही नाश करता है । वैसे भी यह परंपरा शाश्वत नहीं है हमारे शास्त्रो में भी इसका कोई उल्लेख नही है। तथा यह कुछ सदीयो पहले बारुद के आविष्कार के बाद ही यह चलन में आई है।गौरतलब है कि जैन समाज में सुक्ष्म अहिंसा का बहुत महत्व है इसलिए जैन मुनि पटाखे और आतिशबाजी के त्याग के लिए बच्चो और बड़ो को प्रेरित करते हैं। और कई लोग इसके त्याग की प्रतिज्ञा भी लेते है। ऐसी ही पहल सभी समुदायो के पूज्य संतो को भी करनी चाहिए । ऐसी ही पहल हिंगोट युद्ध जो कि अनेक लोगो के जख्मी होने का कारण बनता है के लिए भी होनी चाहिए।

– **विमलेश पगारिया**, बदनावर, मप्र

पाठकगण अपने विचार **responsemail.hindipioneer@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

पायनियर
नई दिल्ली, शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025

योगी की दूरदर्शी पहल से करोड़ों के निवेश जल्द उतरेंगे धरातल पर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश अब सिर्फ देश का सबसे बड़ा राज्य नहीं, बल्कि भारत की सबसे तेजी से उभरती निवेश भूमि बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इन्वेस्ट यूपी द्वारा किए जा रहे नवाचारपूर्ण प्रयासों ने प्रदेश को निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बना दिया है। इसी दिशा में एक अहम कदम साबित हुई है–फोकस सेक्टर डेस्क की स्थापना, जिसने न केवल निवेश प्रक्रिया को सरल बनाया है, बल्कि उद्योग जगत में उत्तर प्रदेश की छवि को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

सीएम योगी के निर्देश पर इन्वेस्ट यूपी द्वारा गठित फोकस सेक्टर डेस्क अब प्रदेश में करोड़ों रुपये के निवेश को जुटाने में सफल रही है। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश प्रस्ताव न केवल मंजूरी के दौर में हैं, बल्कि जल्द ही धरातल पर उतरने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में फोकस सेक्टर डेस्क की रणनीति ने न केवल निवेश प्रक्रिया को गति दी है, बल्कि 'विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत' के विजन को साकार करने की दिशा में ठोस आधार भी तैयार किया है। भारतीय तकनीकी वस्त्र संघ, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ और उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ की साझेदारी से इस सेक्टर में ग्रासिम, ट्राइडेंट, रिलायंस, जीईएसएल और श्याम संस जैसी बड़ी कंपनियां प्रदेश में निवेश कर रही हैं। उनके प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, एसीएमए, एसएमईवी और एआरएआई जैसी संस्थाओं के सहयोग से प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग को नई रफ्तार मिल रही है। अशोक लेलैंड, मिंडा और टाटा मोटर्स (विस्तार परियोजना) जैसे दिग्गज निवेश के लिए तैयार हैं। भारतीय रासायनिक परिषद, आईएससीएम एसोसिएशन और केमएक्सेल के सहयोग से प्रदेश में रिलायंस इंडस्ट्रीज और दीपक नाइट्राइट जैसी कंपनियां बड़े निवेश की योजना पर काम कर रही हैं। आईसीए, एलसिना, आईया, आईमा के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में तेजी से निवेश बढ़ रहा है। डिक्सन, एम्बर, एचसीएल-फॉक्सकॉन, हायर और एलजी जैसी कंपनियों की परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, जिससे प्रदेश भारत का अगला टेक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में अग्रसर है।

भाई दूज की पूजा करतीं महिलाएं

'डिजिटल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' मिशन को देगी नई ऊर्जा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

❖ स्वदेशी 7 नैनोमीटर प्रोसेसर के विकास की घोषणा

भारत ने सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए स्वदेशी 7 नैनोमीटर प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 18 अक्टूबर को इस पहल का अनावरण किया। यह परियोजना न केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि 'डिजिटल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' मिशनों को नई ऊर्जा प्रदान करने वाली साबित होगी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (आईआईटी मद्रास) द्वारा विकसित किया जा रहा यह प्रोसेसर 'शक्ति' पहल के अंतर्गत तैयार किया गया है, जो ओपन-सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पर आधारित है। यह अनूठी तकनीक स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और उद्योगों को कम लागत में उच्च प्रदर्शन वाले माइक्रोप्रोसेसर विकसित करने की स्वतंत्र सुविधा प्रदान करती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'स्वदेशी 7 एनएम प्रोसेसर पहल मात्र एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, यह एक दृढ़ संकल्प है। नवाचार, शिक्षा और उद्योग जगत को जोड़कर, भारत एक आत्मनिर्भर, विश्व-स्तर पर प्रतिस्पर्धी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की नींव रख रहा है। निरंतर अनुसंधान एवं विकास तथा रणनीतिक निवेश के माध्यम से, देश वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरने के लिए तैयार है।' मंत्रालय के अनुसार, 7 एनएम प्रोसेसर उच्च प्रदर्शन और ऊर्जा दक्षता के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उपयोग वित्तीय सेवाओं, रक्षा, संचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में किया जाएगा। यह भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत घरेलू चिप निर्माण क्षमताओं को स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत अब तक 1.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली 10 परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। टी 3 की डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत 288 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता दी गई है और 24 चिप डिजाइन परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत हो चुकी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की श्रेणी में खड़ा करेगा। इस पहल से हजारों उच्च-कौशल नौकरियों का सृजन होगा और भारत विश्व स्तर पर एक विश्वसनीय तकनीकी साथी के रूप में अपनी भूमिका और मजबूत करेगा।

उपभोक्ता परिषद ने राष्ट्रपति को भेजा पत्र, न्याय की गुहार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

यूपी में हो रहा राष्ट्रीय कानून विद्युत अधिनियम 2003 का खुला उल्लंघन

यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने गुरुवार राष्ट्रपति को पत्र भेजकर प्रदेश में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 47(5) के उल्लंघन की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने अपने पत्र में कहा है कि यह अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से संसद द्वारा पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है। जिस प्रकार से यूपी में देश के राष्ट्रीय कानून विद्युत अधिनियम 2003 का खुला उल्लंघन किया जा रहा है उसे पर सूबे ऊर्जा मंत्री और सरकार चुप है या अपने आप में घोर चिंता का विषय है।

उपभोक्ता परिषद ने इसकी एक एक प्रति देश के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर व केंद्रीय ऊर्जा सचिव को भी भेजा है और उनसे भी पूरे मामले पर अभिलंब कार्यवाही की मांग उठाई गई है। वर्मा ने बताया कि धारा 47(5) के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर में से किसी एक को चुनने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। किंतु उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं उसकी वितरण कंपनियां इस वैधानिक अधिकार का उल्लंघन कर रही हैं और उपभोक्ताओं को जबरन केवल प्रीपेड मीटर लगाने के लिए बाध्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, यूपीपीसीएल द्वारा उपभोक्ताओं से विभिन्न प्रकार के शुल्क एवं फीस वसूली जा रही है, जिनकी स्वीकृति उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग से प्राप्त नहीं की गई है। यह न केवल विद्युत अधिनियम, 2003 का उल्लंघन है, बल्कि पारदर्शिता, वैधता और नियामकीय नियंत्रण के संवैधानिक सिद्धांतों के भी विपरीत है। परिषद ने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि पावर कॉरपोरेशन और उसकी वितरण कंपनियों की कार्यप्रणाली की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। किस आधार पर भारत के राष्ट्रीय कानून का उत्तर प्रदेश में घोर उल्लंघन किया जा रहा है, राज्य सरकार और विद्युत नियामक आयोग को निर्देशित किया जाए कि वे अधिनियम की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करें तथा उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर में से चयन का अधिकार पुनः बहाल करने के लिए आगे आए। इसके साथ ही जब तक नियामक आयोग से विधिवत स्वीकृति न मिल जाए, तब तक किसी भी प्रकार की अनधिकृत वसूली पर रोक लगाई जाए। वर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और विद्युत अधिनियम की भावना को अक्षरशः लागू करना समय की आवश्यकता है।

मिजार्पुर में चबूतरा निर्माण पर तनाव

मिर्ज़ापुर (उप्र)। जिले के जिगना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में बुधवार शाम तब तनाव फैल गया जब गांव वालों ने एक घर में मज़ार जैसा चबूतरा बनाए जाने पर आपत्ति जताई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, 22 अक्टूबर को रात करीब आठ बजे जानकारी मिली कि तिवारी पुर कुशहा गांव में राम नारायण सिंह उर्फ शोभा सिंह और रवि सिंह ने अपने घर में मज़ार जैसा चबूतरा बनाया है। उनका दावा था कि यह उनकी बहू पर बुरी आत्माओं के असर को दूर करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि गांव वालों ने इस निर्माण कार्य का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और समझाने पर परिवार ने अपनी मर्ज़ी से चबूतरा हटा दिया, जिससे इलाके में शांति बहाल हो गई। पुलिस ने बताया किया कि गांव में अब हालात पूरी तरह सामान्य हैं।

बसपा के कद्दावर नेता रायनी पार्टी से बाहर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त कद्दावर मुस्लिम नेता समसुद्दीन रायनी को बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी ने उन्हें गुटबाजी व पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में निष्कासित किया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बाद बसपा में रायनी बड़े मुस्लिम नेता माने जाते हैं।

विधानसभा चुनाव से पहले बसपा ने पार्टी में निष्क्रिय हो चुके नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। बर्खास्त किए गए समशुद्दीन राईन लखनऊ और कानपुर मंडल के प्रभारी थे। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष ने बयान जारी कर दिया गया है। जारी किए गए बयान में कहा गया है कि राईन पार्टी में गुटबाजी और अनुशासनहीनता कर रहे थे। उन्हें इस संबंध में चेतावनी भी दी गई लेकिन उन्होंने कार्यशैली में सुधार नहीं किया। ऐसे में उन्हें बसपा से निष्कासित कर दिया गया है।

बसपा में ये कद्दावर मुस्लिम नेता माने जाते थे कुछ दिनों से इनकी शिकायते मिल रही थी। बसपा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गई है। इसको देखते हुए बसपा ने पार्टी को मजबूत करने के लिए नये पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। इसके साथ ही पार्टी में जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी निष्क्रिय हो चुके है अथवा संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य नहीं कर रहे है। ऐसे लोगों को बसपा बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो गयी है।

वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प सात लोग घायल

बलिया (उप्र)। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र के अधिसिझुआ गांव में वर्चस्व को लेकर यादव और बिंद जाति से जुड़े दो पक्षों में हुए हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के कुल सात लोग घायल हो गए। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों के कुल 22 लोगों के साथ ही कुछ अज्ञात के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है और पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अधिसिझुआ गांव में बुधवार रात्रि यादव और बिंद जाति से जुड़े दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान लाठी - डंडा और लोहे के छड़ से हमला किया गया, जिसमें एक पक्ष के सुनील यादव और कमलेश यादव तथा दूसरे पक्ष के धनंजय, लाल बाबू प्रसाद, कपिल देव, रवीन्द्र, और मंटू बिंद घायल हो गए।

सपा ने अखिलेश के जन्मदिन पर लगाया 'प्रबल इंजन की सरकार' होर्डिंग

❖ सूबे के सियासी गलियारें में चर्चा, राजनीति में नया संदेश देने की कवायद

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

राजनीति में नया संदेश देने के लिए संतकबीरनगर की मेंहदावल सीट से प्रत्याशी रहे जयराम पांडेय ने इस बार भाजपा को करारा जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर 'डबल इंजन सरकार' के नारे का जवाब देते हुए इसे 'एक इंजन, मजबूत इंजन' का रूप देते हुए बड़ा होर्डिंग्स लगाया है।

यह होर्डिंग्स सियासी गलियारे में चर्चा का विषय है। इस होर्डिंग में अखिलेश यादव को ट्रेन के ड्राइवर के रूप में दिखाया गया है, जबकि ट्रेन के डिब्बों पर सपा शासनकाल में शुरू की गई प्रमुख योजनाओं का सिलसिलेवार विवरण दिया गया है। इन योजनाओं में समाजवादी पेंशन योजना, कन्या विद्याधन, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे, लैपटॉप योजना, लखनऊ मेट्रो, डायल-100 और मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। इसके अलावा होर्डिंग में संस्कृत में श्लोक भी लिखा गया है, 'अद्रोह : सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। अनुग्रह : दानं च, शीलमेतद् विदुर्बुधाः।' इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने कर्म, मन और वाणी से सभी जीवों के प्रति द्वेष रहित है, दानशील और विनम्र है, वही ज्ञानी कहलाता है। इसके अलावा, होर्डिंग में सपा का नया पीडीए फॉर्मूला भी शामिल किया गया है इसके तहत पीडीए की भी जानकारी दी गयी है जिसमें दिया गया है कि पीः प्रगतिशील, डीः दूरदर्शी, एः अमनपसंद। लोकसभा चुनाव-2024 और विधानसभा चुनाव-2007 को ट्रेन के स्टेशनों के रूप में दर्शाया गया है। सपा के संतकबीरनगर की मेंहदावल सीट से प्रत्याशी रहे जयराम पांडेय पिछले 9 वर्षों से अखिलेश यादव के जन्मदिन पर इस तरह की रचनात्मक होर्डिंग्स लगाते आ रहे हैं। पिछले साल उन्होंने 'सत्ताईस के सत्ताधीश' का पोस्टर लगाया था। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ''प्रबल इंजन की सरकार' का यह नारा सपा की नई आक्रामक रणनीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य भाजपा के प्रचार-स्लोगन 'डबल इंजन सरकार' का जवाब उसी अंदाज में देना और आगामी विधानसभा चुनाव-2027 के लिए सपा की तैयारियों का संकेत देना है। होर्डिंग में यह भी लिखा है कि फिर से चलेगी समृद्धि की बयार, जब 2027 में आएगी प्रबल इंजन की सरकार।

लखनऊ में चित्रगुप्त महाराज की पूजा-अर्चना करते कायस्थ समाज के लोग

स्लीपर बस डिवाइडर से टकरा कर पलटी, 26 यात्री घायल

कुशीनगर (उप्र)। कुशीनगर जिले में तरयासुजान थाना क्षेत्र के राजमार्ग पर बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास बृहस्पतिवार सुबह जयपुर से मधुबनी जा रही एक स्लीपर बस डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। हादसे में 26 से अधिक यात्री घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि स्लीपर बस के रोड डिवाइडर से टकराने के बाद पलट जाने से कम से कम 26 यात्री घायल हो गए, जिनमें से छह की हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक, हादसे के बाद चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बस के शीशे तोड़कर सभी यात्रियों को बाहर निकाला। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को उपचार हेतु भेजा। पुलिस के अनुसार, तेज गति से जा रही स्लीपर बस बहादुरपुर चौकी के निकट एक ट्रक को ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस पलट गई और उसमें सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल यात्रियों में दरभंगा निवासी 55 वर्षीय विजय मिश्र, मधुबनी के प्रेम नगर निवासी विजय महतो (45) व उनकी पत्नी बबीता देवी (40) सहित उनकी तीन बच्चियां शिवानी (11), अनामिका (9) व अंचला (7) को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज पडरौना भेजा गया। अन्य घायलों का उपचार तमकुहीराज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है।

चाइनीज मांझे से कटी युवक की गर्दन, हुई मौत

शाहजहांपुर (उप्र)। शाहजहांपुर जिले में बृहस्पतिवार को भैया दूज के मौके पर पत्नी के साथ ससुराल जा रहे मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की कथित रूप से चाइनीज मांझे से गर्दन कट जाने से मौत हो गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने बृहस्पतिवार को बताया कि आज दोपहर रौजा थानाक्षेत्र में सीतापुर राजमार्ग पर मोटरसाइकिल सवार रवि कुमार शर्मा (25) की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई। एसपी के अनुसार पुलिस ने शर्मा को राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि घटना के वक्त शर्मा अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर भाई दूज के मौके पर अपनी ससुराल जा रहा था।

पत्नी के आत्महत्या कर लेने के बाद पति नदी में कूदा

लखीमपुर खीरी, (उप्र)। लखीमपुर खीरी जिले में धौरहरा थानाक्षेत्र के बम्हौरी गांव में एक महिला ने कथित रूप से पति से झगड़े के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि कानूनी कार्रवाई के डर से आज सुबह उसका पति शारदा नदी में कूद गया तथा उसे ढूंढने के लिए गोताखोरों को लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक बम्हौरी गांव में पूनम (25) ने बुधवार देर रात अपने पति राम निवास से झगड़े के बाद फांसी लगा ली। पुलिस का कहना है कि बृहस्पतिवार सुबह राम निवास ने अपनी पत्नी के इस अतिवादी कदम के बारे में अपने माता-पिता और अपने सास-ससुर को बताया। बाद में, पुलिस की कानूनी कार्रवाई के डर से वह गांव से कुछ किलोमीटर दूर शारदा पुल पर गया। पुलिस के अनुसार राम निवास ने अपना मोबाइल हैंडसेट और चप्पलें पुल पर छोड़ दीं तथा शारदा नदी में कूद गया। पुलिस के मुताबिक इससे पहले कि लोग उसे बचाने की कोशिश करते, वह नदी के तेज बहाव में बह गया। धौरहरा के थाना प्रभारी शिव जी दुबे ने बताया कि मृतक पूनम के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, खमरिया पुलिस सूत्रों ने बताया कि राम निवास को ढूंढने की कोशिशें जारी हैं, नदी में उसे ढूंढने के लिए गोताखोरों को लगाया गया है।

भाकपा (माले) ने दलित हत्या की घटनाओं पर चिंता जताई कहा, अपराधी बेलगाम

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

भाकपा (माले) ने प्रदेश में दलित हत्या की घटनाओं पर गहरी चिंता प्रकट की है। दीपावली के बाद मंगलवार को दो अलग-अलग घटनाओं में दो दलितों की हत्या पर पार्टी ने सरकार को घेरा।

माले के राज्य सचिव सुधाकर यादव ने एक बयान में कहा कि भाजपा सरकार में दलितों की जान सबसे सस्ती है। उनका उत्पीड़न तो हो ही रहा है, उनकी हत्या पर भी कोई लगाम नहीं है। सुल्तानपुर में चांदा कोतवाली क्षेत्र के ढाखापुर निवासी दलित युवक राजकुमार (28) की उनके घर में रात में घुसकर दबंगों ने गला दबाकर हत्या कर दी। कुछ दिन पहले हत्यारोपियों से मामूली विवाद हुआ था।

दूसरी घटना प्रयागराज की है, जिसमें धूमनगंज निवासी रवींद्र उर्फ मुन्नू पासी (40) की भरी दोपहरी पेट्रोल पम्प पर पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। वे रोडवेज के संविदा चालक थे। पत्थर मारने से पहले उन्हें जातिसूचक गालियां दी गईं। इसके पहले, प्रदेश सरकार की नाक के नीचे काकोरी (लखनऊ) में दिवाली की रात एक मंदिर के पास दलित बुजुर्ग रामपाल रावत (65) का अमानवीय उत्पीड़न किया गया। भाकपा (माले) नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के शासन में कानून के राज की जगह दबंग राज चल रहा है। दलितों के संवैधानिक अधिकारों पर हमले हो रहे हैं और उनका जीवन भी सुरक्षित नहीं रह गया है।

भाजपा के लिए दलित सत्ता पाने के साधन मात्र हैं। वह उनकी सामाजिक बराबरी और उन्हें लोकतंत्र देने के खिलाफ है। तभी वह सामंती दबंगों, अपराधियों को संरक्षण देती है। 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा ढकोसला है। संघ-भाजपा की हिन्दू एकता के आवरण के नीचे दलित उत्पीड़न पर कोई रोक नहीं है। अपराधी बेलगाम हैं।

महिला ने 'तीन तलाक' देकर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया

भदोही (उप्र)। भदोही में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी के पांच लाख रुपये मूल्य के गहने कथित तौर पर बेच दिए, उसकी जीवन बीमा राशि हड़प ली, अपने भाइयों के साथ मिलकर उससे मारपीट की और फिर उसे 'तीन तलाक' देकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। गोपीगंज थाना प्रभारी शैलेश कुमार राय ने बताया कि सात बच्चों की मां नाजिश (38) की तहरीर पर उसके पति चिरागुद्दीन, जेठ मैनुद्दीन, और दो देवरों शहाबुद्दीन और निजामुद्दीन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की गई।

यूपी में सिर्फ 11.37 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

यूपी में दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं और युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। योजना के तहत प्रदेश में कुल 11.37 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, जो देश में शीर्ष स्थान रखता है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल वेतन रोजगार के अवसर प्रदान करके गरीबी को कम करना है। यह योजना ग्रामीण परिवारों को स्थायी तथा विविध आजीविका विकल्पों से जोड़ने का प्रयास करती है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। आंकड़ों के मुताबिक, यूपी में अब तक 2.44 लाख ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। महिलाओं और युवाओं के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए 47,952 बैंक सहायिकाएं प्रदेश में तैनात की गई हैं, जो एसएचजी सदस्यों को बैंकिंग एवं ऋण सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। प्रदेश में 3.74 लाख से अधिक कृषि एवं गैर-कृषि उद्यमों का समर्थन किया गया है और 6,000 से अधिक कृषि क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण स्वयं सहायता समूहों को वितरित किया गया है, जिसकी पुनर्भुगतान दर 98 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के लिए स्थायी विकल्प, वित्तीय संसाधन, और प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना से मेघालय की हनीदमांकी कनाई जैसी प्रेरक कहानी भी जुड़ी है, जिन्होंने यूपी के स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर आर्थिक सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन की दिशा में यह योजना प्रभावशाली साबित हो रही है, जिससे सामाजिक व आर्थिक समावेशन बढ़ा है व ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

यम द्वितीया पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी

पायनियर संवाददाता। कालपी,जालौन

गुरुवार को यम द्वितीया नगर व क्षेत्र में आस्था और विश्वास के साथ मनाई गई। इस दौरान लोगों ने परम्परा के अनुसार यमुना स्नान कर पूजा अर्चना की तो बहिनों ने अपने भाईयों का तिलक कर उनके दीघार्यु होने की कामना की।

कार्तिक मास की अमावस्या के बाद आने वाली द्वितीया को यम द्वितीया कहा जाता है पौराणिक मान्यता है कि यमुना यमराज की बहन है और यह तिथि उनके प्रेम और स्नेह पर आधारित है। पौराणिक कथा के अनुसार यमुना ने एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज को अपने घर बुलाकर उनका आदर-सत्कार किया और उन्हें भोजन कराया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने यमुना को वरदान दिया कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को टीका लगाएगी और उसके हाथ का भोजन करेगी, उसे यम का भय नहीं रहेगा और तभी से इस तिथि को यमुना स्नान करने का महत्व है और बहिने भी भाईयो की लम्बी उम्र की कामना के साथ उनका टीका करती है। दीपावली के बाद द्वितीया पर यमुना स्नान की परंपरा काफी पुरानी है जिसमे नगर के साथ ग्रामीण इलाके की महिलाए भी स्नान करती है जिसके चलते नगर स्थित किलाघाट, पीलाघाट में स्नानार्थियों की भारी भीड रही। इस दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो इसको लेकर घाटों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी जिससे कोई गहरे पानी में न जा सके।

यम और यमुना के मिलन की पौराणिक कथा

पौराणिक कथा के अनुसार यमराज और यमुना के पिता सूर्यदेव हैं जिसका नाम यमी भी है जो हमेशा भाई से मिलने के लिए उनका इंतजार करती थीं, लेकिन यमराज अपने व्यस्त कार्यों के कारण नहीं आ पाते थे। लेकिन अचानक एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन, यमराज अचानक यमुना के घर पहुँच गए थे तभी से इस पर्व की परम्परा बन गई है और इसी के चलते गुरुवार को यमुना के घाटों पर भारी भीड़ रही।

दिवाली पर अराजकता का माहौल, मारपीट

कालपी, जालौन। दीपावली का त्योहार भी होली की तरह अराजक हो गया है जिसकी बानगी वुधवार को नगर में कई जगह देखी गई जिसमें अराजकतत्व भयमुक्त होकर लड़ाई झगड़ा करते रहे। यह त्योहार भी होली की तरह अराजक होता जा रहा है आलम यह है कि पहले मुन्ना फुलपावर चौराहा पर पुलिस की मौजूदगी के महज कुछ कदम दूरी पर मारपीट कर डाली तो वुधवार शाम को कोतवाली की चहारदीवारी के पास दो गुटों में संघर्ष हो गया था जिसमे खूब लाठी डण्डे भी चले थे। मामला पुलिस तक भी पहुंचा है तो नगर के अन्य स्थान पर भी देरशाम मारपीट हो गई थी लेकिन पुलिस किसी मामले में कुछ भी नहीं कर सकी है। कोतवाली प्रभारी उदय प्रताप सिंह के अनुसार शिकायतें आई हैं जिनकी जांच हो रही है।

खाकी की फजीहत कराने वाले दरोगा समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित

पायनियर संवाददाता। महोबा

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में पुलिस कप्तान ने गुरूवार को खाकी की फजीहत कराने के आरोपी चरखारी क्षेत्र की गोरहारी पुलिस चौकी इंचार्ज समेत तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित करके लाइन हाजिर कर दिया है।

पुलिस मीडिया सेल द्वारा जारी सूचना के मुताबिक एसपी प्रबल प्रताप सिंह ने यह कार्यवाही सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो को संज्ञान में लेकर की है, जिसमें गोरहारी चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक राकेश दीक्षित व उनके हमराही सिपाही कामिल व कुलदीप के साथ गुढ़ा गांव में कुछ महिलाओ द्वारा धक्का मुक्की करते हुये उनसे पैसे छीनते व खदेड़ते हुये दर्शाया गया है। आरोप है की चौकी प्रभारी ओर हमराही सिपाही बुधवार की शाम एक सूचना पर जुआ पकड़ने के लिए बगैर वर्दी के सिविल ड्रेस में गुढ़ा गए थे. पुलिस छापे को देख जुआड़ी तो मोके से भाग खडे हुये थे किन्तु पुलिस कर्मियों ने जुआ के फड़ पर छापा मार कर उन्होंने सबसे पहले वहां मौजूद रकम को समेट कर अपनी जेब के हवाले किया था.

अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया की गाँव में बगैर वर्दी के कुछ लोगो के एकाएक पहुंचने ओर ग्रामीणों के पैसे छीन कर ले जाने की खबर फैलते ही गुड़ा में बड़ी संख्या में महिलाएं एकजुट हो गई ओर उन्होंने सम्बन्धित पुलिस कर्मियों को न सिर्फ घेर कर उनके साथ धक्का मुक्की करते हुये बेइज्जत किया बल्कि महिलाओ ने पुलिस कर्मियों से सारे पैसे छीन लिए ओर उन्हें खदेड़ कर भगा दिया.इस घटना की कुछ ग्रामीणों ने वीडियो बना ली ओर उसे सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया की प्रकरण संज्ञान में आने पर एसपी ने गोरहारी चौकी इंचार्ज व पुलिस कर्मियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कठोर कार्यवाही करते हुये उन्हें घटना की उच्च अधिकारियों को सूचना दिए बगैर कार्यवाही के लिए जाने का दोषी मान निलंबित कर दिया ओर लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस कप्तान द्वारा घटना की जांच के भी आदेश दिए गए हैं।

कार ने ससुर-दामाद की बाइक में मारी टक्कर, दोनों की दर्दनाक मौत

पायनियर संवाददाता। उरई,जालौन

- कार चालक सौ मीटर घसीटता ले गया
- कार पुलिस ने ली कब्जे में, चालक फ़रार

गुरुवार को आटा थाना क्षेत्र में झांसी-कानपुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार पुलिस लिखी कार ने बाइक सवार ससुर-दामाद को टक्कर मार दी। जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि दूसरे ने अस्पताल में दमतोड़ दिया।

बघौरा गांव निवासी संतराम 70 वर्ष अपने दामाद विशाल 30 वर्ष निवासी धंतौली कोतवाली जालौन के साथ बाइक से जोल्हूपुर इलाज कराने जा रहे थे। जैसे ही वह आटा थाना क्षेत्र के संकट मोचन मंदिर के पास पहुंचे ही थे कि झांसी की ओर से आ रही तेज रफ्तार नेक्सन कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। इतना ही नहीं बल्कि बताया गया कि भागने के प्रयास में कार चालक बाइक सहित दोनों लोगों को करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। जिसके चलते बाइक सवार वृद्ध ससुर संतराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दामाद को राहगीरों की मदद से पुलिस ने अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया।

जहां हालत नाजुक होने पर उसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया। जहां पर इलाज के दौरान उसने ने भी दमतोड़ दिया। घटना की सूचना पर आटा थाना प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार मौके पर पहुंचे और जांच के बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि कार पर पुलिस लिखा हुआ था।

लेकिन जांच में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि वाहन वास्तव में किसी पुलिस विभाग का है या नहीं। फिलहाल वाहन को कब्जे में ले लिया गया है और आरोपी चालक की तलाश की जा रही है।

एसडीएम ने कान्हा गौशाला में गुड़ चना खिला कर गोवर्धन पूजा की

पायनियर संवाददाता। कालपी

उपजिलाधिकारी ने कान्हा गौशाला में गौवंशों को गुड़ चना खिला कर गोवर्धन पूजा कर नागरिकों की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

इस दौरान उन्होंने मोनिया वृतियों स्नेहिल मुलाकात की। उप जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह कान्हा गौशाला कदौरा में पहुंचे। गौशाला परिसर में उन्होंने गौवंश को गुड़ चना खिला कर सेवा की। गोवर्धन पूजा कर-के गौवंशों तथा सभी नागरिकों की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इसी दौरान एसडीएम ने मोनिया वृतियों से स्नेहिल मुलाकात की। उप जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने त्योहारों की महत्ता पर प्रकाश डाला। इस मौके पर गौशाला के कर्मचारियों तथा क्षेत्रीय पर नागरिकों ने सहभागिता की।

भाजपा नेता के पेट्रोल पंप पर सेल्समैन व युवकों में मारपीट पुलिस ने कराया समझौता

पायनियर संवाददाता। राठ,हमीरपुर

- डराने के इरादे से किया हवाई फायर
- भाजपा नेता को कोतवाली में बिठाए रखने पर नाराज़गी

हमीरपुर रोड स्थित पेट्रोलपंप पर पैसे के लेन देन को लेकर कार सवार और पंप के सेल्समैनों के बीच मारपीट हो गई। सूचना पर पंप मलिक भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने आकर बीच.बचाव किया।

सूचना पर पहुंची पुलिस भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सहित कार सवारों को कोतवाली ले गई। वही भाजपा नेता को रात भर कोतवाली में बैठाये रखने पर भाजपाईयों ने नाराजगी जाहिर की है।

हमीरपुर रोड स्थित किसान पेट्रोल पंप के सेल्समैन रामसिंह ने बताया कि बीती रात कार सवार पांच युवकों ने पेट्रोल डलवाया। जब पेट्रोल के 3400 रुपए मांगे तो युवकों ने देने से इंकार कर दिया। जिस पर दोनों पक्ष में विवाद हो गया और मारपीट होने लगी। जानकारी पर पेट्रोलपंप मालिक भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान आए और बीच बचाव किया। प्रीतम सिंह किसान ने बताया कि सेल्समेन और युवकों के बीच हाथापाई हो रही थी और कार सवार युवक मान नहीं रहे थे। मामला निपटाने और डराने के लिए हवाई फायर किया था। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई। सुबह दोनों पक्षों में जान.पहचान होने पर समझौता हो गया। पुलिस ने भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान को कोतवाली में रखा जो सोशल मीडिया पर व लोगों में चर्चा का विषय बना रहा।

कोतवाल अमित कुमार ने बताया कि पेट्रोल के पैसों के लेनदेन था। दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए कोतवाली लेकर आए थे। सुबह होते ही दोनों में राजीनामा हो गया।

वदउंआ के छात्र ने हाईटेक ड्रोन बनाया

वार्ता के दौरान छात्र ने दिखाया अपनी प्रतिभा का हुनर, इंडिया बुक में नाम हुआ दर्ज

पायनियर संवाददाता। कोंच, जालौन

कोंच तहसील के क्षेत्र में एक 17 वर्षीय छात्र ने हाईटेक ड्रोन बनाकर अपनी उपलब्धि को इंडिया बुक में दर्ज करा लिया जिसमें 7.26 किलो मीटर का नया कीर्तिमान स्थापित होनहार छात्र ने किया और वह भविष्य में अत्यधिक उन्नति किस्म के ड्रोन बनाकर आपदा राहत एवं सेना के कार्यों में योगदान देने के लिए प्रयासरत है।

उरई रोड स्थित आशीर्वाद विवाह घर के सभागार में गुरुवार को एक सादा समारोह में तहसील क्षेत्र के ग्राम वदउँआ निवासी रुद्राक्ष पुत्र डॉ राम किशोर उम्र करीब 17 वर्ष ने एक हाईटेक ड्रोन को तैयार कर प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए उसकी खूबियों का बखान किया जिसमें रुद्राक्ष ने बताया कि यह लीगल ड्रोन है जिसमें किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है जिसे मैने 7.26 किलो मीटर तक उड़ाकर इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड में दर्ज 2 किलो मीटर दूरी के ड्रोन को मात देते हुए अपना नाम दर्ज कराया है।

यह ड्रोन 105 किलो मीटर प्रति घण्टे की अधिकतम गति से उड़ने में सक्षम है और इसका बजन 2.9 किलो ग्राम चौड़ाई 2.45 मीटर और ऊंचाई 1.05 मीटर है जो 1.6 किलो मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से उड़ान भरते हुए 18.6 मिनट तक इसने उड़ान भरी जिसमें कैमरा और सेंसर लगाए गए हैं जो निगरानी दुर्गम स्थानों की तस्बीरें व बी डी ओ रिकार्डिंग के लिए उपयोगी है और मैने कोरोना काल के दौरान ही इस ड्रोन तकनीक को विकसित करने का प्रयास शुरू कर दिया था और 14 अगस्त 2021 को पहला ड्रोन सफलता पूर्वक उड़ाया था उन्होंने यह भी बताया कि आने बाले समय में इस ड्रोन को और अत्यधिक मॉडिफाई किया जाएगा जिससे कृषि क्षेत्र डिलीवरी एवं चिकित्सा क्षेत्र में यह अपनी भूमिका अदा करेगा और भीड़भाड़ बाले इलाकों में यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा।

आपको बता दें रुद्राक्ष उर्फ आशु वर्तमान में पदमपद सिंघानियां कालेज कानपुर में 12 वीं का छात्र है जिसमें शिक्षा ग्रहण करते हुए यह कारनामा दिखाया कार्यक्रम में क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों ने रुद्राक्ष को फूल माला पहनाकर उसके उज्वल भविष्य की कामना की और ड्रोन तकनीक के लिए उसे बधाई दी।

न्यायालय के आदेश से रोडवेज परिचालक समेत दो पर केस दर्ज

पायनियर संवाददाता। मौदहा

मौदहा कोतवाली क्षेत्र के गांव छिरका के नजदीक रोडवेज बस की चेकिंग करने वाले विभागीय अधिकारी के साथ में गाली गलौज कर उसे जान.माल की धमकी देने वालों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मौदहा कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। पड़ोसी जनपद महोबा के कस्बा चरखारी के मोहल्ला रायनपुरवा निवासी अभिषेक कुमार पुत्र संतोष कुमार ने बताया है कि वह यातायात निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। बीती जुलाई को वह मौदहा कोतवाली क्षेत्र के गांव छिरका के नजदीक परिवहन विभाग की बसों को चेकिंग कर रहा था। साथ में उसकी गाड़ी का चालक हनीफ व सहायक टी आई सतेन्द्र सिंह उर्फ पिन्टू था। छिरका के पास बस को रोका जो कि हमीरपुर डिपो की बस थी और कानपुर से सागर जा रही थी। बस की कन्डेक्टर सीट पर कौशल किशोर बैठा था जो कि महोबा डिपो में संविदा सह चालक है। निरीक्षण में बस यात्रियों की गिनती करते समय कौशल किशोर ने बताया कि बस में यात्रा कर रहे कुछ लोग उसके साथ में हैं। यातायात निरीक्षक उक्त सवारियों से जानकारी लेने लगा तो कौशल किशोर ने गाली.गलौच शुरू कर दी और किसी भाजपा नेता नरेन्द्र मिश्रा से बात करायी। इस नेता ने भी गाली गलौज कर जान.माल की धमकी दे डाली। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी यातायात निरीक्षक ने मौदहा पुलिस सहित विभागीय उच्चाधिकारियों को दी लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।

अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर गहमागहमी शुरू, चल रही पद हेतु नामांकन की प्रक्रिया

पायनियर संवाददाता। हमीरपुर

जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर चल रही रस्साकशी के बाद आज कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने नामांकन किया,जिसमे अध्यक्ष पद में तीन व महामंत्री पद में दो लोगो ने नामांकन किया है। नामांकन में पुलिस व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही।

जानकारी के मुताबिक चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में कई महीनो से खीचतान चल रही थी बर्तमान अध्यक्ष भगवानदास दीक्षित एल्डर्स कमेटी को मानने से इंकार कर दिया था इसके बाद कुछ अधिवक्ताओं ने बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश से चुनाव का आदेश कराकर चुनाव की तिथि निश्चित कर दी है। कौंसिल ने साफ कहा था कि एक माह के अन्दर चुनाव कराकर कौंसिल को सूचित किया जाये वही अध्यक्ष श्री दीक्षित ने एल्डर्स कमेटी को चार्ज सौप दिया है जिससे विरोध समाप्त हो गया है, गुरुवार को अधिवक्ताओं ने नामांकन कराया जिसमे अध्यक्ष पद में महेंद्र सिंह गौतम,महेश साहू, केके शुक्ला ने नामांकन कराया है इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद में इंद्र पाल यादव व महामंत्री पद में जगत प्रसाद मिश्रा, अश्वनी प्रजापति व कोषाध्यक्ष पद में युंगाक मिश्रा जयपाल ने नामांकन कराया है। आज दिन भर कोर्ट परिसर में गहमागहमी का माहौल रहा। अधिवक्ता भवन में ताला पडा होने के कारण कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने नामांकन कराया है, आगामी 29 अक्टूबर को संघ का चुनाव होगा।

जमीन विवाद में हुई मारपीट में एक घायल, मामला दर्ज

पायनियर संवाददाता। माधोगढ़

माधौगढ़ थाना क्षेत्र के नगर माधौगढ़ में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट होने का मामला सामने आया है। विवाद इतना बढ़ा कि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर एनसीआर दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना माधौगढ़ कस्बे के मोहल्ला गांधी नगर की बताई जा रही है। पीड़ित अनुराग गुप्ता पुत्र सुरेंद्र गुप्ता, निवासी वार्ड नंबर 7 तिलक नगर, माधौगढ़ ने बताया कि उनका एक प्लॉट वार्ड नंबर 1 गांधी नगर में स्थित है। 20 अक्टूबर को दोपहर करीब 2 बजकर 40 मिनट पर अपने प्लाट पर पहुंचे तो वहाँ पहले से मौजूद शिवम, प्रदीप पुत्र रामसनेही और सोनू पुत्र बाला निवासी गांधी नगर ने उनसे गाली-गलौज करते हुए लोहे की रॉड से सिर पर वार कर दिया, जिससे अनुराग गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित का कहना है कि हमलावरों ने उनके प्लॉट पर जबरन बाउंड्री खड़ी कर दी है और एक ढाला भी रख लिया है। करीब 80 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। अनुराग गुप्ता ने यह भी बताया कि वह नोएडा में रहते हैं जिसका फायदा उठाकर विपक्षी पक्ष ने जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। उन्होंने इससे पहले भी 1076 और 112 नंबर पर कब्जे की शिकायत दर्ज कराई थी।

विधवा एवं बेटे को दबंगों ने लाठियों से पीटा

सुमेरपुर, हमीरपुर। क्षेत्र ग्राम बांक में दरवाजे पर बैठी विधवा को गांव के एक दबंग ने गाली गलौज करते हुए लाठी मारकर लहुलुहान कर दिया। बचाने आए पुत्र को भी दबंग ने लाठियों से पीटा और जान से मारने की धमकी देकर चला गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। गांव की विधवा कुसुम देवी ने बताया कि वह बुधवार को शाम घर के दरवाजे पर बैठी थी तभी गांव निवासी जगभान सिंह आया और गालियां देने लगा मना करने पर उसने लाठी मारकर लहुलुहान कर दिया। आवाज सुनकर बचाने आए पुत्र राजेंद्र कुमार को भी लाठी मारकर घायल कर दिया और जान से मार देने की धमकी देकर चला गया। पुलिस ने विधवा की तहरीर में मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है।

सड़क हादसों में एक की मृत्यु, बाकी भर्ती

मौदहा, हमीरपुर। बुधवार की शाम कस्बे के बाहर से निकले नेशनल हाईवे पर चार सडक हादसों में एक युवक की मौत हो गई और चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका कस्बे के सरकारी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर है। पडोसी जनपद महोबा के खन्ना निवासी निवासी ध्रुवराज उर्फ. बच्चा यादव (26) और महेंद्र यादव मौदहा से हाईवे खन्ना जा रहे थे तभी नरायच के निकट अज्ञात वाहन ने बाईक में टक्कर मार दी जिससे दोनों युवक सडक पर गिर गए जिसके बाद टक्कर मारने वाले वाहन ने बच्चा यादव को कुचल दिया और मौके से फरार हो गया घटना में बच्चा यादव की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पप्पू यादव को इलाज के लिए कस्बे के सरकारी अस्पताल लाया गया अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जमीनी विवाद में हुई मारपीट में दस नामजद

सुमेरपुर, हमीरपुर। क्षेत्र के ग्राम कैथी में 20 अक्टूबर की शाम जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया है। कैथी निवासी महावीर निषाद का आरोप है कि उसकी जमीन पैलानी तहसील के गडरिया मौजे पर है। गत 20 अक्टूबर की शाम वह पत्नी भूरी संग खेत पर जानवर चरा रहा था। तभी गडरिया निवासी भैरमए संदीपए शिव मुनिए राम मुनीए मुन्नी देवी आए और गाली गलौज करके उसकी पत्नी भूरी को जमकर मारा पीटा। जिससे उसे गंभीर चोटें लगीं।

बीस हजार रुपये चोरी का मामला दर्ज

मौदहा, हमीरपुर। फार्म हाउस में रखे फावड़ा सब्बल तथा बिना लाक किये खड़ी चार पहिया गाड़ी में रखे बीस हजार रुपए चोरी होने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश से रिपोर्ट दर्ज की है. कस्बे के मोहल्ला हुसैनगंज निवासी मो जावेद ने न्यायालय जूनियर डिवीजन को दिये प्रार्थना पत्र में बताया कि 15 अप्रैल 2025 को रात छिमौली रोड स्थित फार्म हाउस से आरोपी जुनैद पुत्र पप्पू हजारे निवासी उपरौस शफीर अहमद पुत्र बशीर अहमद निवासी चौधराना सहित दो अज्ञात लोगों के विरुद्ध फार्म हाउस से फावड़ा सब्बल तथा बिना लाक किये खड़ी चार पहिया गाड़ी में रखे 20 हजार रुपए निकालने से संबंधित लिखित शिकायत पुलिस से की थी।

राजवैद्य पंडित तुलसीराम की 31 वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनायी गयी

पायनियर संवाददाता। कालपी,जालौन

राजवैद्य पंडित तुलसीराम शुक्ल स्मारक समिति द्वारा राजवैद्य पंडित तुलसीराम शुक्ल की 31 वी पुण्यतिथि धूमधाम के साथ मनाई गई। जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।

गुरुवार को आशुतोष आयुर्वेद भवन स्टेशन रोड कालपी में राजवैद्य पंडित तुलसीराम शुक्ल वैध जी की 31 वी पुण्यतिथि पर सर्व प्रथम गौपूजन, गीतापाठ, आरती, भजन, प्रवचन, यमुना पूजन व यमुना आरती का कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान मौजूद वक्ताओं ने राजवैद्य पंडित तुलसीराम शुक्ल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहाकि उन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से न जाने कितने मरीजों को स्वस्थ किया तथा संस्कृत भाषा को बढाने के लिये संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना आपके द्वारा कराई गई जो कि आज अपनी ऊंचाईयों पर है।

योग व साधना तथा शिक्षा उनके लिये अति प्रिय थी। आज से 31 वर्ष पूर्व उन्होंने योग साधना करते हुवे अपने शरीर को शान्त किया था। उनके बताये मार्ग पर चलने का संकल्प लेने की बात कही गई। इससे पूर्व शिवशंकर शुक्ला शास्त्री, महंत रविन्द्र अवस्थी जी, पागल बाबा समेत तमाम लोगों को सम्मानित किया।

संक्षिप्त समाचार

सरकारी भूमि पर कब्जा कर खेती शुरू की

कुरारा, हमीरपुर। विकास खंड क्षेत्र के अकेहरा हार में सैय्यद बाबा के पास स्थित वीरान स्थान की जगह पर लोगों द्वारा अतिक्रमण कर खेती करना शुरू कर दिया है। तथा बिना किसी पट्टे के अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। क्षेत्र के डामर गांव के मौजा अकेहरा हार में लोगों के खेत है। तथा सैयद बाबा के स्थान के पास वीरान टीला है। तथा टीला के ऊपर एक प्राचीन कुआं भी है। इस टीला के आसपास सरकारी जमीन है। तथा पेड़ भी है। दीपावली के पर्व पर इस स्थान पर दिवारी व मेला लगता है। गांव निवासी बद्री सिंह यादव अब्दुल रहमान राजू भारत सिंह आदि ग्रामीणों ने बताया कि इस टीला में हम लोगों के पूर्वज अपने पशुओं को लेकर बरसात के समय चार माह यही निवास करते थे। इसका क्षेत्रफल चार एकड़ के लगभग है इस सरकारी भूमि पर लोगों ने अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया है। तथा कुछ जमीन पर फसल उगाना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने इसकी जांच कराए जाने की मांग की है।

युवक पर चाकू व हंसिया से हमला, हालत गंभीर

सुमेरपुर, हमीरपुर। सुमेरपुर थाना क्षेत्र में देर रात युवक पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गयाए जबकि दूसरा भी जख्मी हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कस्वा निवासी रामप्रताप तिवारी का पुत्र सौरभ तिवारी 20 अक्तूबर की रात अपने मित्रों से मिलकर घर लौट रहा था। तभी पंचमढ़ी के आगे नरहिया मार्ग में बैठे कुछ युवकों ने उसे बेवजह गाली गलौज देना शुरू कर दिया। जब सौरभ ने विरोध किया तो बऊआ जसवंत सिंह टिंकू प्रिंस व राज तिवारी निवासी चांदथोक कस्बा सुमेरपुर ने उस पर चाकू और हंसिया से हमला कर दिया। बीच.बचाव करने पहुंचे अमित यादव निवासी चांदथोक पर भी हमला किया गया। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों के पहुंचने पर हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल सौरभ और अमित को पीएचसी सुमेरपुर से जिला अस्पताल हमीरपुर भेजा गया सौरभ की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे कानपुर रेफर कर दिया। सौरभ का इलाज रिजेंसी हॉस्पिटल के आईसीयू में चल रहा है जबकि अमित का हमीरपुर में उपचार हो रहा है पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

अवैध असलहे से की फायरिंग, जांच जारी

सुमेरपुर, हमीरपुर। बीती रात सिमनौडी के तीन युवकों ने अवैध असलहों से लैस होकर पड़ोसी के घर आ धमके और हवाई फायर करते हुए गाली गलौज कर जान से मार देने की धमकी देकर चले गए। सिमनौडी निवासी करन सिंह ने पुलिस को बताया कि गांव निवासी सुनील कुमार ओमप्रकाश जितेंद्र कुमार अवैध असलहों से लैस होकर उसके घर में घुस आए और गालीगलौज करते हुए हवाई फायरिंग करके जान से मार देने की धमकी देकर चले गए। पीडित ने मामले की शिकायत पुलिस चौकी पत्योरा में की है। थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है।

पति सहित आधा दर्जन पर दहेज उत्पीड़न का मामला

मौदहा, हमीरपुर। लगभग दो साल से दहेज की प्रताडना झेल रही विवाहिता ने पति सहित आधा दर्जन ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का मामला थाने में दर्ज कराया है पुलिस ने जांच पडताल शुरू कर दी है। कस्बे के मोहल्ला मराठीपुरा निवासी जया त्रिपाठी पुत्री सतीश चंद्र दीक्षित ने बताया कि उसका विवाह मई 2023 में सुमेरपुर थाना क्षेत्र के गांव टेढा निवासी कन्हैया त्रिपाठी पुत्र उपेंद्र त्रिपाठी के साथ कस्बे के एक गेस्ट हाउस में हिन्दू रीति रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ था जिसमे उसके पिता ने खानपान और दान दहेज में लगभग बीस लाख रुपये खर्च किए थे। पीडिता ने बताया कि ससुराल में उसके पति सहित ससुराली जन दहेज को लेकर संतुष्ट नहीं थे और अक्सर उसका उत्पीड़न करते थे। पीडिता की तहरीर पर पुलिस ने पति उपेंद्र सहित अनीता रोहित रागनी संगीता और ससुर उपेंद्र त्रिपाठी पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दबंगों ने की मारपीट, रिपोर्ट दर्ज

राठ, हमीरपुर। मामूली विवाद में दंबगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की है पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जानकारी के मुताबिक जरिया थाने के करौंदी गांव निवासी महिपाल पुत्र ठाकुरदास राजपूत ने बताया कि बुधवार की दोपहर करीब तीन बजे उसके पिता ठाकुरदास से निखिल का विवाद हो गया था। तभी शाम को निखिल पुत्र जगत सिंह अपने साथ इन्द्रपाल पुत्र बिरंचीए हैप्पी पुत्र जगत सिंह चिल्ली गांव निवासी सन्दीप पुत्र कृपाल व अन्य अज्ञात साथियों के साथ घर पर आया और उसके पिता व अजेन्द्र पुत्र हल्के के साथ गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर मारपीट करने लगे। जब उसकी पत्नी कौशल्या रानी व भाई की पत्नी सुनीता बचाने आई तो उन्हे भी लाठी से मारने.पीटने लगे। मारपीट में हल्के पुत्र ठाकुरदास को सिर में व कौशल्या के हाथ में चोटें आईं हैं। बताया कि व्यक्ति जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पीड़ित ने जरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

भास्कर एक्सक्लूसिव पंजाब में पहली बार फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक का किया जाएगा इस्तेमाल, इससे सड़कों का खर्च घटेगा

सड़क बनेगी कड़कः टूटी रोड को उखाड़ उसके मलबे से ही नई तैयार होगी, ज्यादा टिकाऊ

सुखबीर सिंह बाजवा | चंडीगढ़

पंजाब सरकार ने अब सड़कों के निर्माण में फुल डेप्थ रिक्लेमेशन (एफडीआर) तकनीक अपनाने का फैसला किया है। इससे सड़कों की मजबूती और उम्र दोनों में बढ़ोतरी होगी। सरकार अगले महीने 581.20 किमी सड़कों को एफडीआर तकनीक से बनाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा ही है। शुरुआती चरण में राज्यभर के 59 स्थानों पर इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इसके लिए टेंडर से जुड़ी तकनीकी शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है।

पंजाब में पहली बार एफडीआर तकनीक से बनने वाली सड़कों की लागत में 20 प्रतिशत तक की बचत होगी और ये सड़कें लंबे समय तक टिकाऊ रहेंगी। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पहले चरण में मुख्य जिलों को चुना गया है, जिसके बाद इस तकनीक को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक में इसे औपचारिक मंजूरी दी गई। गौरतलब है कि यह तकनीक अब तक देश में अरुणाचल प्रदेश, केरल और हिमाचल में ही इस्तेमाल की गई है।

नई सड़कों के निर्माण के साथ ही लोक निर्माण विभाग ने 19,320 किलोमीटर सड़कों पर व्हाइट लाइन लगाने का कार्य भी शुरू किया है। इससे उन सड़कों पर, जहां पटरियां नहीं हैं, किनारों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सकेगा।

क्या है एफडीआर तकनीक

एफडीआर (Full Depth Reclamation) का अर्थ है पूर्ण गहराई में पुनर्निर्माण या पुनर्स्थापन। यह एक आधुनिक, टिकाऊ और लागत-प्रभावी सड़क निर्माण तकनीक है। इसमें पुरानी और क्षतिग्रस्त सड़क को पूरी तरह तोड़कर उसी सामग्री का पुनः उपयोग किया जाता है। एक विशेष मशीन के माध्यम से सड़क की ऊपरी परत से लेकर बेस लेयर तक की सामग्री को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। मशीन में लगे कंप्यूटर सेंसर यह विश्लेषण करते हैं कि उस सामग्री में क्या कमी है और किन रासायनिक पदार्थों (जैसे डामर इमल्शन या अन्य स्टेबलाइजिंग एजेंट) को मिलाया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया से तैयार हुई नई मिश्रित परत को रोलर से दबाकर मजबूत आधार तैयार किया जाता है। इसके ऊपर नई डामर या कंक्रीट की परत बिछाई जाती है, जिससे सड़क चिकनी, मजबूत और टिकाऊ बनती है। अब तक विभाग के ठेकेदार पुरानी सड़क को पूरी तरह तोड़े बिना ही उसके ऊपर नई परत बिछा देते थे। गड्ढों को भरकर सिर्फ ऊपरी परत डालने से सड़क की नींव कमजोर रहती थी, जिसके कारण कुछ ही महीनों में सड़क टूट जाती थी।

इस तकनीक के फायदे

लागत में बचतः पुरानी सड़क की सामग्री का फिर उपयोग होने से निर्माण लागत में 20-25 फीसदी तक की कमी आती है।

पर्यावरण हितैषीः नई सामग्री की आवश्यकता कम पड़ती है, जिससे प्रदूषण और परिवहन लागत दोनों घटते हैं।

मजबूत नींवः सड़क की निचली परतों को भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सड़क की टिकाऊ उम्र बढ़ती है।

महंगी मशीनरी...इस तकनीक में उपयोग होने वाली मशीन की कीमत लगभग 12 करोड़ रुपये है, जिसे निर्माण करने वाले ठेकेदार को ही उपलब्ध कराना होगा। यही मशीन पुरानी सड़क की सामग्री और नई सामग्री को उचित अनुपात में मिलाकर नई सड़क तैयार करती है।

ठेकेदार रहेगा पांच साल तक जिम्मेदार...एफडीआर तकनीक से बनी सड़कों की मरम्मत की जिम्मेदारी निर्माण करने वाले ठेकेदार की पांच साल तक होगी। इस अवधि में सड़क में किसी भी प्रकार की खराबी या टूट-फूट होने पर वही ठेकेदार उसे ठीक करेगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस तकनीक से बनी सड़कें जल्द खराब नहीं होतीं।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस का तबादला

चंडीगढ़|पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वीरवार को एक प्रशासनिक फेरबदल के तहत अपने रजिस्ट्रार विजिलेंस कमलजीत लांबा का तबादला कर दिया है। उन्हें जालंधर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पद पर नियुक्त किया गया है। जानकारी के अनुसार कमलजीत लांबा पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के करीबी रिश्तेदार हैं। भुल्लर इस समय सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। सूत्रों के मुताबिक, यह तबादला नियमित प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा है। कमलजीत लांबा ने रजिस्ट्रार विजिलेंस के रूप में लगभग तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था। उन्हें नवंबर 2022 में इस पद पर नियुक्त किया गया था।

बघाट बैंक एनपीए मामला • 12 डिफॉल्टर के खिलाफ दिए गए हैं गिरफ्तारी के आदेश

बघाट बैंक का एक लोन डिफॉल्टर गिरफ्तार, 2.10 करोड़ की देनदारी

भास्कर न्यूज | सोलन

द बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सोलन के एक डिफॉल्टर को वीरवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए डिफॉल्टर पर बैंक का 2.10 करोड़ रुपए का लोन है।

एआरसीएस ने बघाट बैंक के एनपीए होने वाले 12 डिफॉल्टर्स के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। वीरवार को इनमें से एक डिफॉल्टर खेमलाल को गिरफ्तार किया गया। हालांकि एआरसीएस अदालत ने पुलिस को 12 डिफॉल्टर को गिरफ्तार करने के लिए पत्र लिखा है।बघाट बैंक के 499 ऋण डिफाल्टरों ने बैंक की वित्तिय स्थिति को हिला कर रख दिया है। इन लोगों का लिया गया लोन एनपीए हो गया है।

एआरसीएस कोर्ट ने 17 अक्टूबर को खेम लाल निवासी सपरून गुरुद्वारा पावर हाउस रोड सोलन तहसील व जिला सोलन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। वारंट के अनुसार खेम लाल ने बघाट बैंक सोलन से व्यापारिक उदेश्य के लिए लोन लिया था, लेकिन वह लोन को तय सीमा के अंदर वापिस करने में नाकाम रहा। इस पर उसे बघाट बैंक सोलन की ओर से डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। इसकी ब्याज सहित कुल देनदारी 2,10,65,893 रुपए बनती है I देनदारी को न चुकाने पर खेम लाल के विरुद्ध सह सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सोलन कोर्ट में लोन रिकवरी का मामला में चल रहा है। खेम लाल को कोर्ट की ओर से बार- बार नोटिस दिए चुके हैं। इसके बावजूद वह कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था। इस पर 23 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार किया गया।

137.5 करोड़ रुपए के एनपीए के कारण बघाट बैंक में लेनदेन पर आरबीआई ने दो सप्ताह पहले 6 माह की कैपिंग लगाई थी

करीब दो सप्ताह पहले आरबीआई ने 137.5 करोड़ रुपए के एनपीए के कारण बघाट बैंक में लेनदेन पर 6 माह की कैपिंग लगा दी है। इस 6 माह के दौरान बैंक के उपभोक्ता सिर्फ 10 हजार रुपए की निकासी ही कर सकते हैं। निकासी पर 6 महीने की रोक के बाद बैंक के 80 हजार खाताधारकों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। इसके बाद बैंक के लोन डिफॉल्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं की अदालत ने 12 डिफॉल्टरों को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए हैं। आरोप है कि यह ऋण धारक रिकवरी में सहयोग नहीं कर रहे थे। इनके अलावा 4 लोन धारकों के वाहन जब्त करने के भी आदेश जारी किए । इस कार्रवाई के बाद अभी तक सिर्फ 65 लाख रुपए रिकवरी हो पाई है। हालांकि सरफेसी एक्ट की धारा 13 में बैंक को भी ऋण की रिकवरी के लिए बहुत शक्तियां मिली हुई है। यह अलग बात है कि बैंक ने इन शक्तियों का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया।

पुलिस ने गिरफ्तार किया लोन डिफॉल्टर

डिफॉल्टर घोषित करने का क्या है नियम

जानकारी के मुताबिक लगातार तीन किस्तों का भुगतान न करने पर बैंक ऋण धारकों को डिमांड नोटिस जारी कर 60 दिनों में पूरी ऋण राशि का भुगतान करने के निर्देश जारी करता है। सरफेसी एक्ट की धारा 13 (4) में बैंक को डिफाल्टर की संपत्ति को जब्त कर सकता है। बैंक अपने स्तर पर भी यह कार्रवाई कर सकता है।

बैंक के 499 डिफाल्टर : इस समय बघाट बैंक के 499 लोन डिफाल्टर हैं। इनसे 6 माह के अंदर 137.5 करोड़ रुपए की रिकवरी करना आसान नहीं है क्योंकि पिछले तीन वर्षों से बैंक ने रिकवरी पर जोर दिया है जिसमें से 184 करोड़ रुपए ही वसूल हुए हैं। बताया जा रहा है कि मार्च 2022 में बैंक का एनपीए 322 करोड़ रुपए था।

रिकवरी पर फोकस के लिए लगाया प्रतिबंध... आरबीआई ने बैंक पर प्रतिबंध इसलिए लगाया है ताकि वह अपना पूरा फोकस सिर्फ रिकवरी पर लगाए। आरबीआई ने बैंक में डिपॉजिट पर भी रोक लगाई है। यही नहीं बैंक के जो ऋण धारक ईमानदारी के साथ ऋण का भुगतान कर रहें है उन्हें भी अब एनएफटी से ऋण की किस्त जमा करना मुश्किल हो गया है क्योंकि आनलाइन ट्रांजेक्शन पर भी रोक लग गई है।

एआरसीएस कोर्ट की ओर से जारी आदेशों की अनुपालना करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दूसरे डिफॉल्टर्स के खिलाफ भी नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। **-गौरव सिंह,** एसपी सोलन

₹50 हजार रिश्वत लेने के आरोप में एसएचओ अरेस्ट

कुरुक्षेत्र | एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) पंचकूला की टीम ने गुरुवार रात 50 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में सिटी थाना प्रभारी को गिरफ्तार कर लिया। टीम एसएचओ को अपने दफ्तर ले गई है। आरोप है कि थानेसर के प्रभारी सब इंस्पेक्टर विनय कुमार ने सिल्वर सिटी वासी सागर के परिजनों को गिरफ्तार न करने के एवज में उसके साढू अनिल कुमार से पांच लाख मांगे। साढ़े 3 लाख रुपए में बात तय हुई। 2 दिन पहले 3 लाख रुपए ले गया। बाकी के 50 हजार देने से पहले एसीबी को शिकायत कर दी। टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर दो और पुलिस कर्मी बताए जा रहे हैं, जो भाग गए। अनिल के मुताबिक उसके साढू सागर ने पार्टनर के साथ बैटरी बनाने की फैक्ट्री लगाई थी। दोनों में विवाद हो गया।

आरोप- परिवार को धमकाकर ₹5 लाख मांगे

कांगड़ा में वीरवार दोपरह को हुआ दर्दनाक सड़क हादसा

अनियंत्रित वैन डंगे से टकराई, पति-पत्नी की मौत; बच्चों को खरोंच तक नहीं आई

कांगड़ा| कांगड़ा में वीरवार दोपहर हुए सड़क हादसे में दंपती की मौके पर ही मौत हो गई, उनके बच्चे चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गए। यह हादसा 23 अक्टूबर 2025 को पुराना कांगड़ा बाईपास फोरलेन पर कछियारी चौक के पास हुआ। वैन रानीताल की ओर से कांगड़ा की दिशा में आ रही थी, जब अचानक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने डंगे (दीवार) से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में दंपती की मौके पर ही मौत हो गई, वैन में सवार उनके दोनों छोटे बच्चे पूरी तरह सुरक्षित रहे। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मृतकों की पहचान तरसूह सकोट निवासी कुलदीप (27) उनकी पत्नी तमन्ना (26) के रूप में हुई है। यह परिवार किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए कांगड़ा की ओर जा रहा था। बच्चों को पास के स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक जांच के लिए ले जाया गया, जहां वे पूरी तरह स्वस्थ पाए गए।

हादसे में क्षतिग्रस्त गाड़ी, इनसेट हादसे में सुरक्षित बचे दोनों बच्चे सक्षम व प्रियंका

तेज रफ्तार और नियंत्रण खोना बनी हादसे की वजह

पुलिस की प्रारंभिक जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि चालक (कुलदीप) ने तेज रफ्तार के कारण वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते वैन सीधे डंगे से जा टकराई। हादसे के समय मौसम साफ था और सड़क पर ट्रैफिक सामान्य था। हादसे के सही कारणों का पता जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।

चगांव में पिकअप दुर्घटनाग्रस्त दो लोगों की मौत और 3 घायल

कंडाघाट|चायल- गौड़ा सड़क मार्ग पर चायल से 19 किमी दूर हिंनर गांव को जाने वाली सम्पर्क सड़क पर बुधवार रात एक पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें दो लोगों की मौत और तीन घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब पिकअप गौड़ा गिरिपुल की तरफ सीमेंट, सरिए को लेकर चगांव जा रही थी। यह पिकअप चायल गौड़ा सड़क से हिंनर चगांव जाने वाले लिंक रोड पर करीब डेढ़ किमी दूर पहुंची की बुधवार रात करीब आठ बजे दुर्घटनाग्रस्त होकर करीब 100 मीटर नीचे गिर गई। ग्रामीणों ने 108 और पुलिस को इसकी सूचना दी। दुर्घटना के समय पिकअप में पांच लोग सवार थे जिनमें से दो लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। मृतकों का नाम चौपाल निवासी चालक अमन और नेपाली पूर्ण सिंह बताया गया है।

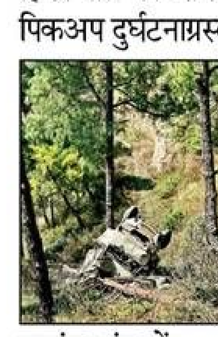

चगांव गांव में दुर्घटनाग्रस्त पिकअप

सैलून में किशोरी से दुष्कर्म, दो युवतियों समेत 3 पर केस

यमुनानगर | शहर के सेक्टर-17 स्थित सन साइन सैलून में युवक पर दो युवतियों के साथ मिलकर 15 वर्षीय किशोरी के साथ गलत काम करने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद दो युवतियों व आरोपी युवक पर पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

जगाधरी की एक कॉलोनी निवासी महिला ने शिकायत में बताया कि प्रीति उर्फ नेहा, सुरभि उर्फ नैना नाम की महिला की उनकी 15 वर्षीय बेटी के साथ जान पहचान थी। दोनों आरोपी 19 सितंबर को उसकी 15 वर्षीय बेटी को सेक्टर-17 स्थित सन साइन सैलून में लेकर गए।

महज एफआईआर होने पर वेतन वृद्धि नहीं रोक सकते : हाईकोर्ट

चंडीगढ़ | पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी के खिलाफ महज एफआईआर दर्ज होना दुर्व्यवहार नहीं माना जा सकता। इस आधार पर वार्षिक वेतनवृद्धि रोकना अवैध है। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने फैसले में कहा कि कर्मचारी को मिलने वाली वेतनवृद्धि उसका अर्जित अधिकार है, जो पिछले वर्ष की संतोषजनक सेवाओं की स्वीकृति के रूप में दी जाती है। एफआईआर दर्ज होना दोष सिद्ध नहीं करता। यह सिर्फ एक जांच की प्रारंभिक अवस्था है जिसका परिणाम अनिश्चित रहता है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि बिना किसी निष्कर्ष या दंडात्मक कार्यवाही के केवल एफआईआर के आधार पर इंक्रीमेंट रोकना न्यायसंगत नहीं है। केवल नियमित विभागीय जांच और सजा मिलने के आदेश के बाद ही वेतनवृद्धि रोकी जा सकती है। अन्यथा यह कर्मचारी के साथ मनमानी और अन्याय होगा।

फर्जी दाखिला मामला • जांच में शामिल 284 बच्चों में से केवल 110 ही पहुंचे

रानियां के दो सरकारी स्कूलों में फर्जी दाखिलों की जांच करने पहुंची सीबीआई

भास्कर न्यूज | रानियां

सरकारी स्कूलों में 2014-15 व 2015-16 के दौरान हुए करीब 4 लाख फर्जी दाखिलों और मिड-डे मील घोटाले की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सिरसा जिले के स्कूलों में छानबीन तेज कर दी है। गुरुवार को सीबीआई की चार सदस्यीय टीम ने रानियां के दो सरकारी स्कूलों में पहुंचकर नामांकन, मिड-डे मील, ग्रांट रजिस्टर, ट्रेजरी रिकॉर्ड, कैशबुक, वर्दी और स्टेशनरी से जुड़े रिकॉर्ड की गहन जांच की।

रानियां के नाथोंवाला मोहल्ले के स्कूल में सीबीआई की सूची में 157 बच्चों के नाम थे, लेकिन केवल 70 बच्चे या उनके अभिभावक ही जांच के लिए पहुंचे। इसी तरह, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रानियां में 91 बच्चों की सूची में से करीब 40 लोग उपस्थित हुए। कई लड़के अब रोजगार के लिए अन्य राज्यों में चले गए हैं, कुछ मजदूरी, हलवाई या वैद्य का काम कर रहे हैं। वहीं, उस समय की कई छात्राओं की शादी हो चुकी है और वे राजस्थान, पंजाब या जम्मू में बस गई हैं। अभिभावक उनकी जगह जांच में शामिल हो रहे हैं। एक अभिभावक करमजीत ने कहा कि मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, इसलिए मैं उसकी जगह आया हूं। सिरसा के सातों खंडों के 35 स्कूलों में 2938 फर्जी दाखिले पाए गए। 2013 तक दाखिले मैन्युअल थे, लेकिन 2014 से एमआईएस पोर्टल लागू होने पर फर्जी नाम उजागर हुए।

रानियां | सीबीआई जांच में शामिल होते बच्चे व अभिभावक

तस्कर एम्बुलेंस में ले जा रहे थे गोवंश, पुलिस को देख छोड़कर भागे

भास्कर न्यूज | पलवल

गो तस्करों ने अब एम्बुलेंस का सहारा लेना शुरू कर दिया है। तस्कर जब गोवंश को ले जा रहे थे तो रास्ते में उनकी एम्बुलेंस खराब हो गई। इसकी सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। उसने एम्बुलेंस से तीन गोवंश बरामद किए। सदर थाने के एएसआई अनिल कुमार को सूचना मिली कि धामाका में कुछ तस्कर गोवंश को एम्बुलेंस में भरकर अहरवां गांव होते हुए मेवात ले जा रहे हैं। इस सूचना पर वे टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस को सड़क पर खड़ी सफेद रंग की ईको एम्बुलेंस गाड़ी मिली। जांच करने पर पाया गया कि गाड़ी के अंदर दो बछड़े और एक गाय है। इनके पैर और मुंह रस्सियों से बंधे थे। पुलिस को आता देख तस्कर एम्बुलेंस व गोवंश को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात गो तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने गोवंश को गोशाला भिजवा दिया।

लुधियाना में वेरका मिल्क प्लांट के बॉयलर में धमाका, कर्मचारी की मौत, पांच जख्मी

लुधियाना | फिरोजपुर रोड स्थित वेरका के मिल्क प्लांट के बॉयलर में बुधवार देर रात ब्लास्ट हो गया। हादसे 42 वर्षीय कुनाल जैन की मौत हो गई जबकि 5 अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। चौकी इंचार्ज अश्विनी कुमार ने बताया कि हादसा एयर हीटर में गैस भरने के कारण हुआ। घायलों की पहचान कुलवंत सिंह, अजीत सिंह, पुनीत कुमार, देविंदर सिंह और गुरतेज सिंह के रूप में हुई है। सभी को डीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुछ दिन पहले हुए निरीक्षण में जांच अधिकारी ने बॉयलर को ओके करार दिया था।

पंजाबः महिला आयोग सी. वाइस चेयरपर्सन ने संभाला पदभार

चंडीगढ़| पंजाब राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त वरिष्ठ वाइस चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और दस सदस्यों ने आज विधिवत रूप से अपना पदभार संभाल लिया। आयोग की चेयरपर्सन राज लाली गिल ने बताया कि जिला बठिंडा की रुपिंदर कौर गिल ने वरिष्ठ वाइस चेयरपर्सन और अजनाला की गीता गिल ने वाइस चेयरपर्सन के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस अवसर पर राज लाली गिल ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि वे पूरी निष्ठा, जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य करते हुए प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और कल्याण सुनिश्चित करने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि महिला आयोग प्रदेश में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इनके साथ ही आयोग के 10 नवनियुक्त सदस्यों ने भी आज अपना पदभार संभाला।

भास्कर खास टिप्पणी- प्रक्रिया में देरी या तकनीकी कारणों से नियुक्ति से वंचित करना सही नहीं

उम्मीदवार को 30 दिन की समयसीमा में ज्वॉइन न करने पर नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकताः हाई कोर्ट

निर्देशों को कठोर नियम की तरह नहीं, बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए

भास्कर न्यूज | चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया कि किसी उम्मीदवार को केवल 30 दिन की समय सीमा में ज्वॉइन न करने के आधार पर नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता, खासतौर पर जब देरी उसके नियंत्रण से बाहर हो। जस्टिस जगमोहन बंसल ने याची हर्ष रावल की नियुक्ति अस्वीकार करने के आदेश को रद्द करते हुए दो सप्ताह के भीतर हरियाणा सरकार को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया।

हाई कोर्ट ने कहा कि हरियाणा में लागू पंजाब पुलिस नियम ऐसे मामलों के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और इनमें 30 दिन की कठोर सीमा निर्धारित नहीं है। जस्टिस बंसल ने कहा कि नौकरी के अवसर देश में सीमित हैं। किसी उम्मीदवार को केवल प्रक्रिया में देरी या तकनीकी कारणों से नियुक्ति से वंचित करना सही नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि निर्देशों को कठोर नियम की तरह नहीं, बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस विभाग को आदेश दिया कि वे दो सप्ताह के भीतर हर्ष रावल को नियुक्ति पत्र जारी करें और उन्हें सेवा में शामिल होने दें, बशर्ते वे अन्य औपचारिकताओं का पालन करें। कोर्ट ने साफ कहा कि प्रशासनिक निर्देश कोर्ट पर बाध्यकारी नहीं होते, न्याय और निष्पक्षता सर्वोपरि है।

याचिका में हर्ष ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 28 जून 2024 को जारी विज्ञापन के तहत कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था। उन्होंने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, फिजिकल परीक्षण और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे किए। परिणाम 17 अक्टूबर 2024 को घोषित हुआ और उन्हें 20 नवंबर 2024 को शामिल होने के लिए पत्र भेजा गया।

इसी अवधि में उनके गांव में राजनीतिक गुटबाजी के चलते झगड़ा हुआ, इसमें दो एफआईआर एक रावल के परिवार की ओर से और दूसरी उनके खिलाफ दर्ज हुई। इस विवाद के चलते वह न्यायिक हिरासत में चले गए। बाद में मामला आपसी समझौते से सुलझा और हाई कोर्ट ने 19 मई 2025 को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी।

याची ने की थी ज्वॉइनिंग के लिए समय की मांग

याची की ओर से ज्वॉइनिंग के लिए समय की मांग की गई थी, लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक ने 8 सितंबर 2025 को इसे यह कहते हुए ठुकरा दिया कि सरकारी निर्देशों के अनुसार नियुक्ति के बाद 30 दिन से अधिक विलंब स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि ये सरकारी निर्देश अनिवार्य नहीं, बल्कि दिशा निर्देशात्मक हैं और इन्हें यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

10वें अंतरराष्ट्रीय गीता सम्मेलन की वेबसाइट लॉन्च की, ऑनलाइन भी जुड़ सकेंगे विशेषज्ञ

24 से 26 नवंबर तक होगा केयू में गीता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

भास्कर न्यूज | कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत इस बार होने वाले अंतरराष्ट्रीय गीता सम्मेलन में 16 देशों के 25 प्रतिभागी शामिल होंगे। केयू कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने गुरुवार को 10वें अंतरराष्ट्रीय गीता सम्मेलन की वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम से भी पूरे विश्व में गीता का वैश्विक संदेश पहुंचेगा। साथ ही देश-विदेश से ऑनलाइन माध्यम से भी विशेषज्ञ इस सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे।

प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि श्रीमद्भगवद्गीता ग्रंथ नैतिक कर्म, आध्यात्मिक विकास एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। वहीं विश्व में गीता का ज्ञान कर्तव्य-चेतना, आंतरिक शांति और सामूहिक सद्भाव के ढांचे को भी दृढ़ करता है। केयू में 24 से 26 नवंबर तक आयोजित होने वाले 10वें अंतरराष्ट्रीय गीता सम्मेलन 2025 को लेकर वेबसाइट https://gitaconferencekurukshetra.in बनाई गई है। गीता सेमिनार के निदेशक प्रो. तेजेंद्र शर्मा ने बताया कि इस वेबसाइट का उद्देश्य सम्मेलन से संबंधित सभी जानकारियों को एक मंच पर उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि इस बार सेमिनार में विदेश मंत्रालय भारत सरकार का भी विशेष सहयोग रहेगा। वेबसाइट पर सम्मेलन की थीम, अनुसंधान पत्र आमंत्रण, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्रों की रूपरेखा, कार्यक्रम-सारणी, मुख्य वक्ताओं की जानकारी और आयोजन से जुड़ी सभी सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी

कुरुक्षेत्र | वेबसाइट लॉन्च करने के बाद जानकारी देते कुलपति व अन्य।

प्रेरणा

आपकी कीमत इसमें है कि आप क्या हैं। इसमें नहीं कि आपके पास क्या है। - **थॉमस अल्वा एडिसन**

संपादकीय

ट्रम्प के शब्दों के आखिर क्या मायने निकालें हम?

ट्रम्प ने एक माह में तीन बार पीएम मोदी से बात की, उन्हें ग्रेट फ्रेंड और भारत को इनक्रेडिबल कंट्री बताया लेकिन भारत पर रूस से तेल खरीदने की सजा के रूप में टैरिफ कायम रखा। दर्जनों बार दावा किया कि उन्होंने भारत-पाक युद्ध रुकवाया। पीएम से हर फोन वार्ता के बाद ऐलान किया कि भारत ने रूस से तेल न खरीदने (या कम खरीदने) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जाहिर है पीएम ने ट्रम्प के किसी भी दावे पर हामी नहीं भरी। इसके बजाय पीएम ने कहा कि आशा है दोनों महान प्रजातंत्र हर किस्म के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की प्रतिबद्धता जारी रखेंगे। शब्दों के पीछे के भाव समझे जा सकते हैं। ट्रम्प की लड़ाई न करने की बात का जवाब था कि पाकिस्तान से आतंकवाद रोकने को कहें। ट्रम्प ने कहा कि हमारे बीच बहुत अच्छी वार्ता हुई और मोदी ने ट्रेड डील में दिलचस्पी दिखाई। लेकिन फिर ट्रेड डील क्यों आज भी अधर में है? ट्रम्प ने दुनिया के नेताओं के साथ इजराइल-फिलिस्तीन युद्ध खत्म होने का जश्न मनाया और समझौते की बिंदु संख्या 19 के अनुसार फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी में स्व-शासन का ऐलान किया लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री की उपस्थिति में इजराइली संसद ने गाजा पट्टी को देश में शामिल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। यूएस ने ट्रम्प-पुतिन भेंट में देरी की घोषणा की और रूस ने परमाणु आईसीबीएम मिसाइल्स टेस्ट कर दिया।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता

humarehanuman@gmail.com

कुछ अचानक हो या अपूर्ण, दोनों में ही ईश्वर को देखो

हम मनुष्यों के जीवन में अचानक और अपूर्ण- ये दो शब्द और उनसे जुड़ी स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत कुछ अनपेक्षित, अज्ञात जीवन में घटता ही है। और जब अचानक होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत कुछ अपूर्ण है। आपको जो भी मिलेगा, वो कहीं ना कहीं अपूर्ण है। तो पूर्ण के लिए बहुत अधिक परेशान न हों। सब मिल जाए, जो कुछ भी दिख रहा है वो हमारा हो जाए... ऐसा हो नहीं सकता। अब अचानक का उदाहरण समझें। जब भी जीवन में कुछ अचानक हो, उसको ऊपर वाले की आज्ञा मानकर स्वीकार करो। श्रीराम के जीवन में दो घटनाएं थीं। उनके राजतिलक की घोषणा भी अचानक थी और वनवास जाने की सूचना भी। और दोनों ही समय उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया। ऐसे ही कृष्ण की सुंदरता पूरी दुनिया में मान्य है, लेकिन वे भी जब जगन्नाथ पुरी में विराजते हैं तो अपूर्ण हैं। तो ये दोनों घटनाएं हमसे कहती हैं- अचानक हो या अपूर्ण, दोनों में ईश्वर को देखो।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

टु द पीपुल • कर्मचारियों की कमी से हर क्षेत्र ग्रस्त है

एक तरफ बेरोजगारी है और दूसरी तरफ लाखों खाली पद

रोजगार

डेरेक ओ ब्रायन

राज्यसभा में टीएमसी के नेता

office@derek.in

मैं पिछले छह सालों से यह कॉलम लिख रहा हूं, लेकिन यह पहली बार है जब मैं एक ही विषय पर लगातार दो कॉलम लिख रहा हूं। एक पखवाड़े पहले इस कॉलम का विषय था- निजी क्षेत्र में बेरोजगारी। इस हफ्ते, हम सार्वजनिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। युवा बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी है। देश की सबसे बड़ी नियोक्ता- यानी सरकार ने लाखों पदों को नहीं भरा है। सरकारी विभागों में रिक्त पदों की संख्या पर करीब नजर डालने पर एक बिल्कुल अलग कहानी सामने आती है। शिक्षकों और डॉक्टरों से लेकर वैज्ञानिकों और सुरक्षाकर्मियों तक- कर्मचारियों की कमी से हर क्षेत्र ग्रस्त है। इससे न केवल रोजगार का संकट पैदा हुआ है, बल्कि सुप्रशासन में भी रुकावट आती है। केवल एक उदाहरण लें : रेलवे की ही 64,000 रिक्तियों के लिए दो करोड़ लोगों ने आवेदन किया था!

शिक्षा : इस क्षेत्र में तो रिक्तियों की समस्या बहुत ही अधिक गंभीर है। जरा इन आंकड़ों पर गौर करें। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में 12,000 से ज्यादा पद खाली हैं। यूडीआईएसई+ रिपोर्ट 2024-2025 के अनुसार, एक लाख से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। इसके अलावा, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी रिक्तियों से जूझ रहे हैं- हर चार में से एक पद खाली है। जैसा कि एक संसदीय समिति ने उजागर किया है, इस कमी ने संकाय-छात्र अनुपात और शिक्षण की गुणवत्ता, दोनों को प्रभावित किया है।

रिसर्च : रिक्तियों की समस्या अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के क्षेत्र तक फैली हुई है। कुछ उदाहरण देखें। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए चार में से एक से ज्यादा पद रिक्त हैं, जबकि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) में वैज्ञानिकों के लिए लगभग पांच में से दो पद रिक्त होने के कारण रिक्तियों की दर और भी ज्यादा है। इसका सीधा असर यह होता है कि भारत इनोवेशन, वैज्ञानिक शोधपत्रों और पेटेंट के मामले में अमेरिका और चीन जैसे देशों से पीछे है।

स्वास्थ्य सेवा : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दस में से सात विशेषज्ञ पद रिक्त हैं, जबकि डॉक्टरों के पांच में से एक पद रिक्त हैं। एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी फैकल्टी की कमी से जूझ रहे हैं। 20 कार्यरत एम्स में पांच में से दो पद रिक्त हैं। इससे न केवल इलाज पर असर पड़ता है, स्वास्थ्यकर्मियों पर भी बोझ पड़ता है।

नागरिक उड्डयन और रेलवे : आसमान में बादल छाए हुए हैं और हालात को पटरी पर लाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है! डीजीसीए में दो में से एक पद रिक्त है। एक संसदीय समिति ने इसे भारत की सुरक्षा निगरानी प्रणाली के मूल में गंभीर कमजोरी बताया है। इसके अलावा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स गिल्ड ने नियंत्रकों की लगातार कमी पर चिंता जताई थी, जिस कारण महत्वपूर्ण परिचालन इकाइयां बंद हो रही हैं और आपातकालीन प्रतिक्रियाएं बाधित हो रही हैं। वहीं हाल ही में प्रकाशित एनसीआरबी की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2023 में रेल दुर्घटनाओं में उससे पिछले वर्ष की तुलना में 6.7% की वृद्धि हुई। रेलवे में अकेले सुरक्षा श्रेणी में ही 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा : इसमें अपने अडिग रवैये को लेकर सरकार बहुत गर्व करती है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? एनआईए में स्वीकृत पदों में से दस में से तीन पद रिक्त हैं, जिससे प्रभावी जांच में बाधा आ रही है। अर्धसैनिक बलों- जिनका कार्यक्षेत्र सीमा सुरक्षा

मानसून सत्र के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में रिक्तियों का आंकड़ा लगभग 15 लाख बताया था। खाली पदों को भरें। नौकरियों को हकीकत में बदलें। समय आ गया है कि 'विकसित भारत' को 'फिक्स-इट भारत' में बदलें।

भी है- में वर्तमान में एक लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा में कमी आती है और मौजूदा बलों पर दबाव बढ़ता है, जिससे कर्मियों में आत्महत्या और हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

वैधानिक प्राधिकरण : सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्थाएं भी रिक्तियों की समस्या से अछूती नहीं। इस स्तंभकार द्वारा हाल में संसद में पूछे एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्वीकारा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त हैं। इसी प्रकार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में उपाध्यक्ष और एक सदस्य (कुल दो में से) के पद मार्च 2024 से ही रिक्त हैं।

मंत्रालय और विभाग : स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग में एक-चौथाई कर्मचारियों की कमी है, जबकि प्रत्यक्ष कर बोर्ड और अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड जैसे निकायों में क्रमशः 34% और 26% की रिक्तियां हैं। जबकि किसी ने तो सालाना दो करोड़ नौकरियों का वादा किया था! जैसा कि रोमन कवि ओविड ने कहा है, 'वादों के मामले में हर कोई करोड़पति है!'

(ये लेखक के अपने विचार हैं। इस लेख की सहायक शोधकर्ता अंजना अंचायिल हैं।)

मुद्दा • सरकारी ईमेल को विदेशी सर्वर में रखना अपराध है

डिजिटल इंडिया में स्वदेशी को बढ़ावा देने के तीन उपाय

डिजिटल

विराग गुप्ता

सुप्रीम कोर्ट के वकील

viraggupta@hotmail.com

आईआईटी की पढ़ाई और अमेरिका के अनुभव के बाद श्रीधर वेम्बू ने डिजिटल इंडिया में स्वदेशी का शंखनाद किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी सरकारी दफ्तरों में जोहो के ऑफिस सुइट के इस्तेमाल का निर्देश दिया है। इसमें वर्ड, नोट टेकिंग और वेब कांफ्रेंसिंग की सुविधाएं शामिल हैं। उनकी सफलता से माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी विदेशी कंपनियों पर भारत की निर्भरता सांकेतिक तौर पर कम हो सकती है। पीएमओ समेत कई मंत्रियों और 12 लाख सरकारी अधिकारियों के जोहो में ईमेल खाते शुरू हो गए हैं। वॉट्सएप के विकल्प के तौर पर बनाए गए जोहो के अरट्टई स्वदेशी मैसेजिंग एप की भी सराहना जा रही है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए कानून सम्मत सहयोग की भी जरूरत है।

1. पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट का पालन : पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट 1993 के कानून के अनुसार सरकारी ईमेल को विदेशी सर्वर में रखना गंभीर अपराध है। इस कानून को लागू करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय ईमेल नीति बनाई थी। उसके अनुसार केंद्र के 45 लाख कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) का इस्तेमाल करना था, लेकिन उसका अभी तक पालन नहीं हुआ। उसके बाद गृह मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी की। उसके अनुसार नियमित कर्मचारियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ, सलाहकार और थर्ड पार्टी स्टाफ सभी पर सरकारी ईमेल के नियम लागू होने चाहिए। कहा जा रहा है कि 12 लाख सरकारी कर्मचारी अब जोहो ईमेल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन शेष सरकारी अधिकारी अभी भी जीमेल जैसी विदेशी सेवा का गैरकानूनी इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? केंद्र और राज्य के लगभग तीन करोड़ सरकारी कर्मचारियों पर स्वदेशी ईमेल का नियम लागू हो तो जोहो जैसी कंपनियों को कारोबारी सफलता मिलने के साथ साइबर सुरक्षा भी बढ़ेगी।

2. राज्यों का डबल इंजन : संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार टेलीकॉम, साइबर और आईटी से जुड़े विषय केंद्र सरकार और संसद के अधीन हैं। राज्यों के पास भूमि, पुलिस, श्रम, राजस्व और नगर प्रशासन से जुड़े विषयों पर अधिकार हैं। आंध्र प्रदेश में गूगल और अदाणी के सबसे बड़े डाटा सेंटर में चार सालों में 15 अरब डॉलर के निवेश के साथ लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। गृह राज्य मंत्री के संसद में दिए गए जवाब के अनुसार साइबर अपराधों से जुड़े मामलों में राज्य सरकारों को कार्रवाई का अधिकार है। लेकिन वर्तमान कानूनी व्यवस्था और आईटी इंटरमीडिएरी नियमों में प्रस्तावित संशोधनों से फील्ड अधिकारियों के अधिकारों में कटौती हो सकती है। कानून के तहत अगर थानेदार को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है तो फिर नियम तोड़ने वाली टेक कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी पुलिस और राज्य प्रशासन के पास पर्याप्त अधिकार होने चाहिए।

3. डेटा चोरी पर रोक : ई-कॉमर्स व ड्राइविंग के लिए गूगल मैप अब सबकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। उसके जवाब में बनाए गए भारतीय एप मैपल्स की आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सराहना की है। एप को डाउनलोड करने के साथ टेक कंपनियां एकतरफा तौर पर मोबाइल का अधिकांश डेटा हासिल कर लेती हैं।

भारत में वॉट्सएप के 85 करोड़, इंस्टाग्राम के 48 करोड़ और फेसबुक के 38 करोड़ यूजर्स हैं, जिनके डेटा का मेटा कंपनी एकीकृत तरीके से व्यावसायिक इस्तेमाल कर रही है। भारत की अदालत एनक्लेट (NCLAT या नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल) में वॉट्सएप ने करोड़ों

वॉट्सएप ने करोड़ों यूजर्स के बहुमूल्य डेटा पर अधिकार का दावा किया है। डेटा की ताकत से मालामाल गूगल, एपल और मेटा कंपनियों के सामने जोहो और मैपल्स जैसी स्वदेशी कंपनियों का व्यावसायिक तौर पर टिकना मुश्किल हो सकता है।

यूजर्स के बहुमूल्य डेटा पर अधिकार का दावा किया है। डेटा की ताकत से मालामाल गूगल, एपल और मेटा कंपनियों के सामने जोहो और मैपल्स जैसी स्वदेशी कंपनियों का व्यावसायिक तौर पर टिकना मुश्किल हो सकता है।

डेटा को गैर-कानूनी तरीके से विदेश ले जाने के आरोप में टिकटॉक और पब्जी जैसे 224 चीनी एप्स पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। डेटा के गैरकानूनी कारोबार से विदेशी कंपनियों के मालामाल होने के साथ देश की सुरक्षा और सार्वभौमिकता खतरे में पड़ रही है। इसे रोकने के लिए 2023 में बनाए गए डेटा सुरक्षा कानून को तुरंत प्रभाव से लागू करने की जरूरत है। केंद्र के अफसर और मंत्री सरकारी कामकाज और विज्ञापनों में विदेशी एप्स के इस्तेमाल को बंद करें तो सही अर्थों में जोहो जैसे स्वदेशी एप्स के साथ आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। **(ये लेखक के अपने विचार हैं।)**

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

ब्रांड से सबक | पोर्शे- जर्मन कार निर्माता कंपनी

कभी जर्मनी की सबसे असफल ऑटो कंपनी कहलाई पोर्शे, दिवालिया होने से दो बार बची, अब प्रीमियम ब्रांड

साल 1993, पोर्शे लगभग दिवालिया होने वाली थी। सेल्स आधी रह गई थी। हर कार पर कंपनी को घाटा हो रहा था। वेंडेलिन वीडेकिंग को सीईओ के तौर पर लाया गया था। वेंडेलिन ने जापानी इंडस्ट्रियल इंजीनियर चिहिरो नाकाओ को कंपनी की दशा और दिशा सुधारने के लिए निरीक्षण पर बुलाया। चिहिरो पोर्शे की जुफेनहौसेन फैक्ट्री में दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने प्रोडक्शन देखा, उनका चेहरा तमतमा गया। हर जगह आधे-अधूरे पार्ट्स, पुरानी मशीनें, बेकार पड़े कंपोनेंट्स और बिना सिस्टम की मैनुअल असेंबलिंग हो रही थी। वे थोड़ी देर चुप रहे फिर फैक्ट्री मैनेजर से कहा- 'यह फैक्ट्री नहीं, एक गोदाम है'। यह वो लाइन थी, जिसने जर्मन इंजीनियरिंग के 'परफेक्शन' के मिथक पर सीधा प्रहार किया था। पोर्शे कारों के निर्माण का काम इतना अस्त-व्यस्त था कि कार की लागत कई गुना बढ़ रही थी। यही कारण थी कि पोर्शे की कुछ कारों की कीमत अमेरिका के एक औसत मकान के बराबर पहुंच गई थीं। एक समय था कि इसे जर्मनी की सबसे असफल आ◌ॅटो कंपनी तक कहा जाने लगा था। हालांकि नेतृत्व में बदलाव और सही रणनीति को अपनाकर पोर्शे न केवल पटरी पर लौटी बल्कि शीर्ष ऑटो कंपनियों में भी शामिल हुई। आज ब्रांड से सबक में पढ़िए कहानी पोर्शे की।

वर्तमान स्थिति

अब इसकी मालिक फॉक्सवैगन

2008 की मंदी में इसने फॉक्सवैगन को खरीदने की कोशिश की, इसके लिए 13 अरब डॉलर का कर्ज लिया, लेकिन मंदी में बैंकों ने लोन वापस मांग लिया, जिससे यह दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गई। बाद में फॉक्सवैगन से पैसा लेकर बैंकों को दिया। इसके बाद फॉक्सवैगन ने इसे अपने समूह में शामिल कर लिया। 2024 करीब 4.08 लाख करोड़ रु. का राजस्व कमाया। 3.10 लाख गाड़ियां बेचीं दुनियाभर में। 120 देशों में इसकी गाड़ियां बिकती हैं। भारत में 2024 में 1006 गाड़ियां बेचीं।

सबक क्यों- 1993 में कंपनी को हर कार पर घाटा हो रहा था। अब सालाना हजारों करोड़ डॉलर का राजस्व।

3.10 लाख कारें बिकी पोर्शे की 2024 में दुनियाभर में

4330 करोड़ डॉलर राजस्व रहा पोर्शे का 2024 में

120 से अधिक देशों में बिकती हैं पोर्शे की गाड़ियां

1006 गाड़ियां बेचीं थीं पोर्शे ने 2024 में भारत में, जो पहली बार हुआ।

1900 में फर्डिनेंड ने पहली हाइब्रिड कार डिजाइन की।

इसलिए पिछड़ी थी पोर्शे

1. **प्रीमियम गाड़ियों के लिए महंगा तरीका-** 90 के दशक तक पोर्शे ने प्रोडक्शन ढांचे को अपडेट नहीं किया। कर्मचारी छोटे-छोटे पार्ट्स को भी हाथों से कस्टमाइज करते, जिससे प्रति यूनिट लागत बढ़ती गई और मुनाफा कम होता गया।
2. **उत्पादन रेंज का अनियंत्रित विस्तार-** पोर्शे ने 1980-90 दशक में मॉडल संख्या बढ़ा दी, लेकिन प्रत्येक मॉडल के लिए अलग इंजन, पार्ट्स, प्लेटफॉर्म रखे। इससे इन्वेंट्री जटिल हो गई।
3. **प्रतिस्पर्धा और मांग में कमी-** 90 की शुरुआत में विशेषकर यूएस व जापान में स्पोर्ट्स कार की मांग घटी। पोर्शे का मुख्य बाजार यूएस था। वहीं प्रतिस्पर्धी कंपनियां उभरीं, जिन्होंने ग्राहकों को आकर्षित किया।
4. **आर्थिक प्रबंधन में गड़बड़ी-** विस्तार के लिए भारी कर्ज लिया, लेकिन उसे मैनेज नहीं कर सकी। इससे कर्ज की अदायगी बढ़ी। नगदी प्रवाह पर दबाव आया।

इस तरह की वापसी

1. **नेतृत्व परिवर्तन-** 1993 में वेंडेलिन वीडेकिंग कंपनी के सीईओ बने, जिन्होंने कड़े नियम लागू कर खर्च घटाया। उन्होंने इन्वेंटरी को 28 दिन से घटाकर 7 दिन किया। जापानी टोयोटा सिस्टम से प्रेरित होकर लीन मैन्युफैक्चरिंग अपनाई। इससे लागत घटी।
2. **मॉडल पोर्टफोलियो का रीस्ट्रक्चर -** कंपनी ने मॉडल लाइन-अप को सरल किया। 1996 में पोर्शे बॉक्स्टर लॉन्च की जो अपेक्षाकृत सस्ती, आकर्षक थी। इसने नए कस्टमर को खींचा।
3. **इनोवेशन और रिसर्च-** पोर्शे ने तकनीकी विकास को प्राथमिकता दी। बेहतर इंजन, माइलेज और नए सुरक्षा फीचर एड किए, जिससे कस्टमर्स का विश्वास कंपनी ने फिर से हासिल किया।
4. **डिस्ट्रिब्यूशन में सुधार-** ब्रांड छवि को फिर से मजबूत किया। मीडिया, विज्ञापन और प्रोडक्ट लाइनअप के विस्तार से ग्राहकों की संख्या बढ़ाई।

कंपनी के मालिक ने खुद के नाम को बनाया ब्रांड

शुरुआत : इंजीनियर फर्डिनेंड ने नवाचार के लिए रखी थी नींव

पोर्शे की शुरुआत चेक रिपब्लिक में जन्मे फर्डिनेंड पोर्शे ने की थी। उन्हें बचपन से ही मशीनरी, इंजन-मैकेनिक्स में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने 1931 में जर्मनी के स्टटगार्ट में Dr. Ing. h.c. F. Porsche GmbH नाम से फर्म शुरू की, जिसका मतलब था 'इंजन और वाहनों के लिए डिजाइन और सलाहकार फर्म।' 1948 में बेटे फेरी पोर्शे ने कंपनी संभाली और 'पोर्शे' कार लॉन्च की।

गिरावट : 1990 में आई मंदी से घटी लग्जरी कारों की बिक्री

90 के दशक में भी पोर्शे की कारें अधिकतर मैनुअली ही तैयार की जाती थीं, जिससे उनकी लागत लगातार बढ़ती गई। 1989 में पोर्शे के मॉडल 911 टर्बो की कीमत अमेरिका में एक औसत घर के बराबर पहुंच गई थी। इससे 'ब्रांड ऑफ द रिच' वाली छवि तो बनी, लेकिन नए ग्राहक दूर होने लगे। इसके बाद 1990 में आई मंदी ने लग्जरी कारों की बिक्री को सर्वाधिक प्रभावित किया।

ऐसे पड़ा नाम : फर्डिनेंड पोर्शे के नाम पर ही इसका नाम पोर्शे रखा गया। चूंकि उन्होंने कंपनी की स्थापना की थी इसलिए उनके उपनाम को ही चुन लिया गया।

सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी : इसके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज और ऑडी हैं। खासकर इनके स्पोर्ट्स मॉडल।

पीपुल भास्कर | एनरीके इग्नेसियस

| स्पेनिश गायक, संगीतकार

41 हफ्ते शीर्ष पर रहा था एनरीके का गाना, यह वर्ल्ड रिकॉर्ड, आया से उधार लेकर बनाया था पहला एल्बम

20 दिसंबर 2015, तत्कालीन श्रीलंकाई राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरसेना ने कहा था कि मेरा तो मन कर रहा है कि एनरीके इग्लेसियस का शो देखने गई कुछ महिला दर्शकों को 'जहरीली स्टिंगरे' की पूंछ से कोड़े मारे जाएं। स्टिंगरे एक मछली है, जिसकी पूंछ जहरीली होती है। दरअसल स्पेन के इस स्टार सिंगर ने अपने कॉन्सर्ट टूर के तहत श्रीलंका में परफॉर्म किया था। इस दौरान कुछ महिला प्रशंसक इस कदर उत्साहित हो गईं कि उन्होंने कपड़े उतारकर फेंक दिए। एक फैन तो मंच पर कूदकर एनरीके को चूमने पहुंच गई। उस दौर में एनरीके के क्रेज का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 2000 में उन्हें 'किंग ऑफ लैटिन पॉप' का खिताब दिया तक दिया गया था।

एनरीके एक बार फिर चर्चा में हैं क्योंकि करीब 13 साल बाद भारत में कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले 2012 में कॉन्सर्ट टूर किया था, जिसमें पुणे, दिल्ली और बेंगलुरु में उन्होंने परफॉर्म किया था। लैटिन टाइम्स को दिए साक्षात्कार में एनरीके कहते हैं कि 'मैं कलाकार से ज्यादा एक जिज्ञासु इंसान हूं जो बंद रास्तों को खोलने की चाह रखता है।' यही नहीं वे मंच को भी कुछ अच्छा करने के लिए इस्तेमाल करने को तवज्जो देते हैं। वे संगीत को खुद के लिए लोगों से जुड़ने और अहसास करने का माध्यम मानते हैं।

खाली समय में उन्हें फुटबॉल और टेनिस देखना पसंद है। सी-फूड और स्पेनिश फूड 'पेला' उनका पसंदीदा है। वे परिवार के साथ बोटिंग और समुद्र किनारे समय बिताना पसंद करते हैं। उन्हें थ्रिलर फिल्में देखना पसंद हैं।

चर्चा में क्यों- 13 साल बाद भारत में कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं। 29 और 30 अक्टूबर को मुंबई में दो दिन कार्यक्रम करेंगे।

पार्टनर अन्ना कुर्निकोवा के साथ एनरीके

एनरीके बताते हैं कि उनके जीवन में अध्यात्म का काफी महत्व है। हमेशा सकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं।

जन्म : 1 मई 1975 (50 वर्ष), मैड्रिड, स्पेन

शिक्षा : यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट

परिवार : पार्टनर- अन्ना कुर्निकोवा, तीन बच्चे

संपत्ति : 878 करोड़ रुपए

(विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स)

शुरुआत

विरासत में मिला संगीत, पिता भी हैं महान सिंगर

एनरीके मशहूर गायक जूलियो इग्लेसियस के बेटे हैं। मां इसाबेल प्रायस्लर पत्रकार और सोशलिस्ट हैं। एनरीके नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें पिता के नाम से पहचाने। ऐसे में उन्होंने पहला एल्बम अपनी आया से पैसे उधार लेकर रिकॉर्ड किया। खुद को ग्वाटेमाला का गायक 'एनरीके मार्टिनेज' बताकर प्रचारित किया। उन्हें बाद में संगीत कंपनी फोनोविसा ने लॉन्च किया।

जीवनसाथी

टेनिस स्टार अन्ना कुर्निकोवा हैं पार्टनर

वे लंबे समय से रूसी टेनिस स्टार अन्ना कुर्निकोवा के साथ रिश्ते में हैं। दोनों की मुलाकात 2001 में उनके म्यूजिक वीडियो 'स्केप' की शूटिंग के दौरान हुई थी। यहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई, जिसे उन्होंने मीडिया से हमेशा दूर रखा। एनरिके और अन्ना के तीन बच्चे हैं। 2017 में जुड़वां निकोलस और लूसी का जन्म हुआ जबकि 2020 में बेटी मैरी पैदा हुई।

करियर

गानों और एल्बम की 18 करोड़ प्रतियां बिकीं

एनरीके ने करीब 19 साल की उम्र में प्रोफेशनली गाना शुरू किया। उस समय जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडिमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई बीच में छोड़ दी। 1995 में उनका पहला एल्बम 'एनरीके एग्लीसियस' रिलीज हुआ, जिसने उन्हें स्टार बना दिया। उनके गानों और एल्बमों की 18 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं।

रोचक : उनके 'हीरो' सॉन्ग को रोमांटिक सॉन्ग ऑफ द डेकेड का अवॉर्ड दिया जा चुका है

खास : दुनियाभर के बच्चों की बेहतरी के लिए काम करते हैं

- हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, द साल्वेशन आर्मी और स्पेशल ओलिम्पिक जैसी संस्थाओं का समर्थन करते हैं ताकि पिछड़े और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान की जा सके।
- एनरीके सेव द चिल्ड्रेन और फंडरेजर जैसी संस्थाओं से जुड़े हैं, जिससे वे दुनियाभर के जरूरतमंद बच्चों के लिए फंड जुटाते हैं।

उपलब्धि : लैटिन एयरप्ले चार्ट पर 31 गाने नंबर-1 रहे

- बिलबोर्ड हॉट लैटिन सॉन्ग चार्ट में 41 हफ्तों तक नंबर-1 रहने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है।
- बिलबोर्ड लैटिन एयरप्ले चार्ट पर उनके सबसे ज्यादा 31 गाने नंबर-1 पर रहे हैं।
- स्पॉटिफाई पर उनके गाने बाय-लान-दो को 108 करोड़ बार स्ट्रीम किया जा चुका है।

सम्मान-पुरस्कार : 1 ग्रैमी, 5 लैटिन ग्रैमी अवॉर्ड मिल चुके

- 1 ग्रैमी, 5 लैटिन ग्रैमी और 23 बिलबोर्ड म्यूजिक अवॉर्ड्स मिल चुके हैं।
- 8 अमेरिकन म्यूजिक अवॉर्ड और 2008 में एमटीवी लीजेंड अवॉर्ड मिल चुका है।
- उनके 'हीरो' सॉन्ग को रोमांटिक सॉन्ग ऑफ द डेकेड का अवॉर्ड मिला। 2000 के दशक में 'किंग ऑफ लैटिन पॉप' का सम्मान मिला था।

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

विरोधी पक्षीयांचे मतदारसंघ 'परराज्यांत'?

'**सत्ताधारी आमदारांना** बोनस' ही बातमी (लोकसत्ता- २२ ऑक्टोबर) वाचली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या आधीची अचूक वेळ वा संधी साधत महायुती सरकारकडून राज्यात पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या सत्ताधारी आमदारांना आपल्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी पाच कोटींचा घसघशीत निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तिजोरीतील पुरेशा निधीअभावी अन्य शासकीय कामांवर परिणाम होऊन मंजूर प्रकल्प रखडले असताही, केवळ आमदारांच्या खुशीसाठी सरकारी निधीची वारेमाप खैरात केली जात आहे, असे म्हटले तर त्यात वावगे ते काय! सत्ताधारी आमदार तुपाशी, तर विरोधी पक्षांतील आमदार उपाशी असा हा प्रकार नव्हे का? सत्ताधारी आमदारांचे मतदारसंघ स्व-राज्यात आणि विरोधी आमदारांचे मतदारसंघ पर-राज्यात असे तर सरकारचे मत नाही ना? राजकीय मतभिन्नतेमुळे एकाच राज्यातील नागरिकांमध्ये भेदभाव करणे सरकारला उचित वाटते काय? सत्ताधारी आमदारांच्या ताटात पाच कोटी वाढण्यास कुणाचीही ना असू शकत नाही; पण विरोधी आमदारांच्या ताटात निदान दीड/दोन कोटी तरी वाढण्यास काय हरकत आहे? तसे करण्यातच सरकारची शान आहे!

■ **बेन्जामिन केदारकर**, विरार

फक्त दहा वर्षे... राज्यात दोनच वर्षे...

'**मराठवाड्याचे अश्रू...** मुख्यमंत्र्यांचे नक्राश्रू!' हा लेख (२२ ऑक्टोबर) वाचला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जवळपास साठ- पासष्ट वर्षे सत्तेवर असूनही काँग्रेस पक्षाने पावसाच्या पाण्याचे योग्य प्रकारे नियोजन केले नाही. पूरपरिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वाजपेयी सरकारने नदीजोड प्रकल्पाची संकल्पना मांडली होती, पण याच विरोधी पक्षीयांनी त्यांना सत्ताभ्रष्ट करून नदीजोड प्रकल्प गुंडाळून ठेवला. विद्यमान केंद्र सरकार गेली फक्त दहा वर्षे सत्तेवर आहे आणि राज्य सरकार दोनच वर्षे सत्तेवर आहे. त्यापूर्वी विरोधी पक्षीयांनी ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी काय केले? विद्यमान केंद्र आणि राज्य सरकार प्रयत्न करतच आहे, पण आपल्यासारख्या खंडप्राय देशात विकासाची फळे दिसायला काही अवधी लागणारच. जागतिक तापमान बदलामुळे पाऊस अनियमित झाला असून राज्यभर ढगफुटीसारखा कोसळत असताना सरकार किती मदत करू शकणार?

■ **रमेश नारायण वेदक**, चेंबूर (मुंबई)

एक झुंज गोंगाटाशी...

'**सणसंहार' हे** संपादकीय (२२ ऑक्टोबर) वाचले. प्रतिबंधक कायद्यांना न जुमानता सणाच्या नावाखाली ध्वनी आणि वायू प्रदूषण सरे आम चालू आहे. रात्री दहानंतर आणि ठरावीक डेसिबलच्या मर्यादेबाहेर फटाके वाजवण्यास बंदी आहे असे जाहीर केले गेले; परंतु अंमलबजावणी शून्य. अशाने कायद्याचे उल्लंघन करण्यास लोक धजावतात. मग चुकीच्या बाजूने येणारी वाहने, मद्यधुंद गाडी चालवणे याचेही काही वाटत नाही.

'ध्वनी प्रदूषणसंबंधी नियमन आणि प्रतिबंध- २०००' हा कायदा धाब्यावर बसवला जातो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा रात्री १० नंतर ध्वनिक्षेपकावरून कर्णकर्कश आवाज करण्यावरील प्रतिबंधही देशभर लागू आहे.

ध्वनी प्रदूषणविरोध हे जीवनध्येय मानून काम करणाऱ्या डॉ. यशवंत ओक यांची आज आठवण होते. 'एक झुंज, गोंगाटाशी' या आपल्या पुस्तकात त्यांनी ध्वनी प्रदूषणाविरुद्धच्या लढ्याची भारतात मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या आठवणी लिहिल्या आहेत.

■ **प्रभा पुरोहित**, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई)

हा माज, ही बेदरकारी कसले द्योतक?

'**सणसंहार' हे** संपादकीय वाचले. कोणताही सण, कोणतेही औचित्य असो, भसाड आवाजात 'मॅशअप' गाणी, 'रीमिक्स' लावून घोळक्याने बेधुंद नाचत राहायचे... वाढदिवस असो, लग्नसोहळा असो- कानठळ्या बसवणारे फटाके काळवेळ न बघता फोडायचे. जोरजोरात हॉर्न वाजवत वाहने हाकायची, मॉडिफाइड सायलेन्सरची दुचाकी गुर्मीत चालवायची!

- हा माज, ही बेदरकारी कसले द्योतक आहे? बेधुंद बेछूट स्वैराचाराचे की बेफाम संपत्तीचे ? कायदा काय सांगतो हे तर सोडाच कारण कायद्याचे रक्षकच कायद्याचे भक्षण करून ढेकर देताना दिसतात; पण मनाची लाज, संवेदना, समाजभान सगळेच संपले?

■ **डॉ मयूरेश जोशी**, पनवेल

शिंदे गटास भयगंडाचे कारण नाही!

'**शिंदेंना भयगंडाने** ग्रासले असावे' या शीर्षकाच्या पत्रातून (लोकमानस- २२ ऑक्टोबर) उपरोधात्मक शब्दांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. वस्तुस्थिती पाहिल्यास भयगंडाने शिंदे व त्यांच्या पक्षाला ग्रासण्याचे काहीही कारण नाही. उलटपक्षी निवडणूक आयोगाच्या तथाकथित घोटाळ्याबाबत विरोधी पक्षातल्या नेत्यांकडून रोजच्या रोज जी टीका केली जात आहे, ती पाहता विरोधी पक्षांतच भयगंड निर्माण झाल्याचे दिसत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीच्या आत घेण्याचे आदेश दिले असूनही निवडणूक आयोगाकडून जोपर्यंत मतदार याद्या दाखवल्या जात नाहीत तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या पाहिजेत, ही मागणी कशाची द्योतक आहे? एका बाजूला राज ठाकरे यांची वक्तव्ये महाविकास आघाडीमधल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षांचे काम परस्पर करीत असल्याचे दिसून येते, तर दुसरीकडे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने महाविकास आघाडीमधल्या उद्धव ठाकरे गटाबरोबर येणे महाविकास आघाडीतल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट यांना मानवणार नसल्याचे त्या पक्षांमधल्या नेत्यांच्या प्रतिक्रियांवरून दिसून येते. एकंदरीत परिस्थिती पाहता, महायुतीमधला शिंदे गट अथवा इतर दोन पक्षांना नैराश्य येण्याचे काहीही कारण नाही. नैराश्य आलेच असेल तर ते महाविकास आघाडीमधल्या घटक पक्षांना.

■ **ॲड. सुरेश पटवर्धन**, कल्याण

सदोष मतदारयाद्यांना पाठिंबा नकोच...

'**निवडणुकीत पराभव** होणार हे कळून चुकल्याने विरोधक मतदारयादीचा मुद्दा पुढे करून रडीचा डाव खेळत आहेत, ते सैरभर झाले आहेत.' असे प्रत्यारोप आता सत्ताधारी वा त्यांच्या समर्थकांकडून होऊ लागले आहेत. जाहीरही न झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा निकाल काहीही लागो, पण मतदारयादीतील मतदारांची नावे गायब होणे, एकाच घरात २०० हून अधिक मतदारांची नावे असणे, मतदारयादीत नाव असून मतदारांचे छायाचित्र नसणे, आई, वडील, मुले यांच्या वयांत तफावत, मराठी मतदारांची तमिळ भाषेत नावे असणे हा निवडणूक आयोगाचा अनागोंदी कारभार सत्ताधारी युतीला कसा खटकत नाही? 'निवडणुका पारदर्शक व्हाव्यात' ही अपेक्षा काही चुकीची नाही.

सदोष मतदारयाद्यांना पर्यायाने बोगस मतदानाला पाठिंबा देणे हे राज्यातील सुज्ञ मतदार खपवून घेणार नाहीत, याचे भान ठेवून सत्ताधारी महायुतीने मतदारयाद्यांची पुनर्रचना झाल्यावरच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात या विरोधी पक्षांच्या मागणीस आपलाही ठाम पाठिंबा दर्शवणे सयुक्तिक ठरेल. नाहीतरी महायुतीला आपणच मताधिक्याने येणार याची खात्री आहे; मग मतदारयाद्यांची पुनर्रचना झाल्यानंतरच निवडणुका घेण्यास काय हरकत आहे?

■ **मुरलीधर हरिश्चंद्र धंबा**, डोंबिवली पश्चिम

लोकपालांना अशाने नैतिक अधिकार उरेल?

भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देणारी लोकपाल ही संस्थाच आता लोक नव्हे, तर लग्झरीकडे झुकण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जनतेसाठी न्याय देणारे लोकपाल आता स्वतःसाठी बीएमडब्ल्यू घेत असल्याची बातमी ताजीच आहे. ७० लाखांची बीएमडब्ल्यू मोटारगाडी म्हणजे सत्ता, वैभव आणि विलास यांचे प्रतीक. वास्तविक लोकपाल साधेपणा, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यांचे प्रतीक असायला हवे होते. सामान्य नागरिक आज महागाईच्या आणि बेरोजगारीच्या खाईत अडकलेला आहे. शेतकरी आपल्या उत्पादनाला भाव मिळावा म्हणून आंदोलने करतो, तर कर्मचारी पगारवाढीसाठी झटतो. आणि याच दरम्यान, लोकपाल सदस्य बीएमडब्ल्यूतून फिरताना दिसले, तर भ्रष्टाचारावर भाष्य करण्याचा नैतिक अधिकार त्यांच्याकडे उरतो का?

यातून एकच गोष्ट ठळकपणे दिसते - सत्ता बदलते, चेहरे बदलतात, पण जनतेचा पैसा नेहमी खर्च होतो तो सत्तेच्या ऐषारामासाठीच!

■ **सागर पिंगळे**, पुणे

अवास्तव प्रकल्पांना विरोध हवाच!

जनतेचा पैसा वापरून सत्ताधारी-कंत्राटदार यांची मनमानी चालणार नाही; हे मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्प-विरोधकांना 'शहरी नक्षलवादी' ठरवल्यानंतरही सांगावेच लागेल...

सुनील माने
प्रदेश सरचिटणीस, प्रवक्ता- राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या पायाभूत प्रकल्पांना विरोध करणारे शहरी नक्षलवादी ठरवून टाकले. वास्तविक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्प विरोधकांना नक्षलवादी ठरवताना अधिक गांभीर्याने बोलणे अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री सरकारचे म्हणजे राज्याचे धोरण सांगत आहेत. कोणत्याही प्रकल्पाला विरोध करणारी व्यक्ती किंवा संस्था ही नक्षलवादी आहे काय? नक्षलवाद आपण संपवल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्यमंत्री व गृहमंत्री फडणवीस यांनी आधीच जाहीर केले आहे. त्यांनी आता नव्याने शहरी नक्षलवादी हे फेक नॅरेटिव्ह पायाभूत सुविधांच्या कामांबाबत चर्चेत आणले आहे. त्या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांच्या, 'पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना सुपाऱ्या घेऊन विरोध करणारे शहरी नक्षलवादीच' या वक्तव्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

फडणवीस यांच्या काही निवडक लाडक्या पायाभूत प्रकल्पांची निवडक तीन उदाहरणे घेऊन याबाबतचा मुद्दा अधिक स्पष्ट केला जाऊ शकतो.

मुंबई-ठाणे पट्ट्यात पायाभूत सुविधांचीही जबाबदारी असलेल्या एमएमआरडीएने 'ठाणे-भाईंदर बोगदा आणि उन्नत मार्गा'ची काढलेली निविदा हे एक महत्त्वाचे उदाहरण ठरू शकते. अवघ्या दहा किलोमीटर लांबीचा पूल आणि उन्नत मार्ग प्रकल्प दुहेरी बोगदा यासाठी एमएमआरडीएने सुमारे १४,००० कोटी रुपयांचा खर्च दाखवला. हे काम 'मेघा इंजिनीअरिंग' कंपनीला देण्याचा निर्णय झाला. तथापि, एल अँड टी कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर हीच निविदा एका दिवसात १४ हजार कोटींऐवजी ११ कोटी रुपयांची करण्यात आली. याचा अर्थ हे तीन हजार कोटी रुपये आधीच राजकीय आणि सरकारी खाबूगिरीत वळवण्यात आले होते.

दुसरे उदाहरण पुणे जिल्ह्यातील बाह्य वर्तुळ मार्ग (आउटर रिंग रोड) या प्रकल्पाचे. कंपनी तीच. २० हजार ३७५ कोटींचा हा प्रकल्प अवघ्या तीन वर्षांत ४२ हजार ७११ हजार कोटींचा झाला आहे. राज्य सरकारच्याच यंत्रणांचे याबाबत खर्च कमी करण्याचे सल्ले ऐकले गेले नाहीत. ही रक्कम जनतेची आहे. तिचा भुर्दंड जनतेला बसू नये यासाठी आवाज उठवणारे मुख्यमंत्र्यांच्या दृष्टीने सुपारी घेणारे शहरी नक्षलवादी ठरणार आहेत?

मुख्यमंत्र्यांनी खाण समृद्ध आणि आदिवासी बहुल (पूर्वी नक्षलग्रस्त म्हणून ओळख असलेल्या) गडचिरोली जिल्ह्याला पोलादाचा जिल्हा - 'स्टील हब' करण्याचा निर्धार करून तिथे लाखो कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाल्याचे जाहीर केले आहे. या पोलादासाठी त्यांना नागपूर (गडचिरोली जोडून) ते गोव्यापर्यंतचा भव्य महामार्ग हवा आहे. हाच तो 'शक्तिपीठ महामार्ग'. हा ८०२ किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाचा ८३ हजार ३०० कोटींचा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या १२ आणि गोव्यातील एका जिल्ह्यातील सुपीक जमीन बाधित करत आहे. याही प्रकल्पाचा खर्च काही हजार कोटींनी वाढवण्यात आला आहे. शेजारी तसाच महामार्ग केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी कमी खर्चात तयार करत असूनसुद्धा हे केले जात असेल तर विरोध करणारे नक्षलवादी ठरवले जाणार आहेत? पिकांखालची जमीन घेऊ नका म्हणणारे शेतकरी नवे नक्षलवादी आहेत?

मुख्यमंत्री फडणवीस जेव्हा राज्यातील प्रकल्पाच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना नक्षलवादी ठरवू लागले आहेत तेव्हा या संस्था व व्यक्ती अशा कोणत्या हिंसक कारवायांमध्ये सहभागी आहेत याचे काही पुरावे राज्य सरकारकडे किंवा पोलिसांकडे आहेत का? की प्रकल्प विरोधकांवर दहशत बसवण्यासाठी हे केले जात आहे? राज्य सरकार त्यातही भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांचे नेते सांगतील तेच प्रकल्प होतील आणि त्याला विरोध करणारे हे नक्षलवादी असे लेबलिंग करण्याचा विडाच या महायुती सरकार व मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उचलला आहे?

समजा मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानात तथ्य असलेच, तरी संपूर्ण पोलीस यंत्रणा आणि इंटेलिजन्स ताब्यात असणारी व्यक्ती म्हणजे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस. त्यामुळे अशा कोणत्या हिंसक नक्षलवादी संस्था आणि व्यक्ती सरकारविरोधात, महाराष्ट्र वा देशाच्या हिताविरोधात काम करत आहेत याची माहिती फडणवीस यांनी नक्कीच जाहीर केली पाहिजे. अन्यथा त्यांनी अशा संज्ञा वापरून सरकार आणि त्यांच्या मनात असलेले प्रकल्प रेटून नेण्याचा जो प्रयत्न सुरू केला आहे, तो राज्यासाठी घातक ठरेल.

लाखो कोटी रुपयांचे हे प्रकल्प आहेत. हे प्रकल्प कोण करत आहे? आजूबाजूच्या परिसरातील लोकांना याचा काय काय उपयोग होणार आहे? त्यासाठी लोकांना विश्वासात घेण्यात आले होते का? प्रकल्पांच्या मान्यतेसाठी शेतकऱ्यांच्या तसेच ग्रामस्थांच्या सुनावणी आणि चर्चांच्या प्रक्रिया झाल्या आहेत का याची माहिती घेतली असता काय दिसते?

अनेक ठिकाणी जबरदस्तीने जमिनी ताब्यात घेणे, शासकीय जमिनी उद्योजकांच्या नावावर करणे, क्षुल्लक किमतीत प्रकल्पासाठी उद्योगपतींना सरकारच्या म्हणजे जनतेच्या जमिनी बहाल करणे, या प्रकल्पांसाठी जनतेचेच बँकेत असलेले पैसे उद्योगपतींना बिनदिक्कत कर्ज म्हणून सहजपणे उपलब्ध करून देणे ही कामे सुरू असल्याचे दिसत आहे. सरकारने प्रकल्पांना साहाय्यभूत धोरण नक्कीच राबवले पाहिजे पण हे प्रकल्प जनतेच्या हिताचे की उद्योजकांच्या हिताचे याचा सवालही जनतेने करू नये ही सरकारची अपेक्षा आहे का?

नुकत्याच एका प्रचंड मोठ्या स्टील व सिमेंट उत्पादक कंपनीच्या प्रकल्पासंदर्भात महाराष्ट्रात झालेल्या सुनावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंडप उभारून स्थानिक ग्रामस्थांना बोलावले. ग्रामस्थांच्या अतिशय काटेकोर शारीरिक तपासणीसह काळे कपडे घातलेल्यांनाही प्रवेश नाकारण्यात आला. सुनावणीवेळी त्यांना अनेक तास प्यायला पाणी दिले गेले नाही. पोलिसांकडून दहशत तयार होईल असे वातावरण निर्माण केले गेले. लोकांची बाजू नीटपणे ऐकूनही घेतली गेली नाही; याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना नाही का? अशा घटनांत या ग्रामस्थांनी वा सरपंच व स्थानिक राजकीय नेत्यांनी सरकारच्या विरोधात भूमिका मांडली तर ती नक्षलवादाची भूमिका ठरेल? ग्रामस्थांच्या बाजूने बोलणारी व्यक्ती किंवा संस्था ही नक्षलवादी ठरेल? हीच फडणवीस यांची नक्षलवादाची व्याख्या?

जगात सध्या प्रमुख देशांमध्ये निवडक आवडती उद्योग घराणी व नेत्यांच्या मनमानी सत्तेचा (ऑलिगार्की) काळ सुरू आहे. चीन- रशियापासून अमेरिकेपर्यंत ही स्थिती दिसत आहे. देशांमध्ये सर्वोच्च नेते सांगतील त्याच प्रकल्पांची कामे होतील, ते सांगतील त्याच औद्योगिक घराण्यांना कामे दिली जातील, ते सांगतील तीच किंमत ठरवली जाईल, ते सांगतील तसेच जनतेने निमूटपणे ऐकावे लागेल ही ऑलिगार्की आता भारतात दिसू लागली आहे.

याच भाजपच्या नेत्यांनी भूतकाळात अशा स्वरूपाच्या प्रकल्पांना कसा विरोध केला होता हे ते स्वतःही विसरले आहेत. ज्या मातृसंस्थेचा म्हणजे संघाचा पूर्वीचा विरोधही आता पूर्णपणे बदलून तथाकथित विकास प्रकल्पांच्या समर्थनार्थ भूमिका तयार झाल्या आहेत. कामगारांच्या कामांचे तास आठवरून बारा केले असता भारतीय मजदूर संघाने काय भूमिका घेतली? शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनचा उत्पादन खर्च साडेसहा ते सात हजार रुपये असताना मिळणारा भाव आज साडेतीन हजार रुपये आहे. त्यातून शेतकरी आत्महत्या करतो आहे. संघाच्या किसान संघाने याबाबत सत्तारूढ भाजपला काय सवाल केला? पुणे शहरातील विद्यापीठीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेत घसरण सुरू झाली असताना 'अभाविप'ने उच्चशिक्षण मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांना घेराव घातला आहे का? राज्यातील मराठी शाळा आणि शिक्षक यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत असताना शिक्षक परिषद महायुती सरकार आणि मुख्यमंत्री यांना सवाल करताना कधी दिसली आहे का? महाराष्ट्रात निमशहरी भागात ड्रग्सचा व्यापार सुरू असताना तथाकथित संस्कृती रक्षक विश्व हिंदू परिषद/ बजरंग दलाने आंदोलन केल्याचे दिसले आहे का? या साऱ्याशी या संस्थांना काही घेणेदेणे राहिले नाही; की सरकारला अशा प्रश्नांवर उत्तर मागण्याची त्यांची धमक संपली आहे?

गेल्या काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र एक ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था होणार असल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा दावा होता नुकताच तो त्यांनी दीड ट्रिलियन केला आहे. त्यांचे खरे मानले गेल्यास या दीड ट्रिलियनसाठी प्रचंड मोठी कामे महाराष्ट्रात उभी राहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उत्पादन प्रकल्प, सेवाक्षेत्र, कृषी यांत अवाढव्य काम करावे लागणार आहे. पण चीनप्रमाणे प्रकल्प रेटून, लोकांवर दडपशाही करून उद्योगांना हवे ते करू देण्याची भूमिका महाराष्ट्राने स्वीकारणे हा राज्याचा घात ठरेल.

संपलेल्या नक्षलवादाच्या विरोधात महाराष्ट्र शासनाने नवा जनसुरक्षा कायदा कशासाठी आणला असेल याची चुणूक मुख्यमंत्र्यांचे या नव्या शहरी नक्षल संकल्पनेतून दिसून येते.

पुणे महापालिकेतील केवळ केबल डक्टचा भ्रष्टाचार मी उघडकीस आणला. हजारो कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात कंपनी आणि अधिकारी यांनी मिळून पालिकेचे म्हणजे पुणेकर जनतेचे शेकडो कोटींचे नुकसान केले याबद्दल आवाज उठवायचा नाही का? हा आवाज उठवणे म्हणजे शहरी नक्षलवाद ठरणार आहे का?

महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने राज्यभर ३६ हजार ९६४ कोटी रुपयांची १४५ कामे कंत्राटदारांना दिली आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेत जबरदस्तीने पायाभूत प्रकल्प सरकार करणार असेल तर याला विरोध करायचा नाही का हाच मुख्य मुद्दा आहे. अशाच पद्धतीने नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. निसर्ग आणि शेतकरी हे एकाच वेळी संपवण्याचे हे कारस्थान ठरेल. त्याला विरोध केला तर तो नक्षलवाद समजला जाईल?

हे संघर्ष टाळण्यासाठी सरकार आणि प्रशासन यांनी जनतेला विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्वात महत्त्वाचे व्यासपीठ म्हणजे विधानमंडळ. राज्य विधिमंडळात आमदारांनी राज्याचे विकासाचे प्रश्न मांडणे अपेक्षित आहे. सरकारने त्यावर धोरणासह उत्तरे देऊन समाधान करणे अपेक्षित आहे; पण गेल्या काही वर्षांत या सर्वोच्च सभागृहात जर जनतेला न्याय मिळत नसेल तरी तिने आपल्या प्रतिनिधींसह रस्त्यांवर येत प्रश्न विचारला तर त्याला आता परवानगी नसेल. कारण माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या व्याख्येनुसार नव्या शहरी नक्षलवादाचा गुन्हा ठरू शकतो.

महाराष्ट्रात दीड ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था उभी करायचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्धार असतानाच; राज्यावर कर्जाचा बोजा नऊ लाख कोटींवर पोहोचला आहे. आर्थिक परिस्थिती गंभीर असताना अशा पद्धतीने ऋण काढून सण साजरे करण्याची मानसिकता महाराष्ट्राला आणि राज्यातील जनतेला आर्थिक संकटात ढकलणारी आहे याबद्दल प्रश्न विचारणारे शहरी नक्षलवादी ठरवले जातील काय हा आता प्रश्न निर्माण झाला आहे.

'लोक-लोलक' हे सदर आजच्या अंकात नाही.

कुतूहल

सूक्ष्मजगताचे अमृतभांडार : एटीसीसी

पेशींचा आद्यगुणविशेष, सूक्ष्मजीवांचे मूलभूत गुणधर्म आणि संदर्भ मानके हे सर्व काळाच्या वादळातूनही अक्षय राहावे, यासाठी विज्ञानाला सुरक्षित कोषाची आवश्यकता भासते. ही दृष्टी १९२५ मध्ये वास्तवात उतरली 'अमेरिकन टाईप कल्चर कलेक्शन' (एटीसीसी) या रूपाने. एटीसीसी हे जगातील प्रत्येक जैवसंशोधकाला विश्वासार्ह, प्रमाणित व मानकीकृत जैवसंपदा देण्याच्या ध्येयाने कार्यरत असलेले एक ना-नफा, पण अमूल्य जागतिक केंद्र आहे.

ही महायात्रा सुरू झाली १९२२ मध्ये, जेव्हा लोर ए. रॉजर्स यांनी 'अमेरिकन म्युझियम ऑफ नॅचरल हिस्ट्री'तील मुख्य संग्रह एका छोट्याशा सुटकेसमध्ये उचलून वॉशिंग्टन डी.सी.च्या 'आर्मी मेडिकल म्युझियम'कडे नेला. १९२५ मध्ये या अंकुराला पहिले अधिकृत आश्रयस्थान शिकागो येथील 'जॉन मॅकॉर्मिक इन्स्टिट्यूट'मध्ये मिळाले. 'रॉकफेलर फाऊंडेशन'च्या अनुदानाच्या आधाराने या प्रवासाला नवे चैतन्य लाभले.

एटीसीसीची वैशिष्ट्ये म्हणजे पेशीसंवर्धनातील काटेकोरपणा, आनुवंशिक विचलन टाळण्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादन पद्धतीचा (सीडलॉट रणनीतींचा) अवलंब करणे आणि प्रत्येक टप्प्याची विलक्षण अचूकतेने नोंद ठेवणे. आज या संस्थेत मानव व प्राणीपेशीरेषा (सेल लाइन्स), मूलभूत पेशी, हायब्रिडोमा, जीवाणू, बुरशी, यीस्ट, विषाणू, प्रोटिस्ट आणि न्यूक्लीक आम्लपर्यंतची संपन्न जैवविविधता तिच्या भांडारात सुरक्षित विसावलेली आहे.

अलीकडच्या वर्षांत एटीसीसीने 'डेटा टू व्हायल' ही अभिनव संकल्पना पुढे आणली. क्लाउड-आधारित एटीसीसी जीनोम पोर्टलच्या माध्यमातून संशोधकांना प्रमाणित व अनुसरणीय अशा संदर्भ-जीनोम्सना थेट प्रमाणित प्रजातींपासून प्राप्त झालेल्या स्वरूपात प्रवेश मिळू लागला. भौतिक व्हायल्स आणि सूक्ष्मपणे संकलित केलेली अनुक्रम माहिती यांतील हे एकास-एक बंधन जणू शास्त्रीय पारदर्शकतेची शृंखला ठरते; ज्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर मागोवा घेणे शक्य होते.

आजची एटीसीसी ही विविध सेवांचे, मानकांचे व आरोग्य भागीदारींचे केंद्रस्थान आहे. फेडरल सोल्युशन्स या उपक्रमांतर्गत एटीसीसी अमेरिकेतील विविध संस्थांशी जैवसंरक्षण व रोगसंशोधन या क्षेत्रांत सहकार्य करते. तसेच बी.ई.आय रिसोर्सेसचे संचालन करते. तिच्या कार्यक्षेत्राचा विस्तार मॅनॅसस, व्हर्जिनिया येथे उत्पादन व वितरणकेंद्रांपर्यंत पोहोचतो. गॅथर्सबर्ग व जर्मनटाउन, मेरीलँड येथे त्यांची संशोधन व विकासकेंद्रे कार्यरत आहेत. येथे त्रिमितीय ऑर्गनॉइड्स, ल्युसिफेरेज रिपोर्टर सेललाइन्स, तसेच क्रिस्पर-संशोधित आयसोजेनिक मॉडेल्स यांचा अभ्यास होतो.

एटीसीसीने केलेला प्रवास म्हणजे जणू विज्ञानातील एक जिवंत वारसा होय... जो सूक्ष्मजगताचे संवर्धन करीत, विज्ञानाला पुढे नेणारा सुवर्णमानक ठरतो.

- डॉ. गिरीश महाजन
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

उलटा चष्मा

उचलून आणले, त्यात काय झाले?

'**हे बघा,** मनात वाईट हेतू ठेवून प्रश्न विचारू नका. मीही एक सभ्य माणूस आहे. राज्याचा जबाबदार मंत्री आहे. मी जे काही केले ते तार्किकदृष्ट्या योग्य कसे हे ऐकून घ्यायचे असेल तर आता अजिबात प्रश्न नको व काय सांगतो ते निमूटपणे ऐका' शिरसाटांचा हा रुद्रावतार बघून जमलेले बूमधारी एकदम गारठलेच. आता आली परिस्थिती आपल्या आटोक्यात, हे लक्षात आल्यावर मग ते म्हणाले- 'शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून गेल्या आठ दिवसांपासून उपोषण करणाऱ्या तरुणाला मी घरी बोलावून सरबत पाजले यात काहीही गैर नाही. माझ्या या कृतीचे संपूर्ण राज्यभरातून कौतुक होतेय. अनेक मंत्र्यांनी मला फोन करून नवा व चांगला पायंडा पाडला म्हणून धन्यवाद दिलेत. शेवटी आम्ही देणारे आहोत. आंदोलनकर्ते कायम मागणारे असतात. मग तुम्हीच सांगा, कुणी कुणाच्या दारात जायचे? मागणाऱ्यानेच देणाऱ्याच्या ना! हाच सृष्टीचा नियम. अलीकडे कुणीही उपोषणाला बसतो व मंत्र्यांनीच यावे असा हट्ट धरतो. आम्ही हीच कामे करत बसलो तर राज्य कोण चालवणार? मंत्री म्हणून किती व्याप असतात आमच्यामागे याची कल्पना जनतेला सोडा पण तुम्हाला तरी आहे का? (सर्वत्र शांतता) त्या महात्म्यापासून सुरू झालेली ही परंपरा कधी तरी थांबवायला हवी की नाही? त्यामुळेच माझे अभिनंदन करणाऱ्यांत काही उजवेही होते. आता काही जण म्हणतात त्याला तहसीलदार व पोलिसांनी उचलून आणले. हे पूर्णपणे असत्य. अहो, आठ दिवस उपाशी असल्याने त्याच्या अंगात उठण्याचेही बळ नव्हते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी त्याचे बखोटे (सॉरी खांदा) धरले. हे वास्तव असूनही माझ्यावर टीका का करता? हो, आहे मला उचलण्याची सवय पण गोरगरीब जनतेला नाही तर आमदारांना उचलण्याची. मित्रांनो, आम्ही राज्यच असे चालवतो की कुणावर उपाशी राहण्याची वेळच येत नाही. इतके अस्मानी संकट येऊनही राज्यातली जनता आनंदी आहे. सर्वांनी कशी झोकात दिवाळी साजरी केली ते बघा जरा! अशा वेळी ऐन सणाच्या काळात कुणी मंडप टाकून उपाशी बसला असेल तर ते मंत्री म्हणून मी कसा सहन करणार? व्यग्र कार्यक्रमामुळे त्याच्या मंडपात जायला मला आणखी दोन दिवस लागले असते. तेवढा काळ त्याला पुन्हा उपाशी ठेवायचे? म्हणून मी त्याला उचलून (सॉरी बोलावून) घेतले. मंत्र्यांच्या घरी, थंडगार हवेत उपोषण सोडायला मिळाले म्हणून तो कर्ताही धन्य झाला असेल. त्याकडे लक्ष न देता मंडपात का गेलो नाही म्हणून तुम्ही माझ्यावरच टीका करता. तेव्हा मन फार व्यथित होते. आम्हालाही भावना असतात याचा विचार तुम्ही करणार तरी कधी? मला सांगा, खरी गरज कुणाला असते? उपोषणकर्त्यालाच ना! मग गरजवंताने लहानपण घेत एक पाऊल मागे घेतले तर बिघडले कुठे? आता तुम्ही म्हणाल की ज्यांच्यामागे हजारो लोक असतात, समाज असतो त्यांच्या उपोषण मंडपात तुम्ही कसे जाता? तुमचा प्रश्न रास्त, पण वेळ व काळ बघून निर्णय घ्यावे लागतात. आता मी ही सुरुवात केलेली तेव्हा पुढे बघा राज्यभर असाच पायंडा पडेल. तोही लवकरच. आता प्रश्न नको. दिवाळीचा फराळ घ्या व निवांत निघा.'

जशी कूस बदलली तशी संजयरावांना जाग आली. भानावर आल्यावर त्यांना पडलेले स्वप्न जसेच्या तसे आठवले. सकाळ होताच त्यांनी साहाय्यकांमार्फत माध्यमांना संदेश पाठवला. 'महत्त्वाची पत्रकार परिषद आहे. लगेच या'!

तर्कतीर्थ विचार

ग्रंथालये : लोकशिक्षणाची विद्यापीठे

महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ ही ग्रंथालयांची राज्यस्तरीय शिखर संस्था. या संस्थेचे वार्षिक अधिवेशन दरवर्षी होत असते. असे ३१वे अधिवेशन २७ व २८ फेब्रुवारी, १९८७२ला वाई (जि. सातारा) येथे झाले, त्याचे स्वागताध्यक्ष तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी होते. संमेलनाध्यक्ष 'स्वामी'कार रणजित देसाई होते. या संमेलनाचे उद्घाटन प्रा. ग. प्र. प्रधान यांनी केले होते. स्वागतपर भाषणात तर्कतीर्थांनी वाईची ग्रंथपरंपरा विशद करून ग्रंथव्यवहाराचे महत्त्व लक्षात आणून दिले होते. त्या भाषणाचा सारसंक्षेप :

''ग्रंथ हा माणसाचा चिरंतन शिक्षक आहे. हाडामांसाचा-रक्ताचा शिक्षक केव्हा दूर जाईल, बाजूला होईल वा केव्हा कालवश होईल, याचा नियम नसतो. ग्रंथाचे तसे नसते. तो नीट सांभाळला तर कायम उपलब्ध होतो. ग्रंथ हे अक्षरामध्ये निबद्ध असल्यामुळे त्यातील माहिती किंवा ज्ञानसंपत्ती महत्त्वाची असेल, तर तो कालवश होण्याची भीती कमी असते, तो तसा सहसा होत नाही. शब्दाने ज्ञान चिरस्थायी बनते आणि तो शब्द अक्षर बनला म्हणजे त्याला अमरत्व प्राप्त होण्याची शक्यता प्राप्त होत असते. प्रतिभावंत कवी, विचारवंत, प्रज्ञावंत, शास्त्रकार व कलाकार हे ग्रंथरूपाने वा चित्ररूपाने अमर होतात. ग्रंथकाराची ग्रंथ ही वाङ्मयमूर्ती असते. या वाङ्मयमूर्ती हजारो वर्षे टिकतात आणि ग्रंथालयामध्ये एकत्र जमत जातात.

ज्ञानसंग्रह जितका मोठा तितकी संस्कृती मोठी. पुस्तक हे संस्कृतीचे मस्तक आहे, म्हणून पुस्तक मस्तकावर जे निरंतर धारण करतात, तेच जीवनयात्रेत यशस्वी होतात. पुस्तक ही संसार तारून नेणारी नौका आहे. हे नौदल ज्यांचे अधिक समर्थ ते भवसागरामध्ये अधिक यशस्वी होतात. मनुष्याच्या शिक्षणाचे अत्यंत यशस्वी असे अमोल साधन म्हणजे पुस्तक होय.

प्राचीन ग्रीक संस्कृतीमध्ये जेव्हा विद्या आणि कला यांची सर्व बाजूंनी भरभराट होत होती तेव्हा विचारवंत, लेखक आणि कलाकार यांना आविष्काराचे संपूर्ण स्वातंत्र्य होते. जगज्जेता सम्राट अलेक्झांडर हा जेव्हा सिंहासनावर आला, तेव्हा त्याच्या लक्षात आले की, यापुढे या उच्च पुस्तकी संस्कृतीचा ऱ्हास होण्याची शक्यता आहे. त्याने इजिप्तवर स्वारी केली आणि तेथे नाईलच्या मुखाजवळ भूमध्य समुद्राच्या किनाऱ्यावर 'अलेक्झांड्रिया' या नावाच्या नगरीचे पुनर्वसन केले. त्या नगरीत एक संग्राहक व सर्वोत्तम ग्रंथालय निर्माण केले. ग्रीकांच्या पुस्तकी विद्यांचे संरक्षण होईल अशी तरतूद केली आणि त्याद्वारे ग्रीकांच्या बौद्धिक संस्कृतीला अमरपट्टा प्राप्त करून दिला. अनेक शतके तेथील आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठात तत्कालीन विद्या व कला यांचे अध्ययन व अध्यापन चालू होते. इसवी सनाच्या चौथ्या शतकाच्या अखेरीस ख्रिश्चन धर्मवेड्यांनी तेथील ज्युपिटरचे देऊळ, ग्रंथालय व संग्रहालयही धुळीस मिळविले. जेव्हा जेव्हा रासवट रानदांडगे, शस्त्रधारी व सत्ताधारी पुस्तकी संस्कृतीची उपेक्षा करतात व नाश करतात तेव्हा राष्ट्रांचा ऱ्हास होऊ लागतो. तेथूनच राष्ट्राच्या व विशेषतः भारताच्या ग्रंथसंपदेचा वारंवार विध्वंस केल्याच्या कथा इतिहासात नमूद झाल्या आहेत.

आज भारतात स्वातंत्र्योत्तर काळात संसदीय लोकशाही राज्यपद्धती स्थापन झाली आहे. या लोकशाहीची स्थापना एका उत्कृष्ट राज्यघटनेने घटना समितीद्वारा झाली आहे. लोकशाहीचे लोकशिक्षण हे अधिष्ठान होय. आपल्या देशामध्ये स्वातंत्र्योत्तर काळात कनिष्ठ, मध्यम व उच्च पातळीवर हजारो किंवा शेकडो शिक्षण संस्था स्थापन झाल्या आहेत. त्यामानाने ग्रंथालयांचा विस्तार फारच अपुरा आणि तोटका दिसतो. ग्रंथालय हीसुद्धा नागरिकांची मुक्त शिक्षण संस्था असते. बालविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय आणि विद्यापीठ या प्रकारच्या आकारिक पद्धतीने शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये शिकणारे आणि शिकवणारे, विद्यार्थी आणि शिक्षक आणि त्यांच्या व्यतिरिक्त असलेले लहान-मोठे नागरिक या सर्वांचे विद्यालय वा महाविद्यालय म्हणजे ग्रंथालय होय. बालपणापासून अखेरच्या क्षणापर्यंत ज्यात प्रवेश मिळतो आणि विद्या मिळते असे विद्यालय म्हणजे ग्रंथालय होय. लोकशाही शिक्षित, समर्थ लोकच चालवू शकतात. त्यामुळे ग्रंथालये ही निरंतर लोकशिक्षण देणारी विद्यापीठेच आहेत. त्यांना ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देणे, हे नित्य वाचनानेच शक्य आहे''

- डॉ. सुनीलकुमार लवटे
drsklawate@gmail.com

तेल तळतळाट

पुतिन बधणारे नाहीत, त्यांच्या देशावर निर्बंध लादणे हाच उपाय हे बायडेन यांच्याप्रमाणेच ट्रम्प यांनीही मान्य केल्याचे स्वागत; पण...

साध्या डासापासून ते डायनासॉरपर्यंत सर्वांस निष्प्रभ करण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प एकच एक अस्त्राचा वापर करताना दिसतात. ते अस्त्र म्हणजे आर्थिक निर्बंध. याआधी त्यांनी इराणविरोधातही त्याचा वापर केला आणि आता पहिल्यांदा ते हे अस्त्र रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्यावर उगारतात. अधूनमधून आयात शुल्क वाढीची छडीही आहेच. ट्रम्प यांच्या अन्य कृतींबाबत, निर्णयांबाबत भिन्न मते असतील. तथापि पुतिन यांच्यासारख्या निर्घृण आणि थंड रक्ताच्या नेत्याविरोधात कडक आर्थिक निर्बंध लादण्याच्या निर्णयासाठी ट्रम्प अभिनंदनास पात्र ठरतात. इतके दिवस त्यांचे पुतिन यांच्या बाबत तळ्यात-मळ्यात सुरू होते. ते आता संपले. ट्रम्प आणि पुतिन या दोन नेत्यांच्या मनोभूमिकेत मूलतःच फरक आहे. ट्रम्प यांच्या बहुतांश निर्णयांमागे अंतःप्रेरणेचा मोठा वाटा असतो. त्यामुळे आज घेतलेला निर्णय उद्या मागे घेण्यास त्यांना काही वाटत नाही. पुतिन यांचे तसे नाही. रशियाचा हा अध्यक्ष कमालीचा निष्ठुर, धोरणी आणि आपल्या अंतःस्थ हेतूंचा कसलाही सुगावा लागू न देणारा आहे. त्यामानाने ट्रम्प बोलघेवडे. मनात येईल ते बोलून जातात आणि छोट्याशा कृतीत विजय साजरा करतात. त्याचमुळे १५ ऑगस्टला अलास्का येथे मोठा गाजावाजा करून झालेल्या चर्चेत आपण पुतिन यांना पटवल्याचा आनंद ट्रम्प यांनी साजरा केला. युक्रेन-रशिया युद्ध आता थांबणारच अशा प्रकारची वल्गना त्या वेळी ट्रम्प यांनी केली. पण तो आनंद किती अल्पजीवी होता याची जाणीव त्यांना लगेच झाली असणार आणि त्याच वेळी पुतिन यांच्याशी चर्चा करणे निरर्थक आहे याचाही अंदाज आला असणार. कारण ट्रम्प यांनी पुतिन यांच्याशी चर्चेची दुसरी फेरी अव्हेरली आणि रशियावर कडक आर्थिक निर्बंधांची घोषणा अखेर केली.

त्यानुसार रोझनेफ्ट आणि ल्युकॉइल या दोन रशियन तेल कंपन्या यापुढे जगात कोणालाही तेल विकू शकणार नाहीत. यातील रोझनेफ्ट ही तर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची आणि रशियातील प्रथम क्रमांकाची तेल कंपनी. सौदी अरेबियातील सरकारी मालकीच्या 'अराम्को' या कंपनीखालोखाल रोझनेफ्टचा विस्तार आहे. त्यामुळे त्या कंपनीवरील निर्बंध हे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडणारे असतील यात शंका नाही. याआधी ट्रम्प यांनी चीनवर मोठ्या प्रमाणावर आयात शुल्क लादले. ते आणखीही वाढवण्याची त्यांची इच्छा आहे. पण त्याचा व्हावा तसा परिणाम चिनी अर्थव्यवस्थेवर होताना दिसत नाही. त्यामुळे रशियावरील निर्बंधांचेही असेच होईल, असे भाकीत काही जण वर्तवतात. ते अयोग्य. याचे कारण चिनी अर्थव्यवस्था ही अत्यंत वैविध्यपूर्ण आहे. म्हणजे चीन निर्यात करत असलेल्या वस्तू अनेक आहेत आणि त्या देशाची बाजारपेठही अधिक मोठी आहे. रशियाचे तसे नाही. मोठ्या कुटुंबात एकच एक कोणी कर्ता/कमावता असावा तसे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेत गेल्या काही वर्षांत खनिज तेल राहिलेले आहे. एखादा भारत, काही प्रमाणात चीन वा बेलारूस सोडल्यास रशियन मालास अन्यत्र उठाव नाही. युरोपीय संघाने युक्रेन युद्ध

... या निर्बंधांमुळे भारतावर होणारे आर्थिक परिणामही अटळ आहेत. दोन खासगी कंपन्यांप्रमाणे सरकारलाही आता अन्य मार्ग शोधावे लागतील...

सुरू झाल्यापासून रशियन अर्थव्यवस्थेविरोधात कडक भूमिका घेतली असून आता अमेरिकाही तसेच करणार असेल तर रशियन अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान निर्माण होईल. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या भूमिकेतील हा बदल महत्त्वाचा ठरतो.

तो करताना ट्रम्प हे रशियाविरोधात युरोप आणि 'अन्य मित्रराष्ट्रांनी'सुद्धा कठोर भूमिका घ्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त करतात. ट्रम्प यांना वास्तवाचे भान येऊ लागले की काय अशी शंका या विधानामुळे निर्माण होते. म्हणजे इतके दिवस युरोपीय देश युक्रेनच्या मुद्द्यावर सातत्याने अमेरिकेस आवाहन करत होते. इतकेच काय 'नाटो' (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) या अमेरिका-केंद्री लष्करी सहाय्य गटानेही ट्रम्प यांस या मुद्द्यावर गळ घातली. त्याकडे ट्रम्प यांनी दुर्लक्ष केले. इतकेच नव्हे तर यात बळी ठरत असलेल्या युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांचा ट्रम्प यांनी जाहीर पाणउतारा केला आणि त्या देशाच्या पराभवाची शापवाणी उच्चारली. तरीही युद्धग्रस्त झेलेन्स्की बधले नाहीत. अखेर ट्रम्प यांना आपल्या भूमिकेत बदल करावा लागला आणि युरोपीय देशांचे सहाय्य मागण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. ट्रम्प यांचे पूर्वसुरी जो बायडेन यांनी याआधी रशियावर कडक निर्बंध लादले होते. त्याची खिल्ली ट्रम्प उडवत आणि आपण त्यापेक्षा युद्ध थांबवून दाखवू अशी वल्गना करत. त्या मुद्द्यावर रशियाच्या पुतिन यांनी ट्रम्प यांच्या हाती धत्तुरा दिला. तेव्हा आपल्या माजी अध्यक्षाच्या मार्गाने जाण्याची वेळ ट्रम्प यांच्यावर आली. अर्थात त्याच मार्गाने जावे लागेल हे स्पष्ट झाल्यावर ट्रम्प यांनी कच खाल्ली नाही आणि आपल्या भूमिकेस मुरड घालण्यात कमीपणा मानला नाही. ही बाबही तशी कौतुकास्पदच म्हणायची. काहीही असो. पुतिन यांच्यासारख्या दुष्टबुद्धी नेत्याविरोधात असे काही करण्याची गरज होती. ती ट्रम्प यांनी पूर्ण केली. हे झाले अमेरिका आणि ट्रम्प यांच्याविषयीचे भाष्य. आता या निर्बंधांमुळे आपल्यावर होणाऱ्या परिणामांची चर्चा.

यात सर्वाधिक फटका बसेल तो आपल्या 'नायरा' या खासगी कंपनीस. पूर्वी 'एस्सार ऑइल' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या कंपनीत 'रोझनेफ्ट'ची लक्षणीय मालकी आहे. तेव्हा 'रोझनेफ्ट'लाच निर्बंधांचा सामना करावा लागणार असल्याने तिच्या उपकंपनीचे काय होईल हे वेगळे सांगायची गरज नाही. रिलायन्स या आपल्या आणखी एका कंपनीवर या निर्बंधांचा दुष्परिणाम होईल. रशियाचे खनिज तेल स्वस्तात घ्यायचे आणि चढ्या दराने पाश्चात्त्य देशांना विकायचे हा उद्योग या दोन्ही कंपन्यांनी केला. त्यास आता आळा बसेल. या दोन कंपन्यांखेरीज ज्यास या निर्बंधांचा जाच होईल असा तिसरा घटक म्हणजे भारत सरकार आणि अर्थातच भारतीय ग्राहक. आपले सरकार रिलायन्स, नायरा या खासगी कंपन्यांप्रमाणेच रशियाचे खनिज तेल स्वस्तात खरेदी करून भारतीय नागरिकांस चढ्या दराने विकत होते. एकेकाळी बाजारभावापेक्षा २० डॉलर प्रति बॅरल इतकी सूट भारतासाठी रशिया देत होती. ती भारत सरकारने घेतली. पण ग्राहकांस मात्र पेट्रोल-डिझेल स्वस्तात दिले नाही. म्हणजे रशियाच्या सवलतीमुळे भारत सरकारची धन होत गेली. आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भले ''आम्ही कोणाकडूनही तेल खरेदी करू'' अशी वल्गना केली असेल. पण या निर्बंधांनंतर तसे करता येणार नाही. आपण रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही अशी 'कबुली' पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपणास दिल्याची वल्गना आताही अध्यक्ष ट्रम्प करतात. ती खरी नाही वा अतिशयोक्तीपूर्ण आहे असे मानले तरी आपले रशियन तेलावरील अवलंबित्व कमी करावे लागणार हे स्पष्ट आहे. याचाच दुसरा परिणाम म्हणजे खनिज तेलाची दरवाढ. ट्रम्प यांनी निर्बंध जाहीर केल्या केल्या खनिज तेलाचे दर, दराचा आलेख वर जाण्यास सुरुवात झाली. या काळात ही बाजारपेठीय संधी साधण्यासाठी सौदी अरेबियादी तेल निर्यातदार देशांनी तेल उत्पादन कमी केले तर ही दरवाढ अधिक असेल.

थोडक्यात एक नवी डोकेदुखी सुरू होणार. ट्रम्प काय किंवा पुतिन काय. दोघांविषयी बरे बोलावे असे फार कमी. पुतिन यांनी रशियाची बंदिशाळा करून टाकली असून ट्रम्प अमेरिकेस तसे करू पाहतात. फरक आहे तो दोन देशांच्या अर्थव्यवस्थेत. ताज्या निर्बंधांमुळे तरी पुतिन यांस तेल तळतळाट लागला तर ते वाईटातील चांगले म्हणायचे.

लेख

युबराज घिमिरे
'इंडियन एक्स्प्रेस'चे सहयोगदायी संपादक

नेपाळमध्ये निवडणूक होईलही; पण लोकशाही?

'जेन झी'ने नेपाळमधील प्रचलित राजकारणापुढे प्रश्न उभे केले. त्या आंदोलनाच्या तडाख्यातून देश प्रशासकीयदृष्ट्या सावरेल; पण वरिष्ठ नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचा खटला चालला नाही, तर मार्चमधल्या निवडणुकांचा तरी काय उपयोग?

नेपाळमध्ये 'जेन झी प्रोटेस्ट' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या, प्रामुख्याने तरुणांच्या आंदोलनानंतर आता महिना उलटून गेला आहे. या हिमालयीन राष्ट्राच्या हंगामी पंतप्रधानपदी माजी न्यायमूर्ती सुशीला कर्की यांची नेमणूक झाली आणि त्यांनी 'मार्च २०२६ पर्यंत सार्वत्रिक निवडणूक घेऊ' असे जाहीर केल्यावर जणू सारे काही शांत झाले. पण नोकरी- शिक्षण- एकंदर भवितव्य यांसारख्या मुद्द्यांवरून आणि सलग १९ वर्षे आलटून-पालटून सत्तेवर असलेल्या त्याच त्या राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध उफाळलेला असंतोष आता शांत झाल्याचे दिसत असले तरी समस्यांतून समाधानाकडे अशी काही वाटचाल या देशाने केलेली नाही. त्यामुळेच शंकेची पाल चुकचुकते... या शांततेमागे कोणती खदखद दडलेली आहे?

तरुणांचे आंदोलन काठमांडूसह अनेक भागांत पसरल्यावर ९ सप्टेंबर रोजी के. पी. शर्मा ओली यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला, त्यामागचे अत्यंत महत्त्वाचे कारण म्हणजे, हे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा ओली यांचा आदेश मानण्यास नेपाळी लष्कराने दिलेला नकार. नेपाळमध्ये गेल्या दोन दशकांत राजकीय अस्थैर्य नवे नसले तरी निर्नायकी स्थिती पहिल्यांदाच उद्भवली. नेपाळी संसदेच्याही सदस्यांनी राजीनामे दिले. अशा अभूतपूर्व परिस्थितीत नेपाळी सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्ती सुशीला कर्की या सर्वसहमतीच्या उमेदवार म्हणून हंगामी पंतप्रधानपदी आल्या. निवडणुकीची तारीख जाहीर झालेली नसताना संसद बरखास्त करण्याची तरतूद नेपाळी राज्यघटनेत नसूनही तसे करावे लागले आणि इतक्या विपरीत परिस्थितीतही राज्यघटनेचा मान राखला जावा म्हणूनच ५ मार्च ही निवडणुकीची तारीख हंगामी पंतप्रधान कर्की यांना जाहीर करावी लागली.

पण त्यापुढला प्रश्न म्हणजे, खरोखरच येत्या अवघ्या चार महिन्यांहून कमी काळात सार्वत्रिक निवडणूक घेणे कर्की यांच्या हंगामी सरकारला शक्य होईल काय? हा प्रश्न केवळ प्रशासकीय स्वरूपाचा नाही. त्याला नैतिक धारही आहे. जर (माजी) सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचा खटला चालला नाही तर नवीन संसद निवडून काय उपयोग?

'जेन झी'चे अचानक उफाळलेले आंदोलन, सरकारने पोलिसी बळ वापरून ते चिरडण्याच्या केलेल्या प्रयत्नात झालेला ७६ जणांचा मृत्यू आणि या आंदोलकांनी स्वीकारलेला विध्वंसाचा मार्ग हे सारेच सामान्य जनतेत भीतीची भावना फैलावणारे ठरले आहे. त्यामुळे जनसामान्यांची अवस्था 'जे होईल ते पाहायचे' अशी आहे.

पण दुसरीकडे, हंगामी सरकारच्या कायदेशीरतेलाच आव्हान देणाऱ्या डझनभराहून अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. देश अभूतपूर्व संकटात आहे यावर एकमत असूनही, प्रस्थापित राजकीय पक्षांमध्ये पुढे जाण्याच्या मार्गाबद्दल मतभेद आहेत. ओली यांच्या नेतृत्वाखालील 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-युनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी' (यूएमएल) हा एकमेव पक्षवगळता, विसर्जित संसदेची पुनर्स्थापना करण्याची मागणी एकाही राजकीय पक्षाने केलेली नाही. ती मागणी मान्य झाल्यास बदनाम झालेले ओली आणि त्यांचा

संग्रहित छायाचित्र

'यूएमएल' पक्ष यांचीच सद्दी पुन्हा कायम राहू शकते. हे इतर पक्षांना मान्य नाही, पण देशाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सामंजस्य हवे असा या प्रस्थापित पक्षांचा कल दिसतो. सामंजस्य, संवाद हा लोकशाहीचा पाया असतो हे कितीही खरे असले तरी इथे नेपाळमध्ये सामंजस्य कोण आणणार आणि कसे?

अन्य पक्षांपैकी 'नेपाळी काँग्रेस' (एनसी) हा खरे तर, विसर्जित नेपाळी संसदेतला सर्वांत मोठा पक्ष होता. त्या पक्षाविरुद्धचा रोष 'जेन झी' आंदोलनात वारंवार दिसला. 'एनसी'चे अध्यक्ष शेर बहादूर देऊबा आणि त्यांची पत्नी अर्झू राणा देऊबा यांच्या निवासस्थानी घुसलेल्या आंदोलकांनी, या जोडप्याला खेचत बाहेर काढून त्यांचे घर पेटवून दिले होते. स्वतःच्या राजकीय भवितव्यातला अंधार त्याच ज्वाळांतून देऊबांनी पाहिला असावा, म्हणूनच पक्षाच्या कार्याध्यक्षपदी पूर्णबहादूर खडका यांची नियुक्ती जाहीर करून आपण राजकारणात यापुढे फार तर मार्गदर्शकाची भूमिका निभावू, असे त्यांनी सूचित केले. पण आजतागायत देऊबा अथवा त्यांच्या समर्थकांनी, देश म्हणून नेपाळचे राजकीय भवितव्य कसे असावे याविषयी कोणतेही मतप्रदर्शन करणे टाळले आहे.

याच 'नेपाळी काँग्रेस' पक्षाचे दुसरे वरिष्ठ नेते गोपाल मान श्रेष्ठ हे नोव्हेंबर २००५ मध्ये भारत सरकारच्या मध्यस्थीने नेपाळमधील 'राजेशाही राज्यव्यवस्था' विसर्जित करण्याबाबतचा जो १२- कलमी समझोता झाला, त्यावर सह्या करणाऱ्यांपैकी एक. त्यांनी परवाच्या रविवारी (१९ ऑक्टोबर रोजी) भलताच सूर लावला. सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहाता 'राष्ट्रीय सहमती' घडवून आणण्याच्या कामी राजघराण्याची मदत घेणे- पर्यायाने राजेशाहीला पुन्हा काही प्रमाणात महत्त्व देणेसुद्धा - गरजेचे असल्याचे ठाम मत त्यांनी जाहीरपणे मांडले. 'त्यांच्याकडे (राजघराण्याकडे) गेल्या १९ वर्षांच्या काळात पूर्णतः दुर्लक्ष करणे चूकच ठरले, असे प्राप्त परिस्थितीचे सांगणे आहे' अशा शब्दांत त्यांनी राजेशाहीला महत्त्व देण्याची इच्छा सूचित केली. याच करारावर स्वाक्षरी करणारे माधवकुमार नेपाल यांनीही अलीकडेच राजेशाहीची भलामण करताना, 'फेरआढावा घेऊन काही सुधारणा केल्याच पाहिजेत' असे म्हटले होते. पण आश्चर्य म्हणजे, २००५ सालच्या त्या ऐतिहासिक कराराचे एक महत्त्वाचे स्वाक्षरीकार आणि नेपाळमधील माओवादी नेते पुष्पकमल दहल 'प्रचंड' हेसुद्धा गुळमुळीत बोलू लागले आहेत. नेपाळच्या राजकीय भवितव्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष व चळवळींचा सहभाग आवश्यक असल्याचे उघड असताना, 'सर्व संबंधितांचा सहभाग' अशी मोघम भाषा त्यांनी वापरली.

नेपाळमधील राजकीय पेचप्रसंग हा अंतर्गत प्रश्न असला तरी त्याच्या आंतरराष्ट्रीय बाजू लपून राहिलेल्या नाहीत. चीनने आता म्हटले आहे की, 'जेन झी' आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी ज्या काही हिंसक कारवाया झाल्या त्या तिबेटी स्वातंत्र्यवादी कार्यकर्त्यांनी केलेल्या आहेत. हा आक्षेप चीनचे नेपाळमधील राजदूत चेन सॉन्ग यांनी गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान कर्की यांची भेट घेऊन नोंदवला आहे. म्हणजेच आता तिबेटींवर कारवाई करण्याचा दबाव चीनकडून वाढणार. हेच, चीनच्या सिचुआन विद्यापीठातील दक्षिण आशिया अभ्यास संस्थेचे उपप्रमुख डॉ. गाओ लिअँग यांनी 'नेपाली खबर' या दैनिकात लगोलग लिहिलेल्या लेखातूनही स्पष्ट झाले. चीन आणि नेपाळ यांच्या 'संबंधांची वीण सखोल आहे' याची आठवण करून देणाऱ्या आणि एकंदर नेपाळचे भले व्हावे असा सूर लावणाऱ्या डॉ. लिअँग यांच्या त्या लेखात कथित तिबेटी कार्यकर्त्यांनी हिंसक प्रकार केल्याचा थेट उल्लेख नसला तरी 'आंदोलनाच्या दरम्यान काही प्रकार असे घडलेले आहेत की, ज्यामुळे चीनदेखील अस्वस्थ होणे साहजिक आहे' - असे त्यांनी म्हटले आहे.

अमेरिका, भारत आणि काही युरोपीय देशांनी कर्की यांना वेळेवर निवडणुका घेण्यासाठी पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु नेपाळमधील राजकीय पक्षांकडून मिळणाऱ्या सहकार्यावर बरेच काही अवलंबून राहील, हे निश्चित. पंतप्रधान कर्की यांनी मंगळवारी (२१ ऑक्टोबर रोजी) सर्व राजकीय पक्षांची बैठक आयोजित केली होती. त्यांच्या कारकीर्दीच्या सहा आठवड्यांत पहिल्यांदाच अशी बैठक झाली असली, तरी तिला अजिबात प्रसिद्धी देण्यात आली नाही. अर्थातच, राजकीय पक्षांकडून त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी सुरू करू नये असा दबाव आणण्याचा प्रयत्न या बैठकीत झाला असणार हे उघड आहे. परंतु जर कर्की यांनी या दबावापुढे मान तुकवली, तर तो 'जेन झी आंदोलना'चा विश्वासघातच ठरेल.

एक बरे की, कर्की यांना पंतप्रधानपदी बसवण्यासाठी राष्ट्रपती, 'जेन झी' आंदोलक आणि राजकीय पक्षांमध्ये निर्णायक मध्यस्थीची भूमिका बजावणाऱ्या नेपाळी लष्कराने हंगामी सरकारला पूर्ण पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. दशकभरापासून बंडखोरी आणि अपुरीच राहणारी शांतता प्रक्रिया पाहिलेल्या या देशात, राजकीय पक्षांना खरोखरच प्रभावी सलोखा धोरण आखायचे असेल तर आता तरी भ्रष्ट नेत्यांना वाचवण्याच्या फंदात त्यांनी पडू नये. निव्वळ प्रशासकीय बाब म्हणून निवडणूक पार पाडण्यातून, 'जेन झी' आंदोलनाने नेपाळच्या राजकारणापुढे उभे केलेले नैतिक प्रश्न सुटणार नाहीत.

अन्वयार्थ

बुद्धिबळाच्या ऑनलाइन पटावरील बळी!

डॅनियल नारोडित्स्की या युवा बुद्धिबळपटूच्या धक्कादायक मृत्यूने सध्या बुद्धिबळ विश्व हादरले आहे. हा मृत्यू नैसर्गिक नव्हता किंवा नसावा हे त्यामागील एक कारण. डॅनियल नारोडित्स्की अवघ्या २९ वर्षांचा होता. त्याचा १९ ऑक्टोबर रोजी आकस्मिक मृत्यू झाल्याचे दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २० ऑक्टोबर रोजी शार्लोट बुद्धिबळ क्लबने डॅनियलच्या कुटुंबाचा हवाला देऊन जाहीर केले. यानंतर काही तासांतच, डॅनियलच्या अपमृत्यूस माजी जगज्जेता व्लादिमिर क्रॅमनिक जबाबदार असल्याचा आरोप अनेक बुद्धिबळपटू तसेच विश्लेषकांनी केला. त्यामुळे या घटनेचे गांभीर्य वाढते. मृत्यूचे नेमके कारण जाहीर झालेले नाही. डॅनियलने आत्महत्या केली असावी, किंवा नैराश्येपोटी अमली पदार्थांचे अतिसेवन केले असावे याविषयी सध्या केवळ तर्क व्यक्त केले जात आहेत. व्लादिमिर क्रॅमनिकने डॅनियलवर, तो ऑनलाइन बुद्धिबळ खेळताना गैरप्रकारांचा अवलंब करून विजय सातत्य दाखवतो असा गंभीर आरोप गतवर्षी केला होता. त्यामुळे डॅनियल कमालीचा हताश झाला होता ही बाब सर्वश्रुत होती. क्रॅमनिकने अशा प्रकारचे आरोप अन्य काही आघाडीच्या बुद्धिबळपटूंवरही केले आहेत. मात्र

आजतागायत त्याबाबत ठोस पुरावे सादर केलेले नाहीत. त्याच्यासारख्या प्रतिभावान माजी जगज्जेत्याने असे आरोप केल्याचा परिणाम दूरगामी होतो, असे भारताचा आघाडीचा ग्रँडमास्टर निहाल सरीनने डॅनियलच्या मृत्यूनंतर लगेचच बोलून दाखवले. डॅनियल त्याच्या मृत्यूच्या आदल्या दिवशी निहालशी दिवसभर ऑनलाइन खेळत होता. आपल्याला काही सांगायचे आहे, असेही त्याने सूचित केले होते. क्रॅमनिकच्या बेछूट आरोपांनी एकाचा (डॅनियल) बळी घेतला असे वक्तव्य निहालने भारतीय माध्यमांकडे केल्यावर त्याची दखल जगभर घेतली गेली. कारण निहाल मितभाषी, विचारी बुद्धिबळपटू म्हणून ओळखला जातो.

बुद्धिबळ या खेळात आणि त्यातही ऑनलाइन प्रारूपामध्ये लबाडीचे प्रकार व्हायचे नि होत असतात. पण अलीकडच्या काळात विशेषतः जलद आणि अतिजलद प्रकाराकडे युवा वर्ग मोठ्या प्रमाणात आकर्षित झाला. कोविड काळात प्रत्यक्ष पटावर खेळण्याच्या स्पर्धांची संख्या कमी झाली, त्यावेळी दूरस्थ अर्थात ऑनलाइन पद्धतीने बुद्धिबळ खेळले जाऊ लागले. ऑनलाइन प्रकारात जिंकण्यासाठी भलेबुरे मार्गही अवलंबले जाऊ लागले. प्रतिस्पर्ध्यास दिसणार नाही अशा प्रकारे संगणक वा इतर उपकरणे दडवून, ती शक्तिशाली सॉफ्टवेअर किंवा इंजिनशी संलग्न करून अत्यंत कठीण आणि अव्वल बुद्धिबळपटूंनाही सहजपणे सुचणार नाही अशा प्रकारे चाली खेळून जिंकणाऱ्या हौश्या-नवख्यांची संख्या वाढू लागली. तेव्हा प्रस्थापित बुद्धिबळपटूंपैकी अनेक या प्रकाराकडे संशयाने पाहू लागले. पण या प्रस्थापितांपैकीच काही आणि इतरही उच्च प्रतिभेचे बुद्धिबळ ग्रँडमास्टर ऑनलाइन प्रकाराकडे वळले आणि विलक्षण यशस्वी ठरले.

डॅनियल नारोडित्स्की अशांपैकी एक. त्याचा जन्म अमेरिकेत कॅलिफोर्नियातला. वडील युक्रेनियन स्थलांतरित. सहाव्या वर्षी डॅनियलला त्याच्या भावाने बुद्धिबळाची गोडी लावली. या खेळात अल्पावधीतच त्याने नैपुण्य मिळवले. शालेय स्तरावर अनेक स्पर्धा जिंकून डॅनियल अमेरिकेत विविध लहान वयोगटांमध्ये अजिंक्य ठरू लागला. त्याने १२ वर्षांखालील जागतिक बुद्धिबळ स्पर्धाही जिंकली. वयाच्या अवघ्या १४व्या वर्षी त्याने बुद्धिबळावर पुस्तक लिहून प्रकाशित केले. तो १७व्या वर्षी ग्रँडमास्टर बनला, स्टॅनफर्ड विद्यापीठातून इतिहासात पदवीही प्राप्त केली. पण बुद्धिबळावरील प्रेमामुळे त्याने या खेळालाच उत्पन्नस्रोत बनवले. एक उत्कृष्ट खेळाडू, प्रशिक्षक, समालोचक, समाज माध्यम प्रभावक आणि सादरकर्ता अशा बहुपैलू डॅनियल नारोडित्सिकीची लोकप्रियता असीम होती. पण क्रॅमनिकने केलेल्या आरोपांमुळे तो सैरभैर झाला.

साक्षात गॅरी कास्पारोवला हरवून या शतकाच्या सुरुवातीस जगज्जेता बनलेल्या क्रॅमनिकची बुद्धिबळ प्रतिभा वादातीत आहे. या खेळातील निष्णात जाणकार म्हणून तो आजही ओळखला जातो. तरीदेखील नारोडित्स्की आणि इतर काही खेळाडूंवरील त्याने केलेले आरोप जसे गंभीर आहेत, तितकेच या आरोपांसाठी पुरावे सादर न करण्याचे त्याचे वर्तनही अक्षम्य ठरते. जगातील सध्याचा अव्वल बुद्धिबळपटू मॅग्नस कार्लसन यानेही मध्यंतरी हान्स नीमन या आणखी एका अमेरिकी खेळाडूवर तो लबाडी करत असल्याचे आरोप केले होते. त्यालाही पुरावे सादर करता आले नाहीत. जागतिक बुद्धिबळ महासंघाने (फिडे) आता क्रॅमनिकच्या आरोपांची शहानिशा करायचा निर्णय घेतला आहे. पण यासाठी एखाद्या बुद्धिबळपटूचा जीव जायची वाट पाहण्याची गरज नव्हती. डॅनियल नारोडित्स्कीचा आकस्मिक मृत्यू हा एरव्ही बौद्धिक समजल्या जाणाऱ्या या खेळासाठी विलक्षण धक्का आहे. असे आणखी धक्के बसू द्यायचे नसतील, तर साऱ्यांनी जबाबदारीने वागण्याची नितांत गरज आहे.

विश्लेषण

हृषीकेश देशपांडे
hrishikesh. deshpande
@expressindia. com

बिहारमध्ये जागावाटप वादांनंतरही रालोआ- महागठबंधन चुरस राहील?

बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत जागावाटपातील वाद भाजपप्रणीत 'रालोआ'ने मिटवले; पण 'महागठबंधन'ने वाद असूनही, मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित करून पाऊल पुढे टाकले...

'मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार'चे महत्त्व

बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी महागठबंधन किंवा महाआघाडीला जागावाटप जाहीर करण्यात अपयश आले. मात्र महाआघाडीने राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते व विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करून पाऊल पुढे टाकले. यामुळे आता भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीवरही त्यांचे नाव घोषित करण्यासाठी दबाव येईल. ही आघाडी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्याच नेतृत्वात सामोरी जात आहे; पण नितीशकुमारांच्या नावाची औपचारिक घोषणा झालेली नाही. परंतु प्रचार 'तेजस्वी बिहार' आणि 'सुशासनबाबू' यांच्याभोवती फिरेल.

जागावाटप वादाचा फटका किती?

बिहारमध्ये गेल्या वेळी दोन्ही आघाड्यांना प्रत्येकी ३७ टक्के मते मिळाली होती. यातून चुरस लक्षात येईल. त्या तुलनेत सत्तारूढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत निदान सर्व २४३ जागांचे वाटप तरी जाहीर झाले. उपेंद्र कुशवाह व जितनराम मांझी यांनी जागावाटपावर नाराजी व्यक्त केली असली तरी, ती दूर करण्यात भाजपश्रेष्ठींना यश आले. याउलट महाआघाडीत जवळपास १० ते १२ जागांवर हे पक्ष एकमेकांविरोधात लढत आहेत. पाटण्यापासून ते दिल्लीपर्यंत जागावाटपाच्या बैठका होऊनही मार्ग निघू शकला नाही. या आघाडीत राजद, काँग्रेस, डावे पक्ष यांमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप) तसेच भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष-एमएल हे आहेत. याखेरीज मुकेश साहनी यांचा विकासशील इन्सान पक्ष (व्हीआयपी) हा प्रादेशिक पक्ष आहे. प्रचारात याचा काही प्रमाणात फटका बसू शकतो.

'महागठबंधन'मध्ये वाद कसे वाढले?

'महागठबंधन' या महाआघाडीत लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल हा केंद्रस्थानी आहे. गेल्या म्हणजे २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत राजदने १४४ जागा लढल्या होत्या. यंदा १४३ ठिकाणी त्यांनी उमेदवार जाहीर केले. थोडक्यात मित्रपक्षांना शंभर जागा सोडल्या. त्यात काँग्रेसचे ६० उमेदवार आहेत. तर तीन डाव्या पक्षांनी तीसवर उमेदवार दिले आहेत. भाकप-मालेचे १२ आमदार होते. गेल्या निवडणुकीत १९ पैकी १२ जागा जिंकल्याने त्यांना यंदा अधिक जागा मित्रपक्षांनी सोडाव्यात अशी अपेक्षा होती. तीनही डाव्या पक्षांनी जवळपास ७५ जागांची मागणी केली होती; तितक्या देणे शक्य नव्हते. काँग्रेसने गेल्या वेळी ७० जागा लढवूनही अवघ्या १९ ठिकाणी यश मिळवले. राजकीय स्थिती पाहून काँग्रेसने अधिक जागांचा आग्रह धरू नये असे घटक पक्षांचे म्हणणे होते. यातूनच अनेक ठिकाणी एकमेकांविरोधात उमेदवार देण्यात आले. मुकेश साहनी यांच्या व्हीआयपी पक्षाने ११ उमेदवार जाहीर केले. बिहारमध्ये आघाडीच्या राजकारणात मित्रांशीच सामना करण्याची वेळ महाआघाडीत आली.

जातीय समीकरणांनुसार उपमुख्यमंत्री?

लोकसभा असो वा विधानसभा, अध्यक्षीय पद्धतीने नेता निवडणुकीपूर्वीच जाहीर करण्याची पद्धत रूढ होत आहे. बिहारमध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) विरोधात 'महागठबंधन' या महाआघाडीचे नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दलाकडे (राजद) यांच्यात अटीतटी दिसते. आता प्रचारातही तेजस्वी विरुद्ध नितीशकुमार हेच केंद्रस्थानी राहतील. तेजस्वी हे उपमुख्यमंत्री होते, तर नितीशकुमार गेली दोन दशके मुख्यमंत्री आहेत. सुशासनबाबू अशी त्यांची ओळख. मात्र अलीकडे त्यांच्या प्रकृतीबाबत बरीच चर्चा होते.

निवडणुकीत जातीय समीकरणेही विचारात घ्यावी लागतील. राज्यात सर्वात मोठा १४ टक्के जात समूह हा यादव आहे. याखेरीज १७ टक्के मुस्लीम हा महाआघाडीचा आधार मानला जातो.

त्यातच आता विकासशील इन्सान पक्षाचे मुकेश साहनी हे सत्ता आल्यास उपमुख्यमंत्री असतील अशी घोषणा करण्यात आली. ते मल्लाह समुदायातून येतात. साहनी स्वतःला मल्लाह पुत्र मानतात. हा समाज २.६ टक्के आहे. तसेच यांच्या जवळचे निषाद हे ७ ते ८ टक्के आहेत. या समुदायांतील सर्वच मते मिळणार नाहीत हे खरे आहे. तरी या ३८ टक्के मतांवर महाआघाडीने लक्ष केंद्रित केले आहे.

आणखी एक काँग्रेसचा उपमुख्यमंत्री असेल. एकूणच जातीय समीकरणे महत्त्वाची ठरतील. बिहारमधील अतिमागास वर्ग ही नितीशकुमार यांची मतपेढी मानली जाते. याखेरीज यादवेतर इतर मागासवर्गीय व खुल्या गटातील १५ टक्के मतदार हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला अनुकूल असल्याचे विश्लेषक मानतात. येथेही या समुदायातील सर्वच मते मिळणार नाहीत. सध्या नितीशकुमार मुख्यमंत्री असताना भाजपने दोन उपमुख्यमंत्री देऊन जातीय समीकरण साधण्याचा प्रयत्न केला आहेच.

डिजिटल पारदर्शिता

डीप फेक वीडियो और एआई से तैयार नकली कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों में संशोधन का जो मसौदा प्रस्तुत किया है, वह इसकी अनिवार्यता को तो रेखांकित करता ही है, अतिरिक्त सावधानी की भी मांग करता है। सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, यह बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगी हैं कि डीप फेक वीडियो के जरिये किसी नामचीन हस्ती के चरित्र-हनन की कोशिश की गई या एआई की मदद से किसी की आवाज की नकल करके आर्थिक मुनाफा कमा लिया गया। हाल ही में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और अभिनेता अभिषेक बच्चन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में गूगल और यू-ट्यूब के खिलाफ चार करोड़ रुपये के हर्जाने का मुकदमा दायर किया है। इस दंपति को खुद से जुड़े काल्पनिक एआई कंटेंट वाले वीडियो यू-ट्यूब और गूगल पर प्रसारित किए जाने के खिलाफ अदालत से संरक्षण की मांग करनी पड़ी। निस्संदेह, सोशल मीडिया पर जिस तरह की गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों की भरमार देखने को मिलती है, वह बाहरा अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे का सीधा-सीधा अतिक्रमण दिखती है। इसलिए इसका नियमन वक्त की मांग है।

मगर यह बेहद संजीदा मामला है। सोशल मीडिया मंचों के नकारात्मक उदाहरणों का हवाला देकर हम इसके अच्छे पहलुओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये मंच स्वतंत्र अभिव्यक्ति के सबसे सशक्त माध्यम बनकर उभरे हैं। इन मंचों की मदद से आम लोग न सिर्फ अपनी बात शासन-प्रशासन तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं, बल्कि कई बार इनके दबाव में अपराधियों को दबोचने में भी प्रशासन को मदद मिली है। एक निर्विवाद तथ्य यह भी है कि लाखों लोग इनकी मदद से अपनी रचनाशीलता को नई धार दे रहे हैं और ये उनकी आमदनी का जरिया बन रहे हैं। इसलिए सरकार ने इस बार काफी सतर्कता बरतते हुए प्रावधान प्रस्तावित किए हैं। गौरतलब है कि उसके सूचना-प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2023 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इस नियम के तहत सरकार फर्जी व भ्रामक सूचनाओं की पहचान के लिए एक 'फैक्ट चेक यूनिट' गठित करना चाहती थी। जाहिर है, इसे सरकार विरोधी लोगों की आवाज दबाने वाले तंत्र के रूप में देखा गया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 19 (भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 19 (1)जी (व्यवसाय की स्वतंत्रता व अधिकार) के विरुद्ध पाया था।

डिजिटल अराजकता को नियंत्रित करने और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों को कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराने की पहल बहुत आवश्यक है।

मौजूदा प्रस्तावों में सरकार ने काफी सावधानी बरतते हुए पचास लाख से अधिक उपयोगकर्ता वाले सोशल मीडिया मंचों से यह अपेक्षा की है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अपलोड सामग्री कृत्रिम तो नहीं है। ऐसी किसी भी सामग्री को उन्हें प्रमुखता से चिह्नित करना होगा। वाकई यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे डिजिटल दुनिया की अराजकता को नियंत्रित करना आसान होगा, बल्कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों को कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराने में भी आसानी होगी। सरकार ने गलत कंटेंट हटाने वाले डिजिटल मंचों को वैधानिक संरक्षण देने की बात भी कही है और 6 नवंबर तक इन मसौदों पर लोगों की राय मांगी है, तो यह अवसर है उन लोगों के लिए, जिन्हें इन नियमों को लेकर कोई अंदेशा है। उन्हें अपने अंदेशे और आपत्तियां अवश्य दर्ज करानी चाहिए, ताकि पारदर्शी व प्रभावी नियम वजूद में आ सकें।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 24 अक्तूबर, 1950

संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुए पांच वर्ष पूरे हो गये और वह आज के दिन अपने जीवन के छठे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का दिवस आज सारे संसार में मनाया जायेगा। इस अवसर पर दुनिया के बड़े-बड़े सत्ताधारी और जन-नेता संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करेंगे।

आज दुनिया के करोड़ों व्यक्तियों की आशाएं संयुक्त राष्ट्र संघ पर केन्द्रित हैं। कइयों को संयुक्त राष्ट्र संघ से निराशा भी हुई है, किन्तु आज दुनिया में कोई यह कामना नहीं कर सकता कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वह भविष्य हो, जो पुराने राष्ट्र संघ का हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य विश्व में शांति कायम रखना है और संसार के करोड़ों व्यक्तियों को शांति से अधिक प्रिय वस्तु दूसरी नहीं हो सकती। लोग युद्ध की विभीषिका का मजा चख चुके हैं और आधुनिक विज्ञान ने युद्ध को इतना भयंकर बना दिया है कि उनमें से अधिकांश उसकी ज्वाला से दूर रहना चाहते हैं।... जो लोग युद्ध की अग्नि भड़काने की चेष्टा में हैं, वे भी शांति की ही दुहाई देते हैं। वे युद्ध करने की शक्ति का संचय इसलिए करना चाहते हैं कि विश्व शांति की रक्षा कर सकें। यह तो कोई नहीं कह सकता कि इस प्रकार शांति को सुरक्षित रखा जा सकेगा, किन्तु शांति की इच्छा विश्व-व्यापी है और संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा मनुष्य जाति के पास आज दूसरा साधन नहीं है, जो उसकी इस इच्छा को पूरा कर सके।

संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है, जिस पर आज विरोधी विचार रखने वाले राष्ट्र एकत्र होकर अपने मतभेदों... को निपटाने की चेष्टा करते हैं। मतभेदों को निपटाने का दूसरा तरीका युद्ध है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने निषिद्ध ठहराया है। युद्ध मतभेदों को निपटाने का एक बर्बर तरीका है और मनुष्य जाति जब सभ्यता की दिशा में इतनी प्रगति कर चुकी है, इस बर्बर तरीके का उसे परित्याग करना ही चाहिए। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्रों के मतभेदों को मिटाने में कुछ सफलता हासिल कर रहा है? जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उस समय कम से कम दुनिया के बड़े राष्ट्रों में बहुत कुछ मतैक्य था।... किन्तु जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, बड़े राष्ट्रों के बीच अनेक मतभेद उत्पन्न हो गये हैं और उनकी खाई बराबर चौड़ी होती जा रही है।

बिहार में अब आमने-सामने की बिसात

विनोद बंधु | स्थानीय संपादक, हिन्दुस्तान, पटना

यहां स्कैन करें

पहली बार महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। इसके साथ यह भी तय हो गया है कि बिहार का चुनाव चाचा बनाम भतीजा होगा।

गुरुवार को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने के साथ बिहार में महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच चल रही नूरा-कुश्ती खत्म हो गई। सातों सहयोगी दलों के नेताओं ने मंच से बढ़-चढ़कर एकजुटता का एलान किया। इससे पहले सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस, राजद और वीआईपी में खींचतान की वजह से बनी संवादहीनता से यह लगने लगा था कि महागठबंधन बिखर गया है। 13 सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारने से इन दलों के साथ-साथ चुनाव लड़ने की उम्मीदें भी खत्म होने लगी थीं। मगर बीते चार-पांच दिनों में 'डैमेज कंट्रोल' की कोशिशों ने रंग दिखाया और अंततः बात बन गई।

पहली बार महागठबंधन ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। इसके साथ यह भी तय हो गया है कि बिहार का चुनाव चाचा बनाम भतीजा होगा। इनमें कौन बीस साबित होगा, इसका जवाब बिहार की जनता देगी। वैसे महागठबंधन ने तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित करने के साथ ही एक दांव भी खेल दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने एनडीए से पूछा कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? साथ ही, उन्होंने दावा भी किया कि महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की तरह भाजपा बिहार में भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। जाहिर है, गठबंधन पूरे चुनाव में यह संदेश देना चाहेगा कि बहुमत मिलने पर भाजपा अपने दल के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी और नीतीश कुमार किनारे कर दिए जाएंगे।

बिहार में अति-पिछड़े व महिला समाज पर नीतीश कुमार की पकड़ मजबूत रही है। उनके गठबंधन को अब तक जीत दिलाने में इन दोनों समूहों का बड़ा योगदान रहा है। महागठबंधन इस बार इन्हीं दो समूहों, खासकर महिला मतदाताओं को साधने के हरसंभव दांव चल रहा है। तेजस्वी यादव ने बुधवार को राजद और गुरुवार को महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े वायदे किए। उन्होंने दो नई योजना लाने, मसलन 'मां' (एमएए- मकान, अन्न और आमदनी) और 'बेटी' (बीईटीआई- बेनिफिट, एजुकेशन, ट्रेनिंग और इनकम) की घोषणा की। इनके अलावा जीविका समूहों के 80 हजार से अधिक समन्वयकों की सेवा नियमित कर उन्हें प्रतिमाह 30 हजार रुपये वेतन और 1.44 करोड़ जीविका दीदियों को पांच साल में डेढ़-डेढ़ लाख रुपये देने का वायदा किया। इससे पहले वह हर ऐसे परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का एलान कर चुके हैं, जिनका कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है। बिहार में ढाई करोड़ से अधिक परिवार हैं और सरकारी नौकरियां करीब 25 लाख हैं। वरिष्ठ एनडीए नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए पूछा है कि तेजस्वी ने जो घोषणाएं की हैं, उनको पूरा करने के लिए करीब 12 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी, इतने पैसे वह कहां से लाएंगे? बिहार का इस साल का बजट 3.17 लाख करोड़ का है।

चाचा-भतीजे की इस जंग में संशय या भ्रम फिर से बड़ा चुनावी शस्त्र साबित होने वाला है। साल 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान घोषित करके भ्रम फैलाया था और उसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा। इस बार के चुनाव में दो पहलू हैं- बिखराव और मुख्यमंत्री का चेहरा। अब यह देखने की बात होगी कि महागठबंधन कैसे भरोसा दिला पाता है कि उसके सहयोगी दलों की एकजुटता के प्रदर्शन के पीछे कोई विवशता नहीं है और एनडीए कैसे यह यकीन दिला पाता है कि महाराष्ट्र की कहानी बिहार में नहीं दोहराई जाएगी।

बिहार में सामाजिक समीकरण चुनाव में कामयाबी की कुंजी रहे हैं। नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग से ही अपने लिए उर्वरा जमीन तैयार की। नब्बे के दशक में लालू प्रसाद को पिछड़ा, अति-पिछड़ा और दलित व मुस्लिमों का समर्थन हासिल था। लेकिन नई सदी के चुनाव नतीजों से जाहिर है कि यह माई समीकरण तक सिमटता गया। एनडीए ने माई के खिलाफ ध्रुवीकरण की रणनीति बनाई और 2005, 2010 और 2020 में विधानसभा के तीन चुनाव जीते। साल 2015 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद महागठबंधन में साथ थे, तो ध्रुवीकरण दोनों के साझा सामाजिक समीकरण का हुआ और एनडीए के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। इस बार चिराग पासवान की लोजपा (रा) पहली बार नीतीश कुमार के साथ विधानसभा चुनाव लड़ रही है। मगर मुकेश सहनी की वीआईपी पिछली बार महागठबंधन से बगावत करके एनडीए में चली गई थी। इस बार वीआईपी न केवल महागठबंधन में है, बल्कि मुकेश सहनी को उप-मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर अति-पिछड़ों, खासकर मल्लाह जाति को बड़ा संदेश दिया गया है।

बिहार में एनडीए के पक्ष में होते रहे ध्रुवीकरण की गंभीरता से तेजस्वी और महागठबंधन के नेता वाकिफ हैं और जनाधार को विस्तार देने की कोशिशें भी खूब हुई हैं। साल 2020 के चुनाव में तेजस्वी ने 'माई' के साथ 'बाप' (बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और गरीब) समीकरण का नारा दिया था। उस चुनाव में महागठबंधन ने तेजस्वी के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया था। वह बहुमत से महज 13 सीट दूर रह गए थे। एनडीए और महागठबंधन के बीच महज 16,825 मतों का अंतर रहा था। उस चुनाव में चिराग पासवान की लोजपा अलग लड़ी थी और उसे 23 लाख से अधिक वोट मिले थे। ये एनडीए समर्थक वोट ही थे।

वैसे तेजस्वी अपने सामाजिक समीकरण को विस्तार देने की रणनीति पर काम करते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए के सामाजिक समीकरण के सशक्त आधार लव-कुश (कुर्मी-कोइरी) वोटों में सेंध लगाने की उनकी पहल कमोबेश दक्षिण बिहार में कामयाब रही। एनडीए को लोकसभा चुनाव में सात सीटों का नुकसान हुआ। हालांकि, उत्तर और मध्य बिहार में इसका खास असर नहीं रहा।

इस बार तेजस्वी यादव ने उत्तर बिहार में भी नए समूह जोड़ने की कोशिश की है। टिकटों के बंटवारे में इसे देखा जा सकता है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार उन्होंने यादव प्रत्याशियों की संख्या में सात की कटौती की है। महागठबंधन ने यादव समेत पिछड़ों को 27 फीसदी और अति-पिछड़ों को 59 प्रतिशत टिकट दिए हैं, तो एनडीए ने 44 फीसदी इस तबके के प्रत्याशी उतारे हैं। एनडीए ने 35 फीसदी, तो महागठबंधन ने 17 फीसदी सवर्ण उम्मीदवारों पर भरोसा किया है। फिर भी महागठबंधन को महिला और अति-पिछड़ा मतदाताओं को अपने पाले में करने की चुनौती से जूझना होगा। बहरहाल, बिहार पहली बार सीधे चाचा-भतीजे के रोचक चुनावी शास्त्रार्थ का गवाह बनेगा।

विलासिता में डूबा लोकपाल कैसे रोकेगा भ्रष्टाचार

सुधांशु रंजन | वरिष्ठ टीवी पत्रकार

यहां स्कैन करें

शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की एक प्रभावी एजेंसी है ऑम्बुड्समैन। इसकी स्थापना 1809 में स्वीडन में हुई और अभी 90 से ज्यादा देशों में यह है। भारत में अनेक भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां थीं, पर ऑम्बुड्समैन नहीं था। भारत में इसे लोकपाल कहते हैं, जो नाम लक्ष्मी मल्ल सिंघवी का दिया हुआ है।

यहां 16 जनवरी, 2014 को लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम लागू हुआ। इसकी स्थापना के लिए 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' के बैनर तले एक आंदोलन चला, जिसके समर्थन में अन्ना हजारे 5 अप्रैल, 2011 को आमरण अनशन पर बैठ गए। इसके रणनीतिकार थे अरविंद केजरीवाल। उनकी टीम ने ऐसा सम्मोहक स्वप्न जाल बुना कि लगा, जैसे लोकपाल नियुक्त होने भर की देर है और भ्रष्टाचार छूमंतर। आंदोलन की लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए एक राजनीतिक दल का गठन किया गया, और इसके कर्ता-धर्ता चुनावी राजनीति में कूद पड़े। सफलता भी उन्हें भरपूर मिली, क्योंकि जनता को चांद दिखाया गया था।

जो भी हो, लोकपाल कानून बन गया, किंतु लोकपाल की नियुक्ति पांच सालों तक नहीं हुई। आज भी अनेक राज्यों में लोकायुक्त नहीं हैं। नियुक्ति हुई भी तो क्या हुआ? लोकपाल की चर्चा किसी बड़े घपले-घोटाले को उजागर करने या कार्रवाई के लिए नहीं हुई है। इसकी चर्चा अभी अचानक एक अन्य कारण से हुई, जो निराश करता है। दरअसल, सात-सदस्यीय लोकपाल ने सात बीएमडब्ल्यू कार खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है। ऐसा शायद इसलिए किया गया है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी ऐसी ही कार मिली हुई है, जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश को मर्सिडीज कार दी गई है।

बीएमडब्ल्यू कारों की खरीद से इतना बड़ा विवाद नहीं बनता, यदि लोकपाल को भ्रष्टाचार का रामबाण नहीं बताया गया होता।

अब्राहम मैस्लो ने मनुष्य की पांच जरूरतों का एक पिरामिड बनाया है। इसमें सबसे नीचे है शारीरिक जरूरत- भोजन, वस्त्र, आवास आदि। इसके ऊपर है सुरक्षा की जरूरत- व्यक्तिगत, आर्थिक व रोगों से सुरक्षा। तीसरे स्थान पर है, प्यार व अपनेपन की जरूरत। इसके ऊपर है सम्मान और सबसे ऊपर आत्मसिद्धि। अधिक आमदनी व सुविधाएं बेहतर प्रदर्शन की गारंटी नहीं होती हैं। बेहतर प्रदर्शन उच्च स्तर की जरूरतों को पूरा करने से आता है, जो है- सम्मान एवं आत्मसिद्धि।

यह सिद्धांत सब पर लागू होता है। इसलिए, सरकारी सेवाओं के वेतनमानों में जबर्दस्त बढ़ोतरी होने के बावजूद कार्य का स्तर उतना बेहतर नहीं हुआ है। न्यायाधीशों पर यह बात और भी लागू होती है। निचली अदालत में न्यायाधीशों की तनख्वाह बहुत कम हुआ करती थी और सुविधाएं तो नगण्य थीं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तक को कार नहीं दी जाती थी। 1999 में शेट्टी आयोग ने उनके वेतन एवं सुविधाएं बढ़ाने की सिफारिश की, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार किया और सरकार को निर्देश देकर लागू करवा दिया, पर यह कहना मुश्किल है कि कार्य-कुशलता बढ़ी है। भारत में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को अच्छी तनख्वाह के अलावा बड़ी-बड़ी कोठियां, लग्जरी कार, निजी स्टाफ सहित अनेक सुविधाएं मिलती हैं। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में शीर्ष अदालत के जजों को कार तो दी जाती है, किंतु सरकारी बंगले नहीं दिए जाते। इंग्लैंड में तो मास्टर ऑफ रोल्स, जो लॉर्ड चीफ जस्टिस के बाद दूसरे सबसे बड़े न्यायिक अधिकारी होते हैं, पहले साइकिल से अदालत जाते थे। हालांकि, इन सबका मतलब यह नहीं कि जजों को पर्याप्त वेतन एवं अन्य सुविधाएं नहीं मिलें।

लोकपाल के सदस्य तकनीकी रूप से न्यायाधीश नहीं हैं। सात सदस्यों में चार पूर्व न्यायाधीश और तीन पूर्व नौकरशाह हैं। इस तरह यह एक पार्किंग स्थल बन गया है। लोकपाल ने करीब 90 प्रतिशत शिकायतों को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि वे सही फॉर्मेट में नहीं थे। इसने अब तक मात्र 24 मामलों में जांच के आदेश दिए हैं और छह में अभियोजन की अनुमति दी है। बीएमडब्ल्यू कारों की खरीद से इतना बड़ा विवाद नहीं बनता, यदि लोकपाल को भ्रष्टाचार के रामबाण के रूप में प्रचारित नहीं किया जाता। मगर सवाल यह भी है कि अगर सादगी का सिद्धांत लोकपाल पर लागू होता है, तो कोई विवाद तब क्यों नहीं हुआ, जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को यही कार दी गई। सवाल तो तब भी उठना चाहिए था।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

शरीर को मंदिर बनाइए

आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि हर चीज बस एक ही ऊर्जा है, जो बस दो विभिन्न तरह से अभिव्यक्त कर रही है। तो जिसे आप ईश्वर कहते हैं या जिसे आदमी या औरत कहते हैं; या एक राक्षस कहते हैं, वे सभी अलग-अलग तरीके से काम करती हुई एक ही ऊर्जा है।

उदाहरण के लिए, वही बिजली इस्तेमाल की गई तकनीक के आधार पर रोशनी या आवाज या कुछ और बन जाती है। अगर आपके पास जरूरी तकनीक है, तो आप अपने आस-पास के साधारण से स्थान को चैतन्यता से सराबोर कर सकते हैं। आप पत्थर के एक टुकड़े को लेकर उसे देवी या देवता बना सकते हैं। इस प्रक्रिया को प्रतिष्ठा कहते हैं।

खासकर भारतीय संस्कृति में जीवन के इस आयाम के बारे में ज्ञान के एक विशाल भंडार को बरकरार रखा गया था। यहीं पर इस चीज को पहचाना गया कि हर इंसान कभी न कभी सृष्टि के स्रोत के संपर्क में आना चाहेगा। अगर इस धरती पर हर जगह ऐसी संभावना पैदा नहीं की जाती है और खोजने वाले हरेक इंसान के लिए यह मुहैया नहीं कराई जाती, तो इंसान के लिए असली खुशहाली पैदा करने में समाज को असफल माना जाएगा। इस जागरूकता की वजह से ही इस संस्कृति में, लोगों ने हर गली में कई मंदिर बनाए हैं। इसके पीछे यह तर्क था कि कुछ मीटर की दूरी भी प्रतिष्ठित स्थान की मौजूदगी के बिना न रहे। ऐसा नहीं था, मंदिर बनाने की होड़ लगी हुई थी। इसके पीछे बस यही सोच थी कि किसी को भी ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए, जो प्रतिष्ठित न हो।

एक इंसान के लिए प्रतिष्ठित स्थान में होना सौभाग्य की बात है; उसके जीने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। आप पूछ सकते हैं, 'क्या मैं उसके बिना रह सकता हूं?' आप रह सकते हैं। उस इंसान के लिए, जो अपने खुद के शरीर को मंदिर बनाना जानता है, मंदिर जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हां, आप अपने शरीर को भी प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उसे वैसा ही कायम रख सकते हैं? मंदिर बनाने का बुनियादी मकसद खासकर उन लोगों को फायदा पहुंचाना है, जिनके जीवन में साधना नहीं है।

सारी आध्यात्मिक दीक्षाएं इस हाड़-मांस के शरीर को मंदिर की तरह प्रतिष्ठित करने की दिशा में होती हैं; उसके बाद तो सिर्फ उसे कायम रखने की जरूरत होती है।

सारी आध्यात्मिक दीक्षाएं इस हाड़-मांस के शरीर को मंदिर की तरह प्रतिष्ठित करने की दिशा में होती हैं; उसके बाद तो सिर्फ उसे कायम रखने की जरूरत होती है। हर दिन साधना करना इस शरीर को कायम रखने की कोशिश है, ताकि यह दीक्षा-प्रक्रिया में बने रहने के योग्य बना रहे। एक निर्जीव वस्तु, जैसे एक पत्थर को प्रतिष्ठित करने में काफी बड़ी मात्रा में जीवन की कीमत देनी होती है। इंसानों को जीवंत मंदिर बनाना काफी कम मेहनत का काम है और यह माहौल के लिए भी फायदे का है।

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

शेखर कपूर | फिल्म निर्देशक

गौरैयों के झुंड को उड़ते हुए देखा है? वे तुरंत अपना रास्ता बदल लेते हैं, बिना किसी नेता के... समूह में, एक साथ। वहां काम करता है उनका अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान ही वह रास्ता है, जिससे हम खुद को संगठित कर सकते हैं।

अनुलोम-विलोम

प्रदूषण

पटाखा चलाने की मांग करने वाले दोषी

जैसा अनुमान था, दीवाली के अगले दिन दिल्ली-एनसीआर और उत्तर देश के कई इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया। यह बताता है कि प्रदूषण अब केवल दिल्ली या उत्तर भारत की समस्या नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय चुनौती बन चुका है। ग्रीन पटाखों की अवधारणा भले ही पर्यावरण हितैषी बताई जाती हो, किंतु वास्तविकता यही है कि इनके नाम पर पारंपरिक, अधिक प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे ही बड़े पैमाने पर जलाए गए। प्रदूषण इन वजहों से ही अधिक फैला। यह सत्य है कि वायु प्रदूषण के कारक केवल पटाखे नहीं होते। इसमें वाहनों का धुआं, निर्माण-कार्य, पराली जलाना और उद्योगों से निकलने वाली गैसें भी शामिल होती हैं। फिर भी यह कहना गलत नहीं होगा कि पटाखों से निकलने वाला धुआं दीवाली की रात हवा को विषाक्त बना देता है। दुखद यह है कि इस खतरे की जानकारी होते हुए भी जनता परंपरा और उत्सव के नाम पर संयम नहीं बरतती। यहां तक कि पटाखों पर प्रतिबंध के खिलाफ अदालती आदेश हासिल कर लिया जाता है, जबकि ग्रीन पटाखे भी आम पटाखों की तरह प्रदूषण फैलाते हैं, बेशक उसकी मात्रा 70 प्रतिशत ही क्यों न हो।

ऐसे में, आज आवश्यकता इसी बात की है कि दीवाली की असली भावना, अंधकार से प्रकाश की ओर, को सही अर्थों में समझा जाए। अगर प्रकाश का अर्थ केवल पटाखों की चकाचौंध रह जाएगा, तो हम अपनी ही स्वास्थ्य पर अंधकार फैला रहे हैं। पटाखे छोड़ना वस्तुतः अपने धन को आग लगाने जैसा है। यह प्रदूषण न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पटाखों का इस्तेमाल करने वाले परिवार के बच्चों, बुजुर्गों और रोगियों को भी प्रभावित करता है। यह धूम्रपान की तरह है, जिसका नुकसान सबको समान रूप से झेलना पड़ता है। इस समस्या का स्थायी समाधान केवल सरकारी आदेशों या न्यायालय के प्रतिबंधों से नहीं निकलेगा। यह आत्मसंयम और सामाजिक चेतना से ही संभव है। हमें ऐसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, जो उत्सव की खुशी तो दें, लेकिन प्रकृति को क्षति न पहुंचाएं।

हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लेजर शो और अल्ट्राइंग्लिश लाइट तकनीक से पटाखों की तुलना में कहीं अधिक सुंदर, रंगीन और सुरक्षित दृश्य प्रस्तुत कर सकते हैं। जिस प्रकार दशहरे पर सामूहिक रूप से रावण दहन देखा जाता है, उसी प्रकार सामूहिक 'लेजर दीवाली' का आयोजन किया जा सकता है। यदि समाज, प्रशासन और नागरिक मिलकर ऐसा प्रयास करें, तो दीवाली न केवल रोशनी का त्योहार बनी रहेगी, बल्कि स्वच्छता, स्वास्थ्य और संवेदनशीलता का प्रतीक भी बनेगी।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

प्रदूषण की वजह सिर्फ दीपावली नहीं

हर साल दीवाली आती है, और हर साल एक 'महान' परंपरा का जन्म होता है- पटाखों पर ज्ञान बांटने की। खासतौर से दीपावली के अगले दिन तो कुछ लोग पटाखों की आलोचना में ही जुटे रहते हैं। ऐसा लगता है, जैसे पूरे साल का प्रदूषण एक छोटे से 'एटम बम' (पटाखे) में भरकर दीपावली के दिन ही छोड़ा जाता है। यूक्रेन-रूस युद्ध या गाजा-इजरायल संघर्ष ने ओजोन की जितनी मोटी परत बनाई है, वह सारी परत दीपावली की रात ही फट पड़ती है। बाकी 364 दिन तो हमारे शहर एकदम स्विट्जरलैंड की हवा का आनंद देते हैं।

दीपावली के दिन सुबह-सुबह वॉट्सएप यूनिवर्सिटी से एक ज्ञानवर्धक मैसेज आता है- 'इस दीपावली, सिर्फ दीये जलाओ, पटाखे नहीं। प्रदूषण से हमारे 'पेट डॉग्स' (पालतू कुत्तों) को कितनी तकलीफ होती है! बेचारे डरे-सहमे रहते हैं!' वाह! क्या बात है! ये वही लोग हैं, जो साल भर अपनी एसयूवी का हॉर्न इस तरह बजाते हैं, जैसे शहर में कोई आपातकाल लग गया हो और जिनकी गाड़ियों का धुआं देखकर लगता है कि प्रदूषण विभाग ने उनसे कोई खास डील कर रखी हो। मगर दीवाली के आसपास इनके अंदर का 'पर्यावरण प्रेम' जागता है, और हमारे 'सोशल एक्टिविस्ट' (सामाजिक कार्यकर्ता) ऐसे-ऐसे तर्क ले आते हैं कि दुनिया के बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी फेल हो जाएं। 'पटाखों में पैसा बर्बाद मत करो, किसी गरीब को खाना खिलाओ!' इनके इस तरह के उपदेशों को सुनते ही मेरा मन इनसे यह पूछने को करता है कि 'भाई साहब, शॉपिंग का आपका बिल कितना था? क्या वह पैसा किसी गरीब के काम आया था, या वह भी 'पेट डॉग्स' के फैंसी बिस्किट पर खर्च हुआ?'

सबसे मजेदार बात तो तब होती है, जब 'पटाखा न फोड़ने' का अनुरोध एक 'राष्ट्रीय कर्तव्य' बना दिया जाता है। अगर आपने एक फुलझड़ी भी जला दी, तो आप राष्ट्र के दुश्मन हैं, सभ्यता के विनाशक हैं, और आपकी वजह से ग्लोबल वॉर्मिंग हो रही है। लेकिन, अगर वही पटाखे नए साल के जश्न में या क्रिकेट मैच जीतने पर फोड़े जाएं, तो वह 'खुशी का इजहार' बन जाता है! वाह रे दोमुंहापन! मतलब, प्रदूषण को भी पता है कि दीवाली पर ही फैलना है, बाकी जश्न के मौके पर वह छुट्टी पर चला जाता है! इसलिए, मेरी तमाम पर्यावरण-प्रेमियों से विनम्र गुजारिश है कि कृपया अपने एसी को, अपनी गाड़ियों को, और अपने अनगिनत फालतू खर्चों को एक दिन की छुट्टी दें। शायद तब हम समझ पाएंगे कि पटाखों का शोर, हमारे साल भर के ध्वनि और ज्ञान प्रदूषण के मुकाबले कितना कम है।

रूप नारायण मांडवे, टिप्पणीकार

मलेशिया-भारत रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देंगे

शिखर सम्मेलन

पेज-1 से आगे

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आसियान शिखर सम्मेलन में वर्चुअल संबोधन संबंधों की मजबूती पर केंद्रित होगा।

मोदी के मलेशिया की राजधानी क्वालालंपुर नहीं जाने के पीछे समय की उपलब्धता की कमी मानी जा रही है। इससे पहले, संभावना थी कि पीएम मोदी की मलेशिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो सकती है, क्योंकि ट्रंप पूर्वी एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच, मलेशियाई प्रधानमंत्री इब्राहिम के साथ फोन पर बातचीत के बाद मोदी ने कहा कि वह आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे और दोनों पक्षों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं।

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि 27 अक्तूबर को होने वाले पूर्वी एशिया सम्मेलन में विदेश मंत्री एस. जयशंकर हिस्सा लेंगे। बता दें कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) को इस क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक माना जाता है और भारत तथा अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देश इसके संवाद साझेदार हैं।

आसियान-भारत संबंधों में प्रगति की समीक्षा होगी

विदेश मंत्रालय ने कहा कि वर्चुअल बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और आसियान नेता संयुक्त रूप से आसियान-भारत संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की पहलों पर चर्चा करेंगे। आसियान के साथ संबंधों को मजबूत करना हमारी एक्ट ईस्ट नीति और हमारे हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ है।

आसियान में 10 देश

आसियान में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम आदि देश शामिल हैं।

26 अक्तूबर को क्वालालंपुर में होना है सम्मेलन का आयोजन

27 अक्तूबर को पूर्वी एशिया सम्मेलन में विदेश मंत्री एस. जयशंकर लेंगे हिस्सा

सम्मेलन में भारत से जयशंकर मौजूद रहेंगे

विदेश मंत्री एस. जयशंकर क्वालालंपुर में 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व करेंगे। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने और क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विकास पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आसियान देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस भी शामिल हैं।

पीएम के भाग न लेने पर कांग्रेस का तंज

नई दिल्ली, वि.सं.। आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया नहीं जाने के पीएम मोदी के फैसले पर कांग्रेस ने तंज कसा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि प्रधानमंत्री आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात नहीं चाहते।

जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में कहा, सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ में संदेश पोस्ट करना एक बात है, लेकिन उनसे मुलाकात दूसरी बात है। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने का दावा 53 बार किया है और पांच बार कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है।

देश-विदेश 30s

न्यूजीलैंड में तूफान से सैकड़ों उड़ानें रद्द

वेलिंगटन। न्यूजीलैंड में गुरुवार को तूफान ने कहर बरपाया। तेज रफ्तार से चल रही हवाओं के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। 200 से ज्यादा उड़ानों को रद्द करना पड़ा। एक हफ्ते में दूसरी बार है, जब ये देश तूफान का सामना कर रहा है। हवा की रफ्तार 160 किमी प्रतिघंटा दर्ज की गई। जबकि दक्षिणी द्वीप के एक सुदूर ग्रामीण इलाके में 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं।

'भारत मानवीय मूल्यों पर एकजुटता का पक्षधर'

हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत की मानवीय भागीदारी की दिशा संप्रभुता, अहस्तक्षेप और नैतिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों से तय होती है। भारत मानवता, निष्पक्षता तथा तटस्थता के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 151वीं बैठक में यह टिप्पणी की।

कट्टरपंथी पार्टी टीएलपी पर प्रतिबंध को मंजूरी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कैबिनेट ने गुरुवार को चरमपंथी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) पार्टी पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाने के फैसले को मंजूरी दे दी। हाल ही में देश में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद यह कदम उठाया गया है। पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। पीएमओ ने कहा, कैबिनेट ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी।

शेख सालेह सऊदी अरब के नए ग्रैंड मुफ्ती बने

दुबई। सऊदी अरब सरकार ने शेख सालेह बिन फौजान अल फौजान को देश का नया ग्रैंड मुफ्ती नियुक्त किया है। बुधवार देर रात इस फैसले की घोषणा की गई। सऊदी के युवराज मोहम्मद बिन सलमान की सिफारिश पर उनको नियुक्त किया गया। बता दें कि शेख सालेह समय-समय पर अपने विवादित बयानों के कारण हमेशा चर्चा में भी रहे हैं।

चीन की दूसरी सबसे ताकतवर कुर्सी पर शेंगमिन

बीजिंग। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने झांग शेंगमिन को केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। देश में सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष को दूसरा सबसे पावरफुल पद माना जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी के चौथे अधिवेशन में झांग शेंगमिन के नाम पर मुहर लगाई गई। झांग से पहले इस पद पर हे वेइदोंग काबिज थे। वेइदोंग को एक वक्त में जिनपिंग का खास माना जाता था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया।

वकील पर अवमानना याचिका पर सुनवाई 27 को

नई दिल्ली। सीजेआई बी आर गवई की ओर जूता फेंकने का प्रयास करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना कार्रवाई संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 27 अक्तूबर को सुनवाई करेगा। वाद सूची के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई होगी।

टॉमहॉक मिसाइलों का कड़ा जवाब देंगे : पुतिन

मॉस्को। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि यदि यूक्रेन को रूस के भीतर तक हमला करने के लिए टॉमहॉक क्रूज मिसाइल जैसे लंबी दूरी के हथियार दिए जाते हैं तो रूस की प्रतिक्रिया जोरदार होगी। पुतिन ने रूसी भौगोलिक सोसायटी की यहां 17वीं कांग्रेस के मौके पर टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में यह टिप्पणी की। पुतिन ने बुडापेस्ट वार्ता के रद्द होने, रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार उपलब्ध कराने से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए यह कहा।

पाक-अफगानिस्तान में फिर शुरू हुआ व्यापार

इस्लामाबाद। पाक-अफगानिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते के बाद दोनों के बीच ट्रांजिट ट्रेड (आगमन वाणिज्य) गुरुवार को फिर से शुरू हो गया। चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा। अफगानिस्तान से आने वाले ट्रकों या पाक से जाने वाले वाहनों की कड़ी जांच हो रही है। कई स्थानों पर फंसे 300 वाहनों को निकाला गया है। बलूचिस्तान प्रांत की चमन सीमा से इसकी शुरुआत की गई। ट्रांजिट ट्रेड निदेशालय ने बताया कि माल ढुलाई का काम तीन चरणों में पूरा किया जाएगा।

ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 में बड़े बदलाव होंगे

तैयारी: आपत्तिजनक सामग्री 36 घंटे के भीतर हटानी होगी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन कंटेंट पर सख्ती बढ़ा दी है। इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) 2000 में संशोधन करते हुए इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 में बड़े बदलावों की घोषणा की। इसके तहत गैरकानूनी सामग्री और प्रतिबंधित कंटेंट को 36 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी नई अधिसूचना के तहत यह संशोधन 15 नवंबर, 2025 से प्रभावी होगा। सरकार ने यह कदम देश की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी ऑनलाइन कंटेंट पर नियंत्रण को ज्यादा सख्त करने के उद्देश्य से उठाया है। अधिसूचना के अनुसार, आईटी रूल्स 2021 के रूल 3(1)(डी) को पूरी तरह से बदल दिया गया है। सरकार नए नियमों के तहत कई प्लेटफॉर्म पर यूजर अकाउंट को सस्पेंड कर सकती है।

दो ही स्थिति में होगी मान्य : यह वास्तविक जानकारी दो ही स्थितियों में मानी जाएगी। पहला, किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से और दूसरा, सरकार या उसकी किसी अधिकृत एजेंसी के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी की गई लिखित सूचना के जरिए। इसके तहत यह सूचना केवल ऐसा अधिकारी दे सकेगा, जो संयुक्त सचिव या उसके समकक्ष पद पर हो। अगर राज्य सरकार ने जारी की है तो वह अधिकारी डायरेक्टर या समकक्ष पद का होना चाहिए। अगर सूचना पुलिस प्रशासन ने दी है तो अधिकारी का पद उप पुलिस महानिरीक्षक से नीचे नहीं होना चाहिए।

हर माह होगी समीक्षा : केंद्र ने स्पष्ट किया कि सभी ऐसी लिखित सूचनाओं की हर महीने समीक्षा की जाएगी। यह समीक्षा संबंधित विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी आदेश आवश्यक, संतुलित और कानून की भावना के अनुरूप हैं। सूत्रों ने बताया कि किसी भी लिखित सूचना में यह विवरण साफ-साफ बताया जाएगा कि किस कानूनी आधार और अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार का अवैध कार्य हुआ है। मंत्रालय के मुताबिक, अब किसी भी इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म (जैसे सोशल मीडिया, वेबसाइट, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर) पर यदि ऐसी कोई जानकारी, फोटो, वीडियो या कंटेंट मौजूद है, जो किसी भी कानून के तहत निषिद्ध है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर किसी इंटरमीडियरी को ऐसी वास्तविक जानकारी मिलती है कि उसके प्लेटफॉर्म पर कोई गैरकानूनी या प्रतिबंधित कंटेंट है, तो उसे 36 घंटे के भीतर उसे हटाना होगा।

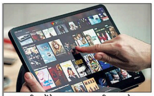

एआई सामग्री पर नियंत्रण मकसद नहीं

केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि कृत्रिम मेधा (एआई) के जरिये बनाई गई या संशोधित सामग्री पर स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य करने के पीछे मकसद ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (मेइटी) सचिव एस कृष्णन ने एआई-निर्मित सामग्री पर अपने मंत्रालय की तरफ से जारी प्रस्तावों के मसौदे के बारे में यह बात कही।

- नए नियमों के तहत प्लेटफॉर्म पर यूजर अकाउंट को सस्पेंड किया जा सकेगा
- सचिव स्तर के अधिकारी लिखित सूचनाओं की समीक्षा करेंगे
- प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित कंटेंट है, तो अफसरों को तुरंत कार्रवाई करनी होगी

15 नवंबर से नई गाइडलाइन लागू होगी, केंद्र सरकार बड़े बदलाव करने की तैयारी में

यूनुस सरकार में दरार, छात्र नेता मंत्रिमंडल से बाहर होंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में शामिल छात्र नेताओं की स्थिति डगमगाने लगी है, जिन छात्रों को यूनुस ने जुलाई-अगस्त आंदोलन का दिमाग बताया था। वही, अब मंत्रिमंडल से बाहर किए जा रहे हैं।

ढाका के एक अखबार के अनुसार यूनुस प्रशासन ने छात्र आंदोलन से जुड़े दो सलाहकारों को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा है। यह कदम तब उठाया गया है जब मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके पूर्व सहयोगी जमात-ए-इस्लामी ने छात्र नेताओं पर नेशनल सिटिजन पार्टी के पक्ष में झुकाव रखने का आरोप लगाया। विपक्ष का कहना है कि छात्र नेताओं की राजनीतिक तटस्थता संदिग्ध है और वे यूनुस प्रशासन के बजाय एक खास पार्टी के हित में काम कर रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम यूनुस की अंतरिम सरकार के भीतर गहराते मतभेदों का संकेत है।

- दो सलाहकारों को मंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्देश

गगनयान मिशन का 90 प्रतिशत काम पूरा : इसरो

बेंगलुरु, एजेंसी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रमुख वी. नारायणन ने गुरुवार को कहा कि गगनयान मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। 90% विकास कार्य पूरा हो चुका है।

नारायणन ने कहा, मिशन के लिए कई जटिल तकनीकों का विकास होना है। इनमें रॉकेट को मानव उड़ान के लिए उपयुक्त बनाना, ऑर्बिटल मॉड्यूल तैयार करना और पर्यावरण नियंत्रण तथा सुरक्षा प्रणाली विकसित करना शामिल है। इसरो प्रमुख ने कहा, 2027 की शुरुआत तक मानवयुक्त मिशन पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

इसरो प्रमुख नारायणन ने कहा कि इसरो नवंबर में दो उपग्रहों सीएमएस-03 और निजी अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लूबर्ड को कक्षा में स्थापित करेगा।

बोले, पहला मानवयुक्त गगनयान मिशन 2027 में लॉन्च होगा

भारतवंशी चालक ने तीन को कुचला

हादसा

न्यूयॉर्क, एजेंसी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के एक ट्रक चालक ने तीन लोगों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हादसे में कई अन्य लोग घायल भी हुए। मिली जानकारी के अनुसार, ये घटना इस सप्ताह के शुरुआत की है।

आरोप है कि जशनप्रीत सिंह नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। धीमी गति से चल रहे ट्रैफिक में उसने सामने रहे कई वाहनों में टक्कर मारी। मिली जानकारी के अनुसार, वह अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहा था, उसने 2022 में दक्षिणी अमेरिकी सीमा पार की थी।

2022 में बॉर्डर पेट्रोल एजेंटों ने उसे हिरासत में लिया था: मार्च 2022 में कैलिफोर्निया के एल सेंट्रो सेक्टर में बॉर्डर पेट्रोल एजेंटों ने उसे हिरासत में लिया था। हिरासत के विकल्प नीति के तहत उसे देश के अंदरूनी हिस्सों में छोड़ दिया, जहां अवैध प्रवासियों को सुनवाई लंबित रहने तक रिहा किया जाता है।

अगस्त के बाद से यह दूसरी ऐसी घटना: बता दें कि अगस्त के बाद से यह दूसरी ऐसी घटना है, जिसमें किसी भारतीय मूल के ट्रक चालक पर अमेरिका में जानलेवा दुर्घटना का आरोप लगाया गया है। 12 अगस्त को, 28 वर्षीय हरजिंदर सिंह ने फ्लोरिडा में ट्रक को गलत तरीके से मोड़ा था, जिससे कई वाहन टकरा गए थे और तीन लोगों की मौत हो गई थी।

- जशनप्रीत सिंह पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप
- अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा था

कनाडा राजनयिक कर्मियों की संख्या अब बढ़ा सकेगा

टोरंटो, एजेंसी। नई दिल्ली धीरे-धीरे कनाडा को भारत में उतनी ही संख्या में राजनयिकों और अधिकारियों को तैनात करने की अनुमति देगी, जितनी संख्या अक्तूबर 2024 से पहले थी।

एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने बताया कि जैसे ही कनाडा उन अधिकारियों के नाम नई दिल्ली को भेजेगा, उसी समय से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह निर्णय इस महीने की शुरुआत में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा के दौरान लिया गया।

पिछले साल अक्तूबर में भारत ने राजनयिक संख्या में समानता की मांग की थी, जिसके बाद 41 कनाडाई राजनयिकों को भारत छोड़ना पड़ा था। उस समय भारत के कनाडा में 21 और कनाडा के भारत में 62 राजनयिक थे। अब दोनों देश राजनयिक संबंधों को सामान्य करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं।

भारतीय कंपनियों पर ईयू की पाबंदी

सख्ती

नई दिल्ली, एजेंसी। यूरोपीय संघ (ईयू) ने रूसी सेना के साथ कथित संबंधों के लिए 45 संस्थाओं पर गुरुवार को प्रतिबंध लगाए। इनमें से भारत की तीन कंपनियां भी शामिल हैं।

यूरोपीय संघ ने अपने 19वें प्रतिबंध पैकेज के तहत इन कंपनियों पर दंडात्मक कार्रवाई की है। ये प्रतिबंध यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के लिए उस पर आर्थिक दबाव बनाने के प्रयासों का हिस्सा हैं। तीन भारतीय कंपनियों की पहचान एयरोट्रस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, एसेंड एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और श्री एंटरप्राइजेज के रूप में की गई है।

यूरोपीय संघ के एक बयान में कहा गया है कि 45 नई संस्थाओं की पहचान की है। ये रूस के सैन्य और औद्योगिक समूहों को समर्थन दे रही है। उनके साथ व्यापार कर रूस को फायदा पहुंचा रही है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि इनमें से 17 संस्थाएं रूस के अलावा तीसरे देशों में स्थित हैं। इन 17 संस्थाओं में से 12 चीन में हैं, तीन भारत में और दो थाईलैंड में हैं।

यूरोपीय संघ ने रूस पर और प्रतिबंध लगाए

ब्रुसेल्स। पुतिन को शांति वार्ता के लिए मजबूर करने के लिए यूरोपीय संघ ने गुरुवार को रूस पर और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इसमें रूस के प्रमुख तेल स्रोतों को निशाना बनाया गया है। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर पहले ही 18 तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। डेनमार्क के यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने कहा कि रूस से होने वाले एलएनजी आयात पर भी नए प्रतिबंध लगा दिए हैं।

हंगेरियन विद्रोह की 69वीं वर्षगांठ पर शांति मार्च निकाला

हंगरी के बुडापेस्ट में 1956 के हंगेरियन विद्रोह की 69वीं वर्षगांठ पर गुरुवार को शांति मार्च निकाला। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मार्च में शामिल लोग देश का राष्ट्रीय ध्वज और बैनर लिए हुए थे। • रॉयटर्स

गूगल ने बनाया 'क्वांटम ईकोज'

न्यूयार्क, एजेंसी। गूगल ने क्वांटम कंप्यूटिंग की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने अपनी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप 'विलो' पर नया एल्गोरिदम 'क्वांटम ईकोज' बनाया है, जो सुपरकंप्यूटर से 13 हजार गुना तेज है। अगले पांच वर्षों में इसके उपयोग में आने की संभावना है।

गूगल ने इस चिप को 2024 में पेश किया था। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने इसे सुपरकंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक निर्णायक कदम बताया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'विलो' चिप ने पहली बार सत्यापित की जा सकने वाली क्वांटम श्रेष्ठता हासिल की है। यह एल्गोरिदम भविष्य में मेडिसिन और मटेरियल साइंस में नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। पिचाई ने आगे कहा कि इसके परिणामों को अन्य क्वांटम कंप्यूटरों द्वारा भी दोहराया जा सकता है या प्रयोगों से प्रमाणित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभी तक क्वांटम कंप्यूटिंग एल्गोरिदम को दूसरे कंप्यूटर या प्रयोगों में दोहराना एक बड़ी चुनौती थी। इसको लेकर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भी गूगल को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग प्रासंगिक होती जा रही है।

गूगल ने बताया 'क्वांटम स्कोप': गूगल ने कहा कि जैसे टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप ने हमें अदृश्य दुनिया की झलक दिखाई थी, वैसे ही यह प्रयोग हमें 'क्वांटम स्कोप' की दिशा में ले जा रहा है। यह प्रकृति के उन रहस्यों को दिखा सकेगा, जिन्हें अब तक कोई नहीं देख पाया। इससे अणु, चुंबक या ब्लैक होल की संरचना समझने में मदद मिल सकती है।

13 हजार गुना तेज होगा सुपरकंप्यूटर से, उद्योगपति एलन मस्क ने भी दी बधाई

- गूगल के सीईओ पिचाई ने इसे सुपरकंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक निर्णायक कदम करार दिया

वेनेजुएला ने ट्रंप की धमकी के बाद मिसाइलें तैनात कीं

काराकस, एजेंसी। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच गुरुवार को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ऐलान किया कि देश में रूस में बनी 5000 मिसाइलें तैनात कर दी हैं।

मादुरो ने ये चेतावनी ऐसे समय दी जब अमेरिका इस देश पर सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। ये मिसाइलें महत्वपूर्ण हवाई सुरक्षा ठिकानों और अन्य क्षेत्रों में तैनात की गई हैं। मादुरो ने कहा कि इग्ला-एस नाम की ये रूसी मिसाइल ड्रोन, हेलीकॉप्टर और सैन्य विमान गिराने में सक्षम हैं। मादुरो ने कहा, हम अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, लाखों स्वयंसेवक मिलिशिया भी अमेरिकी हमलों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।

ट्रंप ने दी थी धमकी : बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला को धमकी देते हुए कहा था कि वह इस देश पर सैन्य कार्रवाई का विचार कर रहे हैं। मादुरो पर दबाव बनाने के लिए कैरेबियन क्षेत्र में हाल ही में 4500 मरीन जवानों की तैनाती की गई है।

- राष्ट्रपति मादुरो बोले, अमेरिका को किसी भी हमले का कड़ा जवाब देंगे

पॉल कपूर अमेरिकी विदेश विभाग में सहायक सचिव

वाशिंगटन, एजेंसी। भारतीय-अमेरिकी लेखक व सुरक्षा विशेषज्ञ पॉल कपूर को अमेरिकी विदेश विभाग में दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो के नए सहायक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बुधवार को उन्होंने पद की शपथ ली।

ब्यूरो ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि सहायक सचिव पॉल कपूर का स्वागत है। डॉ. कपूर भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मालदीव, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में अमेरिका की कूटनीतिक भागीदारी तथा रणनीतिक साझेदारी से जुड़े मामलों को देखेंगे।

नई दिल्ली में जन्म

कपूर का जन्म नई दिल्ली में हुआ। पिता भारतीय थे, मां अमेरिका की रहने वाली थीं। उन्होंने अमेरिकी नौसेना के स्नातकोत्तर विद्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। वह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के हूवर इंस्टीट्यूशन में विजिटिंग फेलो हैं।

निलंबित डीआईजी के आवास पर छापा

चंडीगढ़, एजेंसी। सीबीआई ने गुरुवार को पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के चंडीगढ़ स्थित आवास पर फिर छापा मारा। इस दौरान नकदी और कीमती सामान जब्त किया गया। भुल्लर को पिछले हफ्ते रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

छापेमारी के दौरान सीबीआई ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले और परिसर की कीमत का भी आकलन किया। भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने उनके बैंक लॉकर की भी जांच की है। अफसरों ने कहा, भुल्लर के सेक्टर-40 स्थित आवास पर छापेमारी इन खबरों के बीच हुई कि वह एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।

सम्मान | द बर्निंग अर्थ: एन एनवायरनमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 इयर्स पुस्तक के लिए मिला पुरस्कार, मानव और पर्यावरण पीड़ा पर फोकस

भारतीय मूल के अमृत ने 'ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज' जीता

चर्चा में चेहरा

लंदन, एजेंसी। भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत की पुस्तक 'द बर्निंग अर्थ: एन एनवायरनमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 इयर्स' को इस वर्ष के 'ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज' से सम्मानित किया गया है।

इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के तहत 25,000 पाउंड (लगभग 29 लाख रुपये) दिए जाते हैं। यह पुरस्कार दुनियाभर की सर्वश्रेष्ठ गैर-काल्पनिक पुस्तकों को दिया जाता है। इससे पहले भारतीय मूल के लेखक अमिताव घोष की किताब 'स्मोक एंड एशेज: ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज' 2024 में इस पुरस्कार की सूची में शामिल हुई थी।

46 वर्षीय सुनील अमृत की इस नवीनतम पुस्तक को लंदन में ब्रिटिश एकेडमी में आयोजित एक समारोह में पुरस्कृत किया गया। निर्णायकों ने इस पुस्तक को जलवायु संकट के संदर्भ में 'महत्वपूर्ण' बताया है।

पुस्तक में मानव और पर्यावरणीय पीड़ा का विवरण : अमृत ने कहा कि मुझसे कई बार पूछा गया है कि क्या 'द बर्निंग अर्थ' एक निराश करने वाली पुस्तक है। उन्होंने कहा, इसमें निस्संदेह मानव और पर्यावरणीय पीड़ा का विवरण है, लेकिन यह भी दिखाता है कि इन दोनों का संबंध गहराई से जुड़ा रहा है। फिर भी पुस्तक यह संदेश देती है कि इतिहास में कई ऐसे रास्ते थे जिन्हें हमने नहीं अपनाया- वे विचार, आंदोलन और तकनीकें जो अधिक टिकाऊ और मानवीय थीं। शायद उन भूले-बिसरे रास्तों में ही हमारे भविष्य के लिए प्रेरणा छिपी है। निर्णायक समिति की अध्यक्ष एवं ब्रिटिश इतिहासकार प्रोफेसर रेबेका एरल ने पुस्तक को मानव इतिहास और पर्यावरणीय परिवर्तन के बीच गहरे संबंधों का अद्भुत विवरण बताया है। पुरस्कार के लिए अन्य पांच चयनित पुस्तकों में विलियम डालरिंपल की 'द गोल्डन रोड: हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड' भी शामिल थी।

29 लाख रुपये के करीब इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के तहत दिए जाते हैं

- यह पुरस्कार दुनियाभर की सर्वश्रेष्ठ गैर-काल्पनिक पुस्तकों को दिया जाता

सुनील के माता-पिता दक्षिण भारतीय

1. अमृत का जन्म केन्या में हुआ था
2. उनके माता-पिता दक्षिण भारतीय हैं
3. सुनील अमृत सिंगापुर में पले-बढ़े
4. इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक किया
5. वर्तमान में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। **–वाल्तेयर**

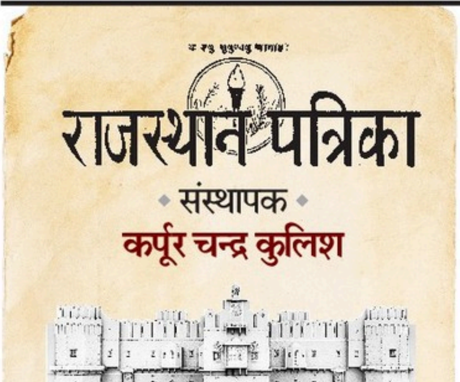

बांग्लादेश में अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रहे कट्टरपंथी

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाने के बाद बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथी अपने एजेंडे पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रति वफादार रहे सेना के 15 अधिकारियों को वहां की 'इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल' ने जेल भेज दिया। इन पर लोगों को गायब करने, हिरासत में प्रताड़ना और हत्या के आरोप में मुकदमा चलेगा। शेख हसीना की गिरफ्तारी के आदेश भी दिए गए हैं। यूनुस सरकार के वरिष्ठ सलाहकारों की प्रतिक्रियाओं से संकेत मिलता है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आर्मी (आइआरए) के गठन का पहला चरण शुरू हो चुका है।

दिसंबर 2024 में एंटी-डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट नामक समूह ने 'आइआरए' सशस्त्र संगठन के गठन की घोषणा की थी। यह एक उग्रवादी सेना के रूप में बांग्लादेश को इस्लामिक राज्य में बदलने में सरकार की मदद करेगी। इसमें जिन युवाओं की भर्ती होगी वे ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आइआरजीसी) की तर्ज पर काम करेंगे। इसका लक्ष्य बांग्लादेश की मौजूदा सेना की संख्या के बराबर लगभग 1,60,000 युवाओं को प्रशिक्षित करना है। यूनुस सरकार के वरिष्ठ सलाहकार आसिफ महमूद शोइब भुइयां ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कई केंद्रों में 8,850 लोगों को मार्शल आर्ट, हथियारों के इस्तेमाल, ताइक्वांडो और जूडो की ट्रेनिंग दी जा रही है। जमात-ए-इस्लामी के नेता डॉ. सैयद अब्दुल्ला मुहम्मद ताहिर ने हाल ही न्यूयॉर्क में कहा कि जमात के 50 लाख युवा भारत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। यदि भारत बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो 1971 में जो बदनामी हुई थी, उसे मिटा देंगे। हम साबित करेंगे कि हम असली स्वतंत्रता सेनानी हैं- जमात के 50 लाख युवाओं में से एक हिस्सा गुरिल्ला युद्ध लड़ेगा, जबकि बाकी भारत के अंदर फैलकर 'गजवा-ए-हिंद' को लागू करेंगे। स्पष्ट है कि बांग्लादेश पर पाक खुफिया एजेंसी आइएसआइ का प्रभाव बढ़ गया है। बांग्लादेश को फिर से 1971 से पहले की स्थिति में लाने की अपनी दबी इच्छा पूरी करने के लिए पाकिस्तान, शेख हसीना की सत्ता से बेदखली के बाद से ही काम कर रहा है।

पड़ोस का घटनाक्रम भारत के लिए फिलहाल भले कोई खतरा न हो मगर भविष्य के लिए चेतावनी जरूर है। जमात-ए-इस्लामी के प्रशिक्षण शिविरों में पाकिस्तान सेना और आइएसआइ के अधिकारी आते हैं। वही धन व उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए समुद्री मार्ग खोलने के बाद, बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि बांग्लादेश की बहुसंख्यक आबादी कट्टरपंथियों के साथ आ गई है। आम चुनाव के बाद ही स्थिति साफ होगी। कट्टरपंथी चुनाव के पहले ही अपनी पकड़ बढ़ाना चाहते हैं। भारत सरकार को अपनी अंतरराष्ट्रीय हैसियत का इस्तेमाल कर इसे रोकने का कूटनीतिक उपाय करना चाहिए।

बिहार विधानसभा चुनाव: राजग में नीतीश को सीएम फेस घोषित करने से परहेज आंतरिक असहजता का संकेत

सीएम चेहरे के दांव से बदलेगी चुनावी चाल

राज कुमार सिंह
वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक
@patrika.com

अगर भाजपा और लोजपा (आर) मिलकर जुगाड़ से सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गए तो नीतीश की पालकी क्यों ढोना चाहेंगे? ऐसी आशंकाओं के बीच राजग में चुनावी भितरघात से कोई कैसे इनकार कर सकता है?

इसीलिए कहते हैं कि चुनावी राजनीति अंत तक रंग बदलती है। 22 अक्टूबर की रात तक बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन (इंडिया गठबंधन) अंतर्कलह से ग्रस्त और रक्षात्मक नजर आ रहा था, लेकिन अगले ही दिन पासा पलट गया। अब दबाव सत्तारूढ़ राजग पर आ गया है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद से ही महागठबंधन सीट बंटवारे पर आपसी रार के चलते कठघरे में था। सीएम फेस के सवाल पर भी राजग लगातार सवाल दाग रहा था। 23 अक्टूबर को महागठबंधन की ओर से न सिर्फ सीएम, बल्कि डिप्टी सीएम फेस भी घोषित करने के बाद अब वे ही सवाल राजग से पूछे जा रहे हैं। महागठबंधन ने दो बार डिप्टी सीएम रह चुके राजद के नेता तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया है, जबकि वीआइपी के नेता मुकेश सहनी डिप्टी सीएम फेस बनाए गए हैं। यह घोषणा करते हुए अशोक गहलोत ने सामाजिक समीकरण के मद्देनजर और भी डिप्टी सीएम बनाने का संकेत दिया। विलंब से साफ है कि घोषणा मजबूरी में की गई है, लेकिन जाति में जकड़ी बिहार की राजनीति में यह मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है।

आखिर सबसे बड़े जनाधार वाले दल राजद के नेता तेजस्वी ओबीसी हैं तो मुकेश सहनी ईबीसी। अल्पसंख्यक समुदाय राजद का परंपरागत वोटर है। फिर महागठबंधन में कांग्रेस और वाम दल भी हैं, जिनकी स्वीकार्यता अन्य वर्गों में भी है। यह विजयी समीकरण बन सकता है। अगर सीएम और डिप्टी सीएम का मुद्दा सुलझ गया, तो दर्जन भर सीटों पर महागठबंधन घटक दलों के आमने-सामने होने का हल भी निकाल ही लिया जाएगा। ऐसे में अब राजग को अपनी चुनावी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है, जो लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री पद पर काबिज नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित करने में हिचक रहा है।

दरअसल जटिल राजनीतिक समीकरणों की दृष्टि से बिहार की तुलना महाराष्ट्र से की जा सकती है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के चंद महीने बाद ही महाराष्ट्र ने विधानसभा चुनाव में चौंकानेवाले नतीजों से राष्ट्रीय राजनीति का विमर्श फिर बदल दिया था। उसके लगभग सालभर बाद बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र में दोनों गठबंधनों: सत्तारूढ़ राजग और विपक्षी 'इंडिया' में सीधा मुकाबला था, जबकि बिहार में चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर इसे त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा की 'बी' टीम बताए जाते रहे प्रशांत की जन सुराज पार्टी सिर्फ 'इंडिया' गठबंधन, जिसे बिहार में महागठबंधन कहा जाता है, को ही नुकसान पहुंचाएगी–ऐसा मानने का कोई तार्किक कारण नहीं है। आखिर अपने तीन उम्मीदवारों पर बीच चुनाव मैदान छोड़ने के लिए दबाव बनाने का आरोप प्रशांत, भाजपा पर ही लगा रहे हैं। महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी सरकार का नेतृत्व अपेक्षाकृत छोटे दल के नेता नीतीश कुमार कर रहे हैं, जबकि बड़ा दल भाजपा सरकार में शामिल है। महाराष्ट्र में राजग, जिसे वहां महायुति कहा जाता है, ने चुनाव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा, पर चुनाव के बाद ज्यादा विधायकों के तर्क के आधार पर भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया, जो शिंदे के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री रहे। कुछ दिन नाराजगी दिखाने के बाद शिंदे उप मुख्यमंत्री बनने को राजी हो गए। तभी से यह सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है कि क्या बिहार में भी महाराष्ट्र दोहराया जाएगा?

राजग के दोनों बड़े घटक भाजपा और जदयू इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री तो निर्वाचित विधायक दल के नेता ही चुनेंगे। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जा रहा है, पर वह 'सीएम फेस' घोषित नहीं किए गए हैं। हां, अतीत में नीतीश के साथ राजनीति कर चुके जीतन राम माझी और उपेंद्र कुशवाहा अवश्य उनके प्रति नरम रुख दिखा रहे हैं। माझी कह रहे हैं कि सीएम फेस घोषित करना अच्छा होता, जबकि कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश ही राजग का सीएम फेस हैं, पर इन दोनों को छह-छह सीटें ही मिली हैं बंटवारे में, जबकि चिराग पासवान की लोजपा (आर) को 29 सीटें दी गई हैं। यह तार्किक लग सकता है कि इस बार जदयू और भाजपा, दोनों ही 101-101 सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव-दर-चुनाव भाजपा आगे बढ़ रही है, जबकि जदयू घट रहा है। पिछले चुनाव में भाजपा ने सार्वजनिक रूप से चिराग के चाचा पशुपति पारस की पार्टी से गठबंधन किया था, जो केंद्र में मंत्री भी थे, लेकिन भतीजे ने चुन-चुन कर जदयू के विरुद्ध उम्मीदवार उतारे। चिराग की पार्टी जीत तो एक ही सीट पाई, पर नीतीश को तीसरे नंबर के दल का नेता बना दिया। भाजपा ने फिर भी नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि वह जदयू के साथ बिना सरकार नहीं बन पाती। उधर लालू-तेजस्वी का राजद फिर नीतीश को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए तैयार ही था। कुछ अरसा बाद नीतीश राजद-कांग्रेस से गठबंधन कर मुख्यमंत्री रहे भी और फिर राजग में वापस लौट गए।

यह सही है कि राजग में सीट बंटवारे को लेकर ज्यादा रार नहीं दिखी, लेकिन बंटवारे का गणित और नीतीश को सीएम फेस घोषित करने से परहेज आंतरिक असहजता का संकेत अवश्य है। अगर भाजपा और लोजपा (आर) मिलकर जुगाड़ से सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गए तो नीतीश की पालकी क्यों ढोना चाहेंगे? ऐसी आशंकाओं के बीच राजग में चुनावी भितरघात से कोई कैसे इनकार कर सकता है? उधर, बिहार की अर्थव्यवस्था को नजरअंदाज कर लोक लुभावन योजनाओं और वादों की बारिश भी शुरू हो गई है। चुनावी मुद्दों की तस्वीर साफ होने में समय लगेगा। हां, आधी आबादी को रिझाने में दोनों गठबंधन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते।

प्रसंगवश

आतिशबाजी के दौरान हादसों का होना बेहद चिंताजनक

बच्चों को सुरक्षित माहौल देना अभिभावकों की जिम्मेदारी

उल्लास व उमंग का त्योहार दीपावली यों तो जीवन में उजास का प्रतीक है। लोग अपनी खुशियों का इजहार आतिशबाजी से करते आए हैं, लेकिन इन्हीं आतिशी खुशियों से निकली चिंगारी हर बार बड़ी संख्या में लोगों को दर्द भी दे जाती है। पांच दिवसीय दीपोत्सव के दौरान भी राजस्थान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होगा जहां आतिशबाजी के कारण झुलसकर लोग अस्पताल नहीं पहुंचे हों। आतिशबाजी में बच्चों के झुलसने की घटनाओं में भी ऐसे मामले ज्यादा सामने आए जिनमें अभिभावकों ने बच्चों को अपनी निगरानी में पटाखे चलाने देने के बजाय उन्हें फ्री छोड़ दिया।

राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में ही पिछले तीन दिन में आतिशबाजी के दौरान झुलसने से 300 से अधिक मरीज पहुंचे, इनमें 80 फीसदी बच्चे हैं। दर्द ऐसा कि किसी की अंगुलियां तो किसी की आंखों की रोशनी ही चली गई। प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी आतिशबाजी के दौरान झुलसकर अस्पताल पहुंचे बच्चों की संख्या ज्यादा है। जाहिर है उत्सव की चमक में हम बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भूलते जा रहे हैं। इन हादसों के पीछे बालहठ एक वजह हो सकती है, लेकिन परिजनों की लापरवाही इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। बच्चों को इस मासूम उम्र में खतरे की इतनी समझ नहीं होती, ऐसे में उन्हें समुचित दिशानिर्देश देना और पटाखों में विस्फोट क्षमता के हिसाब से इन्हें चलाने की अनुमति देना अभिभावकों का कर्तव्य है। आतिशबाजी जहां भी होगी ऐसे हादसे होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए खासतौर से बच्चों को स्कूली स्तर पर भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि सुरक्षित रूप से पटाखे कैसे चलाए जा सकते हैं। बहुत छोटे बच्चे तो आतिशबाजी के दौरान आसपास भी नहीं रहें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जनसंचार माध्यमों और सोशल मीडिया पर ऐसे संदेश प्रसारित होने चाहिए, जो परिजनों को बच्चों की सुरक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील बनाएं। सबसे बड़ी बात यह कि आतिशबाजी बड़े लोगों की निगरानी में नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से करनी चाहिए।

- नरोत्तम शर्मा
narottam.sharma@in.patrika.com

बुक इनसाइट

डेथ इन ए शैलो पॉन्ड

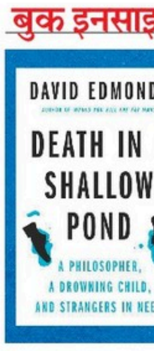

डेविड एडमंड्स की नई किताब डेथ इन ए शैलो पॉन्ड विचारोत्तेजक और भावनात्मक रचना है जो दर्शनशास्त्र और नैतिकता के बीच एक अनोखा पुल बनाती है।

इस पुस्तक में लेखक ने दार्शनिक, एक डूबते बच्चे और जरूरतमंद अजनबियों की कहानी को केंद्र में रखा है, जो पाठकों को जीवन के कठिन सवालों से रूबरू कराती है। एडमंड्स, जो पहले वुड यू किल द फैट मैन? जैसी चर्चित पुस्तक के लेखक हैं एक बार फिर अपनी गहरी समझ और सरल शैली से प्रभावित करते हैं। किताब में एडमंड्स यही सवाल आगे बढ़ाते हैं कि अगर हम सामने दिख रहे बच्चे को बचाना अपनी जिम्मेदारी मानते हैं तो फिर दूर देशों में भूख या बीमारी से मर रहे बच्चों की मदद करने में हम क्यों हिचकिचाते हैं? आधुनिक समाज में इंसान की संवेदनशीलता, परोपकार और दान की मानसिकता को यह किताब नए सिरे से परखती है। लेखक ने बड़े सरल और सहज उदाहरणों से यह समझाने की कोशिश की है कि नैतिकता केवल विचार तक सीमित नहीं हो सकती। इसका असर हमारे रोजमर्रा के फैसलों और जीवनशैली पर होना चाहिए।

फैक्ट फ्रंट

पर्पल फ्रॉग: करोड़ों साल पुरानी प्रजाति

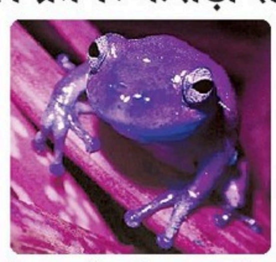

पर्पल फ्रॉग, भारत के वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों में पाया जाने वाला एक अनोखा जीव है। यह केरल और कर्नाटक के घने जंगलों में छिपा रहता है। इसका गहरा बैंगनी रंग और गोल-मटोल शरीर इसे बेहद खास बनाता है।

यह मेंढक अपनी अनोखी जीवनशैली और दुर्लभता के कारण वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों के बीच मशहूर है। पर्पल फ्रॉग की सबसे खास बात यह है कि यह साल के ज्यादातर समय जमीन के अंदर नम मिट्टी में छिपा रहता है। यह केवल मानसून के मौसम में लगभग दो हफ्तों के लिए, प्रजनन के लिए बाहर निकलता है। इस दौरान यह तेज बारिश में नदियों और झरनों के पास देखा जा सकता है। इसका शरीर छोटा लगभग 7-9 सेंटीमीटर लंबा, और चिकना होता है जो इसे मिट्टी में आसानी से रेंगने में मदद करता है। इसका मुंह छोटा और नुकीला होता है जो इसे छोटे जीव खाने में सहायता देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, यह प्रजाति करोड़ों साल पुरानी है और डायनासोर के समय से अब तक जीवित है।

पर्यावरण दिल्ली में रिकॉर्ड स्तर पर प्रदूषण

हवा में जहर, जिम्मेदारी गायब, ग्रीन पटाखों का दावा फुस्स

ज्ञानेन्द्र रावत
वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद्
@patrika.com

अभी दिवाली का त्योहार खत्म ही हुआ है कि दिल्ली ने प्रदूषण के मामले में कीर्तिमान बनाकर यह साबित कर दिया है कि भले हमारी सर्वोच्च अदालत कुछ भी कहे, वह लाख निर्देश दे लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को जहरीली हवा से बचाने के दावे पहले की तरह इस बार भी फिर फेल साबित हुए। वायु गुणवत्ता सूचकांक में दिल्ली दुनियाभर में शीर्ष पर है। भला हो तेज हवाओं का जिन्होंने प्रदूषण को एक जगह ठहरने नहीं दिया वर्ना हालात और खराब होते। यह हालात तब रहे जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के चलाए जाने की अनुमति दी थी लेकिन ग्रीन पटाखों के नाम पर जो पटाखे बेचे गए और चलाए गए, उनसे यह प्रदूषण हुआ।

जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों-आदेशों का खुलेआम उल्लंघन हुआ। उसी का नतीजा रहा कि इस बार पिछले पांच सालों के मुकाबले दिवाली पर पी एम 2.5 की मात्रा सबसे ज्यादा रिकार्ड की गई। यह हालात अकेले दिल्ली की ही नहीं रही, कमोबेश पूरा देश इसका शिकार हुआ है। ग्रीन पटाखों से वायु प्रदूषण कम करने का दावा तो फुस्स हो ही चुका है क्योंकि यदि ग्रीन पटाखे चले होते तो प्रदूषण 50 फीसदी तक कम होता लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उलट।

स्थिति यह रही कि प्रतिबंधित पटाखे न केवल खूब बिके, बल्कि खुलेआम चले भी और जिस पुलिस पर इनके रोकथाम की जिम्मेदारी थी, वह ऐसा होते देखती रही या यूं कहें कि उसने कमाई के चक्कर में अपनी आंखें मूंद लीं। नतीजतन पटाखे 40 फीसदी ज्यादा बिके और दिल्लीवासी जहरीली हवा में सांस लेने को विवश हुए। सीएसआइआर भी इसकी पुष्टि करता है। यह पटाखों की गुणवत्ता तय मानक के अनुरूप रहे, यह अंकुश पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अमिताभ कांत का आशावाद बिल्कुल बेमानी है कि जब लॉस एंजेलिस, बीजिंग और लंदन प्रदूषण कम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं?

उनका यह कहना कि दिल्ली की हवा बेहद खराब है। 38 में से 36 निगरानी केंद्र रेड जोन में हैं। लगातार इस दिशा में काम करने और सख्ती से पहल करने की जरूरत है। इसके लिए एकीकृत कार्ययोजना बेहद जरूरी है। उनकी राय है कि फसल और बायोमास जलाना बंद करना चाहिए। थर्मल पावर प्लांट और ईंट भट्टों को बंद करना चाहिए या फिर उनको क्लीन टेक से मॉडर्न बनाना चाहिए।

2030 तक सभी ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक में बदलना, कंस्ट्रक्शन की धूल पर सख्ती बरतना, कचरे को पूरी तरह अलग करना और प्रोसेसिंग को जरूरी बनाना होगा। दिल्ली को ग्रीन, पैदल चलने लायक बनाना होगा। ट्रांजिट पर फोकस करने के हिसाब से कार्ययोजना बनाकर फिर से डिजाइन करनी होगी। तभी कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।

16 विशाल स्तंभों वाला क्रॉनिकल ऑफ जॉर्जिया

यह जॉर्जिया के त्बिलिसी में स्थित 'द क्रॉनिकल ऑफ जॉर्जिया' स्मारक है। यह केनी हिल पर त्बिलिसी झील के समीप स्थित है। इसे जुराब त्सेरेतेली ने 1985 में बनाया था। इसमें 16 विशाल स्तंभ हैं, स्तंभों के ऊपरी हिस्से में जॉर्जिया के राजा, रानी और वीरों की जीवंत मूर्तियां दिखाई देती हैं।

चिकित्सा आवश्यक है मेडिकल प्रशासन सुधार

हादसे से सबक: भारतीय चिकित्सा सेवा की दरकार

डॉ. अभिषेक व्यास
ईएसआइ हॉस्पिटल बीकानेर
@patrika.com

पिछले दिनों जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में ट्रोमा आइसीयू में आग लगने से कई जिंदगियां खत्म हो गईं। इस दुखद घटना ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। हर व्यक्ति के मन में यही सवाल है कि क्या हमारे सरकारी अस्पताल केवल कागजी नियमों और बैठकों पर चलते रहेंगे या सचमुच रोगियों की देखभाल और उनकी जान की सुरक्षा पर ध्यान देंगे? यह हादसा सिर्फ तकनीकी या प्रशासनिक चूक के साथ उस बड़े सवाल का हिस्सा है, जो वर्षों से उठता रहा है- डॉक्टर्स का दायरा कहां तक होना चाहिए, क्या वे केवल रोगी-सेवा, सर्जरी और शिक्षण कार्य तक सीमित रहें या दवाइयों की खरीद, टेंडर प्रक्रिया, मैनपावर और अस्पताल प्रबंधन जैसे प्रशासनिक क्षेत्रों में भी सक्रिय भूमिका निभाएं? वास्तविकता यह है कि हमारे यहां डॉक्टर्स दोनों ही भूमिकाएं निभाते हैं- कई डॉक्टर रोगी-सेवा, देखभाल और शल्य चिकित्सा को ही सर्वोपरि मानते हैं, वहीं बड़ी संख्या में ऐसे भी डॉक्टर हैं, जिन्हें अस्पताल प्रबंधन और नीतिगत कार्यों में गहरी रुचि होती है और वे इसमें बेहतर योगदान भी देना चाहते हैं।

अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में भिन्न-भिन्न कार्यों के संचालन के लिए डॉक्टरों से रोगियों की देखभाल और शिक्षण के साथ-साथ कई प्रशासनिक जिम्मेदारियों यथा मैनपावर सप्लाई, उपकरणों की निविदा, सरकारी योजनाओं के संचालन, सफाई और रखरखाव आदि में उनकी भागीदारी अपेक्षित रहती है। नतीजतन, कुछ डॉक्टर्स यह मानते हैं कि उनकी मूल चिकित्सा सेवाओं पर प्रभाव पड़ता है, वहीं कई डॉक्टर इसे अवसर मानते हैं और प्रशासनिक तंत्र को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं।

यह भी उतना ही सच है कि अस्पताल चलाना केवल इलाज तक सीमित नहीं है। यदि दवाइयां समय पर न पहुंचें, ऑक्सीजन की सप्लाई में गड़बड़ी हो, भवन जर्जर हो जाए या सफाई व्यवस्था बिगड़ जाए तो इलाज कितना भी अच्छा हो, मरीज सुरक्षित नहीं रह पाएगा यानी प्रशासन और प्रबंधन भी अस्पताल की रीढ़ है।

सवाल यह है कि इस प्रशासनिक भूमिका को कौन निभाए? लंबे समय से यह विचार उठता रहा है कि जिस तरह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) या भारतीय अभियंत्रण सेवा (आईईएस) हैं, उसी तरह भारतीय चिकित्सा सेवा (आइएमएस) का गठन भी किया जाए। यदि आइएमएस बने तो जिन डॉक्टरों को प्रशासनिक कार्य, अस्पताल प्रबंधन और नीति निर्माण में गहरी दिलचस्पी है, वे चयन और प्रशिक्षण के बाद कैडर में जाएं और स्वास्थ्य प्रशासन का नेतृत्व करें। इससे दोहरा लाभ होगा। एक ओर डॉक्टरों को उनके झुकाव और योग्यता के अनुसार कार्यक्षेत्र चुनने का अवसर मिलेगा और वे अपने-अपने क्षेत्र में बेहतर योगदान दे पाएंगे।

आपकी बात

संतुलित पोषण आवश्यक

बच्चों में कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए उनका संतुलित पोषण अत्यंत आवश्यक है। उन्हें जंक फूड, अत्यधिक शक्कर और कोल्ड ड्रिंक्स से परहेज करना चाहिए। शारीरिक गतिविधि मानसिक विकास के लिए अनिवार्य हैं। **- डॉ. राजेन्द्र कुमावत**, जयपुर

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'बच्चों में कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?' ऑनलाइन भी देखें।
इसे स्कैन करें
https://shorturl.at/v6qdx

आज का सवाल

शादियों में फिजूलखर्ची रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

यूएन स्थापना दिवस आज कहीं वीटो का अविवेकपूर्ण, निहित स्वार्थपूर्ण उपयोग यूएन को अप्रभावी तो नहीं बना रहा

संयुक्त राष्ट्र को अधिक सशक्त बनाने के प्रयासों की जरूरत

अजय टुंकलिया
@patrika.com

कुछ वर्षों से ऐसा लग रहा है मानो समूची दुनिया में अराजकता व्याप्त है। हर ओर संघर्ष, शोषण, हिंसा और अव्यवस्था फैल रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समूची दुनिया में अनेक युद्ध लड़े जा चुके हैं और लड़े जा रहे हैं। इतिहास के पन्नों पर दृष्टि डालें तो कह सकते हैं कि इस महायुद्ध के दौरान और उसके तुरंत बाद विश्व नेताओं ने ऐसे मंच की आवश्यकता महसूस की, जो सैनिक अभियानों को तो निरुत्साहित और नियंत्रित करे और दुनिया के देशों में परस्पर सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और बंधुत्व को बढ़ावा दे।

यह भी आवश्यकता महसूस की गई कि सम्पन्न राष्ट्र, विपन्न राष्ट्रों को विकास में मदद करे। आपसी झगड़ों का मध्यस्थता या अंतरराष्ट्रीय कानूनों के दायरे में निराकरण करे। गांधी-विनोबा ने बहुत पहले ही अति राष्ट्रवाद के दुष्परिणामों को समझते हुए, मानव और पृथ्वी के कल्याण के लिए 'जय जगत' की भावना की आवश्यकता प्रतिपादित की थी। भाग्यवश उस समय के विश्व नेताओं ने भी इसी सोच को अंगीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की और उसका चार्टर बनाया।

संघ की स्थापना के साथ ही इस दिशा में सार्थक प्रयास भी हुए। संघर्षों को टालने के लिए अतिरिक्त निरस्त्रीकरण के वास्ते कूटनीतिक प्रयास चलते रहे। परमाणु हथियारों की स्पर्धा पर भी अंकुश लगा। संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेनाओं का भी आवश्यकतानुसार गठन और उपयोग होने लगा। इसके अलावा विकासशील देशों को सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए अनेक स्तरों पर सहायता और सहयोग उपलब्ध होने लगा। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक कार्य हुए। सांस्कृतिक आदान-प्रदान में यूनेस्को की भूमिका उल्लेखनीय रही। किंतु इसके विपरीत, यह भी मानना होगा कि संघर्षों, युद्धों और कुछ राष्ट्रों की महत्त्वाकांक्षाओं को रोकने में संयुक्त राष्ट्र अपेक्षित भूमिका नहीं निभा पा रहा है और इस परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रभावशीलता में भी सतत कमी आ रही है।

पिछले कुछ वर्षों से कतिपय देशों के बीच चल रहे संघर्ष समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बड़े राष्ट्र हथियारों को बेच पैसा कमाने के लालच में एक तरह से परोक्ष रूप से युद्धों को बढ़ावा दे रहे हैं। आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक संकटों के अलावा मानव जाति अब युद्धों की वजह से पर्यावरण पर मंडराते हुए खतरों से सबसे ज्यादा आशंकित है। पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन बहुत तेजी से और खतरनाक गति से बिगड़ रहा है, जिससे मानव जाति के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। इतना सब होने पर भी हमें निराशा के इस अंधकार से निकलकर आशा के उस उजाले को देखना चाहिए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका युद्धों को रोकने में भी कारगर रही। ऐसे अनेक युद्धों की एक सूची बनाई जा सकती है। पिछली सदी के 5वें दशक में कोरियाई युद्ध हो, फिर स्वेज नहर विवाद हो या फिर कांगो के युद्ध की बात हो- संयुक्त राष्ट्र के प्रयास निश्चित रूप से कारगर रहे। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा भी कुछ अति महत्त्वपूर्ण विवादों में निर्णायक भूमिका निभाई गई जैसे कि इंग्लैण्ड और अल्बानिया के मध्य कोर्फू चैनल विवाद, निकारगुआ और अमरीका के बीच का विवाद ऐसे ही कुछ मामले हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व संकट में होते हुए भी नितांत आवश्यक है। शांति और सुरक्षा की दिशा में इसके द्वारा चल रहे प्रत्यक्ष प्रयासों के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष प्रयासों के रूप में किए जा रहे विकास मूलक, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, नई रिसर्च और तकनीक विकास के लिए आवश्यकता इसे और अधिक सशक्त करने की है। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के संगठन और इसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा की भी आवश्यकता है।

कहीं 'वीटो' का अविवेकपूर्ण, निहित स्वार्थवश किया जा रहा उपयोग तो यूएन को अप्रभावी नहीं बना रहा है? वैश्विक मुद्दों चाहे वह सतत विकास की बात हो, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे हों, मानवाधिकार सम्बन्धी मामले हों या आतंकवाद के विरुद्ध वातावरण और आम सहमति बनाने की बात हो, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अत्यंत रचनात्मक रही है और इन पर सतत काम करने की आवश्यकता है। यह समय की मांग है कि इस संगठन को अधिक सशक्त, सक्रिय और सम्मानीय बनाने के लिए सभी सदस्य देश आगे आएं।

मेडिकल कॉलेजों की फीस नहीं बढ़ाई, लेकिन चार साल में 21 लाख महंगी हो गई एनआरआई कोटे की फीस

निजी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे पर महंगाई की मार

एक्सक्लूसिव

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

डॉलर में छलांग, 2021 में कीमत 74.50 तो इस साल 87.68 रुपए

रायपुर. निजी मेडिकल कॉलेजों में पिछले चार साल से एनआरआई कोटे की फीस एक रुपए नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन फीस 21 लाख रुपए महंगी हो गई है। इसका कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कारण है, डॉलर की लंबी छलांग। चार साल पहले जहां डॉलर की कीमत 74.50 रुपए थी, तो यह अब उछलकर 87.68 भारतीय रुपए हो गई है। छात्रों को वर्तमान कीमत के अनुसार फीस देनी पड़ती है। यही कारण है कि एनआरआई कोटे की पढ़ाई महंगी होती जा रही है। हालांकि इसके बावजूद इस कोटे में प्रवेश के लिए काफी मारामारी है।

मेडिकल कॉलेजों की फीस तय करने का काम फीस विनियामक कमेटी का है। निजी मेडिकल कॉलेजों में 15 फीसदी कोटा एनआरआई के लिए होता है। आश्चर्य की बात है कि पिछले 4 साल से इस कोटे की सालाना फीस 35 हजार यूएस डॉलर है। इस तरह एक साल की फीस 30 लाख 68 हजार 800 रुपए तथा साढ़े 4 साल की फीस 1 करोड़ 38 लाख 9 हजार 600 रुपए होती है। यही फीस चार साल पहले यानी 2021 में 1 करोड़ 16 लाख 92 हजार 800 रुपए थी। तब छात्रों को सालाना 25 लाख 98 हजार 400 रुपए फीस देनी पड़ रही थी। डॉलर की छलांग के कारण एनआरआई कोटे से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को ज्यादा फीस देनी पड़ रही है। डॉलर के मुकाबले रुपए के लगातार टूटने के कारण ऐसा हुआ है। इसमें ट्रंप टैरिफ का भी असर है। प्रदेश के 5 निजी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की 135 सीटें हैं। कांउसिलिंग से जुड़े अधिकारियों के अनुसार एनआरआई कोटे के छात्रों को डॉलर के वर्तमान रेट के अनुसार फीस देनी होती है।

720 में महज 113 नीट स्कोर पर प्रवेश

प्रदेश में इस साल नीट यूजी के 720 में महज 113 नंबर लाने पर भी एनआरआई कोटे के तहत एडमिशन हो गया है। अब तक यह सबसे कम कट ऑफ है। कम स्कोर में एडमिशन मिलने के कारण प्रदेश व पड़ोसी राज्यों के धनाढ्य लोग इस कोटे के तहत एडमिशन दिलातें हैं। प्रदेश में पहले राउंड में 81 में 42 एनआरआई सीटों का आवंटन किया गया था। नीट क्वालिफाइड छात्र ही इस कोटे में प्रवेश के लिए पात्र हैं। दरअसल सीमित सीटें होने के कारण सभी एनआरआई छात्रों को एडमिशन नहीं मिल पाता।

स्पांसर्ड एनआरआई के कारण दूर के रिश्तेदार भी प्रवेश के पात्र

एनआरआई कोटे के लिए क्राइटेरिया में बदलाव किया गया है। पहले केवल माता-पिता के विदेश में रहने पर छात्र एनआरआई कोटे के लिए पात्र था। अब नाना-नानी, चाचा-चाची, ताऊ, मामा-मामी या दूसरे रिश्तेदारों के विदेश में होने पर एनआरआई कोटे के लिए पात्र हैं। एमबीबीएस प्रवेश नियम में दो पीढ़ी पहले तक माता-पिता पक्ष से रक्त संबंध की पुष्टि करने वाला प्रवेश के लिए पात्र है। जैसे माता-पिता, भाई- बहन, उनकी संतान, चाचा, उसकी संतान, मामा, उसकी संतान, मौसी, उसकी संतान, बुआ, उसकी संतान, नाना-नानी, दादा-दादी आदि शामिल हैं। इसके लिए वंशावली प्रमाणपत्र जरूरी है, जो तहसीलदार या उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

पत्रिका ने स्टिंग कर दलालों की सौदेबाजी को किया था उजागर: पत्रिका ने दलालों का स्टिंग कर एनआरआई कोटे के तहत एमबीबीएस सीटों में प्रवेश के लिए हो रही सौदेबाजी को उजागर किया था। 8 जुलाई के अंक में 5 लाख दें, सीट पक्की, मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिलाने का दावा शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। यही नहीं 9 जुलाई को निजी मेडिकल कॉलेजों में स्टेट व मैनेजमेंट कोटे की फीस समान, फिर भी एजेंट कर रहे एक करोड़ में सौदे शीर्षक से समाचारों की श्रृंखला प्रकाशित की थी। दलालों ने एक करोड़, एक करोड़ 10 लाख व सवा करोड़ में एनआरआई की सीट पक्की करने का झांसा दे रहे थे। इसके लिए वे 5 लाख एडवांस जमा करने को कह रहे थे। उनका यह भी दावा था कि बिना बुकिंग सीट कंफर्म नहीं हो सकती। हालांकि चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों ने दलालों के दावों को सिरे से खारिज कर दिया था। उनका कहना है कि मेरिट सूची से ही प्रवेश दिया जाता है।

> एनआरआई कोटे की फीस अभी नहीं बढ़ाई गई है। छात्रों को वर्तमान बाजार दर के हिसाब से एमबीबीएस की फीस भरनी होती है। इसलिए डॉलर की छलांग के कारण फीस काफी बढ़ गई है।
> **-डॉ. यूएस पैकरा,** डीएमई, छत्तीसगढ़

> एनआरआई कोटे में प्रवेश के लिए काफी मारामारी है। फीस विनियामक कमेटी ने कोई फीस नहीं बढ़ाई है। विश्व में डॉलर की लंबी छलांग व रुपए में गिरावट के कारण फीस बढ़ी है।
> **- डॉ. देवेंद्र नायक,** चैयरमेन, श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज

प्रदेश में खुलेंगे 6 नए फिजियोथैरेपी कॉलेज

पढ़ाई अगले साल से, प्रत्येक कॉलेज के निर्माण की लागत 13 करोड़ 93 लाख 71 हजार रुपए

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रायपुर. प्रदेश में 6 सरकारी फिजियोथैरेपी कॉलेज बनेगा। प्रत्येक कॉलेज 13 करोड़ 93 लाख 71 हजार रुपए की लागत से बनाया जाएगा। हालांकि पढ़ाई अगले साल से शुरू होने की संभावना है। ये कॉलेज मनेंद्रगढ़, जशपुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग एवं जगदलपुर में खुलेंगे।

सभी कॉलेजों के लिए 83 करोड़ 62 लाख 26 हजार रुपए की राशि मंजूर की गई है। अभी रायपुर में एकमात्र सरकारी फिजियोथैरेपी कॉलेज है। जबकि प्रदेश में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों का संचालन किया जा रहा है। कायदे से सभी मेडिकल कॉलेज वाले स्थानों पर फिजियोथैरेपी कॉलेज होना चाहिए। दरअसल अब हड्डी के अलावा ज्यादातर बीमारियों में इलाज के पहले या बाद में फिजियोथैरेपी कराने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए बीपीटी या एमपीटी डिग्रीधारी फिजियोथैरेपिस्ट की जरूरत होती है। न्यूरो सर्जरी के मरीज यानी लकवा, ऑब्स एंड गायनी में डिलीवरी के पहले व बाद में फिजियो का सुझाव दिया जाता है।

संगठन से मोहभंग, नक्सली कर रहे आत्मसमर्पण : साय

रायपुर@पत्रिका. प्रदेश में नक्सलियों के आत्मसमर्पण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, राज्य में नक्सलियों की विचारधारा से मोहभंग हो रहा है और अब वे मुख्यधारा में लौटने का निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने कांकेर जिले में जल्द ही और भी कई नक्सलियों के आत्मसमर्पण की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री साय ने यह बात रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा, सरकार ने शुरू से ही नक्सलियों से संवाद और सुधार की नीति अपनाई है। हमने नक्सलियों से कहा था कि गोलीबारी से कुछ हासिल नहीं होगा। हिंसा छोड़कर अगर वे विकास और शांति की राह पर चलें, तो सरकार उन्हें पूरा सहयोग देगी। साय ने कहा, राज्य सरकार नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर दे रही है।

सनसनी : पीड़ित महिला का फोटोग्राफ, वीडियो और फोन की टाइमिंग समेत अन्य दस्तावेज होने का दावा

एसआई की पत्नी का आईपीएस डांगी पर यौन उत्पीड़न का आरोप, जांच टीम गठित

- आईपीएस डांगी ने कहा- परेशान करने की झूठी शिकायत
- डीजीपी अरुणदेव ने दिए जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

रायपुर. राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी के निदेशक और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी पर सब-इंस्पेक्टर की पत्नी ने यौन उत्पीड़न और शारीरिक शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। अपने शिकायती पत्र में महिला का दावा है कि पिछले 7 साल से उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। जिसमें आईजी द्वारा दबाव बनाकर घर और अन्य स्थानों में बुलाने, योग सिखाने के बहाने उत्पीड़न करने, फोटोग्राफ, फोन की टाइमिंग और वीडियो सहित अन्य दस्तावेज भी इसका साक्ष्य उसके पास है। उक्त सभी को शिकायत के साथ डीजीपी को सौंपा गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी अरुणदेव गौतम द्वारा दो सदस्यीय टीम को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही इसकी रिपोर्ट जल्द देने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि रतनलाल डांगी भारतीय पुलिस सेवा 2003 बैच के अधिकारी हैं। शिकायत के संबंध में आईपीएस रतनलाल डांगी ने कहा कि उन्हें परेशान करने के लिए महिला झूठे आरोप लगा रही है। जबकि 15 अक्टूबर को पहले ही डीजीपी अरुणदेव गौतम को लिखित शिकायत कर चुके है। सब-इंस्पेक्टर की पत्नी पिछले कई वर्षों से उन्हें ब्लैकमेल कर रही है और उनके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है।

महिला आईएएस की अध्यक्षता में जांच की चर्चा: मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी वरिष्ठ महिला आईएएस को टीम में शामिल किए जाने की चर्चा चल रही है। उसकी अध्यक्षता में टीम जांच करेगी। ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के साथ ही किसी भी तरह का आरोप न लगे। राज्य पुलिस के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि आरोप लगाने वाली महिला की शिकायत उसी पुलिस महकमे के अधिकारी द्वारा करने से विवाद की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। इसे देखते हुए किसी महिला आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में मामले की जांच कराने की कवायद चल रही है।

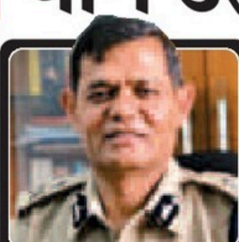

महिला की शिकायत

महिला का आरोप है कि सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक कई बार वीडियो कॉल पर नजर रखने का दबाव डालते थे। शिकायत में लिखा है कि वह अब तक चुप रही क्योंकि उसके पति की नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। विरोध करने धमकी देते थे कि 'अगर तुमने विरोध किया तो तुम्हारे पति को नक्सल क्षेत्र में तबादला कर दूंगा। प्रताड़ना से तंग आकर आइजी से दूरी बनाने की कोशिश करने पर धमकियों और दबाव के जरिए संबंध बनाए रखने को मजबूर किया गया।

परेशान होकर डीजीपी से शिकायत

आईजी रतनलाल डांगी के डीजीपी को लिखे पत्र के प्रमुख बिंदु

महिला जहर की शीशी लेकर कार्यालय आई और मुझे अपनी पत्नी से संबंध न रखने की कसम खिलवाई। उसने कई शर्तें रखीं, पत्नी से बात नहीं करना, तस्वीर नहीं खिंचवाना, जन्मदिन या सालगिरह नहीं मनाना। साथ ही कहा कि रात में बालकनी में सोऊं और आठ घंटे तक लाइव लोकेशन और वीडियो कॉल चालू रखूं ताकि उसे भरोसा रहे कि मेरे साथ कोई नहीं है। नहाते समय, व्यायाम और वॉशरूम जाते समय भी वीडियो कॉल चालू रखे। उसने वाशरूम में फोटो लिए और दिखाकर धमकाया कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो तस्वीरें वायरल कर देगी। विरोध करने पर उसने ब्लेड से खुद का हाथ काटा और आत्महत्या का नाटक किया ताकि मैं डर जाऊं। शिकायत में जहर की शीशी लेकर कार्यालय आने और कहे अनुसार बात नहीं मानने पर आत्महत्या कर मुझे फंसा देने का ब्योरा दिया गया है। उसने मेरी पत्नी और बेटों से मुझे अलग कर दिया। मैं पिछले दो वर्षों से अपने घर में मानसिक अवसाद में जी रहा हूं। करवा चौथ के दिन उसने धमकी दी।

7 प्रमुख बिंदुओं पर जांच के निर्देश

शिकायत के आधार पर टीम ने 7 प्रमुख बिंदुओं पर जांच कर रही है। इसमें शिकायत का आधार, आवेदन में लगाए गए आरोप और साक्ष्य, डिजिटल साक्ष्य, फोटोग्राफ, वाइस कॉल, मोबाइल नंबरों की जांच, टाइमिंग, वीडियो फुटेज, अन्य गवाहों के बयान, आरोप की सत्यता के साथ ही मौखिक और लिखित आरोप को जांच के दायरे में लिया गया है।

> *चाहे कोई भी अधिकारी हो। अगर आरोप लगे हैं तो उस पर जांच होगी, और अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो निश्चित ही कार्रवाई होगी।*
> **-विष्णुदेव साय,** मुख्यमंत्री

उत्पीड़ित महिला ने लगाए ये आरोप कहा-वीडियो कॉल से करते थे परेशान

महकमे के एक सब-इंस्पेक्टर की पत्नी ने आला अधिकारियों को दिए पत्र में आरोप लगाया कि आईजी रतनलाल डांगी 7 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया। महिला ने कहा कि जब उसने अधिकारी से दूरी बनाने की कोशिश की, तो उस पर धमकियों और दबाव के जरिए संबंध बनाए रखने को मजबूर किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब वह सरगुजा में आईजी थे, तभी उत्पीड़न की शुरुआत हुई और बिलासपुर आईजी बनने के बाद यह सिलसिला और बढ़ गया। महिला का कहना है कि अधिकारी अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में उसे बंगले पर बुलाते थे और आपत्तिजनक हरकतें करते थे। चंदखुरी पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में तबादला होने के बाद भी वे वीडियो कॉल के जरिए परेशान करते थे।

दो सदस्यीय टीम करेगी मामले की जांच

डीजीपी ने पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए 2001 बैच के आईजी आनंद छाबड़ा और एआईजी मिलना कुर्रे को जांच के जिम्मेदारी सौंपी है। दो सदस्यीय टीम पूरे प्रकरण की जांच करने करने के साथ ही आरोप लगाने वाली महिला, आईपीएस रतनलाल डांगी और इससे जुड़े हुए सभी उभय पक्षों से पूछताछ कर बयान लेंगे। साथ ही शिकायती आवेदन, फोटो, डिजिटल साक्ष्य की फोरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा जाएगा।

विभागीय लापरवाही से गायों की मौत, पशु चिकित्सा विभाग सचिव को जवाब देने के निर्देश

बिलासपुर @ पत्रिका. हाईकोर्ट ने विभागीय लापरवाही से गायों की मौत होने के मामले में संज्ञान लेते हुए पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव से शपथपत्र पर जवाब मांगा है। मामले में 27अक्टूबर को अगली सुनवाई रखी गई है।

बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक के बेलतरा और सुकुलकारी क्षेत्र में मवेशियों के लिए बनाए गए आश्रय स्थल में गायों की लगातार मौत हो रही है। अस्थायी रूप से रखे गए मवेशी उचित प्रबंधन, भोजन, पानी और चिकित्सा देखभाल के अभाव में मर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, बेलतरा में एक दर्जन से अधिक और सुकुलकारी में 4 गायों की मौत हो चुकी है, लेकिन पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी इस बारे में अनभिज्ञ हैं। इस बीच, विभाग पर निष्क्रियता और असंवेदनशीलता का आरोप लगाया जा रहा है। बड़ी संख्या में गायों की मौत ने पशु चिकित्सा विभाग की उदासीनता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गायों को बेतलारा के मिनी स्टेडियम के एक दलदली और कीचड़ भरे कमरे में रखा गया था।

स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि, लगभग 10 दिन पहले मवेशियों के उचित प्रबंधन और देखभाल, तथा पर्याप्त भोजन-पानी के अभाव में एक दर्जन से ज्यादा गायों की मौत हो गई थी। मवेशियों के लिए न तो भोजन की व्यवस्था है और न ही चिकित्सा की।

परेशानी : हाफ बिजली बिल योजना का दायरा सीमित करने से दोहरी मार झेल रहे उपभोक्ता

बिजली बिल में आ रही भारी गड़बड़ी, ऑनलाइन में ज्यादा

रायपुर @ पत्रिका. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (सीएसपीडीसीएल) में बिजली बिल भेजने को लेकर भारी गड़बडी चल रही है। रीडिंग लेने वाले कर्मचारियों द्वारा फिजिकल बिल कम रुपए का दिया जा रहा है। वहीं, जब उपभोक्ता अपने बीपी नंबर का बिल ऑनलाइन ऐप में चेक करता है, तो उसका ज्यादा दिखा रहा। कुछ उपभोक्ताओं के यहां ज्यादा खपत होने के बाद भी 40-50 रुपए का फिजिकल बिल अक्टूबर माह में आया है। जबकि, ऐप में बिजली बिल शून्य दिखा रहा है। इससे आम उपभोक्ता बेहद परेशान हैं और बिजली कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। बिजली बिल की गड़बड़ी के संबंध कई उपभोक्ताओं ने पत्रिका को फोन कर ऐसे मामलों को बताया है।

भुगतान के बाद भी ऐप में बकाया दिखा रहा: किसी-किसी उपभोक्ता के यहां तो बिजली बिल का भुगतान करने के बाद भी ऐप में पुराना भुगतान बकाया दिखा जा रहा है। ऐसा मामला सड्डू मोवा इलाके में देखने को मिला है। उपभोक्ता ने पिछला भुगतान ऐप के जरिए कर दिया था। लेकिन, अक्टूबर माह में जो बिल आया है, उसमें पिछला बकाया दिखा रहा है।

हॉफ बिजली योजना का दायरा सीमित होने से लोगों का बिल दोगुना से ज्यादा आने लगा है। ऐसे में इसका बोझ किराए पर रहने वाले लोगों पर आ रहा है। मकान मालिक जो पहले 5-6 रुपए प्रति यूनिट खपत का बिल लेता है। अब उसने बढ़ाकर 8-9 रुपए प्रति यूनिट कर दिया है। इससे किराएदार परेशान हैं।

फिजिकल बिल

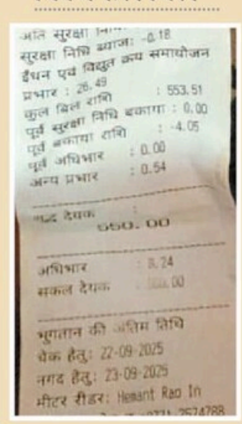

केस-1: शिवानंद नगर के महादेव सरकार नाम के उपभोक्ता का फिजिकल बिल 104 यूनिट खपत का 550 रुपए आया है। जबकि, ऐप में बिजली बिल 1900 रुपए दिखा रहा है। अब उपभोक्ता परेशान है कि भुगतान फिजिकल बिल का करे या ऐप में जो बकाया दिखा रहा है उसका करे।

केस- 2: भीमनगर के एक उपभोक्ता के यहां 1 किलोवाट का कनेक्शन है। उसके यहां फिजिकल बिजली बिल ऊपर 240 रुपए है और नीचे टोटल में 40 रुपए बकाया दिखा रहा है। जबकि, ऐप में कुछ भी बकाया दिखा ही नहीं रहा है। ऐसे में उपभोक्ता बिजली बिल भरने से परेशान है।

उपभोक्ता क्या करे, समझ नहीं आ रहा

बिजली बिल में मिल रही गड़बड़ी से उपभोक्ता काफी परेशान हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वे क्या करें। बिल का भुगतान करें या बाद में करें। इस संबंध में शिकायत कहां पर करें। टोल फ्री नंबर में या बिजली कार्यालयों में। उपभोक्ताओं का कहना है कि सीएसपीडीसीएल को ऐसी गड़बड़ी की शिकायत के लिए एक व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे उपभोक्ता की समस्याओं का तत्काल निराकरण हो।

नारायणपुर : टार्च की रोशनी में हो रहा इलाज

अबुझमाड़ के रेकावाया और घोट गांव में उल्टी-दस्त से पांच ग्रामीणों की मौत

नारायणपुर @ पत्रिका. अबुझमाड़ क्षेत्र के रेकावाया और घोट गांव में उल्टी-दस्त से पांच ग्रामीणों की मौत हो गई है। तीन दिनों से इस बीमारी ने इलाके में कहर बरपा रखा है। जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम बुधवार देर रात घोट गांव पहुंची और झोपड़ी में संचालित स्कूल में अस्थायी शिविर लगाकर इलाज शुरू किया गया। गांव में बिजली व अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव में टीम टार्च की रोशनी में मरीजों का उपचार कर रही है। गंभीर रूप से बीमार ग्रामीणों को भैरमगढ़ स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार, अबुझमाड़ के दुर्गम डूंगा ग्राम पंचायत के घोट और रेकावाया गांव में उल्टी-दस्त के लक्षण तीन दिन पहले दिखने लगे थे।

अस्थाई स्वास्थ्य शिविर में इलाज करते स्वास्थ्यकर्मी।

कई और ग्रामीण बीमार, भर्ती

इलाज के अभाव में कई ग्रामीण गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है। नेटवर्क की कमी से जानकारी देर से मिली, लेकिन अब इलाज और आवश्यक जांचें जारी हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों से साफ पानी उपयोग करने और संदिग्ध लक्षण दिखने पर तुरंत जानकारी देने की अपील की है।

कमी | मेडिकल टीचर को जाना पड़ता है कटक व चेन्नई

एडवांस ट्रेनिंग सेंटर के लिए तरस रहा छत्तीसगढ़

प्रदेश में एक भी रीजनल मेडिकल एजुकेशन सेंटर नहीं

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रायपुर. छत्तीसगढ़ एक एडवांस ट्रेनिंग सेंटर के लिए तरस रहा है। प्रदेश के 15 मेडिकल कॉलेजों की फैकल्टी के लिए एक भी एडवांस ट्रेनिंग सेंटर नहीं होने से समय और खर्चा ज्यादा लगता है। डॉक्टरों को बेसिक के साथ एडवांस कोर्स के प्रशिक्षण के लिए कटक व चेन्नई जाना पड़ रहा है। ट्रेनिंग के लिए उन्हें छुट्टी लेकर जाना पड़ता है। इससे मरीजों का इलाज, बल्कि छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है।

प्रदेश को एक रीजनल सेंटर फॉर मेडिकल एजुकेशन की जरूरत है। यहां एमबीबीएस व पीजी के छात्रों को सरल तरीके से कैसे पढ़ाया जाए, इसकी ट्रेनिंग होती है। अभी ओडिशा के कटक में रीजनल सेंटर है। सड़क मार्ग से रायपुर से इसकी दूरी 543 किमी है। जबकि अंबिकापुर, राजनांदगांव व अन्य कॉलेजों से इसकी दूरी और ज्यादा है। नोडल सेंटर चेन्नई में है। रायपुर से चेन्नई की दूरी 1192 किमी है। डॉक्टरों का कहना है कि रीजनल सेंटर के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन को आवेदन किया गया है। नेहरू मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन एनएमसी क्यों मान्यता नहीं दे रही है, यह सोचने वाली बात है। जबकि कॉलेज को खुले 60 साल से ज्यादा हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी व दूसरी सुविधाओं को देखते हुए आने वाले दिनों में नेहरू मेडिकल कॉलेज में यह सेंटर खुल सकता है।

विषय काफी कठिन इसलिए ट्रेनिंग की जरूरत

डॉक्टरों का कहना है कि एमबीबीएस व पीजी में कई विषय काफी कांप्लीकेटेड होते हैं। उन्हें कैसे अपग्रेड के साथ पढ़ाएं, इसकी ट्रेनिंग टीचर को सेंटर में दी जाती है। उदाहरण के लिए हार्निया का केस काफी कांप्लीकेटेड होता है। हालांकि जनरल सर्जन के लिए यह ऑपरेशन क्रिटिकल नहीं होता, लेकिन छात्रों को बेहतर ज्ञान के लिए थ्रीडी एनीमेशन में पढ़ाने की जरूरत है। इससे छात्र बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। केवल किताबी ज्ञान से इसे समझने में परेशानी होगी। बिना प्रेक्टिकल भी समझने में दिक्कत होती है। नोडल सेंटर चेन्नई में कैरीकुलम कैसे बनाया जाए, समेत कई जरूरी चीजों की ट्रेनिंग दी जाती हैं। टीचिंग के बेहतर तरीके क्या हो, कैसे-कैसे हों, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है।

> रीजनल सेंटर फॉर मेडिकल एजुकेशन के लिए प्रयास किया जा रहा है। सेंटर के लिए कॉलेज में जरूरी सुविधाएं जुटाई गई हैं। यहां सेंटर खुलने की पूरी संभावना है।
> **-डॉ. विवेक चौधरी,** डीन, नेहरू मेडिकल कॉलेज

नीट पीजी एमडी-एमएस की काउंसलिंग शुरू नहीं

रायपुर@पत्रिका. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) ने 25 अगस्त को नीट यूजी का रिजल्ट घोषित कर दिया था, लेकिन छत्तीसगढ़ समेत किसी भी राज्य में पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। इससे सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में फर्स्ट ईयर के छात्र नहीं पहुंचे हैं। ये छात्र सर्जरी से लेकर ओपीडी में इलाज में कंसल्टेंट डॉक्टरों की मदद करते हैं। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज सेकंड व फाइनल ईयर के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। पीजी में एमडी-एमएस कोर्स होता है।

एनएमसी की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) जल्द ही पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर सकती है। जिन अभ्यर्थियों ने नीट पीजी एग्जाम में भाग लिया था वे एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी उम्मीदवारों को तय समय-सीमा के भीतर च्वाइस फिलिंग और च्वाइस लॉकिंग करना अनिवार्य होगा। रैंक के अनुसार छात्रों को कॉलेज अलॉट कर एमडी-एमएस कोर्स में एडमिशन दिया जाएगा। इस साल भी जनरल व ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कट ऑफ 50 परसेंटाइल एवं स्कोर 276, जनरल पीडब्ल्यूबीडी के लिए पर्सेंटाइल 45 एवं स्कोर 255, एससी/एसटी / ओबीसी के लिए कट ऑफ 40 पर्सेंटाइल और स्कोर 235 निर्धारित किया गया है।

महाडमध्ये खैराची वाहतूक करणारा टेम्पो ताब्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

महाड : महाड तालुक्यातील शिरगाव चेकपोस्ट येथे मंगळवारी मध्यरात्री महाड शहर पोलिसांनी नाकाबंदी केली होती. या नाकाबंदीत जीपची तपासणी केली. त्यावेळी चालकाने पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी त्याचा पाठलाग करून पकडले. या तपासणीत जीपमध्ये जंगली खैराची लाकडे आढळली.

महाड शहर पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी मध्यरात्री तालुक्यातील शिरगाव चेक पोस्ट येथे महाड शहर पोलिसांची नाकाबंदी सुरू होती. या नाकाबंदीत पोलिस पथकाने पिकअप जीप थांबविली. मात्र, जीपचालक पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता. त्यावेळी पोलिसांनी जीपचालकाचा पाठलाग करुन त्याला पकडले. या जीपमध्ये जंगली खैर लाकूड सापडली. त्याची अंदाजे किंमत एक लाख ५० हजार रुपये, जीपची किमत तीन लाख ५० हजार रुपये असा एकूण अंदाजे पाच लाख किमतीचा माल मिळून आला. याप्रकरणी जीपचालक देवा शिवाजी पडळकर (वय ४२) आणि आकाश कुंडलीक पडळकर (वय २८, दोन्ही रा. पडळकरवाडी, मुळशी, पुणे) यांना ताब्यात घेऊन पुढील कारवाई करण्यात आली आहे.

आजचे भविष्य

विजय देशपांडे (ज्योतिषविशारद)

शुक्रवार, दि. २४ ऑक्टोबर २०२५
राष्ट्रीय भारतीय सौर दिनांक कार्तिक २, १९४७. **तिथी :** कार्तिक शुक्ल तृतीया (दुसऱ्या दिवशी उत्तर रात्री १.२० पर्यंत) शालिवाहन शके १९४७. विश्वावसू नाम संवत्सर. नक्षत्र : अनुराधा (अहोरात्र).
रास : वृश्चिक. **आज :** चांगला दिवस. **राहू काळ :** सकाळी १०.३० ते १२. (राहू काळात महत्त्वाची कामे टाळा.)

मेष — **महत्त्वाच्या कामात अडथळा येऊ शकतो.** त्यामुळे आपण घाईघाईत कामे उरकण्याचा प्रयत्न करू नका. जीवनसाथीची मर्जी राखा. आपल्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. कार्यक्षेत्रात चांगली परिस्थिती राहील. मात्र, सतत प्रयत्न करावे लागतील.

वृषभ — **मनात सकारात्मक विचार राहतील.** तुमच्या समोरील अनेक अडचणी दूर होतील. जीवनसाथीची चांगली साथ राहील. तरुणवर्गाला प्रेमात अपेक्षित प्रतिसाद मिळेल. नोकरीत तुमचे पारडे जड राहील. विद्यार्थ्यांना अनुकूल काळाचा अनुभव येईल.

मिथुन — **संमिश्र ग्रहमानाचा अनुभव येईल.** आपण ठरवलेले एखादे काम रखडले जाऊ शकते. एखाद्या व्यक्तीकडून अपेक्षाभंग होऊ शकतो. आरोग्याच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करू नका. आपले पत्ते लोकांसमोर उघड करून दाखवणे टाळा.

कर्क — **हाती घ्याल ते तडीस न्याल अशी परिस्थिती राहील.** नोकरीत तुमचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्यात यश मिळेल. अधिकारीवर्गाचे चांगले सहकार्य मिळेल. जबाबदारीचे काम यशस्वीपणे पूर्ण कराल. काहींना जवळच्या प्रवासाचे योग येतील.

सिंह — **कार्यक्षेत्रात तुमच्या कर्तृत्वाला वाव राहील.** नवीन काहीतरी करून दाखवण्याची जिद्द राहील. नवीन नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना योग्य संधी मिळेल. घरात एखाद्या कार्यक्रमानिमित्त पाहुणे मंडळी येतील. आर्थिक आवक चांगली राहील.

कन्या — **ग्रहमानाची चांगली साथ तुम्हाला मिळेल.** व्यवसायात भरभराट होईल. पैशांचा ओघ सुरू राहील. वडीलधाऱ्या मंडळींकडून आशीर्वाद मिळेल. आवडत्या भोजनाचा आस्वाद घेता येईल. मोठी आर्थिक गुंतवणूक करताना खबरदारी घ्या.

तूळ — **महत्त्वाची कामे हातावेगळी कराल.** कामात उत्साह राहील. धनलक्ष्मीची तुमच्यावर प्रसन्नता राहील. आवडत्या खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेता येईल. थोरा मोठ्यांच्या ओळखीचा फायदा होईल. जीवनसाथीशी मधुर शब्दांत संभाषण करा.

वृश्चिक — **तुमच्या अनेक अडचणी दूर होतील.** मात्र, मनात काही शंका असतील. आर्थिक प्राप्तीचे प्रमाण चांगले राहील. काहींना भेटवस्तू मिळतील. तरुण वर्गाला प्रेमात प्रतिसाद मिळेल. जीवनसाथीच्या मर्जीनुसार वागले पाहिजे. किरकोळ कारणाने गैरसमज होतील.

धनू — **संमिश्र ग्रहमानाचा अनुभव येईल.** तुमच्या समोर काही अडचणी असतील. नोकरीत चांगली परिस्थिती राहील. अधिकारी व सहकारीवर्गाची चांगली साथ राहील. अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवा. प्रयत्नपूर्वक मनावर ताबा ठेवणे आवश्यक आहे.

मकर — **तुमच्यावर धनलक्ष्मीची कृपा राहील.** विविध प्रकारचे लाभ होतील. भेटवस्तू प्राप्त होतील. महत्त्वाच्या कामात सफलता मिळेल. मित्र- मैत्रिणींच्या भेटी होतील. नोकरीत तुमचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्यात यश मिळेल. मन आनंदी राहील.

कुंभ — **नोकरीत नवीन प्रकल्पासाठी तुमच्या नावाचा विचार केला जाईल.** त्यामुळे तुमचा उत्साह वाढेल. मात्र, कामांचे नियोजन नीट केले पाहिजे. ऐनवेळी नियोजित कार्यक्रमात बदल होऊ शकतात. त्यामुळे तुम्हाला दगदग होईल. घरी पाहुणे मंडळी येतील.

मीन — **भाग्याची चांगली साथ तुम्हाला मिळेल.** तुमच्यासमोरील अनेक अडचणी दूर होतील. त्यामुळे तुम्हाला हलके हलके वाटेल. मौजमजा करण्यासाठी वेळ मिळेल. समाजात तुमचे महत्त्व सर्वांच्या लक्षात येईल. विद्यार्थ्यांना अनुकूल काळ आहे.

महापालिका अधिकाऱ्यांच्या नावाने बनावट नियुक्ती आदेश

३१ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचा उल्लेख : अतिरिक्त आयुक्तांच्या नावाचा वापर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी मुंबई : महापालिकेच्या आरोग्य विभागात ३१ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाल्याचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांच्या सहीचे पत्र समाज माध्यमांमध्ये फिरत आहे. वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रशांत जवादे यांच्या सहीचे दस्तऐवज पडताळणीचे पत्रही व्हायरल होत आहे. ही सर्व पत्रे बनावट असून उमेदवारांची दिशाभूल करणारी आहेत. कोणीही या पत्रांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन पालिका प्रशासनाने केले आहे.

नवी मुंबई महापालिकेने ६६८ पदांसाठी नोकरी भरतीप्रक्रिया राबविली आहे. यासाठी घेतलेल्या परीक्षेचा निकाल प्रतीक्षेत आहे. दरम्यान ८ ऑक्टोबरला वैद्यकिय आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रशांत जवादे यांच्या नावाने काही उमेदवारांना बनावट पत्र पाठविण्यात आले आहे. यामध्ये पालिकेच्या भरतीप्रक्रियेत आपली निवड झाली असून आपले अभिनंदन. नियुक्तीपत्र पोस्टाने आपणास पाठविण्यात येणार असून त्यामध्ये वेतन व इतर तपशील देण्यात येणार, असा मजकूर आहे. पत्राच्या वर दस्तऐवज पडताळणी मंजुरी पत्र असा उल्लेख केला आहे. १८ ऑक्टोबरला अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांची सही असलेले बनावट पत्र तयार केले आहे.

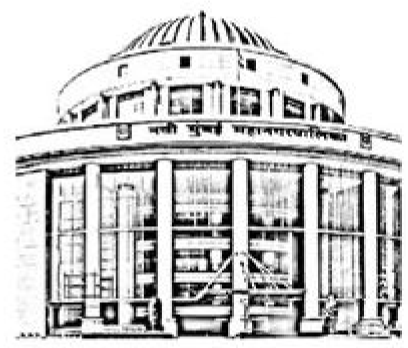

२०२५
आदेशानुसार स्टाफ नर्स, नर्सिंग ब्रदर्स या पदांसाठी ३१ उमेदवारांची निवड केली आहे. सर्व उमेदवारांनी आरोग्य केंद्र किंवा उपजिल्हा रुग्णालय येथे हजेरी लावून हजर व्हावे व स्थानिक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कळवावे, असा उल्लेख केला आहे. निवडलेल्या ३१ जणांची यादी जोडली आहे.

उमेदवारांनी सावध राहण्याचे आवाहन

महापालिका प्रशासनाने स्टाफ नर्स, नर्सिंग ब्रदर्स या पदासाठी निवड झाल्याचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील पावार यांची सही असलेले खोटे आदेश समाज माध्यमांतून फिरत आहेत. अशा प्रकारचे कोणतेही आदेश मनपाने जाहीर केलेले नाहीत. या खोट्या आदेशांबाबत मनपाने आरोग्य विभागाने पोलिस ठाण्यात रितसर तक्रार दिली आहे.

नागरिकांनीही या खोट्या वृत्तावर विश्वास ठेवू नये. पालिकेच्या ६६८ पदांकरीता परीक्षा घेतली असून त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या खोट्या आदेशाचा त्या भरती प्रक्रियेशी काहीही संबंध नाही. भरतीबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती मनपाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून पडताळून पाहावी, असे आवाहन केले

ही दोन्ही पत्र बोगस असून अशाप्रकारे आरोग्य विभागात नियुक्ती केलेली नाही. मनपाने घेतलेल्या परीक्षेचा निकाल अद्याप प्रकाशित केलेला नाही.

अष्टविनायक चौकात दीपोत्सव धडाक्यात

ठाण्याच्या पूर्व विभागातील अष्टविनायक चौकात बुधवारी श्री साई दहिकाला उत्सव मंडळाच्या वतीने दीपोत्सव झाला. मंडळाचे हे २६ वे वर्ष असून, या वर्षीही पारंपरिक उत्साहात दीपोत्सव साजरा करण्यात आला. पावसाच्या गोंधळामुळे सुरुवातीला नागरिकांमध्ये काहीशी नाराजी दिसली. कलाकारांच्या उत्कृष्ट सादरीकरणामुळे कार्यक्रमाचे वातावरण रंगतदार झाले. दिव्यांच्या प्रकाशात चौक न्हाऊन गेला होता. छाया : विशाल हळदे

'नित्य'च्या जागरूकतेमुळे चिमणीचा जीव वाचला

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : फटाक्यांच्या आवाजामुळे प्राणी आणि पक्षी घाबरून जातात. अशा वातावरणात भांडुप येथील नित्य वरांग हिने तिच्या घराजवळ घरट्यातून खाली पडलेली चिमणी पाहिली. क्षणाचाही विलंब न करता तिने वडील निलेश यांच्या मदतीने चिमणीला सावधगिरीने उचलून प्राण्यांच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या नीशा कुंजु यांच्याकडे नेले. नीशा यांनी तत्परतेने चिमणीला पुन्हा तिच्या घरट्यात सुरक्षितपणे ठेवले. त्यामुळे चिमणीचा जीव वाचला आहे.

रस्ता ओलांडताना कारच्या धडकेत पादचाऱ्याचा मृत्यू

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी मुंबई : भरधाव कारच्या धडकेत पादचारी तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना बुधवारी मध्यरात्री घडली. कन्हैया बिंद (२९) असे अपघातात मृत झालेल्याचे नाव आहे. अपघातप्रकरणी कारचालक हामद अब्दुल रहीम सय्यद याच्यावर गुरुवारी सकाळी एपीएमसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदण्यात आला आहे.

कन्हैया बिंद कोपरी येथे राहत होता. बुधवारी मध्यरात्री मित्रांसह परिसरात फिरत होता. यावेळी तो रस्ता ओलांडत असताना त्याला काहीतरी आठवल्याने

पुन्हा मागे आला. त्याच वेळी भरधाव कारने त्याला जोराची धडक दिली. यामध्ये तो काही फुटांपर्यंत उंच उडून रस्त्यावर आपटला. त्याला रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.

पार्किंग केलेली गाडी कोसळली तलावात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवीन पनवेल : पनवेल तालुक्यातील मोहो गावात पार्किंगची सुविधा अपुरी असल्याने तलावाभोवती अनेक जण वाहन पार्किंग करतात. मात्र, हीच सवय एका वाहनचालकासाठी धोकादायक ठरली. हँडब्रेक न लावता पार्किंग केलेली प्रवासी गाडी थेट तलावात कोसळली घटना बुधवारी घडली.

गाडी तलावात कोसळल्याचे समजताच ग्रामस्थांनी जेसीबीच्या

साह्याने दोन तासांच्या प्रयत्नांनंतर गाडी तलावातून बाहेर काढली. गाडीत प्रवासी नसल्याने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, गाडीचे मोठे नुकसान झाले आहे.

कठडे गरजेचे

गावातील मुख्य रस्त्यालगत असलेल्या या तलावाभोवती सुरक्षा कठडे नसल्याने अपघाताचा धोका कायम आहे. रस्ता वळणदार असल्याने वाहनचालकांना वळणाचा अंदाज येत नाही. त्यामुळे कठडे गरजेचे आहेत.

किल्ले बांधणी स्पर्धेत २५ चाळींचा सहभाग

मुंबई : लोअर परळ येथे संयुक्त नवी चाळ उत्सव समिती अंतर्गत पाडव्याच्या दिवशी एका दिवसात गड, किल्ले बनवण्याच्या स्पर्धेत २५ चाळी सहभागी झाल्या. सरकारच्या अमृत संस्थेच्या संकल्पनेतून दीपावलीच्या उत्सवात जे नागरिक महाराजांच्या गड-दुर्ग मातीपासून बनवतात, त्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. 'अमृत'चे मुंबईचे व्यवस्थापक राजेश पवार, अमृत मित्र संतोष नाईक, प्रशांत पळ यांनी गड-दुर्ग बनवणाऱ्या सर्वांचे अभिनंदन केले.

सिडकोच्या तारा प्रशिक्षण केंद्रात चोरीचा प्रयत्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी मुंबई : बेलापूर रेल्वेस्थानक संकुलातील सिडकोच्या तारा प्रशिक्षण केंद्रात मंगळवारी रात्री चोरीचा प्रयत्न झाला. परंतु, तेथील सुरक्षारक्षकांनी हा प्रयत्न हाणून पाडला. सुरक्षारक्षकांनी कार्यालयात घुसलेल्या चोरट्याला पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले.

सुरक्षारक्षकांच्या सतर्कतेमुळे चोरटा जेरबंद, सिडको कार्यालयाच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

मंगळवारी रात्री ९ हा प्रकार घडला. सुरक्षारक्षक आर.के. घरत व एम. एन. घरत यांनी एका अज्ञात व्यक्तीला खिडकीतून आत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करताना पाहिले. यानंतर तत्परता दाखवून त्यांनी त्याला ताब्यात घेऊन सुरक्षा पर्यवेक्षक विशाल घरत यांना माहिती दिली. घरत घटनास्थळी दाखल होऊन त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडे दोन चाकू व पकड सापडली.

चोरीचा प्रयत्न करणारा व्यसनाधीन, गर्दुल्ला

चोरी करणारा व्यसनाधीन (गर्दुल्ला) असून त्याच्याकडे कोणताही चोरीचा मुद्देमाल सापडला नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

असे असले तरी सिडकोच्या महत्त्वाच्या कार्यालयात अशाप्रकारे घुसखोरीचा प्रयत्न होणे, हे सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण करणारे आहे.

त्यामुळे सिडको प्रशासनाने यासंदर्भात कठोर उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे मत सजग नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.

ठाण्यामध्ये ७० कोटींची सोने-चांदीची उलाढाल

दिवाळीत खरेदी : ज्वेलर्स असोसिएशनची माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

ठाणे : यंदाची दिवाळी ठाण्यातील सुवर्णकार आणि ग्राहक दोघांसाठीही 'सोनेरी' ठरली. धनत्रयोदशीपासून पाडव्यापर्यंत सोने-चांदीच्या खरेदीचा उत्साह शिगेला पोहोचला असून, ठाणे शहरात तब्बल ७० कोटी रुपयांची उलाढाल झाल्याची माहिती ठाणे ज्वेलर्स असोसिएशनने दिली.

धनत्रयोदशीच्या दिवशीच सर्वाधिक खरेदी झाली. सोन्याचे दर प्रतितोळा एक लाख १८ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचले असतानाही ग्राहकांनी शुभमुहूर्त साधून मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली. सोन्यापेक्षा चांदीची खरेदी अधिक झाली असून, मुहूर्तावर समई, दिवे, वाटी भेट देण्यासाठी ग्राहकांकडून मोठी पसंती मिळाली. जवळपास ५०० हून अधिक सोने-चांदीची दुकाने दिवाळीमध्ये ग्राहकांनी फुलून गेली. अनेक ठिकाणी ग्राहकांना प्रतीक्षा यादीत उभे राहावे लागले. काही मोठ्या दुकानांनी तर दिवाळीच्या दिवसांतच ४० लाख रुपयांपर्यंत विक्री केली, सरासरी दुकाने १२ ते १५ लाख रुपयांची उलाढाल करीत असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांकडून देण्यात आली. कमलेश जैन यांनी सांगितले की, "या वर्षीच्या धनत्रयोदशीला रेकॉर्डब्रेक खरेदी झाली. सोन्याचे भाव वाढत असतानाही ग्राहकांनी खरेदी थांबविली नाही. लक्ष्मीपूजन आणि पाडव्याच्या दिवशीही सतत गर्दी होती."

ग्राहक वैशाली पेणकर म्हणाल्या, "मी धनत्रयोदशीला ज्वेलरी घेतली. भाव वाढले तरी शुभमूहूर्त साधायचा म्हणून खरेदी केली. दिवाळीत खरेदी न झाल्यास उत्सव अपूर्ण वाटतो." महेंद्र संघवी यांनी सांगितले की, "दसऱ्यापेक्षा दिवाळीला अधिक खरेदी झाली."

जागतिक बाजारातील चढ-उतारांचा थेट परिणाम

दोन महिन्यांपूर्वी मार्केट काहीसे शांत असले तरी सोन्याचा भावाने एक लाख दहा हजारांचा टप्पा ओलांडल्यावर पुन्हा खरेदीचा उत्साह दिसू लागला.

जागतिक सोन्याच्या बाजारात होणाऱ्या चढ-उतारांचा थेट परिणाम भारतीय बाजारावर होत आहे.

सोने-चांदीचा हा 'सोनेरी सीझन' ठाण्यातील व्यापाऱ्यांसाठी उत्साहवर्धक ठरला.

१.१८ लाख रुपये प्रति तोळा सोन्याचा भाव होता.

५०० हून अधिक दुकाने ग्राहकांनी फुलली

ठाण्यातील ५०० हून अधिक दुकाने ग्राहकांनी फुलली

दिवाळीच्या कालावधीत सोन्याचे दर ₹ १.१८ ते ₹ १.३० लाख दरम्यान

चांदीच्या वस्तूंना मोठी मागणी : समई, दिवे, वाटी गिफ्टसाठी पसंती

९० टक्के खरेदी दिवाळीच्या मुख्य दिवसांत एकूण उलाढाल अंदाजे ७० कोटी रुपये

१ हजार ७०३ हेक्टरवरील पिकांचे अवकाळी पावसामुळे मोठे नुकसान

सुरेश लोखंडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क

ठाणे : जिल्ह्यात दोन दिवसांपूर्वी वादळी वाऱ्यासह विजांच्या कडकडाटात आणि ढगांच्या गडगडाटात बरसलेल्या पावसाने शेतकऱ्यांच्या दिवाळीच्या आनंदावर पाणी फेरले. तब्बल एक हजार ७०३ हेक्टर क्षेत्रावरील शेतमालाची हानी झाल्याचा प्राथमिक अंदाज कृषी विभागाने वर्तवला.

जिल्ह्यात यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ३५ हजार ६७६ शेतकऱ्यांचे नऊ हजार ४८० हेक्टर क्षेत्रावरील भात पिकाचे सुमारे ३३ टक्के नुकसान झाले होते. या नुकसानीबाबत कृषी, महसूल व ग्रामविकास विभागाने संयुक्तरित्या पंचनामे करून शासनास अहवाल सादर केला होता. या अहवालाच्या आधारे शासनाने निश्चित दरानुसार आठ कोटी ३७ लाख ५६ हजार रुपयांची मदत वितरित करण्यास मंजुरी दिली. शेतीच्या नुकसानाची ही भरपाई लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याची माहिती ठाणे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रामेश्वर पाचे यांनी दिली.

ठाणे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये शेतात कापून ठेवलेल्या भात पिकांसह भाजीपाल्याचे नुकसान झाले.

Lokmat CLASSIFIEDS classified online क्लिक करा बुक करा http://online.lokmatclassified.com

नोकरीविषयक

पार्ट टाईम जॉब

त्वरित पाहिजेत सेवानिवृत्त, व्हीआरएस, ज्येष्ठ नागरिक, सुशिक्षित गृहिणी, सरकारी, व्यवसायिक, बँकर्स. पगार+ प्रोत्साहन+ पीएफ.+ मेडिकल. पूर्ण/अर्ध वेळ काम. शिक्षण-कमीत कमी 10वी पास - 9821657418 (690814)

अनलिमिटेड अर्निंग महिला आणि पुरुषांसाठी एक्स्ट्रा इन्कम कमवण्याची सुवर्णसंधी. 10 वी पास. वयोमर्यादा 40 च्यापुढे + इतर सुविधा. 8169881070 (691294)

पाहिजेत

वकिलांकडे त्यांचा कोर्टासंबंधित कामाचे सहाय्यक (Legal Assistant) म्हणून काम करून निवृत्त (Retired) झालेला उमेदवार कल्याण जि.ठाणे येथे कामासाठी पाहिजे कामाची वेळ उमेदवाराच्या सोयीनुसार संपर्क : संजय- 9371713917 (690753)

जागा विषयक

फ्लॅट विक्री

1BHK Flat For Sale in Karjat, 16.5 Lakhs, cash sale preferred, call 9867511227. (691260)

व्यवसाय/धंदा

व्यवसाय/धंदा

स्वत:ची टुरिस्ट कार घेऊन दरमहा खात्रीशीर १.५ लाख ते २ लाख चे पॅकिज मिळवा. आम्ही आपला व्यवसाय स्थापित करून देऊ. संपर्क - 7715051159 / 9920925129 (690833)

आरोग्यविषयक

गर्भधारणा

लग्नानंतर लवकर बाळहोण्यासाठी भेटा. चौधरी क्लिनिक, पुणे. 9422282490 www.chaudhariclinic.com (637722)

लोकमत
वाचकांना विनम्र सूचना
लोकमत वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध होणाऱ्या विविध जाहिरातीतील मजकुराची शहानिशा करूनच वाचकांनी त्यासंबंधी आर्थिक व्यवहार करावा. जाहिरातीत आपल्या उत्पादनाच्या संदर्भात वा सेवेच्या संदर्भात जाहिरातदार जे दावे करतात त्याची लोकमत वृत्तपत्र समूह कोणतीही हमी घेत नाही. जाहिरातीत करण्यात आलेल्या दाव्यांची पूर्तता जाहिरातदारांकडून न झाल्यास त्याच्या परिणामाबद्दल लोकमत वृत्तपत्र समूहाचे मुद्रक, प्रकाशक, संपादक व मालक हे जबाबदार राहणार नाहीत, याची कृपया वाचकांनी नोंद घ्यावी.

क्विक Update

पालघर डायरी

कवडासच्या कमळ फुलांना सुगीचे दिवस

कासा : डहाणू तालुक्यातील कासाजवळील कवडास धरणाच्या काठावर उगवणाऱ्या कमळ फुलांना दिवाळीत मुंबई येथील मोठ्या बाजारपेठांमध्ये मोठी मागणी वाढली आहे. वर्षभर येथील महालक्ष्मी मंदिरात विक्रीसाठी ही फुले विक्रीसाठी आणली जातात. स्थानिक बाजारपेठ व शहरात ही मागणी वाढल्याने सध्या कमळाच्या एका फुलाला ५ रुपये भाव मिळत असल्याने धरमपूर, कोसेसरी, भवाडी येथील स्थानिकांना रोजगार मिळाला.

वसई आगाराच्या बसला ‘दे धक्का’

पारोळ : वसई आगाराच्या सर्वच बस नादुरुस्त झाल्या असून सणासुदीच्या दिवसांत त्या मार्गातच बंद पडत आहेत. मंगळवारी वसई आगाराची बंद पडलेली बस सुरू करण्यासाठी प्रवाशांना उतरून बसला धक्का मारावा लागण्याची वेळ आली. त्यानंतरही बस सुरू न झाल्याने प्रवाशांना दुसऱ्या बसने जावे लागले. वसई आगाराची बस मंगळवारी प्रवाशांना घेऊन अंबाडीवरून वसईच्या दिशेने जात असताना पारोळ फाटा येथे आल्यावर बंद पडली होती.

खुनाचा प्रयत्न करणारे दोघे पोलिसांच्या ताब्यात

मीरा रोड : भाईंदर पश्चिमेस भोला नगर स्मशानभूमीजवळ विष्णू ब्रह्मदेव तिवारी व त्याचा भाऊ महेश हे राहतात. पूर्वीच्या भांडणाचा राग धरून अभिषेक विनय मिश्रासह त्याचा भाऊ अनमोल व अनुष मिश्रा या तिघांनी त्या दोघा भावांना ठार मारण्याच्या हेतूने बांबूने मारहाण करून चाकूने वार करत विष्णू व महेश यांना जखमी केले. याप्रकरणी भाईंदर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अभिषेक व अनमोल मिश्रा या दोघांना अटक करण्यात आली आहे.

अत्याचारप्रकरणी काशिगाव पोलिसांत गुन्हा

मीरा रोड : लग्नाचे प्रलोभन दाखवून घरकाम करणाऱ्या तरुणीवर अत्याचार करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. मीरा रोडच्या काशिगाव येथील एका २६ वर्षीय घरकाम करणाऱ्या तरुणीला लग्न करण्याचे प्रलोभन दाखवून जुलै २०२५ पासून इंद्रजीत दिनेश चौहान (वय २५, रा. डाचकुल पाडा, काशिगाव) याने वेळोवेळी अत्याचार केला. त्यानंतर तो पसार झाला आहे. याप्रकरणी २० ऑक्टोबरला काशिगाव पोलिस ठाण्यात चौहान विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

लागले दिवे दारी, उजळल्या ज्योती... रंगात रंगली रांगोळी

दिवाळी सण मोठा, नाही आनंदाला तोटा... काढुनिया रांगोळी दारी, जणू लक्ष्मी येई घरी... दिवाळीत घरोघरी विविधांगी रांगोळ्या काढल्या जातात. दीपावलीच्या उत्साहपूर्ण वातावरणात दरवाजात सुंदर रांगोळी रेखाटून त्यामध्ये रंग भरताना मग्न झालेली महिला व चिमुरडी. छाया : दत्ता खेडेकर

रिसॉर्ट मालकांना धमकावले, तोतया पोलिसांना अटक

कर्जत पोलिसांच्या कारवाईने सोडला सुटकेचा नि:श्वास

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कर्जत : कर्जत तालुक्यातील रिसॉर्ट मालकांना धमकावणाऱ्या तोतया पोलिस अधिकाऱ्याच्या कर्जत पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या आहेत. शुभम राऊत आणि समीर दुधासे यांना बेड्या ठोकल्या.

शुभम हा एसपी तर समीर हा पोलिस निरीक्षक असल्याचे भासवून रिसॉर्ट मालकांना फोन करत होता. तुमच्या फार्मवर अल्पवयीन जोडपे आले होते. त्या मुलाने सोबतच्या मुलीचे बेड सीन शूट केले आहेत. हा प्रकार तुमच्या फार्मवर घडल्याने तुमच्यावरही पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करीत असून तुमचा फार्म कायमचा सील करण्यात येईल, या कारवाईसाठी आमचे पथक पुण्याहून निघाले आहे. तुम्हाला त्वरित अटक करण्यात येईल, अशी दमदाटी करून फार्म मालकाला घाबरवून त्याला सेटलमेंट करायला लावले. त्यानंतर त्यांच्याकडून पैसे वसूल करीत होते.

ऑनलाइन ट्रान्सफर

वारे येथील धनंजय म्हसे यांना २१ ऑक्टोबरला फोनवरून धमकावून त्यांच्याकडून १२ हजार ऑनलाइन ट्रान्सफर करून घेतले. चेतन घुमरे यांच्याकडून १५ हजार घेतले.

२२ ऑक्टोबरला समीर कुडूसकर याला धमकावून त्याच्याकडून पाच हजार घेतले. त्यानंतर टाटा पॉवर हाऊस येथील जयवंत भोसले यांनाही दमदाटी केली. परंतु, त्यांनी काहीही रक्कम दिली नाही.

पैसे केले परत

आरोपींनी सर्व रक्कम आराध्या दुधासे या खात्यावर घेतली. फसवणुकीबाबत सर्वांनी भूमिपुत्र फार्म संघटनेचे अध्यक्ष उदय पाटील यांना हकीकत सांगितली. संघटनेचे बिपीन लाड, अनिल भोसले यांनी कर्जत पोलिस ठाण्यात तक्रार केल्यानंतर उपविभागीय पोलिस अधिकारी राहुल गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनात पोलिसांनी तपास करून शुभम, समीर यांना घेतलेले पैसे परत करण्यास भाग पाडले.

भुकेल्या जिवांनी खायचे काय?

गरिबांच्या ‘शिवभोजन थाळी’ला सरकारी अनुदानाची लागली घरघर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : गरीब व गरजू नागरिकांसाठी सुरू केलेली शिवभोजन थाळी योजना सध्या आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. राज्य सरकारने ही योजना बंद होणार नसल्याचे स्पष्ट केले असले तरी सरकारी अनुदान वेळेत मिळत नसल्याने अनेक केंद्रे अडचणीत सापडली आहेत. त्यामुळे काही चालकांनी केंद्र बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. मुंबईत १३९ केंद्रांमधून दररोज १६ ते २० हजार थाळ्या वितरित केल्या जात आहेत.

रोजगारासाठी शहरात स्थलांतरित झालेले कामगार, गोरगरीब, रस्त्यावर रहाणारे, लहान फेरीवाले, श्रमजीवी कामगारांसाठी शिवभोजन थाळी ही योजना कोविड काळात सुरू करण्यात आली होती. यामुळे गरीब व वंचित घटकांना एक वेळच्या जेवणाची हमी मिळाली आहे. या योजनेंतर्गत १० रुपयांत दोन पोळ्या, एक वाटी भाजी, एक वाटी डाळ व एक वाटी भात असे जेवण दिले जाते.

अनुदान रखडले, संकट वाढले...

गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक शिवभोजन केंद्र चालकांची सरकारी अनुदानाची बिले प्रलंबित आहेत. सुरुवातीला वेळेत मिळणाऱ्या अनुदानासाठी सध्या दोन ते तीन महिने वाट पाहावी लागते.

काही केंद्र चालकांची चार ते पाच महिन्यांच्या बिलांची रक्कम मिळालेली नाही. यामुळे केंद्र चालकांना रोजच्या खर्चासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.

केंद्र सुरू ठेवायचे कसे?

१. १० रुपयांत पोटभर जेवण मिळत असल्याने कामगार, स्थलांतरित, विद्यार्थी यांच्यासाठी 'शिवभोजन थाळी' वरदान ठरत आहे.

२. आधार कार्ड क्रमांक नमूद करून त्यांचे फोटो घेतले जात असल्याने खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत ही योजना पोहोचत आहे.

३. सरकारचे अनुदानच वेळेत मिळत नसेल, तर केंद्र सुरू ठेवायचे कसे? केंद्र बंद केल्यास गरिबांना महागड्या जेवणावर अवलंबून राहावे लागेल. पोटभर जेवण मिळणे कठीण होईल असे , केंद्र चालक म्हात्रे म्हणाले.

शासनाचे अनुदान किती?

'शिवभोजन थाळी'साठी स्वस्त दरात पौष्टिक जेवण उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडून शहरी भागात प्रति थाळी ५० रुपये व ग्रामीण भागात ३५ रुपये अनुदान दिले जाते.

डहाणूतील निसर्गरम्य पर्यटनाकडे फिरली पर्यटकांची पाठ

लोकमत न्यूज नेटवर्क

बोर्डी : यंदा दिवाळी पर्यटनाच्या प्रारंभीच्या हंगामाकडे पर्यटकांनी पाठ फिरवल्याने पर्यटनस्थळांवर शुकशुकाट दिसत आहे. दिवाळीनंतर पर्यटक दाखल झाले तरी या काळात झालेली आर्थिक झळ भरून निघणार नसल्याचे व्यावसायिक सांगतात. त्यामुळे पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांना भौतिक सुविधा, स्वच्छता, सुरक्षितता, परिसरातील निसर्गसंपन्नता टिकवणे, याकडे लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.

दिवाळी पर्यटन हंगामाला प्रारंभ झाला असला तरी येथील चिंचणी, पारनाका, नरपड, चिखले, घोलवड, बोर्डी आणि झाई येथील सागरी पर्यटनस्थळी स्थानिक पर्यटकवगळता परगावातील पर्यटक जास्त संख्येने दाखल झालेले नाहीत. हा भाग शांत आणि निसर्गसंपन्नतेसाठी ओळखला जात असल्याने पर्यटकांना जास्त भावतो. त्यामुळे येथे नेहमी गर्दी होत होती. स्थानिक पर्यटन व्यावसायिकांनी येथील सुविधांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

डॉ. विजया वाड यांच्या अव्याहत लेखनप्रवासाचे कौतुक करताना डॉ. विश्वास पाटील.

डॉ. विश्वास पाटील यांच्या हस्ते ‘शुभारंभ’ चे प्रकाशन उत्साहात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या माजी अध्यक्षा डॉ. विजया वाड यांच्या १५७ व्या पुस्तकाचे प्रकाशन अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष, लेखक डॉ. विश्वास पाटील यांच्या हस्ते नुकतेच झाले.

वय वर्षे ऐंशीच्या टप्प्यावर नव्या लेखनपर्वाचा हा शुभारंभ आहे आणि 'जिद्दीपुढे गगन ठेंगणे' या शब्दांत त्याचे वर्णन करता येईल, असे उद्गार काढत त्यांनी डॉ. विजया वाड यांच्या अव्याहत लेखनप्रवासाचे कौतुक केले. या प्रसंगी डॉ. विजया वाड, सुकन्या डॉ. निशिगंधा वाड -देऊलकर, सोमैया विद्याविहार विद्यापीठाच्या भाषा आणि साहित्य शाखेच्या डीन डॉ. वीणा सानेकर उपस्थित होत्या. यावेळी डॉ. पाटील यांनी संवाद साधला.

वसंतदादा पाटील कॉलेजने युवा महोत्सवात पटकावले ‘सुवर्णपदक’

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मुंबई विद्यापीठ आयोजित ५८ व्या युवक महोत्सवात ‘चित्रपट निर्मिती’ या विभागात वसंतदादा पाटील प्रतिष्ठान्स कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड व्हिज्युअल आर्ट्स, मुंबई यांनी सुवर्णपदक जिंकले आहे. हा चित्रपट ‘आशा’ या नावाने सादर करण्यात आला असून, तो महिलांवरील घरगुती अत्याचाराविरुद्ध संरक्षण या विषयावर आधारित आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील एकूण ६० स्पर्धकांमधून हा सन्मान महाविद्यालयाने पटकावला आहे. या यशामध्ये बी.एफ.ए. तृतीय वर्षाच्या जॅनिस वेगास, वेदिका गोसार, श्रेया शुक्ला, शिरीष सोनटक्के, वंशिका शुक्ला आणि संजना सरंगकर या विद्यार्थिनींनी यामध्ये सहभाग नोंदवला होता. या चित्रपटाला इतर स्पर्धक आणि परीक्षकांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रशंसा मिळाली.

महामार्गावरील माळशेज घाटमार्ग टाकणार कात

रखडलेली कामे मार्गी, प्रकल्पांना मिळणार गती

सुरेश लोखंडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क

ठाणे : जिल्ह्यातून जाणारा कल्याण-माळशेज-नगर या राष्ट्रीय महामार्गावर (क्र. ६१) सध्या भव्य स्वरूपात सुधारणा, मजबुतीकरण व काँक्रीटीकरणाच्या टप्प्यात आहे. पावसाळ्यात जीवघेणा ठरणारा आणि अनेकवेळा अपघातग्रस्त ठरलेला हा माळशेज घाटमार्ग आता पूर्णतः कात टाकणार असून, रखडलेली कामे मार्गी लागणार आहेत. यामुळे वाहनचालक आणि स्थानिकांना दिलासा मिळणार आहे.

या राष्ट्रीय महामार्गावरील ठिकठिकाणच्या कामांसाठी केंद्र सरकारच्या सडक परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या वार्षिक नियोजन निधीतून कोट्यवधींच्या योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे. आता पावसाळा संपल्यामुळे या महामार्गावरील अनेक प्रकल्पांची गती वाढली असून, काही निविदा प्रक्रियेत आहेत. खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली काही दिवसांपूर्वी दिशा समितीची बैठक पार पडली. त्यात या महामार्गाच्या विविध स्वरूपाच्या कामांचा आढावा घेतला.

केंद्र सरकारच्या सडक परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या वार्षिक नियोजन निधीतून विकास

३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

प्रवास होणार सुखकर

१. या महामार्गावर विशेषत: माळशेज घाटात आता पावसाळ्यातील धोके टळणार असल्यामुळे वाहनचालकांना दिलासा मिळाला आहे. या मार्गावर दरवर्षी पावसाळ्यात दरडी कोसळणे, अपघात, वाहतूककोंडी, खराब रस्ते आणि जीवितहानीचे प्रकार घडत होते.

२. रस्त्याच्या मजबुतीकरण आणि संरक्षक उपाययोजनांमुळे या मार्गावर प्रवास अधिक सुरक्षित, जलद आणि टिकाऊ होणार आहे. त्यासाठी ठिकठिकाणी काँक्रीटीकरण, मास्टिक डांबर, स्ट्रक्चरल मजबुतीकरण, नवीन संरक्षक भिंती कामांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारकडून निधी मिळाला असून, वनविभाग व भूसंपादन विभागांनी परवानगी दिल्यानंतर रखडलेली कामे मार्गी लागताहेत.

४२ कोटी खर्चून काम पूर्ण

माळशेज घाट मजबुतीकरण व काँक्रीटीकरणाच्या १५.३० किमीपैकी ११.४५ किमी. लांबीचे काम (७४ टक्के) प्रगतिपथावर आहे. ७२ कोटी खर्चाच्या या कामावर ४८ कोटी ८८ लाख (५८.६२ टक्के) खर्च झाले आहेत.
३१ नोव्हेंबरपर्यंत काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

४८.५८ किमी.चे मजबुतीकरण

या महामार्गावरील ४८.५८ किमीचे मजबुतीकरण, काँक्रीटीकरणचे काम गेल्या वर्षभरापासून हाती घेतले आहे.

४१ हजार ८१८ कोटी रुपये खर्चाच्या या कामावर आजपर्यंत २२ हजार ८९३ कोटी रुपये खर्च होऊन २३.२७ किमी.

मस्ट READ

पुनर्विकासासाठी उपनिबंधकाचे ‘ना हरकत’ अनावश्यक

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : पुनर्विकासासाठी कलम ७९ (अ) अंतर्गत बिल्डर निवड प्रक्रियेत उपनिबंधकांचे ना हरकत प्रमाण पत्र (एनओसी) आवश्यक नसल्याचा, किंबहुना ते बेकायदा असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच एका निर्णयाद्वारे दिला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम ७९ (अ) अंतर्गत ४ जुलै २०१९ च्या शासन निर्णयात निबंधक किंवा उपनिबंधकांना बिल्डर निवडीबाबत गृह संस्थांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे कोणतेही अधिकार दिलेले नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीने स्वागत केले आहे.

१७ ऑक्टोबर रोजी पुनर्विकासाबाबत न्यायालयाने नोंदवले मत

निबंधक अशाप्रकारे आपल्याच अधिकारात या प्रक्रियेत एक नवा स्तर निर्माण करू शकत नाहीत, असे निरीक्षण न्या. अमित बोरकर यांनी १७ ऑक्टोबर २०२५ च्या निर्णयात नोंदवले आहे. उच्च न्यायालयाने यानिमित्ताने गृह-संस्थांचे अधिकार आणि निबंधक / उप-निबंधकांचे अधिकार स्पष्ट केले. अधिकार हे पर्यवेक्षण स्वरुपाचे आणि म्हणूनच मर्यादित स्वरुपाचे असल्याचे स्पष्ट करत बिल्डर निवडीचे संपूर्ण अधिकार हे गृह-संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेचे आहेत, हे अधोरेखित केले आहे.

“ या निर्णयामुळे निबंधक/उपनिबंधकांच्या कार्यालयांतील भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, अशी आशा आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीने बिल्डरांच्या संघटनांना आवाहन केले आहे की, यापुढे उपनिबंधकांच्या बेकायदा कृत्यांना खतपाणी घालू नका.

शिरीष वा. देशपांडे,
कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत

उपनिबंधकांनी ‘हे’ पाहावे

१. विशेष सर्वसाधारण सभेत बिल्डर निवड प्रक्रिया योग्य प्रकारे राबवली जात आहे की नाही, त्यासाठी सभेला आवश्यक ती किमान गणसंख्या आहे की नाही, बिल्डरची निवड आणि मतदान प्रक्रिया पारदर्शक आणि मोकळ्या वातावरणात होत आहे की नाही, त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होते आहे की नाही हे बघणे एवढेच निबंधकांचे काम असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

२. ४ जुलै २०१९ च्या शासन निर्णयात निबंधक अथवा उपनिबंधकांना स्वतःचे स्वेच्छाधिकार वापरण्याचे अथवा ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे वा नाकारण्याचे कोणतेही न्यायिक अधिकार दिलेले नाहीत.

बेकायदा प्रथा बंद करा

न्यायालयाने या निर्णयाची प्रत सहकार आयुक्त आणि सहकार खात्याच्या प्रधान सचिवांना पाठवण्याचे निर्देश दिले असून सहकार आयुक्तांनी एका परिपत्रकाद्वारे उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सर्व निबंधक/ उपनिबंधकांना त्वरीत अवगत करून देऊन ना हरकत प्रमाणपत्राची ही चुकीची आणि बेकायदा प्रथा ताबडतोब बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा प्रकारे परिपत्रक काढल्याचे उच्च न्यायालयास ६ नोव्हेंबरपर्यंत पुराव्यासह प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळवण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

वनवासी पाड्यांवर दिवाळीनिमित्त भाऊबीज भेटीचा कार्यक्रम उत्साहात पार पडला.

वनवासी पाड्यांवर भाऊबीज भेटीचा आनंद झाला द्विगुणित

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, माधव सेवा केंद्र, कुर्ला भागातर्फे बारीवाडी, रामराजवाडी, दवनसरवाडी, तुरमालेवाडी या चार वनवासी पाड्यांवर आणि वाल्मिकी वस्ती खार येथे दिवाळीनिमित्त भाऊबीज भेटीचा कार्यक्रम करण्यात आला. यावेळी २५० भगिनींना नवीन साडी, व फराळाची २२५ पाकिटे भेट देण्यात आली.

अंगणवाडी आणि पहिली ते सातवीपर्यंत एकूण १४० मुलांनाही त्यांच्या वयोगटानुसार खेळणी व बिस्किटाचा पुडा भेट देण्यात आला. महादेव यादव, जीवन म्हात्रे, रवींद्र पाटील व कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला. गेली अनेक वर्षे हा उपक्रम राबवला जातो.

मनेर में ट्रैक्टर से कुचल कर बाइक सवार इलेक्ट्रीशियन की गयी जान

मनेर. थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव के पास बुधवार की देर रात बाइक सवार इलेक्ट्रीशियन को ट्रैक्टर ने कुचल दिया. दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गयी. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर भेज दिया. हादसे के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी गयी. बताया जाता है कि चंदा बुजुर्ग, वजीरगंज गयाजी जिला निवासी विवेकानंद कुमार का 18 वर्षीय पुत्र मोनू कुमार इलेक्ट्रीशियन का काम दानापुर आरपीएस मोड़ पर रहकर करता था. हर रोज की तरह वह काम पूरा कर देर रात दानापुर आरपीएस मोड़ लौट रहा था. इस बीच लोदीपुर गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर तेज रफ्तार में ट्रैक्टर उसकी बाइक में टक्कर मारते हुए उसे कुचलकर फरार हो गया. इस मामले में मनेर की पुलिस ने बताया कि आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे से ट्रैक्टर की खोजबीन की जा रही है.

फतुहा में बाइक सवार को ट्रैक्टर ने रौंदा, मौत

फतुहा. थाना क्षेत्र के फतुहा-दनियावां सड़क मार्ग पर तीन मोहनी मोड़ पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया. घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गयी. मृतक की पहचान सारण जिला के सोनपुर थाना क्षेत्र के भरपुरा गांव निवासी रंजय सिंह के रूप में हुई है. बताया जाता है कि सारण जिले के सोनपुर निवासी रंजय सिंह अपने भाई के ससुराल बख्तियारपुर के बहादुरपुर करौती से बाइक से फतुहा श्मशान घाट किसी परिवार के दाह संस्कार में शामिल होकर लौट रहे थे कि वे ज्यों ही फतुहा-दनियावां सड़क मार्ग पर तीन मुहानी पर उनकी बाइक किसी वाहन के चपेट में आने से अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गयी. उसी समय विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ने उन्हें रौंद दिया. फतुहा पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है. मृतक रंजय सिंह का गौरीचक थाना क्षेत्र के दौलतपुर में ससुराल है.

ऑटो और बस में टक्कर, आधा दर्जन जख्मी

बिक्रम

बिक्रम . थाना क्षेत्र के बिक्रम पालीगंज पथ पर गुरुवार शाम मंझौली महामाया मंदिर के समीप बस और ऑटो में टक्कर हो गयी, जिसमें ऑटो पर सवार आधा दर्जन से अधिक यात्री जख्मी हो गये. प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑटो पालीगंज की ओर जा रहा था वहीं बस बिक्रम की ओर आ रही थी. अचानक दोनों के बीच सीधी टक्कर हो गयी. जख्मी लोगों में कमल प्रवेश शर्मा, बड़की खड़वां, सिमरन प्रवीण, सिगोड़ी, मोनिका खातून, सिगोड़ी, गुलशन आरा, नवीनगर, संतोष मिश्रा, राघोपुर, बिहटा, मंजू देवी भलुआ, मंटू विश्वकर्मा, दुल्हिनबाजार शामिल हैं. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस व ग्रामीणों के सहयोग से सभी जख्मी लोगों को स्थानीय पीएचसी में इलाज कराया गया.

दुखद. घटना के बाद शाहजहांपुर में मचा कोहराम, दो घरों के बुझे चिराग

दनियावां में नये छठ घाट पर पइन में स्नान करने गये तीन बच्चे डूबे, मौत

प्रतिनिधि, दनियावां

शाहजहांपुर गांव में उस समय कोहराम मच गया, जब नये छठ घाट पर पानी भरे पइन में स्नान करने गये पांच बच्चों में से तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गयी. मृतक तीनों की पहचान दनियावां प्रखंड के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर गांव निवासी अमित कुमार के पुत्र अंश राज (12वर्ष), संजय कुमार के पुत्र ऋषभ कुमार (11वर्ष) और सुनील कुमार के पुत्र आशीष कुमार (9वर्ष) के रूप में हुई है. ऋषभ और आशीष अपने घर का इकलौता चिराग था.

बताया जाता है कि शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के रामलालपुर गांव से शाहजहांपुर और मसलनदपुर जाने वाली ग्रामीण सड़क के काजी खंदा के कोना के पास पानी भरे पइन के किनारे गुरुवार की सुबह ग्रामीणों द्वारा छठ घाट का निर्माण किया जा रहा था. घाट की साफ-सफाई कर बास गाड़ कर दोपहर में ग्रामीण अपने-अपने घर चले गये थे. दोपहर बाद करीब साढ़े तीन बजे शाहजहांपुर गांव के पांच बच्चे घाट के किनारे पइन में स्नान करने गये, जिसमें दो बच्चे ऋषभ और आशीष डूबने लगे जिसे बचाने अंश राज गया, तो वह भी डूबने लगा.

घाट तैयार कर ग्रामीण चले गये थे घर, बाद में बच्चे पहुंच गये स्नान करने

घटना के बाद शोकाकुल परिजन. इनसेट में मृत बच्चे का फाइल फोटो.

ऋषभ और आशीष अपने घर का इकलौता चिराग थे

ऋषभ और आशीष अपने घर का इकलौता चिराग था. दोनों की एक-एक बहन है. वहीं अंश राज अपने दो भाइयों में बड़ा था. एक साथ तीन लोगों की हुई मौत से पूरे मुहल्ले में ग़म का माहौल छा गया. आसपास के घरों के भी लोग मातम में डूब गये. सभी लोग मृतक के पहुंच कर बेसुध पड़े परिजनों को सांत्वना देने में जुटे थे.

तीन बच्चों को डूबते देख दो बच्चों ने ग्रामीणों को दी सूचना

तीनों बच्चों को डूबते देख दो बच्चे पइन से निकल कर हल्ला करते हुए गांव की ओर भागे और ग्रामीणों की सूचना दी. सूचना मिलते ग्रामीण और शाहजहांपुर पुलिस मौके पर पहुंची और पइन में डूबे तीनों बच्चे को निकाला और दनियावां पीएचसी ले गये, जहां चिकित्सकों ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया. घटना के बाद अस्पताल में भीड़ जुट गयी.

घटना के बाद शवों का नहीं कराया गया पोस्टमार्टम

घटना के बाद मौके पर दनियावां, शाहजहांपुर के थानाध्यक्ष और फतुहा डीएसपी टू संजीव कुमार मौके पर पहुंच कर शवों के पोस्टमार्टम में भेजने की तैयारी में जुट गये. लेकिन परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम नहीं कराने का फैसला लिया, जिससे कुछ देर तक दनियावां अस्पताल में असमंजस की स्थिति बन गयी. अंत में प्रशासन द्वारा परिजनों से लिखित लेकर शवों को परिजनों को सौंप दिया.

परिजनों के चीत्कार से माहौल हुआ गमगीन

मृत तीनों बच्चों के परिजन और ग्रामीणों के चीत्कार से माहौल गमगीन हो गया. घटना की खबर पूरे प्रखंड में आग की तरह फैल गयी. दनियावां अस्पताल में स्थानीय मुखिया पल्लवी भारती, प्रखंड प्रमुख विनोद कुमार, जिला परिषद सदस्य इंदु देवी समेत सभी दल के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे और परिजनों को सांत्वना देने में जुट गये.

सिटी बाइट्स

पटना सिटी के बनवारी चौक पर गोवर्धन पूजा करतीं महिलाएं.

गंगा स्नान के दौरान डूबने से किशोरी की मौत

अथमलगोला. गंगा स्नान के दौरान डूबने से एक किशोरी की मौत हो गयी. ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र अधीन गंज पर गांव निवासी दुखन राय की 12 वर्षीय बेटी बुढ़रा के सीढ़ी घाट पर स्नान करने गयी थी. जो गहरे पानी में चले जाने के कारण डूब गयई. घटना की सूचना मिलते ही परिजन ग्रामीणों के साथ घाट पर पहुंचे और सीओ को सुचित करते हुए स्थानीय स्तर पर तलाश शुरू की. **गंगा स्नान कर घाट पर गिरी महिला, मौतः मोकामा.** गुरुवार को मोकामा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोलदियार टोला तपस्वी जी गंगा घाट पर गंगा स्नान कर निकली एक महिला घाट पर गिर गयी और उसकी मौत हो गयी. मृतका रेणु देवी (51) बेगूसराय जिले के रतनपुर वार्ड संख्या 20 निवासी राम लक्ष्मण सिंह की पत्नी थी.

शरीर पर फेंका पटाखा, विरोध करने पर की पिटाई

पटना सिटी. अगमकुआं थाना क्षेत्र के कुम्हरार निवासी अर्पित राज ने शरीर पर पटाखा फेंकने का विरोध करने पर मारपीट की शिकायत थाना में दर्ज करायी है. इसमें पुलिस को बताया है कि वह कुम्हरार स्थित घर से निकल कर गायघाट जा रहा था. इसी दौरान कुम्हरार के समीप एक गुट के आधा दर्जन युवक आतिशबाजी कर रहे थे. इसी में एक युवक ने शरीर को टारगेट का पटाखा फेंका, जिसका विरोध किया. तब उन लोगों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया और चेन झपट कर फरार हो गये. पुलिस ने बताया कि इस मामले में पक्का कुआं निवासी राहुल और सागर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

दहेज के लिए मारपीट व प्रताड़ना का आरोप

पटना सिटी. मेहंदीगंज थाना के रानीपुर पश्चिम कस्बा निवासी नेहा कुमारी ने पति मुकेश सोनी और ससुराल के लोगों पर दहेज के लिए मारपीट और प्रताड़ित करने का मामला थाने में दर्ज कराया है. इसमें महिला ने पुलिस को बताया है कि बाढ़ निवासी मुकेश सोनी से शादी करीब चार साल पूर्व हुई थी. शादी के कुछ दिन के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग मारपीट कर नैहर से रुपये की डिमांड करने लगे. महिला का आरोप है कि कुछ दिन पूर्व पति और देवर नैहर आकर मां और भाई के साथ मारपीट की. इसके साथ ही डेढ साल के बच्चे को अपने साथ ले गये.

महिला से पांच हजार रुपये व कानबाली झपटा

पटना सिटी. अगमकुआं थाना के नंदलाल छपरा के समीप ऑटो सवार बदमाशों ने नालंदा निवासी उषा देवी से पांच हजार रुपये और सोने की कानबाली झपट लिया है, जिसकी शिकायत थाना में दर्ज करायी गयी है. पीड़िता ने दर्ज शिकायत में पुलिस को बताया है कि जीरो माइल के पास बस से उतर का ऑटो से जगनपुरा जाने के लिए सवार हुई. आटो में पहले से दो बदमाश यात्री के वेश में सवार थे. इसी बीच रास्ते में एक और लड़का बैठ गया. नंदलाल छपरा के समीप इन लोगों ने मुंह और आंख बंद कर कान से सोने की बाली और पर्स में रखा पांच हजार रुपये झपट कर उसे ऑटो से उतार दिया. इसी बीच चालक भी तेजी से ऑटो लेकर फरार हो गया.

मुफ्त में मिठाई नहीं देने पर पिस्तौल दिखा धमकाया

बाढ़. बाढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोंदी वार्ड नंबर 5 निवासी नीरज कुमार की मिठाई दुकान में कुछ लोगों ने मुफ्त में मिठाई नहीं देने पर पिस्तौल दिखाकर धमकी दी. उल्टे दुकानदार से ही रंगदारी की मांग कर दी. इस संबंध में नीरज कुमार ने बताया कि उसकी दुकान में बच्चा राम, गोलू राम और चुन्नू राम आदि ने मिठाई ली. इसके बाद जब उसने पैसे मांगें तो आरोपियों ने पिस्तौल निकाल लिया. उसके स्टाफ से मारपीट की और उसे काम छोड़ देने का अल्टीमेटम दिया. पीड़ित ने बताया कि उसे आरोपियों ने रंगदारी की मांग की है. नहीं देने पर जान मारने की धमकी भी दी गयी है. पुलिस ने गुरुवार को केस दर्ज कर लिया है.

होटल में कमरा नहीं दिया तो मालिक को पीटा

बाढ़. कचहरी एरिया में स्थित राजनंदनी स्वीट्स दुकानदार को होटल में रूम देने से इनकार करने पर कुछ लोगों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया. खुसरूपुर निवासी दुकानदार राजू कुमार ने बताया कि 2 दिन पहले उसकी दुकान पर दो युवक और दो लड़की होटल में रूम खोजने के लिए आये थे. रूम देने से इनकार करने पर उन्होंने गाली-गलौज कर एक घंटे बाद सात-आठ लोग उसकी दुकान में घुसे और बदसलूकी करते हुए मोबाइल तोड़ कर उसके साथ मारपीट की गयी, जिसमें उसका सिर फट गया. पुलिस ने दुकानदार के बयान पर काली स्थान निवासी वैदेही कुमार और सौरभ कुमार के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है. उनकी तलाश की जा रही है.

एसडीओ ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण

दानापुर. विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर गुरुवार को निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ दिव्या शक्ति ने 57 बूथों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान एसडीओ ने आवश्यक दिशा निर्देश दिये. उन्होंने खगौल नगर परिषद क्षेत्र के 42 और जमालुद्दीनचक पंचायत के 15 बूथों का निरीक्षण किया. एसडीओ ने बताया कि मतदान केंद्र पर मतदाता को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रहे. मतदान केंद्र पर रैंप अति आवश्यक है. साथ ही जो भी भवन के टूटे-फुटे भाग हैं, उसे यथाशीघ्र मरम्मत कराकर रंग रोगन करा दें. मतदान केंद्र पर शौचालय, बिजली, पानी की व्यवस्था अत्यंत जरूरी है. निरीक्षण के दौरान शिक्षक विजय कुमार साह समेत आदि उपस्थित थे.

बाकरगंज के मोबाइल दुकानदार की सड़क दुर्घटना में हुई मौत, चचेरा भाई हुआ जख्मी

- चालक ट्रक छोड़ कर फरार, अगमकुआं थाने के जीरो माइल पवन पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा

संवाददाता, पटना, पटना सिटी

अगमकुआं थाने के जीरो माइल ट्रांसपोर्ट नगर गेट नंबर 2 के समीप ट्रक ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी. बाइक पर सवार मोबाइल दुकानदार शांतनू कुमार उर्फ गोलू व उनका चचेरा भाई बंटी सड़क पर गिर गये. ट्रक चालक भागने के चक्कर में शांतनू को कुचल दिया, घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गयी. जबकि बंटी जख्मी हो गया. साथ ही बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गयी और सारा सामान सड़क पर बिखर गया. हादसे के बाद ट्रक चालक गाड़ी छोड़ कर भाग निकला. इस कारण कुछ देर के लिए आवागमन भी बाधित हुआ. जानकारी मिलने पर ट्रैफिक पुलिस पहुंची और शव

को पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच भेज दिया है. जबकि बंटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शांतनू मूल रूप से वैशाली के बेलसर के नगमा गांव के रहने वाले थे. पटना में कदमकुआं थाने के पश्चिमी लोहानीपुर में किराये का फ्लैट लेकर परिवार के साथ रहते थे. 35 वर्षीय शांतनू अपने पीछे पत्नी के साथ ही एक बेटा और एक बेटी को छोड़ गये हैं. इनके पिता की मृत्यु 14 साल पहले ही हो चुकी है और मां नीलम देवी पटना के एक निजी अस्पताल में काम करती हैं. शांतनू की बाकरगंज में मोबाइल दुकान है. जबकि बंटी परसा बाजार के कुरथौल में रहता है. यह घटना गुरुवार की शाम करीब 4 बजे घटित हुई. जीरो माइल ट्रैफिक थानाध्यक्ष नीरज कुमार ठाकुर ने बताया कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है.

दीवाली मना कर बाइक से लौट रहे थे घर

शांतनू दीवाली मनाने के लिए अपने परिवार के साथ वैशाली स्थित पैतृक गांव गये थे. वहां से चचेरे भाई बंटी के साथ बाइक से कदमकुआं के पश्चिमी लोहानीपुर स्थित घर आ रहे थे. महात्मा गांधी सेतु होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर गेट नंबर 2 पवन पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, वैसे ही तेज गति से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद शांतनू व बंटी सामान लेकर सड़क पर गिर गये और गंभीर रूप से चोट आयी. लेकिन ट्रक चालक ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी और भागने के चक्कर में शांतनू को कुचल दिया.

पांच किलो गांजा के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

बिहटा. पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान बिहटा गांव स्थित नकटा कुआं के पास पांच किलो गांजा के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. साथ ही एक बाइक जब्त की है. गिरफ्तार तस्करों की पहचान अल्हनपुरा निवासी संतोष कुमार, वैशाली जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के मलिकपुर निवासी सिंधु कुमार, और जानदाहा थाना क्षेत्र के सालहा निवासी अरविंद कुमार के रूप में की गयी है. जानकारी के अनुसार, पुलिस जिनपुरा रोड के समीप वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान बाइक पर सवार तीन युवक पुलिस देखकर भागने लगे. शक होने पर पुलिस ने पीछा किया और नकटा कुआं के पास तीनों को पकड़ लिया. तलाशी में उनके पास से पांच किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत करीब पांच लाख रुपये बतायी जा रही है. थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि तीनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

फोन कर कारोबारी से मांगी 40 लाख रुपये रंगदारी, दी धमकी

पटना सिटी

प्रतिनिधि,पटना सिटी

अपराधियों ने कारोबारी से मोबाइल पर फोन कर 40 लाख रुपये की रंगदारी मांगी है. रुपये नहीं देने पर दो माह में हत्या करने की धमकी दी है. फोन करने वाले ने यह भी कहा है कि इसके लिए 20 लाख रुपये की सुपारी दी गयी है. घटना खाजेकलां थाना क्षेत्र के मोगलपुरा के शेखा रोजा निवासी रिजवान आलम के साथ हुई है. पीड़ित रिजवान आलम ने खाजेकलां थाना में दर्ज शिकायत में पुलिस को बताया है कि कॉल 17 अक्तूबर को ही आया था. लेकिन डर और दहशत की वजह से 19 अक्टूबर को इस संबंध में थाने को सूचना दी है. कॉल करने वाले बदमाश ने यह भी कहा कि आपकी सुपारी 20 लाख रुपये में दी जा चुकी है. रंगदारी मांगने वाले बदमाश ने दो माह के अंदर हत्या की धमकी दी है. पीड़ित ने बताया कि पूर्व में ऐसी धमकी दिये जाने की वजह से बडे भाई नोमानूल हक की हत्या 2011 में हो चुकी है. इस स्थिति में परिवार डर और दहशत में है.

खाजेकलां थाना की पुलिस ने बताया कि अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है गयी है. जिस नंबर से फोन आया था, उस नंबर को पुलिस डिडेक्ट करने में लगी है. कारोबारी ने पुलिस को बताया है कि कॉल करने वाले व्यक्ति ने कहा कि जान से मरवा देने की सुपारी देने की सूचना देने के एवज में 40 लाख रुपये की रंगदारी चाहिए. नहीं तो दो महा के अंदर हत्या की धमकी दी है.

तेजी से तैयार हो रहे छठ घाट तालाब में भी पड़ेगा अर्घ

पटना सिटी. छठ को लेकर घाटों पर तैयारी को अंतिम रूप देने के बीच पटना नगर निगम सिटी और अजीमाबाद अंचल ने तालाब में अर्घ अर्पित करने की व्यवस्था की है. अजीमाबाद अंचल के वार्ड 56 में रानीपुर चकिया स्थित तालाब में अर्घ अर्पित करने के लिए साफ सफाई करने के साथ उसे व्यवस्थित किया गया है. इसी प्रकार से पटना नगर निगम सिटी अंचल की ओर से मंगल तालाब में भी घाट पर अर्घ की व्यवस्था की गयी है. निगम सिटी अंचल के इओ आशुतोष कुमार ने बताया कि मंगल तालाब के साथ अंचल के आठ वार्ड में पड़ने वाले 27 गंगा घाटों पर तैयारी को मूर्त रूप दिया गया है. इसी प्रकार निगम अजीमाबाद अंचल में 12 वार्ड में 28 गंगा घाटों में एक कंटाही घाट को खतरनाक घोषित किया गया है. इओ श्रेया कश्यप ने बताया कि राजा घाट, ज्यूडिशियल घाट, गायघाट, भद्रघाट, महावीर घाट, नौजर घाट, आदर्श घाट, दुल्ली घाट, सीढी घाट, मतिन घाट, सीता घाट, खाजेकलां घाट समेत अन्य घाटों पर अर्घ देने की सारी व्यवस्था पूरी कर ली गयी है.

चार साल से फरार अभियुक्त समेत पांच गिरफ्तार

फुलवारीशरीफ. चुनाव के मद्देनज़र थाना क्षेत्र में पुलिस की सघन छापेमारी और गश्ती के दौरान गौरीचक थाना पुलिस ने विभिन्न मामलों में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपितों में एक चार साल से फरार चल रहा अभियुक्त भी शामिल है. पुलिस ने बताया कि गौरीचक थाना कांड संख्या 136/21 धारा 30(ए) उत्पाद अधिनियम के प्राथमिकी अभियुक्त गुड्डू मांझी पिता रामदयाल मांझी, ग्राम अलबक्सपुर, थाना गौरीचक, जिला पटना को चार वर्ष बाद गिरफ्तार किया गया है. वह लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था. इसके अलावा वारंटियों में जिवन मांझी, रामदेव सिंह, महेश, राज किशोर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है. थाना प्रभारी ने बताया कि एक व्यक्ति को नशे की हालत में भी गिरफ्तार किया गया है.

मोकामा में गंगा नदी में मिला घड़ियाल का शव, अफरातफरी

प्रतिनिधि, मोकामा

गुरुवार को हाथीदह थाना क्षेत्र अंतर्गत दरियापुर में गंगा घाट पर एक घड़ियाल का शव पाया गया. दरअसल ग्रामीण छठ महापर्व को लेकर गंगा घाट की साफ सफाई और घाट को दुरुस्त कर रहे थे, उसी दौरान ग्रामीणों ने देखा की पानी में घड़ियाल उल्टा पड़ा है. जिससे लोगों को समझ आ गया कि घड़ियाल की मौत हो चुकी है. उन्होंने हाथीदह थाना को इसकी सूचना दी और मिलकर घड़ियाल के शव को पानी से बाहर निकाला. घटना की सूचना मिलते ही तत्काल हाथीदह थाना की पुलिस पहुंच गयी और उच्च अधिकारी व वन विभाग को इसकी सूचना दी. वन विभाग से कर्मचारी आकर घड़ियाल

के शव को अपने साथ ले गये. वहीं घड़ियाल को देखने ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गयी. बता दें कि कुछ दिन पूर्व भी नदी के इस इलाके में एक घड़ियाल देखा गया था लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जो घड़ियाल पांच दिन पूर्व देखा गया था और जो शव पाया गया है, दोनों अलग-अलग है.

बेलछी में प्रत्याशी की ढाई लाख रुपये की प्रचार सामग्री जब्त

बाढ़. बेलछी थाना क्षेत्र के अंतर्गत तमोलिया पुल के पास पुलिस ने चेकिंग पॉइंट पर शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी विजय की प्रचार सामग्री लदा हुआ पिकअप जब्त किया है. प्रचार सामग्री की कीमत ढाई लाख रुपये बतायी जाती है. बेलछी थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने जांच के दौरान पिकअप पर शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी विजय की प्रचार सामग्री पटना से शेखपुरा पिकअप पर ले जाया जा रहा था, जांच के दौरान सामग्री को जब्त कर लिया गया है. वहीं दूसरी तरफ वाहन जांच के दौरान बेलछी निवासी व्यक्ति के पास एक लाख रुपये बरामद किया गया है. बुधवार को भी एक पेट्रोल पंप संचालिका के पास से भी 93000 रुपये बरामद किया गया. रुपये को जांच के लिए जब्त कर लिया गया है.

प्रभात खबर बिहार जागे... देश आगे
मार्केट प्लस
क्लासिफाइड के संग
विज्ञापन के लिए संपर्क करें - 98354 47208

एक हाथ में डिग्री, दूसरे हाथ में नौकरी
JAY SHREE SHYAM GROUP OF EDUCATION
बिहार शिक्षक नियुक्ति के लिए
UP-D.El.Ed /UP-B.Ed
₹ 30,000/-
बिहार लाइब्रेरियन व कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हेतु
B.LIS/PGDCA/M.LIS
₹ 12,500/-
STET/BPSC हेतु
PG (MA, M.Sc, M.Com, MCA, MBA) डिग्री
₹25,000
बिहार जूनियर इंजीनियर भर्ती हेतु
POLYTECHNIC , B.TECH
OFFER FEE ₹25,000/-
9234190063, 7903508640, 9431477694
मुसल्लहपुर हाट (सब्जी मंडी के सामने), लोहार लेन, पटना

कोर्ट नोटिस

न्यायालय में,
श्रीमान् सिविल जज सिनियर डिविजन प्रथम
बाढ़ पटना
बंटवारा वाद संख्या 29/2025
विनोद कुमार सिंह एवं अन्य .....वादीगण
बनाम्
सुरेन्द्र सिह एवं अन्य ....प्रतिवादीगण
नोटिस बनाम

1 सुरेन्द्र सिंह पिता स्व. कामेश्वर सिंह, 2. अनन्त प्रकाश पिता सुरेन्द्र सिंह, 3. जीतु पिता सुरेन्द्र सिंह, 4. जिसु पिता सुरेन्द्र सिंह, 5. प्रशुराम सिंह पिता चर्तुधन सिंह, 6. मनीष कुमार पिता चर्तुधन सिंह, 7. नीगम कुमार पिता उदय सिंह, 8. शंकर सिंह पिता स्व. उदय सिंह सभी निवासी ग्राम रूपस कमरापर थाना अथमलगोला जिला पटना।

मेरे न्यायालय द्वारा आपलोगों के विरूद्ध पदचर एवं निबंधित डाक द्वारा आपलोगों को नोटिस भेजा गया, परन्तु आपलोग उपस्थित नहीं हुए ।

इस प्रकाशन के माध्यम से आपको निर्देश दिया जाता है कि स्वंय या अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 03.11.25 को 10:30 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे अन्यथा आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जायेगी।

इसे ताकिद जाने।

आज दिनांक 17.10.25 को न्यायालय के आदेश एवं मुहर द्वारा जारी किया जाता हैं।

सिविल जज
सिनियर डिविजन प्रथम बाढ़ पटना
17.10.25

कोर्ट नोटिस

न्यायालय में,
सिविल जज सिनियर डिविजन III
बाढ़ पटना
स्वत्व वाद संख्या 74/2025
श्यामपति देवी...................वादी
बनाम्
मिथिलेश सिंह एवं अन्य ....प्रतिवादीगण

चूकि आपलोगों 1. मिथलेश सिंह पिता स्व0 कपिल सिंह, 2. राजेश सिंह पिता स्व0 कपिल सिंह, 3. अंजेश सिंह पिता स्व. कपिल सिह, 4.राम जतन सिंह पिता स्व. सुरज नारैन सिंह, 5.राम यतन सिंह पिता स्व. सुरज नारैन सिंह, 6. जागो देवी पति राम यतन सिंह सभी निवासी पुरबी मलाही भटगॉव रोड पो. थाना बाढ़ जिला पटना पिन कोड 803213, 7. अनुराधा कुमारी पति पवन कुमार सिंह निवासी महेश तिलकपुर थाना सुल्तानगंज जिला भागलपुर वर्तमान पता पुरबी मलाही भटगांव रोड पो. थाना बाढ़ जिला पटना पिन कोड 803213

इस वाद में वादी ने आपलोगो के विरूद्ध हकियत की घोषणा वाद लाया है जिसमें आप लोगो को नजारत के माध्यम से एवं निबंधित डाक के माध्यम से दिया गया माननीय न्यायालय द्वारा नोटिश दिया गया फिर भी आपलोग उपस्थित नहीं हुए इस लिए वजरिये प्रकाशन आपलोगो को सूचित किया जाता है कि आप खुद या अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 04.11.2025 समय 10:00 बजे पूर्वाहन में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें अन्यथा आपलोगो के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। इसे ताकिद जानें

आज दिनांक 15.10 .2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मोहर से जारी किया गया

सिविल जज सिनियर डिविजन III
बाढ़ पटना

कोर्ट नोटिस

न्यायालय में,
असैनिक न्यायाधीश वरीय कोटि 1
बाढ पटना
स्वत्व वाद सं. 43/2024
श्रीमति विभा देवी ....वादिनी
बनाम्
गंगा सागर सिंह वगैरह.....प्रतिवादीगण
नोटिश बनाम्

1 गंगा सागर सिंह वल्द स्व. लाल किशुन सिंह ग्राम व पोस्ट शिवनार थाना मोकामा जिला पटना

आपके विरूद्ध वादिनी ने मेरे न्यायालय में मोकदमा दायर किया है, जिसमें पदचर, निबंधित डाक से सूचना भेजा गया, पर आप उपस्थित नहीं हुए ।

अतः इस प्रकाशन के माध्यम से आपको आगाह किया जाता है कि आप दिनांक 22.11.25 को 10:30 बजे दिन में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें, अन्यथा आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जायेगी।

इसे आवश्यक समझे ।

मेरे न्यायालय के मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से निर्गत

असैनिक न्यायाधीश वरीय कोटि
बाढ़ पटना

कलमजीवियों ने की आराध्य चित्रगुप्त की पूजा

प्रतिनिधि,पटना सिटी

पाप पुण्य का लेखा-जोखा रखने वाले कलम जीवियों के आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त की पूजा-अर्चना गुरुवार को परंपरागत तरीके से कायस्थ समाज के लोगों ने की. श्री आदि चित्रगुप्त मंदिर नौजर घाट में सामूहिक पूजा का अनुष्ठान वैदिक मंत्रोच्चार से संपन्न कराया. मौके पर मंदिर प्रबंधक समिति के उपाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा, प्रधान सचिव सुदामा प्रसाद सिन्हा, सचिव राजीव मोहन, कोषाध्यक्ष प्रो चंद्रमोहन राय सक्सेना, संयुक्त सचिव चंद्रभानु सिन्हा, अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष नवीन सिन्हा, धर्मेंद्र प्रसाद मुन्ना, लाला प्रकाश, प्रभार बहादुर माथुर समेत अन्य हिस्सा लिया. कायस्थ चित्रगुप्त सेना ने बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में अध्यक्ष पांडेय अखिलेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में पूजा की. आयोजन में बीपी श्रीवास्तव, अवध किशोर प्रसाद, डॉ दिपेन्द्र भूषण, रौशन प्रियदर्शी, सुनील श्रीवास्तव, सुशील सिन्हा, राजेश कुमार चौधरी, रामदेव सिन्हा, धर्मेन्द्र, रघुनाथ, अधिवक्ता रत्न सिन्हा, राजीव रंजन सिन्हा, गिरिधर गोपाल, शांत मनु कर्ण, प्रो संतोष कुमार, विकास श्रीवास्तव समेत अन्य शामिल हुए. चित्रगुप्त पूजा उत्थान समिति की ओर से शनिदेव मंदिर बजरंगपुरी में पूजा-अर्चना की गयी. मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी. आयोजन में समिति के अध्यक्ष अश्वनी कुमार पंकज, उपाध्यक्ष अंजनी कुमार कर्ण, सुबोध कुमार सिन्हा, सुनील कुमार सिन्हा, विनोद सिन्हा, सर्वेश्वर कुमार सिन्हा, रूद्र कुमार मिल्लक, आरकेवर्मा, सुरेश प्रसाद, राकेश कुमार सिन्हा, कौशल किशोर, मिथिलेश कुमार व अवधेश कुमार सिन्हा समेत अन्य शामिल थे. चित्रांश जागृति मंच, महावीर नगर, अनीसाबाद की ओर से भगवान श्री चित्रगुप्त की पूजा-अर्चना की गयी. इस अवसर पर पद्मश्री डॉ. गोपाल प्रसाद, कुमार राकेश रंजन, रितेश रहे.

एफडीआइ में वृद्धि

भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा मासिक बुलेटिन के मुताबिक, वैश्विक चुनौतियों के बीच देश में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से जुलाई के बीच सालाना आधार पर 208.57 फीसदी बढ़ कर 10.8 अरब डॉलर हो गया. एक साल पहले की समान अवधि में यह 3.5 अरब डॉलर रहा था. जबकि सकल एफडीआइ एक साल पहले से 33.2 प्रतिशत बढ़ कर 37.7 अरब डॉलर हो गया. पिछले वित्त वर्ष में अप्रैल से जुलाई की अवधि में 28.3 अरब डॉलर का एफडीआइ आया था. केंद्रीय बैंक के अनुसार, इस साल अप्रैल से जुलाई तक की अवधि में सिंगापुर, अमेरिका, मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड एफडीआइ के शीर्ष स्रोत रहे, जिनकी कुल निवेश में 76 फीसदी हिस्सेदारी रही. विनिर्माण, कंप्यूटर सेवाओं, व्यावसायिक संचार और वित्तीय सेवाओं के साथ-साथ निर्माण तथा बिजली उत्पादन के क्षेत्रों में कुल 74 प्रतिशत एफडीआइ आया. हालांकि जुलाई में चार साल के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद अगस्त में सकल एफडीआइ घट कर छह अरब डॉलर रह गया, जो जुलाई के 11.11 अरब डॉलर से 5.11 अरब डॉलर कम है. अगस्त में विदेशी कंपनियों की ओर से धन वापसी 30 प्रतिशत बढ़ कर 4.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया. इससे शुद्ध एफडीआइ 61.6 करोड़ डॉलर के आउटफ्लो (निकासी) में बदल गया. बुलेटिन के मुताबिक, अगस्त में भारतीयों ने विदेश यात्रा पर 1.61 अरब डॉलर खर्च किये, जो जुलाई के 1.14 अरब डॉलर से ज्यादा है. ऐसे ही, विदेश में शिक्षा पर खर्च मासिक आधार पर 39 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31.9 करोड़ डॉलर हो गया. जबकि विदेश में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने अगस्त में देश में 2.6 अरब डॉलर की रकम भेजी. यह जुलाई की तुलना में 7.7 प्रतिशत अधिक है. बुलेटिन में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल भारत की वृद्धि दर के लिए गंभीर चुनौतियां पेश कर रही हैं. इन चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने लचीलेपन का प्रदर्शन किया है. इसमें यह भी कहा गया है कि वैश्विक नरमी के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू मांग, सरकारी खर्च और निर्यात के विविधीकरण से लाभान्वित हो रही है और रूस से कच्चे तेल की खरीद के जवाब में अमेरिका की तरफ से लगाया गया टैरिफ भारत के विकास के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि देश अब वैश्विक व्यापार पर निर्भरता घटा रहा है. निर्यात में वृद्धि के बाद एफडीआइ में वृद्धि अर्थव्यवस्था की मजबूती के बारे में बताती है.

रिजर्व बैंक के ताजा मासिक बुलेटिन के मुताबिक, सकल एफडीआइ एक साल पहले की तुलना में 33.2 फीसदी बढ़ कर 37.7 अरब डॉलर हो गया. निर्यात में वृद्धि के बाद एफडीआइ में वृद्धि अर्थव्यवस्था की मजबूती के बारे में बताती है.

सामाजिक कल्याण में बाधक बनना ठीक नहीं

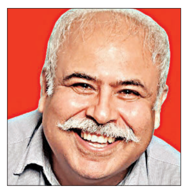

जगदीश रत्नानी
वरिष्ठ पत्रकार
editor@thebillionpress.org

सुधा और नारायण मूर्ति द्वारा कर्नाटक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा लाये गये सामाजिक-आर्थिक सर्वे में शामिल होने से इनकार करने पर बहस शुरू हो गयी है. दोनों जानते होंगे कि पिछड़ी जातियों की बेहतरी के लिए नीति निर्माण और उसके त्वरित क्रियान्वयन में समय पर पेश किये गये ठोस और अद्यतन आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण साबित होते हैं. .

कर्नाटक में राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा लाये गये सामाजिक-आर्थिक सर्वे के दौरान ऐसी बात हुई है, जो पिछड़ों के पक्ष में उठाये जाने वाले कदमों को रोक सकती है या उन्हें धीमा कर सकती है. दरअसल सुधा मूर्ति और उनके पति व इनफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति ने सर्वे में भाग लेने से यह कहते हुए इनकार किया है कि वे पिछड़े वर्ग से नहीं आते. इस इनकार से अहंकार की बू तो आती ही है, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि विज्ञान और इंजानियरिंग से जुड़े हमारे प्रतिभाशाली लोग न केवल इस देश की जमीन से कटे हुए हैं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक गैरबराबरी को बढ़ावा देने में भी उनका कमोबेश हाथ है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सुधा और नारायण मूर्ति द्वारा सर्वे में शामिल न होने के फैसले पर सख्त प्रतिक्रिया जतायी है. उन्होंने कहा, 'यह समझने की जरूरत है कि यह सर्वे सिर्फ पिछड़े समुदायों के लिए नहीं है....वे इन्फोसिस से हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे सब कुछ जानते हैं.' सिद्धारमैया की यह टिप्पणी श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त हर उस भारतीय के लिए प्रासंगिक हैं, जो मानते हैं कि कुछ खास संस्थाओं या कारोबार से जुड़े होना ही श्रेष्ठता की गारंटी है. यह सर्वविदित है कि जीवन मूल्यों से रहित वैज्ञानिक या तकनीकी ज्ञान लाभ के बजाय नुकसान ही ज्यादा करता है, क्योंकि यह अच्छाई, सामाजिक न्याय या नैतिकता से विहीन होता है. इस संदर्भ में एनरॉन का जिक्र किया जा सकता है, जिसने धोखाधड़ी की, और जिसे 2001 में अमेरिका में दीवालिया होने वाली सबसे बड़ी कंपनी के रूप में जाना जाता है. एनरॉन ने अपने यहां दर्जनों दिग्गज इंजीनियरों तथा पीएचडी डिग्रीधारकों तथा एमबीए की डिग्री वाले सैकड़ों होशियार अधिकारियों की नियुक्ति की थी. काबिल लोगों के उस बड़े समूह ने ही एनरॉन के तेजी से ध्वस्त होने में बड़ी भूमिका निभायी थी.

चूंकि कर्नाटक के प्रस्तावित सामाजिक-आर्थिक सर्वे में भागीदारी करना ऐच्छिक है, इस कारण मूर्ति दंपति अगर अपनी जाति या आर्थिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी न देना चाहे, तो इसके लिए वह स्वतंत्र हैं, तथा इस पर कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए. लेकिन आइटी सेवा के शुरुआती दौर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर भारी सफलता पाने के कारण दोनों निश्चित तौर पर यह अच्छी तरह से जानते होंगे कि पिछड़ी जातियों की बेहतरी के लिए नीति निर्माण और उसके त्वरित क्रियान्वयन में समय पर पेश किये गये ठोस और अद्यतन आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण साबित होते हैं. मूर्ति दंपति ने सर्वे में भाग लेने से इनकार करते हुए जो कुछ कहा, और जिसका जिक्र कुछ रिपोर्टों में है भी, उनमें दूसरों के प्रति तिरस्कार या घृणा की भावना है, जबकि अपने बारे में गहन श्रेष्ठता बोध है कि वे कौन हैं, और जाति, वर्ग तथा दूसरे पदानुक्रमों में उनकी हैसियत क्या है.

सर्वे में भाग लेने से इनकार करते हुए सुधा मूर्ति ने जो कुछ कहा, वह इस तरह है, 'हम पिछड़ी जाति से नहीं आते, इसलिए हम उन समूहों के हित में प्रस्तावित किसी सर्वे में भाग नहीं लेंगे'. उन्होंने जिस हिकारत के साथ 'उन समूहों' का जिक्र किया, वह दरअसल 'हम' और 'वे' का वही विभाजन है, जिसके जरिये हाल के दौर में अपनी श्रेष्ठता और दूसरे की निकृष्टता को रेखांकित किया जाता रहा है. उनके कहने का अर्थ यह था कि 'वे लोग' सरकार से कुछ चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते, इसलिए हम इस सर्वेक्षण में हिस्सेदारी नहीं करेंगे. यह श्रेष्ठता ग्रंथि इतनी खतरनाक है कि इसमें सामाजिक न्याय भी भीख की तरह लगती है. मूर्ति दंपति को पता होना चाहिए कि होने वाली जनगणना में केंद्र सरकार ने भी जाति से संबंधित विस्तृत विवरणों का प्रावधान रखा है. यह बतायेगा कि 'केंद्र सरकार देश और समाज के पवित्रतम जीवन मूल्यों और हितों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है'. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पूछा है कि क्या मूर्ति दंपति उसके साथ भी असहयोग करेंगे.

जाति सर्वेक्षण की आलोचना में कहा जाता है कि यह तुष्टिकरण या रेवड़ियों को कल्याणकारी उपायों के तौर पर पेश करता है. लेकिन इस मामले में अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ही अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर (यूटीसी)-यानी बिना किसी शर्त के नकदी हस्तांतरण की नीति अपनायी है. हाल ही में प्रोजेक्ट डीप की एक रिपोर्ट-'अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स इन इंडिया : ट्रेसिंग द जर्नी, शेपिंग द फ्यूचर' में यह रेखांकित किया गया है कि किस तरह यूटीसी महिलाओं की वित्तीय भागीदारी बढ़ाने और उनके समावेशन में एक प्रभावी औजार सिद्ध हुआ है. यह सामाजिक बाधाएं हटाकर महिलाओं को अर्थव्यवस्था तक सीधी पहुंच प्रदान कर रहा है. वर्ष 2015-16 में केंद्र सरकार ने यूटीसी के तहत 8,560 करोड़ रुपये खर्च किये थे, जो 2023-24 में लगभग आठ गुना बढ़ कर 70,860 करोड़ रुपये हो गये. वर्ष 2015-16 में केंद्र और राज्य सरकारों ने मिल कर यूटीसी के तहत 12,190 करोड़ रुपये खर्च किये थे, जो 2024-25 (बजट अनुमान) में 23 गुना बढ़ कर 2,80,780 करोड़ रुपये हो गये. राज्य सरकारों द्वारा यूसीटी के तहत योगदान तेज किये जाने के कारण यह आंकड़ा इतना बड़ा हो गया. रिपोर्ट के मुताबिक, इस पर सर्वसम्मति थी कि 'यूटीसी के कारण राज्यों द्वारा किये जाने वाले आवश्यक खर्चों को बंद नहीं किया जायेगा. इसके बजाय समानता लाने, अनिश्चितता खत्म करने और कल्याणकारी पहुंच को सुधारने के लिए यूसीटी का इस्तेमाल रणनीतिक औजार के रूप में किया जायेगा'. इस कारण सरकारों को बेहतर सड़क निर्माण तथा गुणवत्ता वाले स्कूल और अस्पताल खोलने का काम जारी रखना चाहिए, जिससे कि नागरिकों का जीवन स्तर सुधरे. रिपोर्ट में इस बारे में चेताया भी गया कि ध्वस्त व्यवस्था में यूटीसी का उपयोग बैंड-एड समाधान की तरह नहीं किया जाना चाहिए.

यह विकास के जटिल स्वरूप को ही रेखांकित करता है. चुनाव गरीबों की मदद करने और सेवाओं के निर्माण के बीच कतई नहीं है. दोनों न सिर्फ जरूरी हैं, बल्कि दोनों में तालमेल भी आवश्यक है. जहां जरूरी है, वहां हमें लक्षित कल्याणकारी योजनाएं चलानी होंगी, और आंकड़े बताते हैं कि इनका असर होता है. इसी के साथ हमें योजनाओं पर कड़ी नजर रखनी होगी, ताकि पाई-पाई का सदुपयोग हो. लेकिन जब ताकतवर लोग और विशेषाधिकार प्राप्त समूह ऐसी राय बनाते हैं, जिनमें सिद्धांतों के बजाय पूर्वाग्रह हावी होता है, तो माहौल खराब हो जाता है, जैसा कि फिलहाल मूर्ति दंपति द्वारा सर्वे में भागीदारी से इनकार करने के कारण हुआ है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

ऋण वितरण में तेजी से विकास को मिलेगी गति

सतीश सिंह
आर्थिक मामलों के जानकार
singhsatish@sbi.co.in

केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए कई सुधार किये हैं, जिनमें बैंकों को गैर-वित्तीय क्षेत्र की भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण के लिए रकम मुहैया कराना, प्रतिभूतियों के एवज में ऋण एवं आइपीओ के वित्तपोषण की अधिकतम सीमा बढ़ाना तथा गृह ऋण व अन्य ऋणों पर जोखिम भार में बदलाव शामिल हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के अनुसार 20 सितंबर से तीन अक्तूबर के दौरान बैंकों की ऋण वृद्धि दर पिछले साल की तुलना में 11.4 फीसदी के स्तर पर पहुंच गयी, जबकि जमा वृद्धि दर 9.9 प्रतिशत के स्तर पर. इस दौरान 3.63 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि के ऋण वितरित किये गये, जबकि इससे पिछले पखवाड़े में ऋण के रूप में वितरित की गयी राशि 1.02 लाख करोड़ रुपये थी. वहीं, इस अवधि में बैंकों में जमा वृद्धि राशि 5.51 लाख करोड़ रुपये थी. गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में ऋण वृद्धि दर 9.5 फीसदी रही थी, जो दूसरी तिमाही तक बढ़कर लगभग 11.4 फीसदी के स्तर तक पहुंच चुकी है. घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार बैंकों की ऋण वृद्धि दर में मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के अंत तक 12 फीसदी के स्तर पर पहुंच जायेगी. माना जा रहा है कि त्योहारी सीजन, सरकारी और नियामकीय उपायों और कॉरपोरेट कर्जदारों के बॉन्ड बाजार से बैंक उधारी को पंख लगेंगे.

हालांकि, निजी पूंजीगत व्यय की वृद्धि में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि निजी कंपनियों का विस्तार वैश्विक अनिश्चितताओं की वजह से अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहा. आम लोगों का बैंक जमा में योगदान भी विगत पांच वर्षों में 64 फीसदी से घटकर 60 फीसदी रह गया है, जिससे बैंकों की डिपॉजिट में कमी आई है. पिछले तीन वर्षों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कुल ऋण में वृद्धि दर घटकर विगत 30 मई को खत्म हुए पखवाड़े में 8.97 फीसदी रह गयी. इस क्षेत्र में सकल एनपीए चालू वित्त वर्ष के अंत तक बढ़कर 16 फीसदी होने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष के 8.8 फीसदी से लगभग दोगुना है. इसलिए बैंक परिसंपत्ति की गुणवत्ता को प्राथमिकता दे रहे हैं. साथ ही, वे अंडरराइटिंग मानकों को लगातार सख्त बना रहे हैं, ताकि एनपीए में वृद्धि न हो. कुल उधारी में वृद्धि की धीमी गति से बकाया ऋण भुगतान अनुपात (एलडीआर) घटकर 78.9 फीसदी रह गया. इंक्रीमेंटल एलडीआर भी एक साल पहले के 98.9 फीसदी से घटकर 72.7 फीसदी रह गया. यह किसी बैंक के कुल ऋणों और उसकी कुल जमा राशि के बीच का अनुपात होता है, जो बैंक की तरलता और वित्तीय सेहत को मापने का महत्वपूर्ण संकेतक है. पिछले साल की समान अवधि में जमा वृद्धि की तुलना में ऋण वृद्धि काफी अधिक रही और इसमें 700 आधार अंकों का अंतर रहा, जिस कारण बैंकिंग प्रणाली में एलडीआर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई.

पिछले साल जुलाई से ऋण वृद्धि में नरमी आयी, जिसका प्रमुख कारण उधारी दर का अधिक होना था. स्थिति पर काबू पाने के लिए इस साल फरवरी से अब तक रेपो दर में कुल 100 आधार अंकों की कटौती की गयी है. फिर भी, फरवरी तक ऊंची ब्याज दर के कारण कई कॉरपोरेट्स ने विदेशों के ऋण पूंजी बाजार की तरफ रुख किया. इस साल दीपावली में कारोबार पिछले साल के मुकाबले 25 फीसदी के उछाल के साथ 5.40 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया, जबकि सेवाओं में 65,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई. यह आंकड़ा दर्शाता है कि इस साल भी हमने चीनी उत्पादों की जगह मेड इन इंडिया को तरजीह दी है. पिछले वर्ष दीपावली में 4.25 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था. फिलहाल, मामले में बैंक ऋण के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, पर इतना कहा जा सकता है कि दीपावली में हुई बिक्री में बैंक उधारी का बड़ा योगदान रहा है. केंद्र सरकार की सकारात्मक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर नीतियों से कर प्रणाली सरल, पारदर्शी और व्यापार-अनुकूल हुई है. जीएसटी और प्रत्यक्ष करों में सुधार से उपभोक्ता खर्च, निवेश, और आर्थिक गतिविधियों और विकास को बढ़ावा मिल रहा है. कर दरों को तर्कसंगत बनाने, अनुपालन को सरल करने और एक स्थिर कर नीति को लागू करने से भारत वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए एक मजबूत केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

जीएसटी की नयी दरें लागू होने से भी निरंतर बचत और व्यय को बढ़ावा मिल रहा है. आयकर के तहत भी नयी कर व्यवस्था से मध्यवर्ग को राहत मिली है. रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति से महंगाई काबू में आई है और रेपो दर में इस साल 100 आधार अंकों की कटौती से बैंकों ने खुदरा और कॉरपोरेट उधारकर्ताओं के लिए ऋण को सस्ता किया है, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने में मदद मिल रही है. केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने और बैंकिंग लागत को कम करने के लिए हाल में कई सुधारों को भी अमली जामा पहनाया है, जिनमें बैंकों को गैर-वित्तीय क्षेत्र की भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण के लिए रकम मुहैया कराना, प्रतिभूतियों के एवज में ऋण एवं आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) के वित्तपोषण की अधिकतम सीमा बढ़ाना और गृह ऋण और अन्य ऋणों पर जोखिम भार में बदलाव शामिल हैं. त्योहारी सीजन, करों को युक्तिसंगत बनाने की पहल, राजकोषीय और मौद्रिक मोर्चों पर लिये गये नीतिगत निर्णयों से चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बैंकों के ऋण वितरण के साथ आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने के आसार हैं.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

वैश्विक स्तर पर कोयले के उपयोग में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज

स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के प्रयासों के बावजूद पिछले वर्ष दुनियाभर में कोयले का उपयोग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिसने वैश्विक तापमान वृद्धि पर लगाम लगाने के वैश्विक प्रयासों को संकट में डाल दिया है. हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के कारण बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी कम हुई है, पर हाल में प्रकाशित 'वार्षिक जलवायु कार्रवाई रिपोर्ट' के अनुसार, बिजली की मांग में सामान्य वृद्धि का अर्थ है कि कोयले का अधिक उपयोग हुआ है. इस रिपोर्ट में जलवायु संकट के बढ़ते गंभीर प्रभावों से बचने की दुनिया की संभावनाओं की चिंताजनक तस्वीर पेश की गयी है. देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए जो लक्ष्य तय किये गये थे, उसमें वे पीछे छूट रहे हैं. इस संबंध में वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट थिंक टैंक की शोध सहयोगी क्ली शूमर का कहना है कि 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम काफी हद तक सही काम कर रहे हैं. पर हम पर्याप्त तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं. हमारे आकलन के सबसे चिंताजनक निष्कर्षों में से एक यह है कि कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के प्रयास पूरी तरह से पटरी से उतर गये हैं.' यदि विश्व को 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचना है, ताकि वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित किया जा सके, तो अधिक क्षेत्रों को तेल, गैस या अन्य जीवाश्म ईंधन के बजाय बिजली का उपयोग करना होगा. पर यह तभी संभव होगा जब वैश्विक बिजली आपूर्ति को कम कार्बन उत्सर्जन वाले स्तर पर लाया जाये. रिपोर्ट की मानें, तो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में तेज वृद्धि दर्ज हुई है और सौर ऊर्जा इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऊर्जा स्रोत बन गयी है. हालांकि, यह उपलब्धि अब भी पर्याप्त नहीं है, इस दशक के अंत तक दुनिया को आवश्यक उत्सर्जन कटौती करने के लिए सौर और पवन ऊर्जा की वार्षिक वृद्धि दर को दोगुना करना होगा.

The Guardian

-फ्लोरिना हार्वे

बोधि वृक्ष

सच्चे अध्यात्म की खोज

मानव सृष्टि में धर्म और अध्यात्म शक्ति महत्वपूर्ण स्थान रखती है. इसलिए इन शक्तियों का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व है. अमूमन हम सभी, धर्म और अध्यात्म को एक जैसा ही समझते हैं, इसलिए आज समाज में दो भिन्न सभ्यताओं को लेकर काफी सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं. पर वास्तव में देखा जाये, तो धर्म और अध्यात्म में बहुत अंतर है. आध्यात्मिकता मनुष्य की आत्मा के मूल गुण, स्वभाव और संस्कार का नाम है, इसलिए सार्वभौमिक सत्य होने के कारण उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम और सभी धर्मों के मनुष्यों को वह सहज स्वीकार्य है. आम तौर पर जब आध्यात्मिकता के बारे में कोई बात चलती है, तब लोग भगवान, धर्म, रीति-रिवाज आदि के बारे में ही सोचते हैं. जैसे, कोई व्यक्ति जो प्रतिदिन मंदिर जाकर पूजा-अर्चना करता है, वह स्वयं को बहुत आध्यात्मिक समझता है, फिर भले ही उसका मन पूजा करने में कम और यहां-वहां की बातों में ज्यादा व्यस्त क्यों न हो. इन्हीं सब बातों के कारण आज की आधुनिक पीढ़ी यह समझती है कि व्यावहारिकता और आध्यात्मिकता का दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है. इसी कारण वह इसे अव्यावहारिक समझती है. पर वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि आध्यात्मिकता में सांप्रदायिकता तथा रूढ़ियों का कोई स्थान नहीं होता. वहां तो जो सत्य है, वही स्वाभाविक रूप से ग्रहण किया जाना चाहिए. अमूमन लोगों की यह मान्यता होती है कि घर-बार छोड़े बिना आत्मज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है, परंतु आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के अनुसार, मन की शांति या आत्मबोध की प्राप्ति के लिए अपनी समस्त मानसिक कमजोरियों का त्याग कर स्वयं को आंतरिक स्तर पर स्थिर कर भीतर से जो आदेश मिले उसका पालन करके हम अपनी आत्मा को प्रबुद्ध कर सकते हैं. दुर्भाग्य से, आज समाज के अंदर अध्यात्मवाद की चर्चा तो बड़े पैमाने पर होती है, परंतु उसकी वास्तविकता का लोप हो रहा है. हमें इसे किंचित भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा व्यक्तिगत और अतः हमें सच्चे अध्यात्मवाद की तलाश करनी चाहिए और उसे ही अपनाना चाहिए.

-ब्रह्माकुमार निकुंज जी

कुछ अलग

अदालतों का बोझ घटाने वाली पहल

देवेंद्रराज सुथार
टिप्पणीकार
devendrakavi1@gmail.com

इसी वर्ष अगस्त में सिक्किम ने महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को नयी दिशा देते हुए नारी अदालत की शुरुआत की है, जिसे मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पहले 'अम्मा सम्मान दिवस' के अवसर पर लॉन्च किया. यह एक सामुदायिक न्याय मंच है, जिसका संचालन पूरी तरह महिलाओं द्वारा किया जायेगा. इसका उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को न्याय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका देना और छोटे विवादों का त्वरित व सहानुभूतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है.

भारत में औपचारिक न्याय व्यवस्था जटिल, महंगी और समय लेने वाली है. नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड के अनुसार, 2024 तक देश की अदालतों में पांच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें कई ऐसे हैं जिन्हें स्थानीय स्तर पर सुलझाया जा सकता है. ऐसे में नारी अदालत जैसी पहल महिलाओं और समुदाय को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने का सरल और प्रभावी माध्यम बन सकती है. इस पहल का मूल आधार संवाद, मध्यस्थता और आम सहमति पर आधारित है, जो पारंपरिक अदालतों की औपचारिक कानूनी प्रक्रियाओं से अलग है. इसमें पारिवारिक मतभेद, गैर-गंभीर घरेलू हिंसा के मामले, वैवाहिक विवाद और सामुदायिक टकराव जैसे मुद्दों का समाधान किया जायेगा. विवाद का निपटारा समुदाय के भीतर होने से यह न केवल समय बचायेगा, बल्कि पक्षकारों को सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त समाधान भी देगा. यह मॉडल भारत के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से प्रचलित पारंपरिक समुदाय आधारित विवाद समाधान प्रणालियों से प्रेरित है, जिनमें पंच, महिला मंडल या ग्राम सभा की मध्यस्थता शामिल रही है.

इस प्रणाली से औपचारिक न्यायालयों पर दबाव कम होगा, क्योंकि कम गंभीर मामलों का निपटारा स्थानीय स्तर पर हो सकेगा. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 245वीं रिपोर्ट ने भी सुझाव दिया था कि छोटे मामलों के समाधान के लिए वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र को बढ़ावा देना चाहिए. नारी अदालत इसी दिशा में एक ठोस कदम है, जो न केवल विवाद सुलझाने का मंच देती है, बल्कि संवाद और सहयोग की संस्कृति को भी मजबूत बनाती है. इस पहल का व्यापक प्रभाव सामुदायिक एकजुटता और सामाजिक समरसता पर पड़ेगा. जब विवाद का समाधान संवेदनशील और स्थानीय दृष्टिकोण से होता है, तो पक्षकारों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ता है. नारी अदालत की सफलता अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन सकती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां महिलाएं अब भी न्याय तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करती हैं.

आपके पत्र

विकास की दौड़ व भूख की चुनौती

प्रत्येक देश विकास के पथ पर अग्रसर होने का दावा करता है. अल्पविकसित देश विकासशील बनना चाहते हैं, वहीं विकासशील राष्ट्र विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने की होड़ में हैं. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकारें प्रयास करती हैं. जब विकास के दावों के बीच कोई ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो यह दर्शाता हो कि देश अभी भी 'भूख' जैसी मूलभूत समस्या का समाधान नहीं कर पाया है, तब विकास के सभी आंकड़े अधूरे और निरर्थक लगने लगते हैं.

प्रसिद्ध यादव, बाबूचक (फुलवारीशरीफ)

छठ से जुड़ी हैं परंपराएं

महापर्व छठ पूजा सिर्फ एक पर्व ही नहीं है, बल्कि इसमें हमारी परंपराओं से जुड़ी यादें भी छुपी हैं. इस पर्व के माध्यम से हमारे सभी बिछड़े परिवार एक साथ नजर आते हैं. माता-पिता, भाई व बहन सभी लोग एक साथ बैठकर बचपन की यादों को एक दूसरे से साझा करते हैं और खूब मजे लेते हैं. ये सालभर का एक ऐसा वक्त होता है जिसमें हमारी खुशी व इमोशन छुपी होती है. वास्तव में यह पर्व हमें सिखाती है कि जिंदगी की क्या अहमियत है. इसलिए हमारी अपील है कि आपलोग पूरी ईमानदारी से इस शुभ समय को अपने परिवार को दीजिए.

विमलेंद्र रौनी, सीतामढ़ी

पोस्ट करें : प्रभात खबर, प्लॉट संख्या डी-9-10, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना (बिहार) - 800013, ■ मेल करें : patna @prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

Join My Official Private Channel

GET ACCESS TO 3 NEWSPAPERS CHANNELS MENTIONED BELOW:

Indian Newspapers:

In Just
19 Rupees

1) Times of India
2) Hindustan Times
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) The Hindu
7) Live Mint
8) Financial Express
9) Business standard
+All Editorial PDFs

Click below to

Join

International Newspapers Channel

Magazine Channel (National & International)